सत्यमेव जयते

भारत सरकार

# परिणाम बजट
# 2012-2013

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

# विषय-सूची

## कार्यकारी सारांश

### सूचना क्षेत्र


विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय ..... 2
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय ..... 3
एम्पलॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार ..... 4
भारतीय जन संचार संस्थान ..... 4
फोटो प्रभाग ..... 6
भारतीय प्रेस परिषद ..... 6
पत्र सूचना कार्यालय ..... 8
प्रकाशन विभाग ..... 9
भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय ..... 10
गवेषणा संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग ..... 10
गीत एवं नाटक प्रभाग ..... 11
मुख्य सचिवालय की सूचना विंग की स्कीमें
(क) सूचना भवन का निर्माण चरण-V ..... 11
(ख) पूर्वोत्तर राज्यों/जम्मू एवं कश्मीर एवं अन्य चिह्नित क्षेत्रों में विकास ..... 11
(ग) अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम ..... 12
(घ) नीति संबंधी अधययन, सेमिनार, मूल्यांकन आदि। प्रसार भारती को छोड़कर सभी तीनों क्षेत्र ..... 13
(ङ) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण (प्रसार भारती को छोड़कर) ..... 13


### फिल्म क्षेत्र


केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ..... 15
बाल फिल्म समिति, भारत ..... 15
फिल्म समारोह निदेशालय ..... 16

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे ..... 17
फिल्म प्रभाग ..... 17
भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ..... 18
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ..... 18
सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता ..... 19
मुख्य सचिवालय की फिल्म विंग की स्कीमें
(क) एंटी पायरेसी में पहल ..... 19
(ख) भारतीय सिनेमा के 100 वर्षों (1913-2013) पर आयोजन ..... 19
(ग) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन ..... 19
(घ) भारत और विदेशों में फिल्म समारोहों और फिल्म बाजारों के जरिए भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना ..... 20
(ङ) विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों तथा वृत्तचित्रों का निर्माण ..... 20
(च) ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना ..... 22

**प्रसारण क्षेत्र**

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी) ..... 23
एफएम सैल ..... 24
प्रसार भारती ..... 25
मुख्य सचिवालय के प्रसारण विंग की स्कीमें
(क) अन्तरराष्ट्रीय चैनल ..... 30
(ख) सामुदायिक रेडियो ..... 30

**अध्याय - I**

**उद्देश्य एवं लक्ष्य, नीति निर्धारण एवं नीतिगत ब्यौरा**

**सूचना क्षेत्र**

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय ..... 31
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय ..... 32
एम्पलॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार ..... 32
भारतीय जन संचार संस्थान ..... 33
फोटो प्रभाग ..... 36

भारतीय प्रेस परिषद ..... 36
प्रकाशन विभाग ..... 36
भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय ..... 45
गवेषणा संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग ..... 46
गीत एवं नाटक प्रभाग ..... 48
मुख्य सचिवालय की सूचना विंग की स्कीमें
(क) सूचना भवन का निर्माण चरण-V ..... 49
(ख) पूर्वोत्तर राज्यों/जम्मू एवं कश्मीर एवं अन्य चिह्नित क्षेत्रों में विकास ..... 49
(ग) अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम ..... 50
(ग) नीति संबंधी अधययन, सेमिनार, मूल्यांकन आदि। प्रसार भारती को छोड़कर सभी तीनों क्षेत्र ..... 51
(ङ) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण (प्रसार भारती को छोड़कर) ..... 51

## फिल्म क्षेत्र

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ..... 52
बाल फिल्म समिति, भारत ..... 52
फिल्म समारोह निदेशालय ..... 53
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे ..... 54
फिल्म प्रभाग ..... 55
भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ..... 55
सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता ..... 56
मुख्य सचिवालय की फिल्म विंग की स्कीमें
(क) एंटी पायरेसी में पहल ..... 57
(ख) भारतीय सिनेमा के 100 वर्षों (1913-2013) पर आयोजन ..... 57
(ग) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन ..... 57
(ग) भारत और विदेशों में फिल्म समारोहों और फिल्म बाजारों के जरिए भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना ..... 58
(ङ) विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों तथा वृत्तचित्रों का निर्माण ..... 58
(च) ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना ..... 59

**प्रसारण क्षेत्र**


इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी) ..... 60

एफएम सैल ..... 60

प्रसार भारती ..... 60

मुख्य सचिवालय के प्रसारण विंग की स्कीमें

(क) अन्तरराष्ट्रीय चैनल ..... 68

(ख) सामुदायिक रेडियो ..... 68


**अध्याय - II**

**वित्तीय परिव्यय, अनुमानित वास्तविक परिणाम एवं अनुमानित परिणाम**

**सूचना क्षेत्र**


विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय ..... 69

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय ..... 71

एम्पलॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार ..... 74

भारतीय जन संचार संस्थान ..... 76

फोटो प्रभाग ..... 78

भारतीय प्रेस परिषद ..... 80

प्रकाशन विभाग ..... 84

भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय ..... 88

गवेषणा संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग ..... 90

गीत एवं नाटक प्रभाग ..... 93

मुख्य सचिवालय की सूचना विंग की स्कीमें

(क) सूचना भवन का निर्माण चरण-V ..... 104

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों/जम्मू एवं कश्मीर एवं अन्य चिह्नित क्षेत्रों में विकास ..... 105

(ग) अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम ..... 107

(ग) नीति संबंधी अधययन, सेमिनार, मूल्यांकन आदि। प्रसार भारती को छोड़कर सभी तीनों क्षेत्र ..... 109

(ङ) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण (प्रसार भारती को छोड़कर) ..... 110

**फिल्म क्षेत्र**

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ..... 112
बाल फिल्म समिति, भारत ..... 114
फिल्म समारोह निदेशालय ..... 116
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे ..... 118
फिल्म प्रभाग ..... 120
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ..... 123
सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता ..... 124
मुख्य सचिवालय की फिल्म विंग की स्कीमें
(क) एंटी पायरेसी में पहल ..... 128
(ख) भारतीय सिनेमा के 100 वर्षों (1913-2013) पर आयोजन ..... 129
(ग) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन ..... 130
(ग) भारत और विदेशों में फिल्म समारोहों और फिल्म बाजारों के जरिए भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना ..... 131
(ङ) विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों तथा वृत्तचित्रों का निर्माण ..... 133
(च) ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना ..... 134

**प्रसारण क्षेत्र**

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी) ..... 135
एफएम सैल ..... 136

मुख्य सचिवालय के प्रसारण विंग की स्कीमें

(क) अन्तरराष्ट्रीय चैनल ..... 137
(ख) सामुदायिक रेडियो ..... 138
दूरदर्शन ..... 140

**अध्याय - III**

**सुधार के लिए उठाए गए कदम और नीतिगत पहल**

**सूचना क्षेत्र**

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय ..... 151

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय ..... 152
एम्पलॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार ..... 152
प्रकाशन विभाग ..... 153
भारतीय जन संचार संस्थान ..... 154
फोटो प्रभाग ..... 154
भारतीय प्रेस परिषद ..... 154
पत्र सूचना कार्यालय ..... 155
भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय ..... 156
गवेषणा संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग ..... 156
गीत एवं नाटक प्रभाग ..... 157
मुख्य सचिवालय की सूचना विंग की स्कीमें
(क) सूचना भवन का निर्माण चरण-V ..... 157
(ख) पूर्वोत्तर राज्यों/जम्मू एवं कश्मीर एवं अन्य चिह्नित क्षेत्रों में विकास ..... 158
(ग) अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम ..... 158

**फिल्म क्षेत्र**

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ..... 159
बाल फिल्म समिति, भारत ..... 159
फिल्म समारोह निदेशालय ..... 159
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे ..... 160
फिल्म प्रभाग ..... 160
भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ..... 160
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ..... 160
सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता ..... 161
मुख्य सचिवालय की फिल्म विंग की स्कीमें
(क) एंटी पायरेसी में पहल ..... 161
(ख) भारतीय सिनेमा के 100 वर्षों (1913-2013) पर आयोजन ..... 161
(ग) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन ..... 161

(ग) भारत और विदेशों में फिल्म समारोहों और फिल्म बाजारों के जरिए भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना ..... 161
(ङ) विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों तथा वृत्तचित्रों का निर्माण ..... 162
(च) ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना ..... 162

**प्रसारण क्षेत्र**

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी) ..... 162
एफएम सैल ..... 163
प्रसार भारती ..... 163
मुख्य सचिवालय के प्रसारण विंग की स्कीमें

(क) अन्तरराष्ट्रीय चैनल ..... 166
(ख) सामुदायिक रेडियो ..... 166

**अध्याय - IV**

**सूचना क्षेत्र**

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय ..... 167
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय ..... 172
एम्पलॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार ..... 177
भारतीय जन संचार संस्थान ..... 178
फोटो प्रभाग ..... 181
भारतीय प्रेस परिषद ..... 183
प्रकाशन विभाग ..... 189
भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय ..... 193
गवेषणा संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग ..... 197
गीत एवं नाटक प्रभाग ..... 201
मुख्य सचिवालय की सूचना विंग की स्कीमें

(क) सूचना भवन का निर्माण चरण-V ..... 203
(ख) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण (प्रसार भारती को छोड़कर) ..... 205

**फिल्म क्षेत्र**

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ..... 206
बाल फिल्म समिति, भारत ..... 207
फिल्म समारोह निदेशालय ..... 209
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे ..... 212
फिल्म प्रभाग ..... 214
भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ..... 218
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ..... 220
सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता ..... 221
मुख्य सचिवालय की फिल्म विंग की स्कीमें
(क) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन ..... 223
(ख) भारत और विदेशों में फिल्म समारोहों और फिल्म बाजारों के जरिए भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना ..... 224
(ग) विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों तथा वृत्तचित्रों का निर्माण ..... 227
(घ) ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना ..... 228

**प्रसारण क्षेत्र**

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी) ..... 229
एफएम सैल ..... 230
आकाशवाणी ..... 231
प्रसार भारती ..... 246

**अध्याय - V**

वित्तीय समीक्षा ..... 276

**अध्याय - VI**

**स्वायत्तशासी संस्थाओं का प्रदर्शन एवं समीक्षा**

**प्रसारण क्षेत्र**

भारतीय जन संचार संस्थान ..... 296

भारतीय प्रेस परिषद ..... 296

**फिल्म क्षेत्र**

बाल फिल्म समिति, भारत ..... 297
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे ..... 298
सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता ..... 299

**प्रसारण क्षेत्र**

एफएम सैल ..... 301
प्रसार भारती ..... 301
मुख्य सचिवालय के प्रसारण विंग की स्कीमें ..... 301
सामुदायिक रेडियो ..... 301

# कार्यकारी सारांश

माध्यम एककों सहित (प्रसार भारती) नई स्कीम को छोड़ कर सभी तीनों क्षेत्रों के लिए नीतिगत अध्ययन, संगोष्ठी, मूल्यांकन आदि का विवरण : –

अर्थव्यवस्था में मनोरंजन तथा मीडिया क्षेत्र का अत्यंत प्रभावकारी विकास हुआ है। कार्य में विकास को गति प्रदान करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा फिल्म सूचना और प्रसारण क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों/उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्कीमें/कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही नियमित निगरानी और मूल्यांकन हेतु एक क्रियाविधि का प्रतिपादित किया जाना भी आवश्यक है। यह स्कीम माध्यम एककों सहित (प्रसार भारती को छोड़कर) सभी तीनों क्षेत्रों के लिए नीतिगत अध्ययन, संगोष्ठी, मूल्यांकन आदि पर 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान लागू की जाएगी जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं : –

- फिल्म, सूचना तथा प्रसारण क्षेत्रों में सूचना प्रबंधन प्रणाली का विकास करना।
- फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्रों में विनियामक और विकास नीतियों के प्रभाव के संबंध में अध्ययन और मूल्यांकन करना।
- संगोष्ठी कार्यशाला का आयोजन करना तथा उनमें भाग लेना और मनोरंजन विषयक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं में कागजातों/प्रलेखों का प्रस्तुतिकरण करना।
- मीडिया तथा मनोरंजन क्षेत्रों में नवीनता को बढ़ावा देने के लिए क्रियाकलापों से संबंधित कार्य करना।

# सूचना क्षेत्र

## विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

**(क) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय का कार्य** : विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को प्रचारित करने वाली नोडल मल्टी मीडिया एजेंसी है। यह प्रेस विज्ञापनों, टीवी स्पॉट तथा केबल और सेटेलाइट नेटवर्क चैनलों, रेडियो/टेलीविजन पर प्रायोजित कार्यक्रमों, स्पॉट/जिंगल्स, डिजीटल सिनेमा, प्रदर्शनियों, मुद्रित प्रचार सामग्रियों और बाहरी प्रचार माध्यमों की सहायता से केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए प्रचार अभियान चलाती है।

**(ख) योजना स्कीमों के लिए निधियों में सुधार :** शीर्षस्थ कार्यक्रमों के संपूर्ण तरीके से प्रचार को सशक्त करने और उसकी सेवाओं/कार्यों को प्रभावी बनाने हेतु विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय को दो सुनियोजित योजनाओं – 1. विकास प्रचार कार्यक्रम : अवधारणा एवं प्रसार (जारी योजना) और 2. डीएवीपी का आधुनिकीकरण (नई योजना) हेतु मंजूरी प्राप्त की गई है। व्यय समिति ने डीएवीपी को अद्यतन पंचवर्षीय योजना 2007–12 के अंतर्गत विगत दो वर्षों के लिए निधियों में वृद्धि को अनुमोदित कर दिया है।

तथापि डीएवीपी ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिए विकास प्रचार (अवधारणा और प्रसार) के माध्यम से लोक सशक्तिकरण स्कीम के अंतर्गत 700 करोड़ रुपये तथा डीएवीपी के पुनरुद्धार और पुनर्गठन हेतु 15 करोड़ रुपये के सैद्धांतिक व्यय की सिफारिश की है।

| वर्षवार प्रस्तावित आबंटन (करोड़ रुपये में) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **(I) विकास माध्यम के द्वारा लोगों में अधिकारिता (अवधारणा एवं प्रसारण)** | | | | | |
| 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 | 2015–16 | 2016–17 | योग |
| **100.00** | **120.00** | **140.00** | **160.00** | **180.00** | **700.00** |
| **(II) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय का पुनरुद्धार एवं पुनर्गठन** | | | | | |
| 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 | 2015–16 | 2016–17 | योग |
| **10.00** | **5.00** | -- | -- | -- | **15.00** |

**(ग) प्रचार को सुस्पष्ट और सरल बनाया जाना :** सरकारी विज्ञापनों और प्रचार के विभिन्न पहलुओं को सुस्पष्ट एवं कारगर बनाने तथा इस संबंध में और अधिक पारदर्शिता लाने हेतु सरकार ने प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रानिक माध्यम से विज्ञापन/प्रचार के संबंध में नई विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार नीति जारी की है। समाचार पत्रों की नई सूची बनाई गई है जबकि श्रव्य-दृश्य मीडिया की दरों का निर्धारण प्रक्रियाधीन है।

**(घ) इलेक्ट्रानिक भुगतान माध्यम :** भुगतान की गति और उसमें सुधार लाने के लिए डीएवीपी ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक फाइल ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से भुगतान करना प्रारंभ कर दिया है ताकि इसमें पारदर्शिता लाई जा सके। बिलों की स्थिति वेबसाइट www.davp.nic.in पर मॉनीटर की जा सकती है।

**(ड) आरटीआई मामलों से संबंधित शिकायतों के निवारण को सरल तथा सुस्पष्ट बनाया जाना :** डीएवीपी की आरटीआई से संबंधित व्यवस्था को विकेंद्रित करते हुए विंग के प्रत्येक निदेशक को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी बनाया जा रहा है। यह भी उल्लेख किया जाता है कि डीएवीपी ने नागरिक चार्टर में भी संशोधन किया है। **सेवोत्तम** व्यवस्था के तहत शिकायतों का निवारण हो सके जिसके द्वारा नागरिकों को समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराई जा सके।

**(त) काम पर निगरानी/जांच :** डीएवीपी की योजना स्कीमों/गैर योजना व्यय पर वित्तीय एवं प्रत्यक्ष उपलब्धियों अर्थात वार्षिक योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों की विश्लेषण के माध्यम से नियमित रूप से समीक्षा तथा जांच की जाती है।

**(थ) डीएवीपी की संरचना एवं सेवाओं का आधुनिकीकरण :** डीएवीपी के आधुनिकीकरण एवं सेवा अदायगी के संबंध में निष्पक्ष परामर्शदाता एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है जिसे अब बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित किया जाएगा।

**(द) प्रभावी मूल्यांकन :** डीएवीपी अब बाहर की एजेंसियों से मंत्रालयों/विभागों के लिए चलाए जा रहे विज्ञापन अभियान के परिणामों/प्रभावों के मूल्यांकन को सरल एवं सुस्पष्ट तरीकों और प्रक्रिया के लिए प्रयासरत है। इस संबंध में एक व्यापक मसौदा मंत्रालय के अनुमोदन एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रस्तावित है।

## क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय का मुख्य उद्देश्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में आम लोगों को जानकारी देना और लक्षित समूहों में विशेषकर दूर-दराज के लोगों में स्वास्थ्य, राष्ट्रीय एकता और अन्य सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरुकता पैदा करना है। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय और अधिक सुधारों एवं इस विषय में संशोधन हेतु जनता से प्राप्त फीडबैक भी सरकार को देता है।

सूचना को तीव्र गति से तथा प्रभावी ढंग से पहुंचाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय मल्टीमीडिया प्रोजेक्टरों, डीवीडी प्लेयरों और वायरलेस पब्लिक ऐड्रेस प्रणालियों आदि के माध्यम, फिल्म प्रदर्शनों तथा अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि का उपयोग करता है। प्रचार के लिए यह विभिन्न भाषाओं में अनेक विषयों पर अलग-अलग माध्यमों - फिल्म प्रभाग, एनएफडीसी, सीएफडी आदि के माध्यम से फिल्मों और कैसेटों की खरीद भी करता है। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय देशभर की सभी 207 क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों तथा 22 क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए त्वरित और शीघ्र संचार हेतु आई टी उपकरणों का भी इस्तेमाल करता है। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के कामकाज की निगरानी नियमित रूप से की जाती है। सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए देशभर से प्रतिक्रियाएं प्राप्त की जाती हैं। व्यय की स्थिति की जानकारी हासिल करने के लिए क्षेत्रीय प्रचार निदेशलय से समय-समय पर व्यय विवरणों और तिमाही कार्य निष्पादन रिपोर्टें भी मंगाई जाती हैं। किसी महीने के कार्यक्रम के विभिन्न स्वरूपों का इस्तेमाल करके चलाए गए कार्यक्रमों की संख्या के बारे में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय से भी इसी प्रकार की रिपोर्टें मंगाई जाती हैं और किसी अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में उनकी जांच परख भी की जाती है।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की वेबसाइट को समय समय पर अद्यतन किया जाता है और ऐसी सभी तर्कसंगत सूचनाओं को साइट में सम्मिलित कर लिया जाता है ताकि आम लोग आसानी से उन तक पहुंच सकें।

## एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार

साप्ताहिक रोजगार समाचार अंग्रेजी, हिंदी तथा उर्दू में प्रकाशित होता है। यह प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का प्रमुख प्रकाशन है। इस साप्ताहिक पत्र में केंद्रीय एवं राज्य सरकारें, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, स्वायत्त निकायों, विश्वविद्यालयों, विदेशी संस्थानों जैसे फोर्ड फाउंडेशन, ब्रिटिश काउंसिल आदि में नौकरियों के विज्ञापन, व्यावसायिक पाठयक्रमों के लिए प्रवेश अधिसूचनाएं, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग जैसे संगठनों तथा अन्य सामान्य भर्ती निकायों की परीक्षा अधिसूचनाएं और उनके परिणामों तथा मध्य-स्तरीय रोजगार उन्नयन के अवसरों (प्रतिनियुक्तियों) की सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त एक सम्पादकीय हिस्सा भी है जो कैरियर से सम्बन्धित दो मुख्य लेख प्रकाशित करता है।

इस साप्ताहिक पत्र का मूल लक्ष्य सिविल सेवा के अभ्यार्थियों, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं तथा साक्षात्कार में बैठने वाले उम्मीदवारों, अपने कैरियर तथा पेशे को चुनने के लिए तैयार युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करना है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि अपनी सामाजिक जिम्मेवारी, जिसके लिए इस पत्र को शुरू किया गया था, निभाने के साथ-साथ एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार नियमित रूप से पर्याप्त लाभ कमा रहा है। यह पत्र, जिसे सबसे अधिक प्रसारित साप्ताहिक पत्रों में शामिल होने का गौरव प्राप्त है, हर शनिवार को देश के कोने-कोने में उपलब्ध होता है।

एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार की वेबसाइट www.employmentnews.gov.in बहुत अधिक सफल है तथा युवाओं में बहुत लोकप्रिय है। हर रोज औसतन 20,000 से अधिक लोग इस वेबसाइट को खोलते हैं।

## भारतीय जन संचार संस्थान

भारत सरकार ने वर्ष 1965 में भारतीय जन संचार संस्थान की स्थापना की थी। यह संस्थान 18.8.1966 को सोसायटीज़ रजिस्ट्रेशन अधिनियम (XXI), 1860 के अंतर्गत सोसायटी के रूप में दर्ज किया गया था।

भारतीय जन संचार संस्थान के मुख्य लक्ष्य हैं देश के सामाजिक-आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के विशेष संदर्भ में जन संचार के मीडिया के प्रयोग एवं विकास में शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध का आयोजन करना।

भारत सरकार सूचना व प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से कुल वार्षिक मदद अनुदान के रूप में इस संस्थान को वित्त प्रदान करता है।

भारतीय जन संचार संस्थान के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स आम लोगों के लिए खुले हैं और लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। यह संस्थान विदेश मंत्रालय के सहयोग से विकासशील देशों के कार्यरत पत्रकारों और सूचना अधिकारियों के लिए प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के दौरान विकास पत्रकारिता में दो कोर्सों का आयोजन करता है।

यह संस्थान भारतीय सूचना सेवा (आईआइएस) के गुप 'ए' और ग्रुप 'बी' के परिवीक्षार्थियों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रमों का भी आयोजन करता है। भारत सरकार के विभिन्न विभागों/संगठनों के अधिकारियों के लिए और आम लोगों के लिए भी कई अन्य अल्पकालीन पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। यह संस्थान लोक मीडिया से संबंधित विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं का आयोजन करता है। अधिकांश अध्ययन प्रायोजित होता है। यह समय-समय पर पत्रकारिता/ जनसंपर्क पर पुस्तकें आदि भी प्रकाशित करता है।

भारतीय जन संचार संस्थान मीडिया एवं संचार उद्योग की जरूरतों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रबंध आयोजित करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय तथा अकादमिक स्तर की बराबरी हेतु भारतीय जन संचार संस्थान को अब शुरुआती स्तर से परे आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन तथा अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक जगत में स्वयं के पुनर्विन्यास की भी आवश्यकता है। भारतीय जन संचार संस्थान को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियों तथा डाक्ट्रेट कार्यक्रमों की पहल के स्तर तक लाने हेतु अपने पाठ्यक्रमों को सशक्त करने के अलावा मौलिक अनुसंधान कार्य भी अपेक्षित हैं। इसके फलस्वरूप इस संस्थान को सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के मीडिया सूचना और संचार मामलों पर सुनियोजित तरीके से बड़े पैमाने पर कार्य करने में बड़ी सहायता मिलेगी।

यह अनुभव किया गया है कि वर्तमान स्थिति में इस संस्थान द्वारा चलाए जा रहे एक वर्षीय एडवांस पाठ्यक्रमों को दो वर्षीय एडवांस पाठ्यक्रमों के समकक्ष घोषित किया जाए। वर्तमान में भारतीय जन संचार संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया विश्वविद्यालय के स्तर तक अपग्रेड करने हेतु संचार अनुसंधान विभाग को सशक्त किए जाने की आवश्यकता अनिवार्य होगी। भारतीय जन संचार संस्थान को संसद अधिनियम द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित/एलान के पश्चात एडवांस पाठ्यक्रम तथा डायरेक्ट कार्यक्रम शुरु किए जा सकते हैं।

## योजनागत गतिविधियां

उपर्युक्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए योजना स्कीम भारतीय जन संचार संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेडेशन विषयांतर्गत सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में 62.00 करोड़ रुपये के सकल परिव्यय के लिए 51.50 करोड़ रुपये का बजट अनुमोदित किया है। फिर भी इस स्कीम के प्रत्यक्ष लक्ष्यों को धीरे-धीरे अर्थात वर्ष 2010-11 से 2016-17 सात वर्षों में प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना स्कीम के अंतर्गत चार नए केंद्र जम्मू कश्मीर, मिजोरम, महाराष्ट्र (विदर्भ) तथा केरल राज्यों में खोले जाना प्रस्तावित है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नई योजना ''भारतीय जन संचार संस्थान के नए क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना'' के अतर्गत भारतीय जन संचार संस्थान द्वारा प्रस्तावित सकल परिव्यय 129.20 करोड़ रुपये अनुमोदित हुए हैं।

## जन सूचना तंत्र

भारतीय जन संचार संस्थान की वेबसाइट www.iimc.gov.in आम जनता के लिए उपलब्ध है और वे इसे वेबसाइट के माध्यम से भारतीय जन संचार संस्थान की सारी गतिविधियों की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसके डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु देश के विभिन्न अग्रणी दैनिक समाचारपत्रों में सूचना प्रकाशित की जाती है। सूचनाप्रद माध्यम विकसित करने तथा सामाजिक दायित्वों के भली भांति निवर्हन के उद्देश्य से इस संस्थान का सामुदायिक रेडियो केंद्र समुदाय से कार्यक्रमों को 96.3 मेगाहट्ज पर प्रसारित करता है। अपना रेडियो ने गैर सरकारी संगठनों, सरकारी विभागों, सामाजिक सेवा संगठनों तथा डच बैले से गठजोड़ कर लिया है। वर्तमान में सायं 3 बजे से 5 बजे तक सामुदायिक रेडियो केंद्र पर रोजाना प्रसारित किया जाता है तथा दूसरे दिन दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक पुन: प्रसारण किया जाता है। प्रसारण के समय में और अधिक बढ़ोतरी किए जाने का प्रयास किया जाएगा।

## निगरानी तंत्र

प्रत्यक्ष और वित्तीय लक्ष्यों के बारे में नियमित रूप से रिपोर्ट भेजी जाती है और उस पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निगरानी रखी जाती है।

# फोटो प्रभाग

फोटो प्रभाग भारत सरकार की एक मीडिया इकाई है जो आंतरिक और बाह्य प्रचार के लिए फोटोग्राफ्स तैयार करने एवं दृश्य प्रलेखन के लिए उत्तरदायी है। फोटो प्रभाग देश के विकास के विभिन्न पहलुओं और ऐतिहासिक घटनाओं का रिकार्ड रखता है और देश को एक समग्र फोटोग्राफिक दस्तावेज उपलब्ध कराता है। यह फोटो प्रतियोगिताओं तथा कार्यशालाओं के माध्यम से युवाओं को बढ़ावा देता है। विभाग अपनी मूल्य योजना के द्वारा प्रचार-इतर संगठनों और आम जनता को भी भुगतान करने पर फोटोग्राफ उपलब्ध कराता है। फोटोग्राफिक उद्योग में बदलती प्रवृत्तियों के मद्देनज़र तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष जोर देते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय फोटोग्राफी केंद्र एवं पूवोत्तर राज्यों के लिए विशेष अभियान नमक एक प्लान योजना कार्यान्वित की गई है जिससे कि प्रयोक्ताओं/ग्राहकों को बेहतर सेवा और गुणवत्ता दी जा सके तथा उनकी वर्तमान मांगों को पूरा किया जा सके।

# भारतीय प्रेस परिषद

प्रेस परिषद ने नीति एवं निर्णय पर सक्रियता के पक्ष में सुदृढ़ प्रभाव के लिए इस वर्ष शुरुआत की। न्यायाधीश श्री एम. काटजू ने दिनांक 05 अक्तूबर, 2011 को अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालते हुए उत्तरोन्मुखी लोकतंत्र में मीडिया की चतुर्थ स्तंभ के रूप में संभावित भूमिका पर मीडिया में तथा मीडिया के साथ ही नागरिकों में वाद-विवाद और आत्म निरीक्षण की शुरुआत करने की बात कही। उनके मार्गदर्शन में परिषद ने मीडिया को अपनी शक्ति और कमजोरियों को पहचानने और अपने विचारों के माध्यम से आमजन को दिशा देने के लिए ही नहीं बल्कि दृढ़ता के साथ प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि मीडिया अपने कार्यों को स्वतंत्र एवं निष्पक्षता के साथ निर्वहन करने में सक्षम है।

दसवीं परिषद का समय 6 जनवरी, 2011 को समाप्त हुआ था। 11वीं परिषद 15 जून, 2011 को अस्तित्व में आई और इस नवगठित परिषाद ने 31 दिसंबर, 2011 तक एक जांच के द्वारा मीडिया के मानकों और इसकी स्वतंत्रता दोनों को प्रभावित करते हुए 50 मामलों पर फैसला दिया जबकि प्रेस परिषद अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाए जाने पर 524 मामलों को शुरुआत में ही बंद कर दिया।

ज्योतिष विज्ञापनों के संबंध में विधि आयोग से प्राप्त संदर्भों पर परिषद ने अपना अभिमत व्यक्त किया। पेड न्यूज पर फैसला लेने हेतु कुछ सुदृढ़ उपाय उपलब्ध कराने के लिए भारत का निर्वाचन आयोग भी परिषद के पास आया था। यह भी उल्लेखनीय है कि परिषद के अनुसरण में भारत के निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज के लिए एक समाचारपत्र को उत्तरदायी मानते हुए इसकी जांच की और पाया कि प्रभावित उम्मीदवार ने निर्वाचन खर्च के विवरण में पेड न्यूज़ का खर्च नहीं दर्शाया था। अतः एमएलए अथवा एम पी चुने जाने के लिए अयोग्य करार कर दिया। यह कार्यवाही देश की साफ-सुथरी लोकतांत्रिक राजनीति पर देश के दो महत्वपूर्ण स्तंभों की सामूहिक कार्रवाई के सकारात्मक प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

मीडिया से संबधित मामलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए परिषद मीडिया में उभरती प्रवृत्तियों जैसे कि - मीडिया कंपनी का निजी लिखित कार्य, मीडिया में महिलाओं का अभद्र प्रतिनिधित्व और पत्रकारों द्वारा कठिनाइयों का सामना भी एवं लघु और मध्यम समाचारपत्रों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन का अध्ययन कर रही है। प्रत्येक पहलू को समाहित करते हुए सभी मामलों पर सुदृढ़ सिफारिशें देने के लिए ये रिपोर्टें अगले वर्श आनी संभावित हैं।

भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस परिषद की विश्व संस्था (डब्ल्यू ए पी सी) की एक सक्रिय सदस्य भी है। डब्ल्यूएपीबी की कार्यकारी परिषद की बैठक दिनांक 26 अप्रैल 2011 को नई दिल्ली में हुई थी जिसमें डब्ल्यूएपीसी सदस्य देशों ने भाग लिया था।

इसके बाद दिनांक 28-29 अप्रैल 2011 को नई दिल्ली में मानवाधिकारों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शीर्षक पर परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें संयुक्त राष्ट्र और भारतीय प्रतिनिधियों के अलावा विभिन्न देशों जैसे - आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, टर्की, इजराइल, तंजानिया, नेपाल, इंडोनेशिया आदि से मीडिया संस्थानों ने इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ अपने देशों के परिप्रेक्ष्य में विचार-विमर्श किया। विचार-विमर्श और प्रस्तुतीकरण को प्रकाशित कर सभी देशों में परिचालित किया गया।

प्रेस की स्वतंत्रता को कायम रखने और विश्व स्तर पर इसके मानकों और आचारों के उन्नयन में सक्रिय प्रोत्साहन देने के लिए विश्व के विभिन्न भागों में प्रेस/मीडिया परिषद और ऐसे ही निकायों के साथ परिषद ने परामर्श और बातचीत की प्रक्रिया की शुरुआत भी की है। देश में प्रेस परिषद की स्थापना के लिए आपसी कार्रवाई के तहत हांगकांग और इंडोनेशिया, कुआलालामपुर, मलेशिया के साथ परामर्श किया गया। परिषद को अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका से भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

लक्ष्यों और परिणामों के संबंध में परिषद पिछले एक वर्ष के दौरान किए गए अपने सभी न्यायिक फैसलों को द्विभाषी रूप में अपनी त्रैमासिक रिपोर्ट के जरिए लोगों के बीच लेकर आई। वर्ष 1966 से लेकर न्यायिक फैसलों के सार संग्रह के साथ अपने सभी न्यायिक फैसलों की सूची तथा प्रेस एवं पंजीकरण अपीलीय बोर्ड के आदेशों की सूची को भी वेबसाइट पर डालने के लिए प्रक्रिया चल रही है और वर्ष 2010-11 के लिए वार्षिक रिपोर्ट भी प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2012-13 के लिए मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं : -

1. प्रेस परिषद अधिनियम के तहत प्रेस परिषद को सशक्त बनाने के लिए संशोधन।
2. मीडिया और प्राधिकरणों के मार्गदर्शन के लिए आचार संहिता बनाना।
3. समिति/परिषद की बैठकों की जांच के माध्यम से न्यायिक मामलों के फैसलों को देश के विभिन्न भागों में घर-घर तक पहुंचाना।
4. वेबसाइट की सामग्री को समृद्ध और बाधामुक्त बनाना।
5. प्रेस द्वारा और प्रेस के विरुद्ध की गई शिकायतों पर परिषद द्वारा दिए गए न्यायिक फैसलों की सूची को अद्यतन करना।
6. मीडिया संबंधी मामलों पर वार्तालाप का आयोजन करना।
7. पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकरण (स्वचालित पुस्तकालय)।
8. समाचारपत्रों के लेवी शुल्क के संदर्भ में दस्तावेजों (रिकार्ड्स) का कम्प्यूटरीकरण करना।

अपने अधिदेश के अनुसरण में परिषद का इष्टतम निष्पादन अपने न्यायिक फैसलों को प्रभावित समाचार पत्रों में इसके पाठकों को यह बताने के लिए कि प्रकाशन का मूल्यांकन इसके समकक्षों द्वारा किया गया है और प्रकाशन के लिए दिशा-निर्देशों के अनुपालनार्थ इसके प्राधिकारी में निहित होने पर निर्भर है।

# पत्र सूचना कार्यालय

लोगों को सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों के संबंध में जानकारी देने के लिए पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार की अग्रणी संस्था है। मीडिया (इलेक्ट्रानिक और प्रिंट) के साथ संवाद के प्रमुख सरकारी चैनल के रूप में पत्र सूचना कार्यालय इस मूल विचार के साथ काम करता है कि लोकतंत्र में सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसकी नीतियां और कार्यक्रम प्रेस और अन्य मीडिया के जरिए सही और उपयुक्त तरीके से उन लोगों तक पहुंचे जिनके समर्थन और विश्वास पर वह सत्ता में है।

2. पत्र सूचना कार्यालय मुख्यालय के अधिकारी मीडिया को सूचना प्रदान करने और फीड बैक उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सम्बद्ध किए जाते हैं। वे मीडिया परामर्शदाता के रूप में काम करते हैं और प्रचार कार्य का समन्वयन करते हैं।

3. इसके क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय कम्प्यूटर नेटवर्क के जरिए जुड़े हैं। कार्यालय का इंटरनेट पर एक होमपेज भी है जिसे www.pib.nic.in पर देखा जा सकता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए प्रचार समग्री इस होमपेज पर डाली जाती है। पीआईबी की प्रेस विज्ञप्तियां अब कम्प्यूटर के जरिए स्थानीय समाचारपत्रों, महत्वपूर्ण बाहरी समाचारपत्रों के स्थानीय संवाददाताओं और इसके क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को भेजी जाती हैं। विशेष लेख और ग्राफिक्स आदि भी इंटरनेट के साथ-साथ पीआईबी नेटवर्क के जरिए जारी किए जाते हैं।

4. यह कार्यालय मीडिया प्रतिनिधियों को पेशागत सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इसके लिए यह भारतीय और विदेशी मीडिया प्रतिनिधियों, न्यूज कैमरामैनों और तकनीशियनों को प्रत्यायन उपलब्ध कराता है। दिसंबर 2011 तक 86 तकनीशियन, 111 संपादक/ मीडिया समीक्षक, 5 कार्टूनिस्ट और 13 संवाददाता-सह-कैमरापर्सन्स के अलावा 1450 संवाददाता, 441 कैमरामैन, इसके मुख्यालय से प्रत्यायित थे। भारतीय और विदेशी संवाददाताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीआईबी का नई दिल्ली में आधुनिक संचार सुविधाओं वाला एक राष्ट्रीय प्रेस केंद्र कार्यरत है।

5. मीडिया को जानकारी प्रदान करने के लिए यह कार्यालय विभिन्न तरीके अपनाता है - प्रेस विज्ञप्तियों और विशेष लेख, प्रेस ब्रीफिंग्स, संवाददाता सम्मेलन और प्रेस टूर।

6. प्रेस विज्ञप्तियों, संवाददाता सम्मेलनों, विशेष लेखों आदि के संदर्भ में भी पीआईबी के कार्य निष्पादन की निगरानी तत्काल की जाती है और यह समाचारपत्रों में प्रकाशित खबरों की संख्या से परिलक्षित होती है।

**समग्र निष्पादन**

वार्षिक योजना 2011-12 के दौरान स्वीकृत प्रावधान 35.25 करोड़ रुपये का है। दिसंबर 2011 तक योजना के अंतर्गत 24.73 करोड़ रुपये व्यय किए गए। वर्ष 2011-12 के दौरान (दिसंबर 2011 तक) वित्तीय संदर्भ में पत्र सूचना कार्यालय का प्रदर्शन इस प्रकार रहा : -

| क्र सं | | योजना | गैर-योजना | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बजट अनुमान 2011-12 | 35.25 | 41.23 | 76.48 |
| 2 | संशोधित अनुमान 22011-12 | 44.75 | 36.33 | 81.08 |
| 3 | वास्तविक खर्च दिसंबर 2011 तक | 24.73 | 28.20 | 52.94 |
| 4 | बजट अनुमान 2012-13 | 26.00 | 38.33 | 64.33 |

# प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग देश के सबसे बड़े प्रकाशन संस्थानों में से एक है। हिंदी, अंग्रेजी और अन्य प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रकाशन विभाग द्वारा निकलने वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि उनके माध्यम से इस देश के लोगों की समझ का विकास हो सके।

प्रकाशन विभाग का कार्य है लोकप्रिय पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन, बिक्री और वितरण करना। अपने कार्य के द्वारा यह विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है : -

1. राष्ट्रीय महत्व के उन विषयों पर पुस्तकों को प्रकाशित करना जिन विषयों पर अन्य प्रकाशकों ने ध्यान नहीं दिया हो और ऐसी पुस्तकों को कम कीमत पर आम जनता के लिए उपलब्ध कराना।
2. विविधता में एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय अखंडता इत्यादि की विचारधारा और आत्मा को मजबूत करना और बढ़ावा देना।
3. वर्ष 2011-12 के दौरान 20 पत्रिकाएं और 90 पुस्तकें प्रकाशित करने का हमारा लक्ष्य है। प्रकाशन विभाग देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित बिक्री केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से अपनी पुस्तकों और पत्रिकाओं को बेच रहा है। समय के साथ चलने के लिए प्रकाशन विभाग ने चरणबद्ध तरीके से अपने बिक्री केंद्रों को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव किया है।

4. प्रकाशन विभाग के बिक्री केंद्र नई दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई, पटना और तिरूवनंतपुरम में स्थित हैं। बिक्री के आउटलेट बंगलुरु, गुवाहाटी और अहमदाबाद में स्थित हैं।

5. वर्ष 2012-13 के लिए बजट आकलन गैर योजना में 2223.00 लाख रुपये (प्रकाशन विभाग) और योजना में रोजगार समाचार सहित 20.00 लाख रुपये है।

## भारत के समाचार के पंजीयक का कार्यालय

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आरएनआई) बुनियादीतौर पर प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण कानून 1867 से संबधित प्रशासनिक कार्य करता है। वैधानिक कार्यों के अंतर्गत देश में प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों/पत्रिकाओं का अद्यतन रिकार्ड तथा आंकड़े संभाल कर रखता है, नए प्रकाशनों के लिए शीर्षक उपलब्ध कराता है, पंजीकरण के प्रमाणपत्र जारी करता है, प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रसार दावों की समीक्षा करता है तथा 'भारत के समाचारपत्र' नामक शीर्षक से प्रिंट मीडिया के हालात पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है। आरएनआई समाचारपत्रों के प्रसार के दावों पर भी नियंत्रण रखता है। अपने गैर वैधानिक कार्यों के अंतर्गत यह कार्यालय अखबारी कागज के आयात के लिए प्रयोक्ताओं को पात्रता प्रमाणपत्र जारी करता है। इसके अलावा आरएनआई प्रायोजिक प्राधिकरण भी है जो प्रिंटिंग मशीनरी के आयात के लिए पात्रता प्रमाणपत्र जारी करता है जैसे कि न्यूजपेपर पेज, ट्रांसमिशन एवं रिसेप्शन फेसीमाइल सिस्टम अथवा इक्विपमेंट तथा टेलीफोटो ट्रांसमिशन और रिसेप्शन सिस्टम आदि।

## गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग

गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों को शोध के संबंध में एकत्रित, संकलित और तैयार सामग्री के प्रकाशन कार्य आदि में सहायता करता है। मीडिया इकाइयों के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी का सारांश निर्मित करना और सामयिक एवं अन्य विषयों पर मार्गदर्शन एवं पृष्ठभूमि नोट तैयार करना भी इस प्रभाग का दायित्व है। यह प्रभाग जनसंचार क्षेत्र की प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हुए जनसंचार की संदर्भ एवं प्रलेखन सेवा को कायम रखता है।

यह प्रभाग वर्ष के दौरान दो वार्षिक संदर्भ ग्रंथ तैयार करता है, *इंडिया* - संदर्भ वार्षिकी, यह केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य/संघ-शासित क्षेत्रों तथा पीएसयू/स्वायत्त निकायों द्वारा किए गए विकास और उन्नति कार्यों का संकलन है। भारत में मास मीडिया *(मास मीडिया इन इंडिया)* यह भारत के जनसंचार पर एक विस्तृत प्रकाशन है। साथ ही इंडिया को हिंदी में *भारत* शीर्षक से प्रकाशित किया जाता है।

## गीत एवं नाटक प्रभाग

गीत एवं नाटक प्रभाग की स्थापना 1954 में आकाशवाणी की एक इकाई के रूप में की गई थी और 1956 में इसे विकासात्मक संचार की अनिवार्यता के साथ ही स्वतंत्र मीडिया इकाई का दर्जा दे दिया गया। इस विभाग की स्थापना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

– देश की प्रगति में सहायक सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक विचारों और आदर्शों को लोगों के बीच पहुंचाने और जागरूकता जगाने के लिए।

– सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच रक्षात्मक भावना और देश के अन्य भागों के लोगों के साथ उनके सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए।

– लोक कलाओं और शहरी कलाओं दोनों के माध्यम से दूरदराज के कठिन इलाकों में तैनात सेना के जवानों में साहस का संचार करने के लिए।

गीत एवं नाटक प्रभाव प्रदर्शन कलाओं को संचार माध्यम के साथ इस्तेमाल करने वाला देश का सबसे बड़ा संगठन है। प्रभाग नाटक, नृत्य नाटिका, गीत नाट्य, लोक कलाओं, पारंपरिक गीतों, कठपुतली कला जैसी कलाओं का प्रदर्शन करता है। प्रभाग सांप्रदायिक सदभाव, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहित करने के लिये, पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्शखा जैसे विषयों को लोगों तक पहुंचाने के लिए गीत एवं नाट्य कार्यक्रम आयोजित करता है।

# मुख्य सचिवालय की सूचना विंग स्कीमें

## सूचना भवन का निर्माण

सूचना भवन के निर्माण पर होने वाला व्यय योजना आयोग की मंजूरी के पश्चात इस मंत्रालय को उपलब्ध कराए गए योजना बजट से पूरा किया जाता है। अब तक उपलब्ध निर्मित स्थान विभिन्न मीडिया इकाइयों को आवंटित किया गया है, जैसे सिविल कंस्ट्रक्शन विंग, गीत एवं नाटक प्रभाग, फोटो प्रभाग, प्रकाशन विभाग, गवेषणा संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग, भारतीय प्रेस परिषद, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (अंशत:) और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। सूचना भवन के चरण V के पूरा होने पर उपलब्ध निर्मित स्थल का आबंटन बाकी मीडिया इकाइयों जैसे डीएफपी, आरएनआई आदि को किया जाएगा और यदि फिर भी स्थल बचता है तो उसे अन्य विभागों को किराए पर उपलब्ध कराया जाएगा।

## एनई/जे एंड के तथा अन्य चिह्नित क्षेत्रों में विकास सहयोग

इस स्कीम के दो हिस्से हैं – (क) ढांचागत विकास सहयोग तथा (ख) पीआईबी, डीएवीपी, डीएफपी तथा एस एंड डीडी के सामान्य कार्यक्रमों का संवर्धन जिनके लिए क्रमश: 15 तथा 10 करोड़ रुपये का व्यय।

(क) ढांचागत विकास सहयोग उत्तर पूर्व और जम्मू तथा कश्मीर, सीमा और एलडब्ल्यू प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपकरणों के लिए फंड तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की

मीडिया इकाईयों को वित्तीय सहायता के रूप में तथा केंद्रीय सूचना सदनों, प्रेस केंद्रों, राज्य सूचना विभागों के आधुनिकीकरण के रूप में प्रदान किया जाएगा। इसके लिए कुल 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ख) पीआईबी, डीएवीपी, ईएफपी तथा एस एंड डीडी के सामान्य कार्यक्रमों के संवर्धन पर 2012-13 के लिए निम्न प्रकार से व्यय किया जाएगा -

| | |
|---|---|
| पीआईबी | 1.0 करोड़ रुपये |
| डीएफपी | 2.0 करोड़ रुपये |
| एस एंड डीडी | 2.0 करोड़ रुपये |
| डीएवीपी | 5.0 करोड़ रुपये |
| **कुल** | **10.00 करोड़ रुपये** |

## अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम

सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों/मीडिया आदान प्रदान कार्यक्रमों के उद्देश्य भारत और अन्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाना और मास मीडिया, प्रसारण तथा फिल्मों के क्षेत्र में विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। देश के पत्रकारों, मासमीडिया विशेषज्ञों के आपसी आदान-प्रदान के साथ-साथ विशेष कार्यक्रमों के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं -

- देशों के बीच बेहतर समझ बढ़ाने में जो भूमिका मीडिया निभाता है उसे पहचानना और मीडिया के लोगों के बीच प्रभावी बातचीत के जरिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने में और एक दूसरे के बारे में सूचना प्रसार के लिए मीडिया को महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना।
- मीडिया की उस महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना जिसे मीडिया लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक समझ विकसित करने में निभाता है।
- इस स्कीम का एक बड़ा उद्देश्य सूचना और प्रिंट मीडिया के क्षेत्रों में बेहतर समझ को बढ़ावा देकर विभिन्न देशों के साथ दोस्ताना संबंधों को मजबूत बनाना है। सूचना और मास मीडिया के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ नजदीकी संबंध स्थापित और विकसित करने की एक समान इच्छा से यह स्कीम प्रेरित है।
- आधुनिक मीडिया प्रशिक्षण
- संकटकालीन संचार
- सामाजिक और मल्टीमीडिया प्रशिक्षण

स्कीम के हिस्से हैं :

(क) मीडिया आदान-प्रदान कार्यक्रम

(ख) सूचना और फिल्म क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह और समझौता

(ग) अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेमिनार/कार्यशालाएं

**(क) मीडिया आदान-प्रदान कार्यक्रम**

सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम (सीईपी) भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और अन्य देशों के संस्कृति मंत्रालय के बीच समझौते पर हस्ताक्षर कर आयोजित किए जाते हैं जिनका उद्देश्य शिक्षा, कला और संस्कृति, सूचना और मास मीडिया युवा और खेलों के क्षेत्र में नजदीकी संबंध स्थापित और विकसित करना है। क्रियान्वयन की प्रक्रिया में मीडिया के लोगों का आदान-प्रदान और मीडिया के लिए महत्वपूर्ण मीडिया संस्थानों/संगठनों में मीडिया के लोगों के दौरे आयोजित करना शामिल है।

**(ख) सूचना और मास मीडिया के क्षेत्र में संयुक्त कार्यसमूह और समझौते**

ये समझौते दो देशों की सरकारों के बीच किए जाते हैं जो सूचना और मास मीडिया के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए एक उपकरण की तरह कार्य करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस तरह के समझौते कई देशों के बीच हुए हैं। यद्यपि पिछले तीन वर्षों के दौरान संयुक्त कार्य समूह के अंतर्गत ब्यूरो ने कोई समझौता नहीं किया है।

**स्कोप :** मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के पर्याप्त क्रियान्वयन और बुनियादी उद्देश्य की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम विशेष रूप से चलाया जाएगा जिसमें 5 पत्रकारों और दो अफसरों का आदान-प्रदान शामिल है जो दो वर्षों से अधिक अवधि तक नहीं होगा।

**(ग) अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेमिनार/ कार्यशालाएं**

उदारीकरण के बाद वाले दौर में ब्रिक्स, जी-20, सार्क बैठकों आदि बहुत से अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अपनी केंद्रीय भूमिका के प्रकाश में भारत की मौजूदगी और इमेज बढ़ाने की दिशा में भारत में अलग से मीडिया प्रतिनिधियों के लिए सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करने का प्रस्ताव है और विदेश में भी इसी तरह की कार्यशालाएं सेमिनारों को आयोजित करना और उनमें शामिल होना प्रस्तावित हैं। स्कीम के प्रावधान में प्रवासी भारतीय दिवस/राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस आदि के साथ-साथ ऐसी ही सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित करना शामिल होगा। इससे संगठन के मूल्यों के संचार और उन्हें बढ़ावा देने के लिए आवश्यक पेशेवर मिलेंगे और संकटकालीन संवेदनशील मुद्दों को सुलझाने में मदद करेंगे।

**नीति संबंधी अध्ययन, सेमिनार, मूल्यांकन इत्यादि (प्रसार भारती छोड़कर सभी क्षेत्र और मीडिया इकाइयां)**

12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017 के दौरान अर्थव्यवस्था के मनोरंजन और मीडिया क्षेत्र ने उच्च विकासक संभावनाएं दर्शाई हैं। विकास गति पकड़ने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्रों के संबंध में विभिन्न स्कीमें/कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं ताकि निर्धारित लक्ष्य हासिल किए जा सकें। स्कीम में मीडिया के क्षेत्र में नीति संबंधी अध्ययनों, सेमिनारों और मौजूदा नई योजना स्कीमों के मूल्यांकन का कार्य करने का प्रावधान है। अध्ययनों सेमिनारों और मूल्यांकन का कार्य नई स्कीमों की नीति निर्धारण, गठन और निगरानी में सहायता करेगा।

**मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण**

सिविल सेवा की दिशा में एक रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली होनी आवश्यक है जो प्रत्येक सिविल सेवक को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखेगी जिन्हें मंत्रालय विभाग संगठन के मिशन और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उनका मूल्यांकन, प्रेरित और विकास करेगी।

1. इस परिवर्तन प्रक्रिया के भीतर, यह आवश्यक है कि उस सेवक की क्षमता और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य में मिलान आवश्यक है और प्रशिक्षण के माध्यम से वर्तमान और भविष्य की भूमिका के लिए क्षमता अंतर को पाटना आवश्यक है।

2. **सक्षमता** ज्ञान, कौशल और व्यवहार में है जिनकी पद के कार्य प्रभावी तरीके से करने के लिए एक व्यक्ति में होना आवश्यक होता है। सक्षमता मुख्यत: उन को कौशल में बांटी जा सकती है जिसकी सरकारी सेवकों को विभिन्न कार्यों अथवा स्तर के लिए विभिन्न सक्षमता स्तरों की आवश्यकता होगी। इनमें से कुछ सक्षमताएं नेतृत्व, संचार, वित्तीय तथा मानव प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, परियोजना प्रबंधन आदि से संबंधित होती है। अन्य का संबंध पेशेवर अथवा

विशेषज्ञता कौशल से होता है, जो कि विशेष कार्यों जैसे कि सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं, बाढ़ नियंत्रण उपाय करना, नागरिक उड्डयन, चिकित्सीय देखभाल, मीडिया प्रबंधन आदि के लिए प्रासंगिक हैं।

3. सूचना और प्रसारण मंत्रालय सूचना, प्रसारण और फिल्म क्षेत्रों के लिए नोडल मंत्रालय हैं। अपनी विभिन्न मीडिया इकाईयों के माध्यम से मंत्रालय विभिन्न सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों संबंधी सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए उत्तरदायी है। विभिन्न मीडिया हैं - इलेक्ट्रानिक, प्रिंट, फिल्म, अंतरवैयक्तिक प्रचार, जीवंत कला और संस्कृति, जनसूचना अभियान आदि। अपने कैरियर के दौरान भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट तथा अंतर वैयक्तिक मीडिया इकाईयों में तैनात किए जाते हैं। इसी प्रकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के अधिकारी मीडिया क्षेत्र के लिए नीतियां बनाने में कार्यरत हैं और विभिन्न मीडिया इकाईयों के लिए प्रशासनिक सुविधा प्रदान करते हैं। यह आवश्यक है कि ये सभी अधिकारी प्रशिक्षित हैं और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों को लेने के लिए तैयार हैं।

# फिल्म क्षेत्र

## केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

फिल्मों को लोक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित करने के उद्देश्य से सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा फिल्म सेंसर बोर्ड को जून 1983 में 'केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड' के नए नाम से स्थापित किया गया था।

वर्तमान बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा 19 गैर सरकारी सदस्य हैं जिन्हें 25 मई 2011 को नामित किया गया था। बोर्ड का मुख्यालय मुम्बई में तथा 9 क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलुरु, तिरूवनंतपुरम, दिल्ली, कटक तथा गुवाहाटी में कार्यरत हैं।

प्रमाणन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सीबीएफसी ऑन लाइन प्रमाणन प्रक्रिया में है। सीबीएफसी की तिविधियों को प्रेस विज्ञप्ति तथा इसकी वेबसाइट http://cbfcindia.gov.in के द्वारा प्रचारित किया जाता है।

## बाल फिल्म समिति, भारत

बाल फिल्म समिति, भारत की स्थापना 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत मई, 1955 में हुई थी। यह भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में स्वायत्तशासी निकाय के तौर पर कार्य करती है और इसे अपनी योजना और गैर योजना गतिविधियों के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। बाल फिल्म समिति, भारत (सीएफएसआई) बच्चों को मूल्यपरक मनोरंजन प्रदान करने के साथ ही फिल्मों के माध्यम से उनकी मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक आवश्यकताओं को भी पूरा करती है।

इसका अध्यक्ष, सिनेमा के क्षेत्र की किसी प्रतिष्ठित हस्ती को बनाया जाता है। अध्यक्ष कार्यकारी परिषद तथा आम सभा का भी प्रमुख होता है। प्रमुख कार्यकारी अधिकारी प्रशासन, निर्माण, विपणन और लेखा विभाग की दैनिक गतिविधियों का संचालन करता है। समिति का मुख्यालय मुम्बई में तथा शाखा कार्यालय नई दिल्ली और चेन्नई में हैं।

सीएफएसआई की विभिन्न गतिविधियों के बारे में पत्र सूचना कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति, बुकलेट के प्रकाशन तथा सीएफएसआई की वेबसाइट www.cfsiindia.org के माध्यम से लोगों को सूचना दी जाती है।

# फिल्म समारोह निदेशालय

फिल्म समारोह निदेशालय की स्थापना देश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के आयोजन के लिए की गई थी। निदेशालय विदेशी फिल्म समारोहों में भारत के भाग लेने की व्यवस्था करता है, भारत में विदेशी फिल्मों तथा विदेशों में भारतीय फिल्मों के कार्यक्रम आयोजित करता है और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की भी अयोजन करता है।

निदेशालय सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हुए अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव मजबूत बनाता है। विश्व सिनेमा के नए रूझानों से परिचित कराता है, फिल्म क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देता है और भारतीय फिल्मों का स्तर बेहतर बनाने में योगदान देता है।

निदेशालय निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां संचालित करता है:

1. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
2. विदेशी फिल्म्म समारोहों में भाग लेना
3. भारतीय पैनोरमा के लिए फिल्मों का चयन
4. सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
5. भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के स्तर के उन्नयन के लिए विशेषज्ञ समिति की भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए 'विशेष कार्य वाहन (एसपीवी)' गठित करने की सिफारिश मानने का प्रस्ताव है। मुख्य सचिवालय की प्रस्तावित नई योजना स्कीम 'भारत और विदेशों में फिल्म समारोहों और फिल्म बाजारों के जरिए भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना' के अंतर्गत भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन, भारतीय पैनोरमा फिल्मों का चयन और विदेशों में फिल्म समारोहों में भाग लेना आदि कार्य शामिल हैं।

'सीरी फोर्ट परिसर का उन्नयन', नाम की नई योजना के अंतर्गत सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में सुविधाओं में लगातार सुधार शामिल है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत निदेशालय प्रीव्यू थियेटर बनाने और सीरी फोर्ट परिसर में अतिरिक्त पार्किंग विकसित करने का भी प्रस्ताव करता है ताकि वर्तमान ऑडिटोरियम सुविधा को किराए पर लगाया जा सके और सरकार को ज्यादा राजस्व मिल सके।

2. इन प्रमुख गतिविधियों के बारे में लोगों को निम्न माध्यमों से जानकारी दी जाती है:

   1. पत्र सूचना कार्यालय के नियमित विज्ञप्तियों के जरिए
   2. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशायल के माध्यम से समाचार पत्रों में नियमित विज्ञापनों के जरिए
   3. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशायल के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों के दौरान बैनर और पोस्टर लगाकर

4. विभिन्न समारोहों के दौरान संबंधित प्रकाशन जारी किए जाते हैं।

5. भारत स्थित विदेशी दूतावासों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के जरिए

6. वेबसाइट http://www.dff.nic.in तथा http://www.iffi.nic.in के जरिए

## भारत का फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

भारत का फिल्म एवं टेलीवजन संस्थान, पुणे फिल्म निर्माण और टेलीविजन कार्यक्रम तैयार करने की कला और तकनीकी का प्रशिक्षण देने वाला प्रमुख संस्थान है। इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत गठित किया गया है।

बाद के अध्यायों में संस्थान के स्वरूप, निर्धारित कार्यकलापों, उद्देश्य नीतियों और 2012-13 की गतिविधियों के लिए लक्ष्यों, प्रस्तावित नीतिगत पहलों की जानकारी दी गई है और पिछले कार्य निष्पादन की समीक्षा, वित्तीय समीक्षा तथा संस्थान के कार्य निष्पादन की समग्र समीक्षा की गई है।

अनुदान सहायता की किस्तें जारी किये जाते समय, मंत्रालय में तथा गर्वनिंग काउंसिल, स्थाई वित्त समिति आदि (इन समितियों में सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं) की बैठकों के दौरान इस संस्थान के कामकाज की सरकार द्वारा निगरानी की जाती है। संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिटेड स्टेटमेंट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

संस्थान के पाठ्यक्रमों और अन्य शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी इसकी वेबसाइट पर दी जाती है और समाचार पत्रों के जरिए भी इसे विज्ञापित किया जाता है ताकि पर्याप्त पारदर्शिता बनी रहे। मशीनों और उपकरणों का आयात खुले विज्ञापनों में प्रकाशित सार्वजनिक निविदाओं के जरिए किया जाता है।

## फिल्म प्रभाग

फिल्म प्रभाग की स्थापना जनवरी 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके तीन निर्माण केंद्र बंगलूरु, कोलकाता और नई दिल्ली में हैं। इसके अलावा प्रभाग के देश भर 10 वितरण शाखा कार्यालय भी हैं। फिल्म प्रभाग कृषि, कला, संस्कृति, उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, स्वास्थ्य, आवास, विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी जैसै विविधतापूर्ण विषयों पर वृत्त चित्र बनाता है।

देश में वृत्त चित्र निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्विवार्षिक मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करता है।

फिल्म प्रभाग की विभिन्न गतिविधियों के बारे में लोगों को निम्नलिखित माध्यमों के जरिए जानकारी दी जाती है:

1. पत्र सूचना कार्यालय की नियमित प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए

2. फिल्म प्रभाग की वेबसाइट www.filmsdivision.org के जरिए

# भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार

भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (एन एफ ए आई) देश की फिल्म धरोहर के संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इस उद्देश्य का प्राप्ति के लिए एन एफ ए आई अभिलेखीय महत्व की फिल्में हासिल करने तथा इनके संरक्षण की उपयुक्त व्यवस्था करने सहित अनेक स्कीमों को कार्यान्वित करता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के दौरान एन एफ ए आई की निम्नलिखित दो योजना स्कीमों को कार्यान्वित करने की योजना है -

1) अभिलेखीय महत्व की फिल्मों और फिल्म सामग्री की प्राप्ति

2) जयकर बंगले सहित एन एफ ए आई के बुनियादी ढांचे का उन्नयन तथा डिजिटल लाइब्रेरी बनाना

एन एफ ए आई की योजना स्कीमों के काम की प्रगति और वित्तीय स्थिति की मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक विवरणों के जरिए निगरानी होती है। ये विवरण नियमित रुप से मंत्रालय को भेजे जाते हैं। विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के जरिए एन ए एफ आई की गतिविधियों की प्रगति की जानकारी एन ए एफ आई की वेब साइट www.nfaipune.nic.in पर भी उपलब्ध है।

# राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एन एफ डी सी) मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है। इसके कार्यकलाप निम्नलिखित हैं -

i) किसी निर्देशक की प्रथम फिल्म के निर्माण के पूरे कार्य का दायित्व लेकर नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन

ii) नई फिल्मों की पटकथा तैयार करने में सहायता देना

iii) भारतीय और विदेशी फिल्म निर्माताओं के सहयोग से व्यवसायिक दृष्टि से चल सकने वाली अच्छे स्तर की फिल्मों का सहनिर्माण

iv) विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए प्रचार अभियान चलाना

v) पुराना फिल्मों का जीणोद्धार

vi) गोआ में हर वर्ष फिल्म बाजार का आयोजन

12वीं योजना अवधि के लिए विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण के लिए 60 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है यह कार्य विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों तथा वृत्तचित्रों का निर्माण स्कीम के अंतर्गत है जिसका प्रस्तावित परिव्यय 142 करोड़ रुपये है। इस कार्य के लिए वर्ष 2012-13 में 17 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है। एन एफ डी सी 12 वीं पंचवर्षीय योजना की भारत तथा विदेशों में फिल्म समारोहों और फिल्म बाजारों के जरिए भारतीय सिनेमा को प्रोत्साहन स्कीम के एक घटक-फिल्म बाजारों में भाग लेना क्रियान्वयन के प्रति भी उत्तरदायी है। इस योजना की ताजा स्थिति निगम की वेबसाइट www.nfdcindia.com पर उपलब्ध है।

भारत और विदेशों में फिल्म समारोहों में भाग लेना घटक के अंतर्गत फिल्म समारोह निदेशालय की गतिविधियों में विभिन्न अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में चुनी हुई भारतीय फिल्मों की प्रविष्टि कराना तो शामिल है ही, इस के साथ साथ विभिन्न विषयों पर फिल्म समारोहों का आयोजन कर देश के हर क्षेत्र में फिल्म आंदोलन को बढ़ावा देना है।

## सत्यजित राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान

सत्यजित राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान फिल्मों और टेलीविजन के क्षेत्र में शिक्षा देने वाला सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित दूसरा राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। फिल्म और टेलिविजन उद्योग के लिए अत्यंत कुशल व्यक्तियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से संस्थान की स्थापना की गई।

बाद के अध्यायों में संस्थान के स्वरूप, निर्धारित कार्यकलापों, उद्देश्य नीतियों और 2012-13 की गतिविधियों के लिए लक्ष्यों, प्रस्तावित नीतिगत पहलों की जानकारी दी गई है और पिछले कार्य निष्पादन की समीक्षा, वित्तीय समीक्षा तथा संस्थान के कार्य निष्पादन की समग्र समीक्षा की गई है।

अनुदान सहायता की किस्तें जारी किये जाते समय, मंत्रालय में तथा गर्वनिंग काउंसिल, स्थाई वित्त समिति आदि (इन समितियों में सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं) की बैठकों के दौरान इस संस्थान के कामकाज की सरकार द्वारा निगरानी की जाती है। संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिटेड स्टेटमेंट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

# मुख्य सचिवालय की फिल्म विंग स्कीमें

## एंटी पाइरेसी पहल ( नई स्कीम )

पाइरेसी किसी भी सृजनात्मक क्षेत्र विशेषकर फिल्म क्षेत्र में एक बड़ा खतरा है। इसलिए स्कीम का मुख्य उद्देश्य सभी हितधारकों के बीच पाइरेसी के खिलाफ जागरुकता फैलाने और इससे पार पाने के लिए शिक्षित करना है। स्कीम में उन कदमों को ही आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है जिन्हें मत्रालय पहले ही उठा चुका है। स्कीम के तहत फिल्म, प्रसारण और संगीत उद्योग से सभी को शामिल कर मल्टी-मीडिया अभियान शुरु करने का विचार है। फिल्म और मीडिया से कई हस्तियों को अनुरोध किया जाएगा जो पाइरेटेड सामान खरीदने से मना करने का लोगों से अनुरोध करेंगे। ये अभियान दूरदर्शन/एआइआर, निजी टी वी चैनलों और निजी एफएम पर चलाए जाएगें। कॉपीराइट अधिनियम के बारे में जागरुक करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में पुलिस,न्यायिक तथा प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। पाइरेसी से लड़ने के लिए पाइरेसी के प्रभाव पर शोध कराया जाएगा ताकि विकास के साथ साथ सार्वजनिक निजी रणनीतियों को कारगर बनाया जा सके।

## भारतीय सिनेमा के 100 वर्षों ( 1913-2013 ) पर आयोजन

भारत में दादा साहब फालके ने 1913 में पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई जो 13 अप्रैल 1913 को प्रदर्शित हुई। भारत में बनने वाली यह पहली फिल्म थी। इसके बाद देश भर में फिल्मों का निर्माण शुरु हो गया। ध्वनि की खोज के बाद विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्म निर्माण की बाढ़ सी आ गई और क्षेत्रीय, स्थानीय तथा राष्ट्रीय कलेवर की फिल्में बनने लगीं। समय बीतने के साथ, फिल्में ने केवल मनोरंजन का स्रोत बनी हैं बल्कि आजादी के बाद से लोगों और सांस्कृतिक स्वरूप तथा संवेदनशीलताओं की सामाजिक-आर्थिक अभिलाषाओं को परलिक्षित करती हैं। इस स्कीम के तहत भारत में सिनेमा के 100 वर्षों पर आयोजन करने का विचार है। इसके तहत विभिन्न गतिविधियां चलाने का प्रस्ताव है जिसमें भारतीय सिनेमा के विभिन्न पहलुओं पर गैर-फिक्शन फिल्मों का निर्माण, गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सिनेमा के 100 वर्षों पर एक झांकी का प्रदर्शन

तथा एक कॉफी टेबल बुक का मुद्रण, भारतीय सिनेमा के भूले बिसरे नायकों पर टीवी सीरियल, छात्रों के लिए फिल्म क्लब की शुरुआत, स्मारक डाक टिकट जारी करना, टी-शर्ट, मग, उगा स्तरीय थीम गीत, सबसे पुराने चालू थिएटरों पर वृत्तचित्र निर्माण, फिल्मोत्सव आदि आयोजित करना शामिल है। स्कीम को लागू करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर कार्य किया जा रहा है।

## राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन

स्कीम के तहत प्रिजर्वेशन विदाउट एरर्स, एक्सेज विदाउट एंड के लक्ष्य के साथ फिल्म विरासत के संरक्षण का प्रस्ताव है। योजना स्कीम में प्रस्तावित गतिविधियां इस प्रकार है:

(क) 1500 फीचर फिल्म और 1500 लघु फिल्मों का पुनरुद्धार,

(ख) 1000 फीचर फिलमों और 2000 लघु फिल्मों का डिजिटलीकरण,

(ग) अभिलेखीय उद्देश्य के लिए 1500 फीचर फिल्मों तथा 1500 लघु फिल्मों के इंटर-निगेटिवों की स्ट्राइकिंग,

(घ) पुनरुद्धार की गई वॉलट निर्माण,

(ड़) पुनरुद्धार और संरक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन। संपूर्ण परियोजना सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सीधी देखरेख में।

## भारत और विदेशों में फिल्म समारोहों और फिल्म बाजारों के जरिए भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना

देश में अच्छी फिल्मों के निर्माण में मदद करने और इन फिल्मों की विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों और फिल्म बाजारों में पहुंच को बढ़ावा देने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक योजनागत स्कीम तैयार की थी। उक्त उद्देश्य के लिए विभिन्न मीडिया ईकाइयों की गतिविधियों में बेहतर तालमेल, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जैसी गतिविधियों के सुचारू आयोजन, भारत और विदेशों में फिल्म बाजारों और विभिन्न फिल्म समारोहों में भागीदारी, वृत्त चित्रों के लिए मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह का आयोजन तथा देश भर में बच्चों के फिल्मों के प्रर्दशन की गतिविधियों को 12वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य सचिवायल की एक ही योजना स्कीम में शामिल कर लिया गया, जिसका शीर्षक है 'भारत और विदेशों में फिल्म समारोहों और फिल्म बाजारों के जरिए भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना'। इस स्कीम के विभिन्न घटक इस प्रकार हैं:

1. भारत और विदेशों में फिल्म समारोहों का आयोजन और भागीदारी (इसमें विदेश यात्रा का खर्च शामिल है), गैर सरकारी संगठनों/राज्य सरकारों के संगठनों को देश में फिल्म समारोहों के आयोजन के लिए अनुदान सहायता देना, कलात्मक महत्व की फिल्मों के प्रर्दशन के लिए एफएफएसआई को अनुदान सहायता देना, फिल्म चेतना को बढ़ावा देना, फिल्मों की समझ बढ़ाने वाली पत्रिकाओं का प्रकाशन और संगोष्ठियां, सम्मेलन आदि आयोजित करना।

2. भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन, भारतीय पैनोरमा के लिए फिल्मों का चयन, भारतीय पैनोरमा फिल्में हासिल करना तथा भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के विशेष कार्यवाहन (एसपीवी) की व्यवस्था।

3. भारत और विदेशों में फिल्म समारोहों में भागीदारी

4. वृत्त चित्रों के लिए द्विवार्षिक मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन

5. द्विवार्षिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोहों का आयोजन (एक वर्ष राष्ट्रीय और एक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समारोह का आयोजन)

6. देश भर में विद्यालयों में बाल फिल्मों का प्रर्दशन

उपर्युक्त घटकों में से, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए एसपीवी के गठन से पहले, घटक संख्या एक और दो का क्रियान्वयन फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा किया जाएगा। घटक संख्या तीन का क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान- राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा किया जाएगा। घटक संख्या पांच का क्रियान्वयन फिल्म प्रभाग और घटक संख्या 6 और 7 का क्रियान्वयन बाल फिल्म समिति, भारत द्वारा किया जाएगा।

इस स्कीम का दूसरा घटक है, भारत के अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोह (आई एफ एफ आई) के आयोजन के लिए (स्पेशल परपज वैहिकल) एसपीवी का घटन। आई एफ एफ आई के ज्यादा कारगर आयोजन और ऐसे आयोजनों के निष्पादन की समीक्षा के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 2010 में एक समिति गठित की जिसे आई एफ एफ आई को एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्टीय समारोह बनाने के तरीकों की जांच तथा समीक्षा कर अपनी सिफारशें देनी थीं। समिति ने आई एफ एफ आई को विश्व भर में अलग पहचान वाला श्रेष्ठ समारोह बनाने के लिए अनेक उपाय सुझाए। इनमें से मुख्य सिफारिश हर वर्ष आई एफ एफ आई के आयोजन के लिए विशेष उद्देश्य तंत्र (स्पेशल परपज वैहिकल-एस पी वी) बनाने के थी। इस कार्य की शुरूआती तैयारी के रुप में, संयुक्त निदेशक, फिल्म समारोह निदेशन को निदेशक आई एफ एफ आई नामित किया गया। आई एफ एफ आई-2012 के आयोजन के अलावा, इस समारोह के लिए अलग से एस पी वी गठित करने की जरुरी प्रक्रियाएं भी संपन्न की जानी है।

सिनेमाई, विषय-वस्तु और कलात्मक उत्कृष्टता के आधार पर भारतीय पैनोरमा के लिए फीचर और गैर-फीचर फिल्मों के चयन का काम जारी रहेगा। इसी तरह, हर वर्ष के भारतीय पैनोरमा के प्रिंट तैयार कर इन फिल्मों के देश-विदेश के फिल्म समारोहों में बिना मुनाफे के प्रदर्शन कर फिल्म कला को बढ़ावा देने का काम जारी रहेगा।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम देश-विदेश के फिल्म समारोहों में फिल्म बाजारों में भागीदारी के जरिए भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने की एजेंसी बनी रहेगी ताकि भारतीय फिल्म उद्योग को बल मिले।

फिल्म प्रभाग के जरिए वृत्तचित्रों के लिए मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समोरोह (एम आई एफ एफ) का आयोजन जारी रहेगा। फिल्म प्रभाग ने 2 फरवरी से 9 फरवरी तक एम आई एफ एफ का सफल आयोजन किया।

बाल फिल्म समिति, भारत (सी एफ एस आई) ने हैदराबाद में 2011 के अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह (आई सी एफ एफ) का सफल आयोजन किया। यह एक द्विवार्षिक समारोह है। अगला समारोह 2013 मे होगा। सी एफ एस आई 2012 से द्विवार्षिक राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह का भी आयोजन करेगा। इस तरह सी एफ एस आई एक वर्ष राष्ट्रीय और एक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह आयोजित करेगा। सी एफ एस आई की देश के अन्य भागों में राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करने की योजना है ताकि देश के सभी भागों के बच्चों को उनके लिए खास तौर पर बनी फिल्मों में भागीदारी के समान अवसर मिल सकें।

योजना स्कीम बाल फिल्मों का म्युनिसिपल स्कूलों में प्रदर्शन के अंर्तगत कस्बाई और ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में सुविधाओं से वंचित बच्चों के लिए बाल फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी ताकि म्युनिसपिल/जिला परिषद स्कूलों के सुविधाओं से वंचित बच्चों को भी उत्कृष्ट बाल फिल्में देखने का मौका मिल सके।

इन प्रमुख गतिविधियों के बारे में लोगों को जानकारी निम्न तरोकों से दी जाती है –

1) पत्र सूचना कार्यालय (पी आई बी) की नियमित प्रेस विज्ञप्तियां
2) डी ए वी पी के जरिए पत्र-पत्रिकाओं में नियमित विज्ञापन
3) विभिन्न समारोहों/आयोजनों के दौरान लगाए जाने वाले बैनर/पोस्टर
4) समारोहों के दौरान संबंधित प्रकाशन
5) http://www.dff.nic.in, http:www.iffi.nic.in, http://www.filmdivision.org तथा http://www.cfsindia.org वेबसाइटों के जरिए।

## (ड़) विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों तथा वृत्तचित्रों का निर्माण

नई 12वीं योजना स्कीम विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों तथा वृत्तचित्रों का निर्माण एनएफडीसी, सीएफएसआई और फिल्म प्रभाग द्वारा संयुक्त रूप से लागू की जाएगी। विवरण इस प्रकार है:-

| क्रं. सं. | स्कीम के भाग | क्रियान्वयन एजेंसी |
|---|---|---|
| i | विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्म निर्माण | एनएचडीसी |
| ii | बाल फिल्मों का निर्माण | सीएफएसआई |
| iii | वृत्तचित्र और लघु फिल्मों का निर्माण | फिल्म प्रभाग |

विभिन्न भारतीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को सहयोग और प्रोत्साहन देकर उत्कृष्ट सिनेमा के बढ़ावा देने का अधिदेश एनएफडीसी के प्राप्त है। योजना स्कीम के पहले भाग का उद्देश्य नई प्रतिभा, भारतीय सिनेमा की बहुयामी अनेकता और अंतर्राष्ट्रीय सह-निर्माताओं को प्रोत्साहित कर उन्हें बढ़ावा देने के विचार से फिल्मों का निर्माण करना है। सीएफएसआई को भारत में बनने वाली बाल फिल्मों के विश्वभर में प्रचार और बाल फिल्म आंदोलन को बढ़ावा देने का जिम्मा दिया गया है। स्कीम के दूसरे भाग का उद्देश्य देश में बाल सिनेमा का विकास, बच्चों को स्वस्थ और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान कर उनकी दुनिया के प्रति समझ विकसित करना और आधुनिक भारत के जिम्मेवार नागरिक बनने में मदद करना है।

फिल्म प्रभाग का उत्तरदायित्व जनसूचना, शिक्षा, प्रेरणा तथा शैक्षिक तथा सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए भारत सरकार के लिए आवश्यक वृत्तचित्रों, एनीमेशन तथा लघु फिल्मों का निर्माण और वितरण करना है। स्कीम के तीसरे भाग का उद्देश्य ने केवल फिल्म प्रभाग बल्कि निजी निर्माताओं को अधिक से अधिक फिल्म निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना है।

# ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

तीव्र प्रौद्योगिकी विकास ने एनीमेशन, गेमिंग और विशेष दृश्य प्रभावों के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा दिया है। एनीमेशन सॉफ्टवेयर कार्यक्रमों का इस्तेमाल कंटेंट विकसित करने के लिए 2 डी सैल एनीमेशन तथा 3 डी एनीमेशन तकनीकों का इस्तेमाल होता है। 3 डी मोशन केप्चर एनीमेशन तकनीकों का इस्तेमाल लो रिजोल्युशन गेम, इंटरनेट करेक्टर्स, विशेष प्रभाव इत्यादि में होता है। इसी तरह, गेमिंग उद्योग गेम डिजाइन, प्लेटफार्म डिजाइन तथा प्ले करेक्टरिस्टिक सिस्टम के लिए आधुनिक गेमिंग सॉफ्टवेयर पर निर्भर है। भारतीय गेमिंग उद्योग मोबाइल तथा ऑन लाइन गेमिंग क्षेत्रों में अवसरों का इस्तेमाल करना चाहता है। ऐनीमेशन, गेमिंग तथा दृश्य प्रभाव उद्योग प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी/व्यवसायिक दोनों

मानवशक्ति की मांग वाला क्षत्र है। भारतीय उद्योग पहले से ही विरोध का सामना कर रहा है। ऐसे में जब इन उद्योगों में भारत का एक छोटा हिस्सा है, वैश्विक मांग और भारत में आईटी व्यावसायिकों का विशाल पूल होने के नाते इसमें अत्यधिक संभावनाएं हैं।

दृश्य प्रभाव एक अत्यंत कौशलपूर्ण गतिविधि है जो लगातार श्रव्य दृश्य उद्योग को व्यक्त करता है। इस संबंध में फिल्में जैसे मिशन इम्पॉसिबिल तथा हालीवुड की 'मैटिक्रस' और 'धूम-2' एवं 'डॉन' स्मरण में आती है। यह कौशल विकास का एनीमेशन तथा गेमिंग के अनुरूप है जिसमें राजस्व की संभावनाएं अधिक हैं।

तथापि, लगातार बढ़ती हुई एनिमेशन, गेमिंग एवं दृश्य प्रभाव उद्योग में प्रशिक्षित व्यवसायिकों का अभाव है। विभिन्न रिपोर्टों में अनुमानों के अनुसार लगभग 10,000 एनिमेशन व्यवसायिकों की आवश्यकता है जबकि वर्तमान में केवल 3000 ही उपलब्ध है। इसी प्रकार गेमिंग उद्योग में 6000 व्यवसायिक हैं जबकि मांग अधिक की है। उद्योग के विकास के बाद कुशल व्यवसायिकों की मांग और अधिक बढ़ सकती है। अत: एनीमेशन, गेमिंग और दृश्य प्रभाव सैक्टर में प्रशिक्षित व्यवसायिकों की मांग भारत में और बढ़ना अवश्यम्भावी है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस क्षेत्र हेतु मानव संसाधन योजना की आवश्यकता है जिससे प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या बढ़ सके। अत: उच्च शिक्षा में स्कूल पाठयक्रमों तथा एनीमेशन प्रशिक्षण में लक्ष्य के मद्देनजर एनीमेशन, गेमिंग तथा दृश्य प्रभाव सैक्टर के लिए एक विशेष प्रशिक्षण एवं सलाहकार संस्थान की स्थापना सरकारी/निजी भागीदारी में लिए जाने की परिकल्पना की गई है।

संस्थान इस क्षेत्र में अनुसंधान के अवसर भी उपलब्ध कराएगा। इससे और अधिक तकनीकी पहलों एवं सॉफ्टवेयर का विकास होगा। दूरगामी दृष्टिकोण से अनुसंधान से न केवल बौद्धिकता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि राजस्व अर्जित करने में भी सहायक होगा तथा संबंधित सैक्टर का नेतृत्व भी हो सकेगा।

संस्थान की स्थापना सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत करना प्रस्तावित है।

# प्रसारण क्षेत्र

## इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी)

(i) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों में निहित कार्यक्रम और विज्ञापन की मानीटरिंग, एवं

(ii) निजी एफ एम रेडियो आदि के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) शर्तों की निगरानी तथा

(iii) ऐसे अन्य कार्य जो प्रसारण क्षेत्र की विषयवस्तु की निगरानी से संबंधित जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपा गया हो।

वार्षिक योजना 2010-11 के अन्तर्गत ईएमएमसी परियोजना के लिए रु. 2.18 करोड़ का आवंटन किया गया है। ईएमएमसी का गैर-योजना बजट वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान के अन्तर्गत रु. 4.10 करोड़ का आवंटन था, जिसे संशोधित बजट के द्वारा बढ़ाकर रु. 4.36 करोड़ कर दिया गया। वर्ष 2011-12 के लिए अनुमानित परिव्यय रु. 2.18 करोड़ (योजना) एवं रु. 450 करोड़ (गैर योजना है।

# एफ एम सेल

एफ एम रेडियो क्षेत्र जुलाई 1999 में पहली बार निजी भागीदारी के लिए खोला गया। उस समय मंत्रिमंडल ने एफ एम रेडियो नेटवर्क के प्रथम चरण का निजी एजेंसियों के जरिए विस्तार का नीतिगत निर्णय लिया। प्रथम चरण में खुली नीलामी से सफल बोली लगाने वालों को चुना गया। इस योजना के तहत 12 शहरों में 21 चैनलों ने काम करना शुरु किया। एफ एम प्रथम चरण नीति को सीमित सफलता मिली। इसके कार्यान्वयन में करार पूरा न करने और अदालती मामलों के अनेक वाकये हुए। इन दिक्कतों की वजह से 108 चैनलों की नीलामी लगी लेकिन केवल 21 चैनल ही प्रसारण कर सके।

प्रथम चरण की समिति सफलता को देखते हुए, डॉ. अमित मिश्रा समिति और टेलीकॉम रेगुलेटरी कमेटी ऑफ इंडिया (ट्राइ) की सिफारिशों के अनुरूप एफ एम नीति में सुधार किए गए। एम एम द्वितीय चरण के लिए संशोधित नीति 13 जुलाई 2005 को अधिसूचित की गई। इसके बाद, 91 शहरों में 337 चैनलों के लिए बोली लगाई गई। राज्यों की राजधानियों सहित 3 लाख अथवा अधिक जनसंख्या वाले शहरों को शामिल किया गया। (राज्यों की राजधानियों की जनसंख्या 3 लाख से कम होने पर भी उन्हें शामिल किया गया।) यह अनुमति दस साल के लिए दी गई और इसके लिए दो चरणों वाली क्लोज्ड टेंडर बिडिंग प्रणाली अपनाई गई।

मंत्रिमंडल ने 7 जुलाई 2011 को अपनी बैठक में निजी एजेंसियों के जरिए एफ एम रेडियो प्रसारण सेवाओं का विस्तार (तृतीय चरण) को अनुमोदित किया। नीति के दिशा-निर्देश 25 जुलाई 2011 को अधिसूचित किए गए। इस नीति के तहत एफ एम रेडियो चैनलों के लिए अनुमति बढ़ते क्रम में ई-नीलामी के आधार पर दी जाएगी। दूरसंचार विभाग ने 3 जी और बी डब्ल्यू ए आवंटन में यही नीति अपनाई है। लाइसेंसिंग के तरीके के बारे के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने भी एफ एम चरण-III के बारे में यही सिफारिश की थी। एफ एम चरण-III नीति में एफ एम रेडियो सेवाएं वर्तमान 86 शहरों के अलावा 227 अन्य नये शहरों मे शुरु करने की योजना है। इस तरह 294 शहरों में 839 नये एफ एम रेडियों चैनल हो जाएंगे और एक लाख से ज्यादा आबादी वाले सभी शहर एफ एम रेडियो प्रसारण के दायरे में आ जाएंगे। मंत्रिमंडल ने बढ़ते क्रम में ई-नीलामी कर के एफ एम चैनलों के लाइसेंस आबंटित करने के मंत्रालय के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। एम एफ चरण-III के बारे में लाइसेंस देने का तरीका तय करने के लिए मंत्रियों की समिति ने भी ऐसी ही सिफारिश की थी। यही तरीका दूरसंचार विभाग ने 3 जी और बी डब्ल्यू स्पैक्ट्रम के आबंटन के लिए भी अपनाया था।

एफ एम सेल की एकमात्र योजना स्कीम है- निजी एफ एम रेडियो (चरण-III)। इसके अंतर्गत 7 शहरों (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद और जयपुर) में निजी एजेंसियों के लिए को-लोकेशन फैसिलिटी तैयार की जानी हैं। यह कार्य ब्रॉडकास्ट इंजिनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) के जरिए किया जाना हा। 10 वीं योजना में इस काम के लिए 18.18 करोड़ रुपयों का परिव्यय स्वीकृत किया गया था और (मूल योजना के अनुसार) यह काम 31 मार्च 2007 को पूरा होना था। चूंकि बाद में मुंबई और बंगलुरु में को-लोकेशन फैसिलिटी के लिए आकाशवाणी/दूरदर्शन के टॉवर बनाने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया। इससे योजना का खर्च 18.18 करोड़ रुपये से घटकर 13.11 करोड़ रुपये हो गया। इस घटी लागत में से 2008-09 तक 9.73 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। 2009-10 में 108.89 लाख की फाइनल ग्रांट स्वीकृत की गई और इतनी ही राशि मंजूर की गई। इस तरह इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कुल 1311.24 लाख रुपये के संशोधित/घटाए गए परिव्यय में से अब तक 1081.89 लाख रुपये स्वीकृत/जारी किए गए। इस कार्य के तहत, स्वीकृत फाइनल ग्रांट/बजट अनुमान में से बेसिल को टॉवर लगाने के लिए जारी वर्ष-वार रकम का विवरण इस प्रकार है।

| वर्ष | फाइनल ग्रांट/ब.अ. | राशि जारी/स्वीकृत |
|---|---|---|
| 2005-06 | 800.00 | 800.00 |
| 2006-07 | 63.00 | 63.00 |
| 2007-08 | 100.00 | 100.00 |
| 2008-09 | 10.00 | 10.00 |
| 2009-10 | 100.89 | 108.89 |
| 2010-11 | 0.01 | -- |
| 2011-12 | 0.01 | -- |
| **कुल** | | **1081.89** |

जहां तक योजना के सयुक्त होने का प्रश्न है, शुरु में यह परियोजना 10 वीं योजना में 18.18 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 9 शहरों में को-लोकेशन फैसिलिटी मुहैया कराने की थी लेकिन बाद में इसे संशोधित कर दिया गया, इसकी संशोधित अनुमानित लागत 13.11 करोड़ रुपये रखी गई और इसमें देहरादून सहित 6 शहरों में ऐसी ही को-लोकेशन फैसिलिटी लगाना शामिल कर लिया गया। कोलकाता को छोड़कर 5 शहरों में टॉवर लगाए जा चुके हैं। कोलकाता में टॉवर लगाने के स्थान का चयन होने में देरी हुई और दूरदर्शन केन्द्र, गोल्फ ग्रीन, कोलकाता मे स्थान चुन लिए जाने के बाद भी आकाशवाणी द्वारा स्थान की मंजूरी नही दिए जाने से वहां टॉवर नहीं लगाया जा सका जबकि बेसिल ने अगस्त 2009 में ही इस बारे में आवेदन कर दिया था। बेसिल ने स्पष्ट किया कि लाइसेंस आवेदन दाखिल करने वाले (एल थ्रो आई होल्डर) को कोलकाता के टॉवर के लिए सामग्री प्रदान की जानी चाहिए और यह किसी और टॉवर के लिए उपयोग में नहीं लाई जानी चाहिए। 13.11 करोड़ रुपये के संशोधित परिव्यय में से बेसिल को अब तक 1081.89 करोड़ रुपये मंजूर/जारी हो चुके हैं। इस बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष 2010-11 की वार्षिक योजना और 2011-12 के बजट अनुमान ने 0.01 लाख का जो टोकन प्रावधान किया गया था, उसमें से कोई राशि व्यय नहीं की गई।

# प्रसार भारती

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) देश की एक सार्वजनिक प्रसारक सेवा है और उसके दो संघटक हैं, आकाशवाणी और दूरदर्शन। यह 23 नवंबर 1997 से अस्तित्व में आया। इस सेवा का उद्देश्य सार्वजनिक प्रसारण सेवा के रूप में सर्वसाधारण को जानकारी देना, उन्हें शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना एवं देश में प्रसारण के संतुलित विकास को सुनिश्चित करना है।

## संगठनात्मक ढांचा

निगम के मामलों का सामान्य निरीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन प्रसार भारतीय बोर्ड करता है। बोर्ड समय-समय पर बैठकें करता है और महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श करता है एवं नीतियों के कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश देता है। कार्यकारी सदस्य निगम मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)के रूप में कार्य करते हैं और बोर्ड का नियंत्रण और निरीक्षण करते हैं। सीईओ बोर्ड में इस तरह अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा और अपने सभी कार्य इस प्रकार करेगा

जिस प्रकार अधिनियम के तहत निगम द्वारा किए जाते हैं।

महानिदेशक आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रमुख के तौर पर कार्य करते हैं। बोर्ड के नीति निर्देश और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की दैनंदिन मामलों के प्रबंधन के लिए वे सदस्य(वित्त), सदस्य (कार्मिक) और सीईओ के निकट सहयोग से कार्य करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन में, विभिन्न गतिविधियों, जैसे प्रोग्राम, इंजीनियरिंग, प्रशासन, वित्त और समाचार के लिए व्यापक स्तर पर चार भिन्न खंड हैं।

## आकाशवाणी

आकाशवाणी (एआईआर)प्रसार भारती अधिनियम, 1990 में दिए गए प्रावधान के तहत कार्य करता है। आकाशवाणी विभिन्न स्टेशनों पर अपने कार्यक्रम प्रसारणों के माध्यम से सर्वसाधारण को जानकारी देता है, उन्हें शिक्षित करता है और उनका मनोरंजन करता है। ध्वनि प्रसारण के माध्यम से यह देश के सभी लोगों को सरकारी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की जानकारी देता है। इसके कार्यक्रम संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, महत्वपूर्ण समाचार और प्रासंगिक रुचि की समसामयिक घटनाओं पर आधारित होते हैं। यह राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने के लिए अपने प्रसारण के माध्यम से विभिन्न विचारों को प्रस्तुत करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम संतुलित और निष्पक्ष हैं(अध्याय-1)।

वार्षिक योजना 2011-12 के लिए आकाशवाणी का प्रत्यक्ष बजटीय सहयोग 260.37 करोड़ रुपये है जिसमें 243.37 करोड़ रुपये पूंजी घटक के अंतर्गत एफएम सेवा के विस्तार, उत्तर पूर्व के विशेष पैकेज के तहत एफएम सेवा के विस्तार, आकाशवाणी नेटवर्क के डिजिटलीकरण के लिए हैं और 17.00 करोड़ रुपये सीमांत क्षेत्रों में आकाशवाणी/दूरदर्शन के दायरे को मजबूत करने और राजस्व फुटकर व राजस्व सॉफ्टवेयर के लिए सुनिश्चित हैं। पूंजी योजना स्कीमें सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण द्वारा वित्त पोषित होती हैं जबकि राजस्व योजना के तहत स्कीमें अनुदान के रूप में प्रदान की जाती हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए नया प्रस्ताव मंत्रालय के पास भेजा गया है। इसी के अनुरुप 2012-13 का वार्षिक योजना प्रस्ताव अध्याय-II में दिया गया है। सार्वजनिक प्रसारक के रूप में संगठन के अधिक विकास से संबंधित नीतिगत फैसलों के आधार पर आकाशवाणी द्वारा विभिन्न पहल की गई हैं। इन्हें आम जनता की जरूरतों और विशेष लक्षित समूहों, जैसे अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के कल्याण, महिला सशक्तीकरण और उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर लागू किया जाता है (अध्याय-III)।

वार्षिक योजना 2010-11 और 2011-12 (दिसंबर 2011 तक) के दौरान भौतिक एवं वित्तीय प्रदर्शन का योजनागत विवरण अध्याय V में दिया गया है। वार्षिक योजना 2010-11 का स्वीकृत परिव्यय 183.48 करोड़ रुपए था और खर्चा 86.93 करोड़ रुपये था। इसी प्रकार वार्षिक योजना 2011-12 का कुल परिव्यय 260.37 करोड़ रुपये है और दिसंबर 2011 तक खर्चा 97.07 करोड़ रुपए है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान का योजनागत विवरण और संशोधित अनुमान तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 (दिसंबर 2011 तक) की जानकारी अध्याय-V में दी गई है। वित्तीय वर्ष 2010-11 तक जारी किए गए अनुदान के संदर्भ में आवश्यक उपयोग सर्टिफिकेट (यूसी) प्रासंगिक नियमों के अनुसार प्रसार भारती (आकाशवाणी) द्वारा जुटाए गए हैं और कोई लंबित यूसी नहीं है।

## निरीक्षण प्रणाली

विभिन्न स्तरों पर समीक्षा और प्रसार भारती को जारी अनुदान के समय ही मासिक व्यय विवरण के माध्यम से आकाशवाणी की सभी योजना स्कीमों के प्रदर्शन का नियमित निरीक्षण किया जाता है। मंत्रालय द्वारा रखी गई अन्य शर्तों को पूरा करने के आधार पर अनुदान को जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत फॉरमेट में अर्द्ध वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट (एचवाईपीआर)को तैयार किया जाता है जो समग्र रूप से सभी योजनाओं के विकास की समीक्षा करती है।

## दूरदर्शन

भारत में दूरदर्शन की शुरुआत, दिल्ली में एक प्रायोगिक प्रसारण के माध्यम से सितंबर 1958 में की गई जिसे बाद में 1965 में एक स्थायी सेवा के तौर पर जारी किया गया। 1976 तक दूरदर्शन आकाशवाणी का ही हिस्सा रहा, तत्पश्चात इसे अलग किया गया और महानिदेशक की अध्यक्षता में इसे अलग विभाग बना दिया गया। रंगीन टीवी और राष्ट्रीय प्रसार की शुरुआत 1982 में की गई। तब से दूरदर्शन विश्व के प्रमुख सार्वजनिक प्रसारक के रूप में निरंतर प्रगति कर रहा है। निशुल्क डीटीएच सेवा के साथ, दूरदर्शन 35 चैनलों का संचालन करता है। दूरदर्शन का 67 स्टूडियो का क्षेत्रीय नेटवर्क है और देश के भू-भागीय रूप को देखते हुए दूरदर्शन ने देशभर में 1415 ट्रांसमीटर लगाए हैं। इसके 35 चैनल इस प्रकार हैं :

## दूरदर्शन सैटेलाइट चैनल

**अखिल भारतीय चैनल-7**

डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, डीडी भारती, डीडी ज्ञान दर्शन, डीडी स्पोर्ट्स, डीडी राज्य सभा, डीडी उर्दू।

**क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल- कुल 11**

मलयालम, (केरलम), तमिल (पोदिगई), उड़िया, तेलुगू, (सप्तगिरी), बंगाली (बांग्ला), कन्नड़ (चंदना), मराठी (सहयाद्रि), गुजराती, कश्मीरी (कशीर), उत्तर पूर्व, पंजाबी आदि

**राज्य नेटवर्क- 15**

राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश

**अंतरराष्ट्रीय चैनल**

डीडी इंडिया

# भूभागीय नेटवर्क

## कार्यक्रम निर्माण केंद्र

देश भर में कार्यक्रम निर्माण के लिए 67 स्टूडियो केंद्र हैं इनमें राज्यों की राजधानियों में 17 बड़े स्टूडियो केंद्र, दिल्ली में एक केंद्रीय निर्माण केंद्र, गुवाहाटी में एक क्षेत्रीय निर्माण केंद्र और देश के विभिन्न भागों में 48 अन्य स्टूडियो केंद्र शामिल है। इन 67 स्टूडियो केंद्रों में से 23 पूरी तरह डिजिटलाइज, 31 आंशिक रूप से डिजिटलाइज और 13 एनालॉग मोड में है। वर्तमान परियोजनाओं के पूरा होने तक चार को छोड़कर सभी स्टूडियो केंद्र पूरी तरह डिजिटल हो जाएगें। बाकी चार केंद्रों को 12वीं योजना के दौरान डिजिटलाइज करने का प्रस्ताव है।

## भूभागीय ट्रांसमिटर

भूभागीय कवरेज के लिए, इस समय अलग-अलग क्षमता के 1415 ट्रांसमिटर हैं। डीडी1 के अंतर्गत 1242 ट्रांसमिटर हैं (इनमें से 108 प्रसारण की पूरी अवधि के दौरान क्षेत्रीय कार्यक्रम रिले करते हैं) । डीडी न्यूज के अंतर्गत 169 और 4 डिजिटल ट्रांसमिटर हैं। भूभागीय मोड में डीडी1 चैनल की कवरेज देश के करीब 92 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध है। डीडी न्यूज चैनल में 49 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध है। क्षेत्र-वार, डीडी1 चैनल 81 प्रतिशत और डीडी न्यूज चैनल 26 प्रतिशत भू-भाग को कवर करता है।

## नि:शुल्क डीटीएच ''डीडी डायरेक्ट प्लस''

दूरदर्शन ने दिसम्बर 2004 में 33 टीवी चैनलों के गुच्छे के साथ अपनी नि:शुल्क ''डीडी डायरेक्ट प्लस'' सेवा शुरू की। इस सेवा का प्रमुख उद्देश्य अब तक भू-भागीय प्रसारण से अछूते क्षेत्रों को टेलीविजन कवरेज उपलब्ध कराना था। इसके बाद डीटीएच प्लेटफार्म की क्षमता बढ़ाकर इसमें 59 टेलीविजन चैनल शामिल कर लिए गए। अंडमान और निकोवार द्वीप समूह को छोड़कर डीटीएच सिग्नल देश के सभी हिस्सों में छोटे आकार की डिश के जरिए उपलब्ध हैं। अंडमान और निकाबार द्वीप समूह में सितम्बर 2009 में सी-बैंड के साथ 10 चैनलों वाली डीटीएच सेवा शुरू की गई। ये चैनल नि:शुल्क उपलब्ध है और दर्शकों को इनके लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता।

## 2011-12 के दौरान विकास गतिविधियां

## स्टूडियो परियोजना

दूरदर्शन केंद्र, लेह में 12 सितम्बर 2011 को पूरी तरह डिजिटल और स्थाई स्टूडियो तैयार हो गया।

तिरूपति में 23 दिसम्बर 2011 को नए स्टूडियो सेंटर ने काम करना शुरू कर दिया।

आंशिक रूप से डिजिटलाइज 31 स्टूडियो को पूर्णत: डिजिटलाइज किया जा रहा है। यह कार्य मार्च 2012 तक पूरा होने की उम्मीद है।

## राज्यों का नेटवर्क

जम्मू-कश्मीर के लेह जिले में 13 सितम्बर 2011 से सभी वीएलपीटी से क्षेत्रीय सेवाओं के लिए आवंटित समय में इन सेवाओं का प्रसारण शुरू हो गया।

## ऑटोमोड एलपीटी (पुराने एलपीटी के स्थान पर)

निम्नलिखित पांच ऑटोमोड एलपीटी (500 वॉट के और 1 कनफिगरेशन वाले) स्थापित किए गए:

नारनौल (हरियाणा) पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) खरगौन (मध्य प्रदेश)

जगदीशपुर (उत्तर प्रदेश) चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

इन पांच स्थानों के अलावा, निम्न 6 स्थानों पर भी स्थापना का काम पूरा हो गया है और मार्च 2012 तक ये एलपीटी लगा दिए जाएंगे।

पन्ना (मध्य प्रदेश) भिन्ड (मध्य प्रदेश) कुण्णूर (तमिलनाडु)

शोरानूर (केरल) आजमगढ़ (डीडी न्यूज) (उत्तर प्रदेश)

चंदेरी (मध्य प्रदेश)

## एचपीटी

कुंभकोणम टॉवर को 150 मीटर की पूरी ऊंचाई तक ले जाया गया। कुंभकोणम (स्थाई व्यवस्था) के मार्च 2012 तक काम शुरू कर देने की उम्मीद है।

अमृतसर में टॉवर को पूरी ऊंचाई तक ले जाया गया।

## भू-केंद्रों का उन्नयन

गैंगटोक, इंफाल, कोहिमा, इटानगर, अगरतल, लेह, चंडीगड़, पोर्ट ब्लेयर, हिसार और पणजी में 10 भू-केंद्रों का कनफिगरेशन 1:1 से बढ़ाकर 2:1 करने की परियोजना जारी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पांच भू-केंद्रों के एसआईपीसी के लिए आदेश दिया गया है। फरवरी 2012 तक इन भू-केंद्रों के तैयार हो जाने की संभावना है। बाकी पांच भू-केंद्र 2012 के अंत तैयार हो जाएंगे। इन भू-केंद्रों के उन्नयन के साथ ही कार्यक्रमों की प्राप्ति और वितरण शुरू हो जाएगा।

## नए भू-केंद्र

विजयवाड़ा, इंदौर, ग्वालियर, राजकोट और गोरखपुर में पांच नए भू-केंद्रों की परियोजनाएं शुरू हो गई हैं और इन पर विभिन्न चरणों में काम चल रहा है। वर्ष 2012-13 में उनके पूरा हो जाने की उम्मीद है।

## डीएसएनजी

इस समय उपलब्ध पुरानी डीएसएनजी के स्थान पर 6 नई डीएसएनजी खरीदने के आदेश दिए जा चुके हैं। महत्वपूर्ण घटनाओं की सजीव प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए 9 और डीएसएनजी हासिल की जा रही है।

## विविध गतिविधियां

दूरदर्शन भवन परिसर में टॉवर सी बिल्डिंग के निर्माण का कार्य शुरू किया जा चुका है।

भूभागीय मोड में, देश की 92 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन की कवरेज उपलब्ध है। दूरदर्शन का अधिदेश, लक्ष्य तथा उद्देश्य और नीतिगत दायरा **अध्याय 1** में दिए गए हैं।

2011-12 की योजना के लिए सीधा बजट समर्थन 271.40 करोड़ रुपये है इसमें 196.51 करोड़ रुपये पूंजीगत घटक में ट्रांसमीटरों, स्टूडियो और हाई डेफिनेशन टीवी (एचडीटीवी) के डिजिटलाइजेशन के लिए है। जबकि 74.89 करोड़ रुपये राजस्व घटक के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष पैकेज तथा सॉफ्टवेयर हासिल करने (सामान्य) के लिए है। पूंजीगत योजना स्कीमें सरकार से प्राप्त ऋण के जरिए वित्तपोषित होती हैं। जबकि राजस्व योजना स्कीमों के लिए अनुदान सहायता दी जाती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए नए प्रस्ताव मंत्रालय को भेजे जा चुके हैं। इसके अनुरूप 2012-13 के लिए वार्षिक योजना प्रस्ताव **अध्याय 2** मे दिए गए हैं।

दूरदर्शन ने संगठन के विकास के बारे में नीतिगत निर्णयों और लोक प्रसारक के रूप में अपनी भूमिका के अनुरूप अनेक कदम उठाए हैं। ये कदम आम लोगों की जरूरतों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों/जनजातियों की भलाई, महिलाओं का सशक्तीकरण और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए उठाए गए हैं। इनका विवरण **अध्याय 3** में दिया गया है।

वार्षिक योजना 2010-11 और 2011-12 (दिसम्बर 2011 तक) के भौतिक और वित्तीय कार्य निष्पादन का स्कीम-वार ब्यौरा **अध्याय 4** में दिया गया है। 2010-11 की वार्षिक योजना के लिए स्वीकदत परिव्यय 157.00 करोड़ रुपये और व्यय 129.37 करोड़ रुपये था। 2011-12 की वार्षिक योजना के लिए कुल परिव्यय 271.40 करोड़ रुपये है।

विधायी और स्वायत्त संस्था के रूप में प्रसार भारती के कार्य निष्पादन की समीक्षा **अध्याय 4** में दी गई है।

## निगरानी की व्यवस्था

दूरदर्शन की स्कीमों का नियोजन, निर्माण और लागू करने की प्रणाली दूरदर्शन महानिदेशालय में तय की जाती है। विभिन्न केंद्रों/कार्यालयों से जुड़ी स्कीमों का कार्यान्वयन उस क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है। ऐसे चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं- दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपूरा और सिक्किम में रख-रखाव गतिविधियों की देखरेख के लिए गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत के लिए विशेष क्षेत्र बनाया गया है। विभिन्न परियोजनाओं का सिविल कार्य आकाशवाणी और

दूरदर्शन के सिविल कंस्ट्रक्शन विंग (सीसीडब्ल्यू) द्वारा किया जाता है। विभिन्न परियोजनाओं के प्रमुख कार्यों की निदेशालय में निगरानी की जाती है। क्षेत्रीय चीफ इंजीनियर और सीसीडब्ल्यू के चीफ इंजीनियर विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत अपने-अपने क्षेत्रों की निगरानी करते हैं।

दूरदर्शन की सभी प्रमुख स्कीमों के लिए लक्ष्य तय किए गए हैं जिनकी क्षेत्रीय कार्यालयों और निदेशालय में लगातार निगरानी होती है ताकि ये परियोजनाएं समय पर पूरी हो जाएं और पूर्व निर्धारित लागत से ज्यादा रकम खर्च न हो। क्षेत्रीय चीफ इंजीनियर सिविल कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए समय-समय पर सीसीडब्ल्यू अधिकारियों के साथ बैठकें करते रहते हैं। मुख्यालय में इंजीनियर इंन चीफ के स्तर पर और क्षेत्रीय अधिकारियों और सीसीडब्ल्यू अधिकारियों के स्तर पर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठकें नियमित रूप से की जाती है। महानिदेशक दूरदर्शन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती के स्तर पर भी निश्चित समय अंतरालों में समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। दूरदर्शन की स्कीमों के कार्यान्वयन का जायजा लेने के लिए मंत्रालय ने समय-समय पर बैठकें आयोजित करता है।

मंत्रालय का योजना समन्वय सेल मासिक विवरण के जरिए प्रसार भारती के आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्य निष्पादन के स्कीम-वार ब्यौरे की लगातार समीक्षा करता रहता है।

तीन फरवरी 2011 को वित्तीय मामलों में विशेषाधिकार प्राप्त तीन सदस्यीय समिति गठित की गई। 7 जून 2011 को नए सदस्यों को शामिल करके इस समिति का पुर्नगठन किया गया और इसका नाम अधिकार प्राप्त समिति (एम्पावर्ड कमेटी) रखा गया है इसमें आकाशवाणी के और दूरदर्शन के महानिदेशक और प्रसार भारती के सीनियर ग्रेड मैनेजर (बी एण्ड ए) शामिल किए गए। इनके अलावा समिति में प्रसार भारती बोर्ड के दो अंशकालिक सदस्य भी होते हैं। यह समिति वित्त से जुड़े सभी मामलों का जायजा लेती है और उन्हें संपन्न करती है। मंत्रालय में संयुक्त सचिव (प्रसारण) हर सप्ताह प्रत्येक स्कीम के कार्य निष्पादन की निगरानी करते हैं और योजनागत व्यय की समीक्षा करते हैं।

# मुख्य सचिवालय की प्रसारण विंग स्कीमें

## (क) स्कीम इंटरनेशनल चैनल

भारत के वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने से यह अनिवार्य हो गया है कि संवेदनशील मुद्दों पर भारत की स्थिति और विचार कम से कम समम में अधिक से अधिक देशों में पहुंचने चाहिए। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य अल-जजीरा, बीबीसी, सीएनएन, सीसीटीवी आदि की तरह विश्व भर में भारतीय स्थिति को प्रसारित करना है। इसमें मौजूदा डीडी न्यूज चैनल को डीडी इंडिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज और कार्यक्रम शुरू करने होंगे। डीडी इंडिया के काफी देशों में दर्शक हैं।

## (ख) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग

2002 में मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की स्थापना के लिए प्रथम नीति दिशा निर्देषों को मंजूरी दी। इसके तहत केवल शैक्षिक संस्थाओं को ही सामुदायिक रेडियो स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। ये दिशा-निर्देष 2006 में बदले गए और नए दिशा निर्देशों को मंजूदी दी गई। इनमें पात्रता का दायरा बढ़ाकर नागरिक समितियों और स्वैच्छिक संगठनों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू), आईसीए आर संस्थाएं, कृषि विज्ञान केंद्रों, पंजीकृत समितियों/स्वायत्त निकायों/सोसायटीज एक्ट के तहत पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट आदि को भी शामिल कर लिया गया। आज देश में 130 केंद्र चालू हैं और 200 पाइप लाइन में हैं। प्रामाणिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय ने कार्य समूह का गठन किया है ताकि ये संस्थाएं अपने रेडियो स्टेशन स्थापित कर सकें। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक योजना स्कीम लागू है जिसके दो भाग हैं-सीआरएसएस तथा आईईसी गतिविधियां। इसके लिए 170 करोड़ रुपये के परिव्यय की मांग की गई है। जिसमें से 150 करोड़ सीआरएसएस तथा बाकी 20 करोड़ रुपये आईईसी गतिविधियों के लिए हैं।

# अध्याय-1

## अधिदेश, लक्ष्य, उद्देश्य, नीतिगत ढांचा तथा नीति वक्तव्य

# सूचना क्षेत्र

## विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

**1.1 अधिदेश :** विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) भारत सरकार की प्रमुख मल्टी मीडिया विज्ञापन एजेंसी है। यह विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए जनता तक पहुंचाने का काम करती है। डीएवीपी अनेक स्वायत्त संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रचार आवश्यकताओं को भी पूरा करती है। समाज से जुड़े संदेशों का आम आदमी तक पहुंचाने के लिए यह निम्नलिखित माध्यमों का सहारा लेती है-

(क) समाचारपत्रों में विज्ञापन

(ख) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रव्य/दृश्य स्पॉट, जिंगल्स इत्यादि,

(ग) उभरता नया मीडिया अर्थात डिजिटल सिनेमा मोबाइल टेलीफोनी इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग साइट,

(घ) मुद्रित प्रचार साहित्य, पुस्तिकाएं, ब्रोशर, पोस्टर इत्यादि,

(ङ) बाह्य प्रचार माध्यमों - होर्डिंग्स, मेट्रो रेल पैनल, बस पैनल, कियोस्क, सार्वजनिक सुविधाएं इत्यादि।

(च) ग्रामीण तथा कस्बाई क्षेत्रों में भीड़भाड़ वाले इलाके जैसे कि मेले इत्यादि में फोटो प्रदर्शिनियां

(छ) साफ्टवेयर, आफिस के बुनियादी ढांचे और कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि।

**1.2 नीतिगत ढांचा :** कुल मिलाकर डीएवीपी कई वर्षों से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और विकास के क्षेत्र में उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है और यह जनता के बीच जागरूकता निभाने, विकासात्मक गतिविधियों में जनता की भागीदारी प्राप्त करने और गरीबी तथा अन्य सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। मुद्रित माध्यम प्रचार तथा श्रव्य-दृश्य प्रचार को भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी क्रमशः विज्ञापन नीति और दृश्य-श्रव्य प्रचार नीति के तहत किया जाता है।

**लक्ष्य**

वेबसाइट www.davp.nic.in पर उपलब्ध चार्टर अपने ग्राहकों, नागरिकों आदि को मात्रातमक तरीके से सेवाएं देने का एक प्रयास है। डीएवीपी वर्तमान में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बार-बार गुणवता बोध के साथ ग्राहक समर्पित संगठन बनने के लिए तैयार कर रहा है। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी, सेवाओं का व्यावसायीकरण तथा कार्य प्रक्रियाओं और ढांचे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आगे, मीडिया आउटलेट के लिए मंत्रालयों/विभागों की आवश्यकताओं के लिए मात्र डाक घर होने के स्थान पर डीएवीपी ऐसी सामग्री/विषयवस्तु को तैयार करने का लक्ष्य बना रहा है जोकि सरकारी सूचना और संचारी टूलों के लिए एकीकृत भूमिका निभा सके।

# क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

**संक्षिप्त परिचय**

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाई, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय में 207 क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां कार्यरत हैं और देश भर में 22 क्षेत्रीय कार्यालयों के नियंत्रण में ये कार्यरत हैं। केन्द्र सरकार की इन नीतियों, कार्यक्रमों तथा योजनाओं पर उनका लक्ष्य और उद्देश्य केन्द्रित है जिनमें लोगों के उत्थान पर अधिक जोर दिया गया है। इस प्रकार इनके कार्यकाल देश के ग्रामीण, पिछड़े, सीमावर्ती तथा जनजातीय क्षेत्रों तक केन्द्रित हैं। बहुमाध्यम अभियानों, फिल्म प्रदर्शनों, फोटो प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, ग्रुप विचार-विमर्शों तथा विशेष वार्ता कार्यक्रमों जिनमें गोष्ठी, संगोष्ठी, रैलियां तथा ग्रामीण खेल आदि शामिल हैं, के माध्यम से संदेशों का प्रचार-प्रसार किया जाता है। निदेशालय के लक्ष्य और उद्देश्य मोटे तौर पर इस प्रकार हैं—

(1) लोगों और सामग्री को एक दूसरे के निकट लाकर सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना और उनके लाभ के लिए कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जानकारी देना।

(2) लोगों को लोकतंत्र, समाजवाद और धर्म निरपेक्षता के बुनियादी राष्ट्रीय मूल्यों की जानकारी देना तथा लगातार व्यक्तिगत संपर्कों के माध्यम से ऐसे मूल्यों में उनकी आस्था को दृढ़ बनाना।

(3) विकासात्मक गतिविधियों में सक्रिय, सहभागिता के लिए सबसे निचले स्तर के लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना और कल्याण तथा विकास कार्यों पर अमल करने के संबंध में जनमत को भी सक्रिय करना।

(4) सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया हासिल करना। इस प्रकार निदेशालय सरकार और जनता के बीच संचार के दो तरफा चैनल की तरह कार्य करता है।

# एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार

साप्ताहिक रोजगार समाचार अंग्रेजी, हिंदी तथा उर्दू में प्रकाशित होता है। यह प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का प्रमुख प्रकाशन है। इस साप्ताहिक पत्र में केंद्रीय एवं राज्य सरकारें, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, स्वायत्त निकायों, विश्वविद्यालयों, विदेशी संस्थानों जैसे फोर्ड फाउंडेशन, ब्रिटिश काउंसिल आदि में नौकरियों के विज्ञापन, व्यावसायिक पाठयक्रमों के लिए प्रवेश अधिसूचनाएं, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग जैसे संगठनों तथा अन्य सामान्य भर्ती निकायों की परीक्षा अधिसूचनाएं और उनके परिणामों तथा मध्य-स्तरीय रोजगार उन्नयन के अवसरों (प्रतिनियुक्तियों) की सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त एक सम्पादकीय हिस्सा भी है जो कैरियर से सम्बन्धित दो मुख्य लेख प्रकाशित करता है।

इस साप्ताहिक पत्र का मूल लक्ष्य सिविल सेवा के अभ्यार्थियों, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं तथा साक्षात्कार में बैठने वाले उम्मीदवारों, अपने कैरियर तथा पेशे को चुनने के लिए तैयार युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करना है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि अपनी सामाजिक जिम्मेवारी, जिसके लिए इस पत्र को शुरू किया गया था, निभाने के साथ-साथ एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार नियमित रूप से पर्याप्त लाभ कमा रहा है। यह पत्र, जिसे सबसे अधिक प्रसारित साप्ताहिक पत्रों में शामिल होने का गौरव प्राप्त है, हर शनिवार को देश के कोने-कोने में उपलब्ध होता है।

एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार की वेबसाइट www.employmentnews.gov.in बहुत अधिक सफल है तथा युवाओं में बहुत लोकप्रिय है। हर रोज औसतन 20,000 से अधिक लोग इस वेबसाइट को खोलते हैं।

| क्र.सं. | वर्ष | राजस्व | कुल राजस्व (लाख रुपये में) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2008-09 | 5765.85 | 3342.60 |
| 2. | 2009-10 | 7157.01 | 4887.33 |
| 3. | 2010-11 | 5425.33 | 2865.32 |

# भारतीय जन संचार संस्थान

भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) 17 अगस्त, 1965 को अस्तित्व में आया। इस संस्थान का उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री और तत्कालीन सूचना व प्रसारण मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। इस संस्थान की स्थापना जन संचार के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध कार्य के उद्देश्य से की गई थी। यूनेस्को के दो परामर्शदाताओं समेत कुछ कर्मचारियों के साथ शुरू किया गया था जिसमें मुख्य तौर पर केन्द्रीय सूचना सेवा अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम और छोटे स्तर पर शोध अध्ययन का आयोजन होता था लेकिन पिछले लगभग 44 वर्षों में यह संस्थान आधुनिक समय में तेजी से बढ़ते हुए और बदलते हुए मीडिया एवं संचार उद्योग की विविध और बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई कोर्स आयोजित करने वाला संस्थान बन गया।

हाल के समय में जन संचार में काफी बदलाव आया है और यह निर्णय लेने की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली गतिविधि के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरा है। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने मास मीडिया के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसने इस विधा के छात्रों, शिक्षकों और प्रयोगकर्ताओं के लिए बड़ी चुनौतियां भी खड़ी की हैं। तेजी से बदलती हुई प्रौद्योगिकी इस विद्या के पूरे रंग को एक ऐसे रूप में बदल रही है जिसके बारे में शैक्षणिक गतिविधि के किसी अन्य क्षेत्र में कोई जानकारी नहीं है। निस्संदेह समय की मांग है मीडिया और संचार के निर्वाह और प्रभाव क्षमता को बढ़ाने के लिए आने वाली चुनौतियों का कारगर ढंग से जवाब देना।

यह संस्थान एक ऐसे सूचना ढांचे के निर्माण और उसकी मजबूती में योगदान करता है जो न केवल भारत बल्कि अन्य विकासशील देशों की आवश्यकताओं के लिए भी अनुकूल होता है। यह संस्थान देश के और विदेश के अन्य संस्थानों/निकायों को अपनी विशेषज्ञ और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। भारतीय जनसंचार संस्थान केन्द्रीय/राज सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, विश्वविद्यायों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त किए गए अनुरोध के जवाब में प्रशिक्षण, शोध और परामर्श सेवा प्रदान करता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियों की बढ़ती लोकप्रियता और क्षेत्रीय आकांक्षा को पूरा करने के लिए इस संस्थान ने पूर्वी क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए 1993 में ओडिशा के ढेंकनाल में एक शाखा खोली। वर्तमान में इस शाखा में दो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पत्रकारिता (अंग्रेजी) और पत्रकारिता (ओड़िया) का आयोजन किया जाता है।

अमरावती (महाराष्ट्र) के संत गजबाबा अमरावती विश्वद्यिालय में एक नया क्षेत्रीय केंद्र खोला गया है जहां अगस्त 2011 से पाठ्यक्रम शुरू किया जा चुका है। इसी तरह का एक और क्षेत्रीय केंद्र आयजोल (मिजोरम) में अस्थायी तौर पर खोला गया है जहां मिजोरम विश्वद्यिालय में अस्थायी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है।

भारत सरकार सूचना व प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से भारतीय जन संचार संस्थान को वित्तीय सहयोग प्रदान करती है। इस संस्थान की गतिविधियों का मार्ग निर्देशन इसकी कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता है। सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सचिव इस कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष होते हैं और इस संस्थान (सोसायटी) के भी अध्यक्ष होते हैं। इस परिषद के अन्य सदस्यों में अन्य लोगों के साथ-साथ दुनिया की विख्यात हस्तियां शामिल हैं।

## शैक्षणिक कार्यक्रम

संस्थान की गतिविधियां तीन क्षेत्रों - शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध पर केंद्रित है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्थान में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों कासंचालन किया जाता है।

1. भारतीय सूचना सेवा (ग्रुप ए और बी) के अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम
2. नई दिल्ली, अमरावती (महारष्ट्र), आइजोल (मिजोरम) और ढेंकनाल में पत्रकारिता (अंग्रेजी) का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
3 पत्रकारिता (हिन्दी) का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, नई दिल्ली
4 विज्ञापन और जनसंपर्क में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, नई दिल्ली
5. रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, नई दिल्ली
6. पत्रकारिता (ओड़िया) का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, और
7. विकास पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (मध्य स्तर के कार्यरत पत्रकारों और एशिया, अफ्रिका, लातिन अमरीका तथा पूर्वी यूरोप के सूचना अधिकारियों के लिए)

क्रम संख्या-7 का पाठ्यक्रम विकासशील देशों के कार्यरत पत्रकारों और सूचना अधिकारियों के लिए है। अफ्रीका, एशिया और लातिन अमरीका के मध्य स्तर पर कार्यरत पत्रकार इस पाठ्यक्रम में शामिल होने के बेहद इच्छुक रहते हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रत्येक वर्ष औसतन 20-25 लोगों को दाखिला दिया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में दो पाठ्यक्रमों का संचालन होता है।

ये पाठ्यक्रम आईटीईसी/एससीएएपी योजना के तहत विदेश मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से संचालित होते हैं।

संस्थान ने भारतीय नागरिकों के लिये प्रदान किये जाने वाले डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) संबंधी आरक्षण के अंतिम चरण को लागू कर दिया है।

## भारतीय सूचना सेवा के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम

आई आई एम सी, भारतीय सूचना सेवा (आई आई एस) के अधिकारियों के प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र है। यह संस्थान इस सेवा के अधिकारियों को संचार तकनीकों को सीखने का अवसर देता हैं तथा उन्हें जन सूचना प्रणाली के प्रति अभिमुख करता है। पाठ्यक्रम में सूचना नीतियों और रणनीतियों पर विशेष रहता फोकस है।

## अल्पकालीन पाठ्यक्रम, कार्यशाला, संगोष्ठी और सम्मेलन

भारतीय जन संचार संस्थान द्वारा भारत और विकासशील देशों के परिप्रेक्ष्य में जन संचार के मुद्दों की बेहतर समझ के प्रति सहयोग की दृष्टि से संचार के विभिन्न विषयों पर संगोष्ठी और सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। संस्थान, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों के कार्मिकों के लिए नियमित और लघु-अवधि के पाठ्यक्रमों को चलाता है। रक्षा अधिकारियों और केंद्र/राज्य और निजी क्षेत्र के विभिन्न मीडिया/सूचना संगठनों में कार्य कर रहे कर्मिकों के लिए एक सप्ताह से तीन माह तक की अवधि वाले कई अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

## शोध व प्रकाशन

भारतीय जन संचार संस्थान जन संचार शोध का एक शीर्ष केन्द्र रहा है। इन वर्षों में संस्थान ने कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों, सरकार और गैर सरकारी निकायों के लिए प्रमुख शोध अध्ययनों का आयोजन किया है। संस्थान ने पहले 165 से भी अधिक शोध व मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किए हैं और इसके अलावा यहां अनेक शोध-निर्बंध तैयार किए गए हैं। इसके द्वारा आयोजित किए जाने वाले अधिकांश शोध अध्ययनों को प्रायोजकों द्वारा वित्त प्रदान किया जाता है। यह संस्थान अपनी वार्षिक योजनाओं के हिस्से के रूप में मास मीडिया से संबंधित मुद्दों के विविध पहलुओं पर भी शोध अध्ययन आयोजित करता है।

संस्थान अंग्रेजी में *कम्यूनिकेटर* और हिन्दी में *संचार माध्यम* अर्द्धवाषिक पत्रिकाओं को प्रकाशित करता है। यह लेबोरेटरी पत्रिकाओं (विभिन्न डिप्लोमा कोर्सों के छात्रों द्वारा) जैसी अन्य पत्रिकाओं को अपनी गतिविधियों पर एक वार्षिक रिपोर्ट और पत्रकारिता/जनसंचार पर पुस्तकों को प्रकाशित करता है।

## योजनाएं

1. आईआईएमसी को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उन्नत बनाना
2. चार राज्यों - जम्मू एवं कश्मीर, मिजोरम, महाराष्ट्र (विदर्भ) और केरल में आईआईएमसी की चार शाखाओं की स्थापना

## शोध अध्ययन

संस्थान ने वर्ष 2009-10 के दौरान 4 जारी अध्ययनों को पूरा कर लिया है। इन अध्ययनों को पूरा करने के अलावा संस्थान ने सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अनुरोध पर नीति के मुद्दों और भारत में विदेशी समाचार एजेंसियों के न्यूज ऑपरेशन नामक एक नया प्रायोजित अध्ययन भी शुरू किया है।

कुछ और अध्ययन मौजूदा वित्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान किये जाने का प्रस्ताव है।

## महिला/लिंग समानता

यह देखा गया है कि संस्थान में पी जी डिपलोमा पाठ्यक्रमों में औसतन 60 प्रतिशत छात्राएं हैं।

# फोटो प्रभाग

देश भर में सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकासात्मक कार्यक्रमों तथा सामाजिक परिवर्तन के फोटोग्राफ्स का दस्तावेजीकरण फोटो प्रभाग का मुख्य कार्य है। यह प्रभाग प्रचार के लिए आंतरिक तथा बाह्य तौर पर फोटोग्राफ्स की आपूर्ति करता है। इसके अलावा फोटो प्रभाव पी आई बी (प्रेस इनफोर्मेशन ब्यूरो) को फोटो ग्राफ्स देता है ताकि उसे समाचार पत्रों को वितरित किया जा सके। प्रदर्शन के लिए डीएवीपी तथा विदेश में प्रचार के किए प्रभाग एक्स पी डिवीजन को भी फोटोग्राफ्स की आपूर्ति करता है।

इसके अतिरिक्त प्रभाग केंद्र/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, पब्लिक सेक्टर उपक्रम तथा 'मूल्य स्कीम' के तहत अन्य लोगों को भी फोटोग्राफ की आपूर्ति करता है।

# भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना प्रथम प्रेस आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 1966 में की गई थी। प्रेस की आजादी को बनाए रखने और उसके स्तर में सुधार लाने के अपने दोहरे उत्तरदायित्व की पूर्ति की दिशा में परिषद बहुमुखी भूमिका अदा करती है। एक ओर यह सिविल न्यायालय की शक्तियों सहित न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है, वहीं परामर्शदायी भूमिका में यह प्रेस और सरकारी अधिकारियों को प्रेस की आजादी और उसके संरक्षण से जुड़े मसलों पर मार्गनिर्देश भी देती है।

प्रेस परिषद का मुखिया चेयरमैन कहलाता है जो परंपरा से सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान/सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। इसके 28 अन्य सदस्यों में 20 प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं और 5 संसद से आते हैं और 3 सदस्य सांस्कृतिक, साहित्यिक और विधि के क्षेत्र से होते हैं जिन्हें क्रमश: साहित्य अकादमी, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय बार काउंसिल द्वारा नामित किया जाता है।

परिषद का वित्त पोषण पंजीकृत समाचार पत्रों पर उनकी प्रसार संख्या के अनुसार शुल्क भी वसूला जाता है, धनराशि की कमी केन्द्र सरकार के अनुदान से पूरी की जाती है हालांकि काफी हद तक परिषद वित्तीय रूप से सरकार पर आश्रित है, फिर भी अपने काम में इसने कभी भी किसी बाहरी प्रभाव को हावी नहीं होने दिया है।

परिषद के अर्ध न्यायिक कार्य प्रेस परिषद अधिनियम की धारा 14 और 15 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों और प्रक्रियाओं के अनुसार किए जाते हैं और परामर्शदायी एवं मार्ग निर्देशन कार्य धारा 13 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत किए जाते हैं।

# पत्र सूचना कार्यालय

पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार की उन प्रमुख एजेंसियों में से एक है जिनका कार्य नीतियों, कार्यक्रमों और विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसके आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, भोपाल, चंडीगढ़, गुवाहाटी, लखनऊ और हैदराबाद में स्थित हैं। इसके 27 शाखा कार्यालय, 5 कार्यालय-सह-सूचना केंद्र और दो सूचना केंद्र हैं जो देश भर में फैले हुए हैं। इन स्थानों से अनेक पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं और नित्य प्रति बड़ी संख्या में पत्रकार वहां आते हैं। मंत्रियों/सचिवों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भारत सरकार की नीतियों की जानकारी देने के लिए प्रेस कांफ्रेस आयोजित करते हैं।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान समाचार जगत में दो बड़े घटनाक्रम हुए हैं, – प्रथम, इंटरनेट का बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार और दूसरे–चौबीसों घंटे चलने वाले न्यूज चैनलों का अभ्युदय। इन दोनों के कारण संचार की गति बहुत तेज हो गई है, राष्ट्रों की सीमाएं महत्वहीन हो रही हैं और समाचार संग्रह तथा वितरण में बहुत तेजी और त्वरित महत्व आ गया है। इन हालात में जहां परंपरागत मीडिया–खासतौर से प्रिंट मीडिया का महत्व बना हुआ है, वहीं अब पत्र सूचना कार्यालय को नए माध्यमों की जरूरतें पूरी करने के लिए भी काम करना है। नए उभरते साधनों का इस्तेमाल करते हुए अब उसे पूरी जनसंख्या तक पहुंचना है।

चूंकि आजकल इंटरनेट के जरिए सूचनाएं जल्दी मिल जाती हैं और उनमें पारदर्शिता रहती है अत: इस कार्यालय के पुराने साधनों को आधुनिक और आज के मीडिया की जरूरतों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। इसलिए पत्र सूचना कार्यालय को आज के ग्राहकों को तुरन्त और रोचक तरीके से सूचना पेश करने के लिए नई गतिविधियां शुरू करनी होंगी।

पत्र सूचना कार्यालय अखबारों और अन्य मीडिया से मिलने वाली प्रतिक्रिया विभिन्न सरकारी विभागों को उपलब्ध कराता है ताकि वे उसके अनुकूल कदम उठा सकें और अपने प्रयासों को नई दिशा दे सकें।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2012–13 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों/स्कीमों/परियोजनाओं को चलाने का प्रस्ताव है :

**1. नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केंद्र की स्थापना :** राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को कान्फ्रेंस हाल, प्रेस लांज, ब्रीफिंग/कान्फ्रेंस रूम, लाइब्रेरी तथा अन्य आधुनिक उपकरणों सहित अति आधुनिक सुविधा एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए ब्यूरो नई दिल्ली में अलग इमारत में एक राष्ट्रीय प्रेस केंद्र स्थापित कर रहा है।

परियोजना के आकार और लागत में वृद्धि के कारण इस परियोजना की लागत 35 करोड़ रुपये से बढ़कर 60 करोड़ रुपये हो चुकी है। जिसे ईएफसी ने 15 सितंबर 2009 को अनुमोदित कर दिया है। एनबीसीसी के साथ पुराने के स्थान पर नए समझौते पर 22 मार्च 2010 को हस्ताक्षर किए गए। मार्च 2006 तथा मार्च 2010 में एनबीसीसी को क्रमश 7 करोड़ तथा 4 करोड़ रुपये अदा किए गए। 2010–11 के बजट अनुमान में 10 करोड़ रुपये आबंटित किए गए जिन्हें खर्च कर लिया गया। दिसंबर 2011 तक एनबीसीसी को 18 करोड़ रुपये का भुगतान तीन किस्तों में क्रमश: 8, 6 और 4 करोड़ रूपये किया गया है। कार्य अगस्त 2012 तक पूर्ण हो जाएगा। चौथी मंजिल तक कार्य पूरा हो चुका है। बजट अनुमान 2011–12 में 20.50 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। स्कीम के लिए आर ई स्तर पर 9.5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशी का प्रस्ताव है जो वितीय वर्ष 2011–12 के लिए कुल 30.00 करोड़ रुपये हो जाएगी। यह स्कीम 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए चालू रखने का प्रस्ताव है और 2012–13 के लिए 9.00 करोड़ रुपये आबंटित किए जा चुके हैं। अगले वित्तीय वर्ष के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है जिनमें से बजट अनुमान 2011–12 के लिए 20.50 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

**2. मीडिया आउटरीच कार्यक्रम और विशेष आयोजनों के लिए प्रचार :** यह स्कीम 11वीं पंचवर्षीय योजना की दो पहली स्कीमों का मिलन है, जिसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित तीन भागों के साथ नई स्कीम के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है।

**( क ) मीडिया आउटरीच कार्यक्रम :** इस स्कीम का उद्देश्य जन सूचना अभियानों, मीडिया से बातचीत, सफलता की कहानियों तथा प्रेस दौरे आयोजित कर सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में सूचना देना है। 11वीं योजना के दौरान 49.00 करोड़ रुपये का प्रशासनिक अनुमोदन 16.11.2007 को प्राप्त हुआ था। 2011–12 की अवधि में 136 पीआईसी के लिए 14.50 करोड़ रुपये आबंटित किए गए। दिसंबर 2011 तक 89 पीआईसी, 89 सफलता की कहानियों पर 6.6573 करोड़ रुपये व्यय किए गए। बी ई स्तर पर आर ई 2011–12 को बनाए रखा गया। अप्रैल 2012 से 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हो रही है और नई योजना स्कीम के रूप में इसे शामिल करने का प्रस्ताव है। मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में परियोजना प्रबंधन इकाई को शामिल कर इसे विस्तार देने का प्रस्ताव है। वर्ष 2012–13 के दौरान इस स्कीम के लिए 11.90 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। जिसमें 136 पीआईसी, स्थानीय नेतृत्व के साथ 5 इंटरेक्टिव सेशन/सेमिनार, 10 प्रेस दौरे आयोजित करने का प्रस्ताव है। मानव संसाधन और परिवहन पर भी फंड का इस्तेमाल होगा। वार्षिक योजना 2012–13 में 11.90 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

**ख. भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह :** फिल्म समारोह स्थल पर मीडिया केंद्र की स्थापना तथा पत्रकारों को विशेष मान्यता, स्वागत व्यवस्थाएं, प्रेस कान्फ्रेंस, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन, समाचारपत्र, स्टेशनरी, फोटो कॉपियर इत्यादि सुविधाओं वाले प्रेस विज्ञप्ति वर्क रूम जैसी सुविधाओं का विस्तार। वर्ष 2011-12 के लिए इस कार्यालय को गोवा में फिल्म समारोह हेतु 8.00 लाख रुपये आबंटित हुए। यह समारोह 23 नवंबर से-3 दिसंबर 2011 में आयोजित हुआ। 2012 में आईएफएफआई के लिए वार्षिक योजना 2012-13 के लिए प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार 9 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं।

**ग. प्रवासी भारतीय दिवस समारोह :** पत्र सूचना कार्यालय प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के दौरान मीडिया की सुविधा के लिए अपने अधिकारी नियुक्त करता है जो मौके पर ही पत्रकारों की सुविधा और मीडिया केंद्र में कंप्यूटर उपलब्ध कराते हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान 1.25 लाख रुपये आवंटित किए गए थे। 7 से 9 जनवरी 2012 में जयपुर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। इस भाग को 12वीं पंचवर्षीय योजना में योजना स्कीम के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है। जनवरी 2013 में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस के लिए 1.00 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं।

**3. पीआईबी का आधुनिकीकरण :** इसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करना प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य संचार और सूचना निस्तारण प्रणाली को आधुनिक बनाना है ताकि पीआईबी आधुनिक प्रौद्योगिकी को पूरी तरह इस्तेमाल कर मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य क्षमता में बड़ा परिवर्तन ला सके। इसके लिए, इस स्कीम के तहत निम्नलिखित भाग होंगे-

**( क ) संचार और सूचना प्रचार प्रणाली का आधुनिकीकरण :** 2012-13 के दौरान इस स्कीम के लिए 2.50 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। उद्देश्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर सूचना प्रचार करना है और लक्षित समूह से फीडबैक प्राप्त करना है। विज्ञापन, मीडिया सुविधा और प्रत्यायन पर एमरजेंसी प्रतिक्रिया सहयोग प्रदान करना है।

**( ख ) एमरजेंसी के लिए 24x7 नियंत्रण कक्ष :** एमरजेंसी में यह फीडबैक और प्रतिक्रिया प्रणाली है। भारत सरकार के मंत्रियों/अधिकारियों को फीडबैक होने के लिए समाचार चैनलों की 24 घंटे निगरानी होनी चाहिए ताकि सही समय में विकासशील मुद्दों/समाचार कहानियों पर प्रतिक्रिया तैयार कर सकें। इसके तहत दो भाग हैं -

(i) मुख्यालय में समाचार चैनलों 24x7 निगरानी

(ii) एजेंजी टिकर्स की 24x7 निगरानी

# प्रकाशन विभाग

1.1 प्रकाशन विभाग सार्वजनिक क्षेत्र में देश के सबसे बड़े प्रकाशन घरों में से एक है। हिंदी, अंग्रेजी और अन्य प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रकाशन विभाग द्वारा निकलने वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि उनके माध्यम से इस देश के लोगों की समझ का विकास हो सके। इन प्रकाशनों का लक्ष्य है इस देश के जीवन और संस्कृति के रंग-बिरंगे रूपों पर तथा पंचवर्षीय योजनाओं समेत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में दर्ज की गई प्रगति पर सूचना को सम्प्रेषित करना। इस विभाग के महत्वपूर्ण प्रकाशनों में महात्मा गांधी के कार्यों के संग्रह पर गौरवशाली श्रृंखलाएं, राष्ट्रीय नेताओं के भाषण, राष्ट्रीय महत्व के विषयों तथा बाल साहित्य पर शिक्षाप्रद और जानकारी देने वाली किताबें और रोजगार समाचार शामिल हैं।

1.2 प्रकाशन विभाग का कार्य है देश और विदेश में आम लोगों को भारत के बारे में अद्यतन और सही जानकारी देने के लिए आंतरिक और बाहरी प्रचार के लिए राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर लोकप्रिय पुस्तकों, पत्रिकाओं का उत्पादन, उनकी बिक्री और उनका वितरण करना। ऐसा करते हुए प्रकाशन विभाग निम्ननिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने

का लक्ष्य बनाना है :-

(i) राष्ट्रीय महत्व के उन विषयों पर पुस्तकों को प्रकाशित करना जिन विषयों पर अन्य प्रकाशकों ने ध्यान नहीं दिया हो और ऐसी पुस्तकों को कम कीमत पर आम जनता के लिए उपलब्ध बनाना।

(ii) विविधता में एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय अखंडता इत्यादि की विचारधारा और आत्मा को मजबूत करना और उसको बढ़ावा देना।

वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान प्रकाशित पुस्तकों की सूची नीचे दी गई है -

**अनुलग्नक I**

**अप्रैल 2010 से मार्च 2011 तक प्रकाशित पुस्तकों की सूची :**

**भाषा : अंग्रेजी**

| क्र.सं. | पुस्तक का नाम |
|---|---|
| 1. | बाबू जगजीवन राम (बीएमआई) |
| 2. | जमशेदजी टाटा (बीएमआई) |
| 3. | राजेंद्र प्रसाद (बीएमआई) |
| 4. | चिल्ड्रेंस रामायण (पुनर्मु.) |
| 5. | इंडिया 2010 (पुनर्मु.) |
| 6. | सी. एन. अन्नादुरई (बीएमआई) |
| 7. | प्राइम मिनिस्टर डा. मनमोहन सिंह: सलेक्टेड स्पीचेज (खं. v) डीलक्स |
| 8. | भूला भाई देसाई (बीएमआई) |
| 9. | के कामराज (बीएमआई)(पुनर्मु.) |
| 10. | मुहम्मद कुली कुतुब शाह-द फाउंडर आफ हैदराबाद (पुनर्मु.) |
| 11. | लाजपत राय-लाइफ एंड वकर्स (बीएमआई) (पुनर्मु.) |
| 12. | प्रेसीडेंट-एपीजे अब्दुल कलाम-सलेक्टड स्पीचेज (खंड-ii) डीलक्स |
| 13. | मास मीडिया इन इंडिया-2009 |

14. मौलाना जलालुद्दीन रूमी

15. इंडिया इन द स्पेस ऐज (पुनर्मु.)

16. इंडिया-2011 (पुनर्मु.)

17. एन्युअल रिपोर्ट 2010-11 (सू और प्र मं.)

18. आउटकम बज़ट: 2011-12

19. सी. एन. अन्नादुरई (बीएमआई) (पुनर्मु.)

20. के कामराज (बीएमआई) (पुनर्मु.)

21. टेंपल्स आफ इंडिया (पुनर्मु.)

22. ए ब्रीफ हिस्ट्री आफ वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया

23. चितरंजन दास (बीएमआई)

24. राजगुरु द इनविंसिब्ल रिवॉल्युशनरी

25. रबींद्र नाथ टेगोर (बीएमआई)

26. द गीत गोविंद (पुनर्मु.) डीलक्स

**हिंदी**

1. लोक जीवन के सदाबहार पत्र

2. पहेलियां

3. हमारा भारत

4. संयुक्त राष्ट्र बच्चों के लिए

5. मेरे अधिकारों की पहली किताब

6. सूचना भारती

7. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और उपभोक्ता के अधिकार (पुनर्मु.)

8. चार्ल्स डार्विन

9. भारतीय हॉकी तथा राष्ट्रमंडल खेल

10. सलेक्टेड स्पीचेज आफ पीएम मनमोहन सिंह (खंड-V) 2008-09 (डीलक्स)

11. भारतीय भोजन की परंपरा और विविधता

12. एक महात्मा का अभ्युदय

13. ठक्कर बापा (बीएमआई) (पुनर्मु.)

14. प्रकाश भारती खंड-XIII

15. भारत-2011

16. केटलॉग-2011 (द्विभाषी)

17. हमारा राष्ट्रीय चिह्न (पुनर्मु.)

18. ए थॉट फार द डे (पुनर्मु.)

19. ग्राम विकास और स्वदेशी संसाधन

20. सरदार पटेल की अनमोल वाणी (पुनर्मु.)

21. सुब्रह्मण्य भारती (पुनर्मु.)

22. खुदी राम बोस

23. भारतीयों की समुद्री यात्राएं

24. आधुनिक हिंदी साहित्य के कीर्ति स्तंभ

25. मूर्ति का रहस्य (पुनर्मु.)

26. जंतु व्यवहार

27. जब्तशुदा गीत (पुनर्मु.)

28. भारत की लोककथाएं (पुनर्मु.)

29. लोह पुरुष सरदार पटेल (पुनर्मु.)

30. भीगा चंद्रमा

31. कार्बन कापियों की करामात (पुनर्मु.)

32. देशभक्ति के नाटक (पुनर्मु.)

33. बोद्ध धर्म के 2500 वर्ष (पुनर्मु.)

34. स्वराज्य के मंत्रदाता तिलक (पुनर्मु.)

35. भारत के महान शिक्षा शास्त्री (पुनर्मु.)

36. विज्ञान में महानता की ओर (पुनर्मु.)

37. रहमत चाचा का घोड़ा

38. रबींद्र नाथ ठाकुर (पुनर्मु.) (बीएमआई)

39. हम भारत के लोग

40. रेडियो समाचार

41. पंपू और पुनपुन

42. हिमालय स्मृति, स्वप्न और सच

43. पंजाब के प्रांगण में

44. राष्ट्रीय एकता में कवियों का योगदान (पॉप.)

45. वाणी आकाशवाणी

46. एन्युअल रिपोर्ट 2010-11 (सू. और प्र.मं.)

47. भारत-2011 (पुनर्मु.)

48. आउटकम बजट 2011-12 (सू. और प्र.मं.)

49. राष्ट्रीय एकता में कवियों का योगदान (डीलक्स)

**क्षेत्रीय भाषाएं**

1. आल आर इक्वल इन द आईज ऑफ गॉड (उर्दू)

2. जातक कथाएं (तमिल)

3. सी. राजगोपालचारी (बीएमआई) (पुनर्मु.) (तमिल)

4. नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया (पुनर्मु.) तमिल

5. डा. एस. राधा कृष्णनन (पुनर्मु.) तमिल

6. अवर नेशनल प्लेग (पुनर्मु.) तमिल

7. विष्णुपुरेर टेराकोटा मंदिर (बांग्ला)

8. साइंस : नेचरस कॉपीकेट (तेलुगु)

9. गुरुनानक से गुरुग्रंथ साहिब तक (गुजराती)

10. सी. राजगोपालचारी (बीएमआई) (तमिल) (पुनर्मु.)

11. जातक कथाएं (तमिल) (पुनर्मु.)

12. अवर नेशनल फ्लेग (पुनर्मु.) (तमिल)

13. नेशनल पार्क्स आफ इंडिया (पुनर्मु.) (तमिल)

14. डा. एस. राधाकृष्णन (मुनर्मु.) (तमिल)

**कुल पुस्तकें**

| | |
|---|---|
| **अंग्रेजी** | **30** |
| **हिंदी** | **49** |
| **क्षेत्रीय भाषाएं** | **14** |
| **कुल** | **93** |

**अंग्रेजी**

1. इंडिया–2011 (पुनर्मु.)

2. वंडरफुल मेरीन वर्ल्ड

3. बिहारी सतसई (डीलक्स)

4. अवर स्काउट एंड गाइड

5. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन (डीलक्स)

6. नाना साहब पेशवा

7. तात्या टोपे

8. ट्री – द इनसाइड स्टोरी5.

**हिंदी**

1. भारत 2011 (पुनर्मु.)

2. बाल नाटक

3. नेताजी संपूर्ण वाङ्मय (खंड 12)

4. लोक कलाएं और सामाजिक संवाद

5. छत्रपति शिवाजी (पुनर्मु.)

6. भारत के बोद्ध तीर्थ स्थल (पुनर्मु.)

7. भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड

8. खेल है विज्ञान

9. मनके : भाव, सुर, लयके

10. दक्षिण भारत के मंदिर (पुनर्मु.)

11. क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले (पुनर्मु.)

12. आओ सुनें कहानी

13. पूर्वोत्तर भारत के नारी रत्न (पुनर्मु.)

14. सुंदर लोक कथाएं

15. नेल्सन मंडेला

16. भारतीय मुस्लिम त्योहार और रीति रिवाज

17. गांधी : जीवन और दर्शन (डीलक्स)

18. गांधी : जीवन और दर्शन (पॉप.)

19. भारतीय लोक साहित्य : परंपरा और परिदृश्य

20. भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड – 2010

**भाषा : क्षेत्रीय भाषाएं**

1. अध्धी चुंज वाली चिरी (पंजाबी)

2. युगपुरुष सरदार स्वर्ण सिंह (पंजाबी)

3. वीर कुंवर सिंह (बांग्ला)

4. डायबिटीज दे नाल जीन दी कला (पंजाबी)

5. अजेय क्रांतिकारक राजगुरु (मराठी)

**अप्रैल 2011 से दिसंबर 2012 तक प्रकाशित पुस्तकों की संख्या**

| | |
|---|---|
| **अंग्रेजी** | **8** |
| **हिंदी** | **20** |
| **क्षेत्रीय भाषाएं** | **5** |
| **कुल** | **33** |

# भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक

भारत के समाचार पत्र पंजीयक का कार्यालय की स्थापना पहली जुलाई 1956 को प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम 1867 में संशोधन करके की गई थी। यह कार्यालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करता है। अधिनियम के अन्तर्गत कुछ विधि विहित कार्य इस प्रकार हैं :

(1) देश भर में प्रकाशित समाचार पत्रों/पत्रिकाओं का एक रजिस्टर तैयार करना उसका रख-रखाव करना तथा उसमें समाचार पत्रों/पत्रिकाओं का विवरण संकलित करना।

(2) संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई सिफारिश के बाद समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के शीर्षक की उपलब्धता की जांच के बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना।

(3) समाचार पत्रों के प्रकाशकों द्वारा प्रेस एवं पुस्तक पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के प्रकाशन की जानकारी सुनिश्चित करना।

(4) प्रकाशकों द्वारा समाचार पत्रों की प्रसार संख्या के दावों की जांच करना।

(5) भारत में प्रेस के बारे में उपलब्ध समस्त सूचनाओं, आंकड़ों और विशेष तौर पर विभिन्न श्रेणियों के समाचार पत्रों-पत्रिकाओं के आए बदलावों पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

इसके अतिरिक्त कार्यालय के सामान्य कार्य इस प्रकार हैं :

(क) अखबारी कागज आंबटन के लिए समाचार पत्रों को योग्यता प्रमाणपत्र जारी करना ताकि वह अखबारी कागज का आयात कर सकें।

(ख) समाचार प्रतिष्ठानों की प्रिंटिंग मशीनें (मुद्रण) और अन्य संबंधित सामग्री आयात करने की आवश्यक जरूरतों का मूल्यांकन ओर प्रमाणपत्र जारी करना।

# गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग

गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों को शोध के संबंध में एकत्रित, संकलित और तैयार सामग्री के प्रकाशन कार्य आदि में सहायता करता है। मीडिया इकाइयों के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी का सारांश निर्मित करना और सामयिक एवं अन्य विषयों पर मार्गदर्शन एवं पृष्ठभूमि नोट तैयार करना भी इस प्रभाग का दायित्व है। यह प्रभाग जनसंचार क्षेत्र की प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हुए जनसंचार की संदर्भ एवं प्रलेखन सेवा को कायम रखता है।

यह प्रभाग वर्ष के दौरान दो वार्षिक संदर्भ ग्रंथ तैयार करता है, *इंडिया* - संदर्भ वार्षिकी, यह केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य/संघ-शासित क्षेत्रों तथा पीएसयू/स्वायत्त निकायों द्वारा किए गए विकास और उन्नति कार्यों का संकलन है। भारत में मास मीडिया *(मास मीडिया इन इंडिया)* यह भारत के जनसंचार पर एक विस्तृत प्रकाशन है। साथ ही इंडिया को हिंदी में *भारत* शीर्षक से प्रकाशित किया जाता है।

यह प्रभाग नियमित रूप से हर पखवाड़े 'डायरी ऑफ इवेंट्स' निकालता है जो अभिलेख और संदर्भ के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित स्रोत होता है। यह प्रभाग विषय विशेष पर आधारित पत्रिकाओं की मासिक रिपोर्ट भी तैयार करता है। इन पत्रिकाओं में एफडीआई की हिस्सेदारी होती है और ये विषय विशेष से संबंधित होती हैं जिसके लिए इन्हें भारत में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाती है। इन पत्रिकाओं का अनुवीक्षण यह देखने के लिए किया जाता है कि ये सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन कर रही हैं अथवा नहीं।

## संदर्भ पुस्तकालय

इस प्रभाग का पुस्तकालय विभिन्न विषयों पर दस्तावेजों के बड़े संग्रह, चुनी हुई पत्रिकाओं के सजिल्द ग्रंथों तथा मंत्रालय की विभिन्न रिपोर्टों से सुसज्जित है। इसके संग्रह में पत्रकारिता, जनसंपर्क, विज्ञापन एवं दृश्य-श्रव्य प्रचार माध्यम, प्रमुख विश्वकोष, सम-सामयिक लेख और वार्षिकी शामिल हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त पुस्तकालय की सुविधाएं मान्यता प्राप्त भारतीय एवं विदेशी पत्रकारों के लिए भी उपलब्ध हैं। जगह की कमी के चलते वर्ष 2011-2012 के दौरान (दिसंबर 2011 तक) केवल 7 नई किताबें ही शामिल की जा सकीं। 2008 में लाइब्रेरी को सूचना भवन में स्थानांतरित किया गया।

## राष्ट्रीय जनसंचार प्रलेखन केन्द्र

राष्ट्रीय जनसंचार प्रलेखन केन्द्र (एनडीसीएमसी) का गठन 1976 में मंत्रालय की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया। इसकी सावधिक सेवाओं के माध्यम से जन संचार माध्यम की प्रवृत्तियों और उनसे जुड़ी घटनाओं की जानकारी एकत्र कर उनकी व्याख्या करना इसका मुख्य दायित्व है। एनडीसीएमसी जनसंपर्क/संचार पर उपलब्ध बड़े समाचारों, लेखों तथा सूचनाओं का प्रलेखन करता है। यह पूरे देश में जनसंचार के विकास के लिए ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रवाह में शामिल होने के लिए सूचना के संग्रहण और प्रलेखन से लेकर इसके प्रचार-प्रसार तक समसामयिक गतिविधियों का केंद्रीय क्षेत्र है।

एकत्रित सूचना को विभिन्न सेवाओं के द्वारा अनुरक्षित एवं प्रचारित किया जाता है जैसे - *करंट अवेयरनेस सर्विस* - केंद्र द्वारा खरीदे जा रहे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में मास मीडिया पर चुनिंदा लेखों की प्रकाशित सूची, *बिब्लियोग्राफी सर्विस* - केंद्र द्वारा खरीदे जा रहे समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में पिछले एक वर्ष के दौरान प्रकाशित मास मीडिया पर लेखों की विषय सूची, *बुलेटिन ऑन फिल्म्* - भारत के फिल्म उद्योग के विकास का एक सारांश, *रिफरेस इनफोरमेशन सर्विस* - मास मीडिया क्षेत्र के प्रासंगिक हितों के विषयों पर पृष्ठभूमि दस्तावेज, - *हूज हू इन मास मीडिया*-लोक प्रसिद्ध विभिन्न मीडिया व्यक्तियों की जीवनियां, जनसंचार में कौन क्या है, *जनसंचारकों को दिए गए पुरस्कार* - वर्ष के दौरान जनसंचारकों को दिए गए पुरस्कारों के साथ-साथ घोषित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की झलकियां और *मीडिया अपडेट* - यह प्रलेख और संदर्भ के लिए बड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को केंद्रित करती है।

राष्ट्रीय जनसंचार प्रलेखन केंद्र *मास मीडिया इन इंडिया* नामक एक संदर्भ पुस्तक का संकलन एवं संपादन भी करता है। इस वार्षिकी में केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मीडिया संगठनों की स्थिति पर सूचना और मास मीडिया के कई पहलुओं पर लेखों को शामिल किया जाता है। इसमें प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आम सूचना को भी शामिल किया जाता है। गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग के अधीन राष्ट्रीय जनसंचार प्रलेखन केंद्र ने वर्ष 2011-12 के दौरान (दिसंबर 2011 तक) मास मीडिया इन इंडिया का 23 वां संस्करण जारी।

### वर्ष 2011-12 की झलकियां

- इंडिया-2012 का 56 वां संस्करण सफलतापूर्वक निकाला।
- मास मीडिया इन इंडिया-23वां संस्करण।
- गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग की एक इकाई राष्ट्रीय जनसंचार प्रलेखन केंद्र ने वर्ष 2011-12 के दौरान (दिसंबर 2011 तक) मास मीडिया के विभिन्न पहलुओं पर 43 सेवाएं जारी कीं।

# गीत एवं नाटक प्रभाग

## परिचय

प्रभाग की स्थापना 1954 में संचार माध्यम के रूप में पारंपरिक कलाओं और विलुप्त हो चुकी लोक कलाओं को फिर से पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से एक छोटी प्रयोगात्मक इकाई के रूप में की गई थी। प्रभाग ने कलाओं के माध्यम से समकालिक विचारों, मुद्दों और तरीकों को अपनाकर लोगों के साथ तात्कालिक तादात्म्य स्थापित किया जिससे लोगों के बीच में एक जीवन्त माध्यम के रूप में लोकप्रियता हासिल की है। प्रभाग ने दुर्गम पहाड़ी इलाकों, रेगिस्तान और सीमावर्ती क्षेत्रों में निचले स्तर पर लोगों के साथ प्रभावी ढंग से सम्पर्क स्थापित करके अपनी पहुंच और प्रभाव के क्षेत्र में बहुत विस्तार किया है।

## उद्देश्य

प्रभाग के कार्यों के बारे में इसकी वेबसाइट में विस्तार से बताया गया है। इसके मुख्य कार्यों में देश की प्रगति के अनुकूल सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक विचारों को आम जनता में जागरूकता और भावनात्मक स्वीकार्यता पैदा करना है। यह सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों के मन में रक्षा की तैयारियों और देश के बाकी हिस्सों से सांस्कृतिक एकजुटता को लेकर विश्वास पैदा करने के लिए काम करता है। इसके कामकाज में सीमा के अलग थलग इलाकों में तैनात सैनिकों के मनोबल को बनाए रखना भी शामिल है। यह अपना काम मनोरंजन के जीवंत साधनों के जरिए करता है जिनमें देश के सभी क्षेत्रों की शहरी नाट्य विधाएं और लोक विधाएं भी शामिल हैं। समाज की संपूर्ण भलाई के लिए विकास, नीतियों, कार्यक्रमों तथा स्कीमों के प्रति जन जागरूकता पैदा करना भी है। एल डब्लू ई क्षेत्रों, सीमावर्ती क्षेत्रों, जम्मू और कश्मीर, पंजाब तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष प्रचार का जिम्मा लिया है।

अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रभाग नाटक, नृत्य नाटिका, ओपेरा, वाचन और कठपुतली जैसी विभिन्न लोक और पारंपरिक विधाओं का सहारा लेता है। यह प्राचीन परंपरा वाले सैकड़ों जादुगरों की सेवाएं भी लेता है। इसके अलावा यह ध्वनि और प्रकाश की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए साम्प्रदायिक सदभाव, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य, पर्यावरण और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कार्यक्रम करता है जिनमें सैकड़ों कलाकारों की सेवाएं ली जाती हैं।

इस तरह प्रभाग देश के विभिन्न हिस्सों की अनगिनत लोक और पारंपिक विधाओं को पुनर्जीवित करने और उनहें बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। साथ ही वह हजारों कलाकारों की कलाओं का सोद्देश्य संवाद के लिए उनकी भाषाओं, मुहावरों और बोलियों में इस्तेमाल कर उन्हें आजीविका भी मुहैया करता है।

(i) प्रभाग का मुख्यालय दिल्ली में है और इसका प्रमुख एक निदेशक होता है। (ii) इसके 10 क्षेत्रीय केन्द्र बंगलूरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, पुणे और रांची में हैं। (iii) दरभंगा, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, इंफाल, नैनीताल और शिमला में इसके सात सीमा केन्द्र हैं जिनका अधयक्ष सहायक निदेशक होता है। प्रभाग के छह विभागीय नाटय दल भुवनेश्वर, दिल्ली, हैदराबाद, पटना, पुणे और श्रीनगर में हैं।

प्रभाग की विभिन्न फील्ड यूनिट प्रचार केंद्रित कार्यक्रम तैयार करने, प्रस्तुत करने और उनकी निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा सशस्त्र बल मनोरंजन शाखा योजना के तहत कलाकारों के नौ दल (आठ दल दिल्ली में और एक चेन्नई में) हैं। इन नौ दलों की जिम्मेदारी सीमा के सुदूर और अलग-थलग इलाकों में सशस्त्र बलों का मनोरंजन करना है।

# मुख्य सचिवालय की सूचना विंग स्कीमें

## सूचना भवन का निर्माण

सूचना भवन के निर्माण पर होने वाला व्यय योजना आयोग की मंजूरी के पश्चात इस मंत्रालय को उपलब्ध कराए गए योजना बजट से पूरा किया जाता है। अब तक उपलब्ध निर्मित स्थान विभिन्न मीडिया इकाइयों को आवंटित किया गया है, जैसे सिविल कंस्ट्रक्शन विंग, गीत एवं नाटक प्रभाग, फोटो प्रभाग, प्रकाशन विभाग, गवेषणा संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग, भारतीय प्रेस परिषद, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (अंशत:) और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। सूचना भवन के चरण V के पूरा होने पर उपलब्ध निर्मित स्थल का आबंटन बाकी मीडिया इकाइयों जैसे डीएफपी, आरएनआई आदि को किया जाएगा और यदि फिर भी स्थल बचता है तो उसे अन्य विभागों को किराए पर उपलब्ध कराया जाएगा।

## उत्तर पूर्व और जम्मू तथा कश्मीर के तथा अन्य चिह्नित क्षेत्रों में विकास सहयोग

इस स्कीम के दो हिस्से हैं - (क) ढांचागत विकास सहयोग तथा (ख) पीआईबी, डीएवीपी, डीएफपी तथा एस एंड डीडी के सामान्य कार्यक्रमों का संवर्धन जिनके लिए क्रमश: 15 तथा 10 करोड़ रुपये का व्यय।

(क) ढांचागत विकास सहयोग उत्तर पूर्व और जम्मू तथा कश्मीर, सीमा और एलडब्ल्यू प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपकरणों के लिए फंड तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाईयों को वित्तीय सहायता के रूप में तथा केंद्रीय सूचना सदनों, प्रेस केंद्रों, राज्य सूचना विभागों के आधुनिकीकरण के रूप में प्रदान किया जाएगा। इसके लिए कुल 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ख) पीआईबी, डीएवीपी, ईएफपी तथा एस एंड डीडी के सामान्य कार्यक्रमों के संवर्धन पर 2012-13 के लिए निम्न प्रकार से व्यय किया जाएगा -

| | |
|---|---|
| पीआईबी | 1.0 करोड़ रुपये |
| डीएफपी | 2.0 करोड़ रुपये |
| एस एंड डीडी | 2.0 करोड़ रुपये |
| डीएवीपी | 5.0 करोड़ रुपये |
| **कुल** | **10.00 करोड़ रुपये** |

# अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम

सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों/मीडिया आदान प्रदान कार्यक्रमों के उद्देश्य भारत और अन्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाना और मास मीडिया, प्रसारण तथा फिल्मों के क्षेत्र में विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। देश के पत्रकारों, मासमीडिया विशेषज्ञों के आपसी आदान-प्रदान के साथ-साथ विशेष कार्यक्रमों के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं -

- देशों के बीच बेहतर समझ बढ़ाने में जो भूमिका मीडिया निभाता है उसे पहचानना और मीडिया के लोगों के बीच प्रभावी बातचीत के जरिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने में और एक दूसरे के बारे में सूचना प्रसार के लिए मीडिया को महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना।
- मीडिया की उस महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना जिसे मीडिया लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक समझ विकसित करने में निभाता है।
- इस स्कीम का एक बड़ा उद्देश्य सूचना और प्रिंट मीडिया के क्षेत्रों में बेहतर समझ को बढ़ावा देकर विभिन्न देशों के साथ दोस्ताना संबंधों को मजबूत बनाना है। सूचना और मास मीडिया के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ नजदीकी संबंध स्थापित और विकसित करने की एक समान इच्छा से यह स्कीम प्रेरित है।
- आधुनिक मीडिया प्रशिक्षण
- संकटकालीन संचार
- सामाजिक और मल्टीमीडिया प्रशिक्षण

स्कीम के हिस्से हैं :

(क) मीडिया आदान-प्रदान कार्यक्रम

(ख) सूचना और फिल्म क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह और समझौता

(ग) अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेमिनार/कार्यशालाएं

**(क) मीडिया आदान-प्रदान कार्यक्रम**

सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम (सीईपी) भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और अन्य देशों के संस्कृति मंत्रालय के बीच समझौते पर हस्ताक्षर कर आयोजित किए जाते हैं जिनका उद्देश्य शिक्षा, कला और संस्कृति, सूचना और मास मीडिया युवा और खेलों के क्षेत्र में नजदीकी संबंध स्थापित और विकसित करना है। क्रियान्वयन की प्रक्रिया में मीडिया के लोगों का आदान-प्रदान और मीडिया के लिए महत्वपूर्ण मीडिया संस्थानों/संगठनों में मीडिया के लोगों के दौरे आयोजित करना शामिल है।

**(ख) सूचना और मास मीडिया के क्षेत्र में संयुक्त कार्यसमूह और समझौते**

ये समझौते दो देशों की सरकारों के बीच किए जाते हैं जो सूचना और मास मीडिया के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए एक उपकरण की तरह कार्य करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस तरह के समझौते कई देशों के बीच हुए हैं। यद्यपि पिछले तीन वर्षों के दौरान संयुक्त कार्य समूह के अंतर्गत ब्यूरो ने कोई समझौता नहीं किया है।

**स्कोप :** मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के पर्याप्त क्रियान्वयन और बुनियादी उद्देश्य की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम विशेष रूप से चलाया जाएगा जिसमें 5 पत्रकारों और दो अफसरों का आदान-प्रदान शामिल है जो दो वर्षों से अधिक अवधि तक नहीं होगा।

**(ग) अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेमिनार/ कार्यशालाएं**

उदारीकरण के बाद वाले दौर में ब्रिक्स, जी-20, सार्क बैठकों आदि बहुत से अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अपनी केंद्रीय भूमिका के प्रकाश में भारत की मौजूदगी और इमेज बढ़ाने की दिशा में भारत में अलग से मीडिया प्रतिनिधियों के लिए सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करने का प्रस्ताव है और विदेश में भी

इसी तरह की कार्यशालाएं सेमिनारों को आयोजित करना और उनमें शामिल होना प्रस्तावित हैं। स्कीम के प्रावधान में प्रवासी भारतीय दिवस/राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस आदि के साथ-साथ ऐसी ही सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित करना शामिल होगा। इससे संगठन के मूल्यों के संचार और उन्हें बढ़ावा देने के लिए आवश्यक पेशेवर मिलेंगे और संकटकालीन संवेदनशील मुद्दों को सुलझाने में मदद करेंगे।

**घ. नीति संबंधी अध्ययन, सेमिनार, मूल्यांकन इत्यादि (प्रसार भारती छोड़कर सभी क्षेत्र और मीडिया इकाइयां)**

12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017 के दौरान अर्थव्यवस्था के मनोरंजन और मीडिया क्षेत्र ने उच्च विकासक संभावनाएं दर्शाई हैं। विकास गति पकड़ने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्रों के संबंध में विभिन्न स्कीमें/कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं ताकि निर्धारित लक्ष्य हासिल किए जा सकें। स्कीम में मीडिया के क्षेत्र में नीति संबंधी अध्ययनों, सेमिनारों और मौजूदा नई योजना स्कीमों के मूल्यांकन का कार्य करने का प्रावधान है। अध्ययनों सेमिनारों और मूल्यांकन का कार्य नई स्कीमों की नीति निर्धारण, गठन और निगरानी में सहायता करेगा।

**ड. मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण**

सिविल सेवा की दिशा में एक रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली होनी आवश्यक है जो प्रत्येक सिविल सेवक को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखेगी जिन्हें मंत्रालय विभाग संगठन के मिशन और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उनका मूल्यांकन, प्रेरित और विकास करेगी।

1. इस परिवर्तन प्रक्रिया के भीतर, यह आवश्यक है कि उस सेवक की क्षमता और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य में मिलान आवश्यक है और प्रशिक्षण के माध्यम से वर्तमान और भविष्य की भूमिका के लिए क्षमता अंतर को पाटना आवश्यक है।

2. **सक्षमता** ज्ञान, कौशल और व्यवहार में है जिनकी पद के कार्य प्रभावी तरीके से करने के लिए एक व्यक्ति में होना आवश्यक होता है। सक्षमता मुख्यत: उन को कौशल में बांटी जा सकती है जिसकी सरकारी सेवकों को विभिन्न कार्यों अथवा स्तर के लिए विभिन्न सक्षमता स्तरों की आवश्यकता होगी। इनमें से कुछ सक्षमताएं नेतृत्व, संचार, वित्तीय तथा मानव प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, परियोजना प्रबंधन आदि से संबंधित होती है। अन्य का संबंध पेशेवर अथवा विशेषज्ञता कौशल से होता है, जो कि विशेष कार्यों जैसे कि सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं, बाढ़ नियंत्रण उपाय करना, नागरिक उड्डयन, चिकित्सीय देखभाल, मीडिया प्रबंधन आदि के लिए प्रासंगिक हैं।

3. सूचना और प्रसारण मंत्रालय सूचना, प्रसारण और फिल्म क्षेत्रों के लिए नोडल मंत्रालय हैं। अपनी विभिन्न मीडिया इकाईयों के माध्यम से मंत्रालय विभिन्न सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों संबंधी सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए उत्तरदायी है। विभिन्न मीडिया हैं - इलेक्ट्रानिक, प्रिंट, फिल्म, अंतरवैयक्तिक प्रचार, जीवंत कला और संस्कृति, जनसूचना अभियान आदि। अपने कैरियर के दौरान भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट तथा अंतर वैयक्तिक मीडिया इकाईयों में तैनात किए जाते हैं। इसी प्रकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के अधिकारी मीडिया क्षेत्र के लिए नीतियां बनाने में कार्यरत हैं और विभिन्न मीडिया इकाईयों के लिए प्रशासनिक सुविधा प्रदान करते हैं। यह आवश्यक है कि ये सभी अधिकारी प्रशिक्षित हैं और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों को लेने के लिए तैयार हैं।

# फिल्म क्षेत्र

## केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अधिदेश फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन का प्रमाणपत्र देने के उद्देश्य से सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 (1852 का 37) के नियमों और दिशा-निर्देशों के तहत की गई थी। बोर्ड का उद्देश्य सिनेमेटोग्राफ अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप जनता को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान हो यह सुनिश्चित करना है।

सीबीएफसी का प्रयास प्रमाणन प्रक्रिया को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। इस दिशा में सीबीएफसी कंपयूटरीकृत प्रमाणन प्रक्रिया के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाता है। सीबीएफसी कार्यशालाओं तथा बैठकों के माध्यम से फिल्मों में दिशा-निर्देशों तथा वर्तमान चलन के बारे में सलाहकार पैनल सदस्यों, मीडिया और फिल्म निर्माताओं के बीच भी जागरूकता पैदा करता है।

## बाल फिल्म समिति, भारत

सीएफएसआई की विभिन्न गतिविधियां निम्नलिखित हैं :

सीएफएसआई बच्चों तथा युवाओं के लिए फिल्म तथा वीडियो फॉरमेट में फीचर फिल्म, लघु फीचर फिल्म, एनीमेशन, लघु फिल्म, पपेट फिल्म तथा टीवी सीरियल बनाता है। संगठन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लोकप्रिय रही कुछ फिल्मों के प्रदर्शन अधिकार भी खरीदता है। इन फिल्मों तथा समिति द्वारा निर्मित फिल्मों की विभिन्न भारतीय भाषाओं में डबिंग कराई जाती है।

**अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह :** सीएफएसआई हर दूसरे साल प्रतियोगी बाल फिल्म समारोह का आयोजन करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल एवं युवा फिल्म केंद्र जो कि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों को नियंत्रित करने वाली यूनेस्को से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ने इसे 'ए' श्रेणी में रखा है।

**अंतर्राष्ट्रीय बाल समारोहों में भागीदारी :** सीएफएसआई की फिल्में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रदर्शित हुई हैं, इससे विदेशों में बच्चों की फिल्मों को बढ़ावा देने में मदद मिली है।

**निजी प्रदर्शन :** कई स्कूल और व्यक्ति, स्कूलों या सिनेमाहॉल में गैर व्यावसायिक प्रदर्शनों के लिए नियत शुल्क देकर इन फिल्मों को किराए पर लेते हैं।

**जिला और राज्य स्तर के समारोह :** यह गतिविधि जिला प्रशासनों के साथ मिलकर की जाती है। विभिन्न राज्यों के कुछ जिलों को चिह्नित कर वहां मामूली प्रवेश शुल्क पर फिल्में दिखाई जाती हैं। सरकारी निगम, स्कूलों या जिला परिषद के स्कूलों में जाने वाले बच्चों को ये फिल्में देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

ग्रामीण और मनोरंजन के दूसरे साधनों से वंचित बच्चों तथा अनाथ बच्चों तक पहुंचने के लिए सीएफएसआई ने सरकारी स्कूलों के बच्चों और आदिवासी बच्चों को मुफ्त फिल्में दिखाने की एक नई योजना शुरू की है। नेहरू युवा केंद्र संगठन जैसे गैर सरकारी संगठनों की इसमें मदद ली जाती है।

**वितरकों के जरिए प्रदर्शन :** सीएफएसआई, स्कूल और सिनेमाहॉलों में फिल्मों के प्रदर्शन के लिए वितरकों/आयोजकों से भी सहयोग लेती है। यह एक तय मासिक शुल्क लेकर फिल्में ले लेते हैं और आवंटित क्षेत्र में उनका प्रदर्शन करते हैं।

**एनिमेशन तथा फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं :** सीएफएसआई बच्चों को फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने के लिए फिल्म निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया तथा एनीमेशन पर कार्यशालाएं आयोजित करती है। इनमें एनिमेशन कार्यशाला, पटकथा लेखन कार्यशाला, फिल्म समालोचना कार्यशाला तथा फिल्म निर्माण कार्यशालाएं शामिल हैं।

**टेलीविजन पर फिल्मों का प्रदर्शन** : समिति की फिल्में दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क और क्षेत्रीय चैनलों के अलावा सेटेलाइट चैनलों सहित निजी चैनलों पर दिखाई जाती हैं।

**पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर में गतिविधियां :** समिति पूर्वोत्तर राज्यों सहित क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों के निर्माण पर कार्यशालाओं के आयोजन और प्रदर्शन के जरिए उन्हें प्रोत्साहन देती है।

# फिल्म समारोह निदेशालय

फिल्म समारोह निदेशालय को अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देने तथा भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों (आईएफएफआई) का आयोजन करने, देश और विदेश में भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने, फिल्म सप्ताहों का आयोजन तथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

निदेशालय भारत में और विदेशों में सर्वश्रेष्ठ भारतीय सिनेमा को प्रदर्शित करने के प्रयास भी करता है। निदेशालय द्वारा आयोजित फिल्म समारोह भारत और विदेश के एक जैसी सोच वाले पेशेवरों के लिए विचार विनिमय और अपने दृष्टिकोण और अवधारणाओं को एक-दूसरे के साथ बांटने के एक मंच के रूप में कार्य करते हैं।

मंत्रालय ने 2010 में इसे एक अंतर्राष्ट्रीय समारोह बनाने की दिशा में निरीक्षण, समीक्षा और अद्यतनीकरण के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था जिसे अपनी सिफारिशें सौंपनी थीं। समिति ने आईएफएफआई को गलोबल ब्रांड और विश्व के अग्रणी फिल्म समारोहों में से एक बनाने के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की है। प्रमुख सिफारिश आईएफएफआई को वार्षिक आधार पर आयोजित करने के लिए स्पेशल परपज व्हिकल (एसपीवी) स्थापित करने की है। इसकी स्थापना के लिए मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के तहत प्रस्तावित नई 12वीं योजना स्कीम के तहत गतिविधियां शुरू करना है।

12वीं योजना स्कीम के एक भाग के रूप में निदेशालय की गतिविधियां 'भारत और विदेशों में फिल्म समारोह के जरिए निर्यात संवर्धन' योजना के माध्यम से चलाई जाती हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) भारत और विदेशों में आयोजित फिल्म समारोहों में भारतीय पैनोरमा फिल्मों की भागीदारी

(ख) भारतीय पैनोरमा फिल्मों का चयन

फिल्म समारोहों के जरिए निर्यात संवर्धन की योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के दृष्टिकोण से निदेशालय को एक तकनीकी रूप से सुसज्जित प्रिंट यूनिट, जो प्रिंटों की लम्बी अवधि तक भंडारण में मदद करेगी, प्रदान करने के लिए एक नई योजना का भी 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान है।

इसके अलावा, सीरीफोर्ट फिल्म समारोह परिसर के रख-रखाव तथा देखभाल की जिम्मेदारी भी निदेशालय की है। परिसर में सुविधाएं/सुधार का कार्य 'फिल्म समारोह परिसर - संयोजन और बदलाव' योजना स्कीम के माध्यम से हाथ में लिया गया है।

# भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

इस संस्थान की स्थापना 1960 में फिल्म निर्माण कला और तकनीक में प्रशिक्षण के लिए की गई थी। 1974 से इसने दूरदर्शन कर्मचारियों को फिल्म निर्माण में प्रशिक्षित करने का काम शुरू किया और इसका नाम भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कर दिया गया। यह अपने ढंग का अग्रणी संस्थान है और फिल्म निर्माण एवं टेलीविजन प्रशिक्षण की पूरी जिम्मेदारी संभाले हुए है।

संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य फिल्म तथा टेलीविजन उद्योग के लिए प्रशिक्षित प्रतिभाएं प्रदान करने के लिए मुख्य उद्देश्य के साथ फिल्म तथा टेलीविजन निर्माण पर विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करना है। प्रत्येक वर्ष 424 छात्र लिए जाते हैं। संस्थान द्वारा संचालित पाठ्यक्रम नीचे दिए गए हैं:

| **क्र.सं.** | **पाठ्यक्रम** | **वर्तमान में छात्रों की संख्या** |
|---|---|---|
| **( क ).** | **फिल्म एवं टेलीविजन में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम** | |
| 1. | निर्देशन | 65 |
| 2. | सिनेमेटोग्राफी (फिल्म एवं टेलीविजन) | 65 |
| 3. | संपादन (फिल्म एवं टेलीविजन) | 61 |
| 4. | ऑडियोग्राफी (फिल्म एवं टेलीविजन) | 50 |
| **( ख ).** | **दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम** | |
| 1. | अभिनय | 61 |
| 2. | कला निर्देशन तथा निर्माण डिजाइन | 32 |
| **( ग ).** | **एमीमेशन एवं कंप्यूटर ग्राफिक्स में डेढ़ वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम** | 35 |
| **( घ ).** | **टेलीविजन में एक वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम** | |
| 1. | निर्देशन | 12 |
| 2. | इलेक्ट्रॉनिक सिनेमेटोग्राफी | 11 |
| 3. | वीडियो संपादन | 12 |
| 4. | ऑडियोग्राफी एवं टेलीविजन इंजीनियरिंग | 09 |
| (ई). | फीचर फिल्म पटकथा लेखन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम | 13 |
| | **कुल** | **424** |

**लघु पाठ्यक्रम :** एफटीआईआई कार्यरत पेशेवरों और संबंधित क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वालों के लिए विभिन्न लघु पाठ्यक्रम चलाता है।

**योजना स्कीमें :** संस्थान मुख्यत: संवर्धन और प्रशिक्षण ढांचा और प्रशिक्षण के तरीकों के आधुनिकीकरण के लिए योजना स्कीमें लागू करता है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षित पेशेवरों का आउटपुट बढ़ाना, उपलब्ध सुविधाओं को विकसित करना और राजस्व पैदा करने के विचार से यथा संभव फिल्म शूटिंग की सुविधाएं प्रदान करना। योजना स्कीम में आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ फिल्म तथा टेलीविजन शिक्षा के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने पर भी जोर रहता है।

## फिल्म प्रभाग

भारत सरकार की जरूरतों के अनुसार वृत्तचित्र, एनिमेशन तथा लघु फिल्म बनाने तथा उनके वितरण की जिम्मेदारी फिल्म प्रभाग की है। इन वृत्तचित्रों, एनिमेशन तथा लघु फिल्मों का प्रयोग जनता तक सूचना पहुंचाने, उन्हें जानकारी देने, शिक्षित करने, प्रोत्साहित करने तथा सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इस अधिदेश को हासिल करने के लिए प्रभाग विभिन्न विषयों पर वृत्तचित्र बनाता है। निजी निर्माताओं को भी प्रोत्साहित किया जाता है। वृत्तचित्र आंदोलन को बढ़ाने के लिए प्रभाग द्विवार्षिक मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित करता है। महोत्सव में विश्व के सभी निर्माता एक दूसरे के करीब आकर अपने विचार साझा करते हैं।

## भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय

विश्व भर में कलाकृतियों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के रूप में फिल्मों को संरक्षित करने की आवश्यकता महसूस की गई है। सिनेमा को उसकी सभी विविधतापूर्ण अभिव्यक्तियों और स्वरूपों के साथ संरक्षित करने का दायित्व किसी ऐसे राष्ट्रीय संगठन को दिया जाता है जिसके पास पर्याप्त संसाधन, एक स्थाई व्यवस्था और फिल्म उद्योग का आत्मविश्वास हो। जोकि फरवरी 1964 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र मीडिया इकाई के रूप में इसकी स्थापना हुई थी।

**भारत के राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय के लक्ष्य और उद्देश्य :**

(क) राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय की विरासत का पता लगाना, अर्जित करना और संरक्षित करना तथा विश्व सिनेमा का प्रतिनिधित्व संग्रह बनाना (ख) फिल्म संबंधी डाटा को वर्गीकृत और प्रायोजित करना, सिनेमा पर शोध करना और प्रोत्साहित करना एवं प्रकाशित तथा उसे वितरित करना (ग) देश में फिल्म संस्कृति के प्रसार के केंद्र तथा विदेशों में भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के केंद्र के रूप में कार्य करना।

## राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

1. भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय एजेंसी राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी) की स्थापना भारतीय फिल्म उद्योग की वृद्धि को प्रोत्साहित करने और सिनेमा में श्रेष्ठता को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है।

2. एनएफडीसी द्वारा वित्त पोषित/निर्मित फिल्मों और उनके निर्माण से संबंधित कलाकारों ने पूर्व में अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किये हैं। एनएफडीसी (पूर्ववर्ती फिल्म वित्त निगम सहित), ने अब तक करीब 300 ऐसी फिल्मों का निर्माण/सहनिर्माण/वित्तपोषण किया है। भारतीय फिल्म उद्योग ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में सिनेमा को समाविष्ट किया है और 17 से अधिक फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सह-निर्माण करने वाला निगम एक मात्र निर्माता है।

3. एनएफडीसी का लक्ष्य उत्कृष्ट फिल्मों को बढ़ावा देना और विभिन्न भारतीय भाषाओं में बनी फिल्मों द्वारा भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना है।

4. नई गतिविधियों के माध्यम से भारत के सिनेमा को बढ़ावा देने की अपनी वचनबद्धता को नया रूप देने का प्रस्ताव है।

5. विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण के लिए 12वीं योजना के दौरान 60.00 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है जोकि विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्म तथा वृत चित्र निर्माण शीर्षक स्कीम का एक हिस्सा होगा। कुल परिव्यय 142 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। 2012-13 के दौरान 17.00 करोड़ रुपये का वार्षिक परिव्यय आबंटित है। 12वीं योजना स्कीम के तहत फिल्म बाजारों में भागीदारी भाग भी क्रियान्वित होगा।

# सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

फिल्म तथा टेलीविजन कार्यक्रमों की विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित मानवशक्ति उपलब्ध कराने के मकसद से भारत सरकार ने एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान के रूप में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कोलकाता के सत्यजीत राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान की स्थापना की थी और यह प्रसारण और सूचना मंत्रालय एवं पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के तहत पंजीकृत है। कोलकाता में संस्थान की स्थापना का विशेष उद्देश्य पूर्वी तथा उत्तरपूर्वी भारत के लिए फिल्म एवं टेलीविजन निर्माण में शिक्षा प्रदान करना है। संस्थान का प्राथमिक मूल उद्देश्य छात्रों के लिए फिल्म और टेलीविजन पर विभिन्न पाठ्यक्रम चलाना है। 2010-11 तक यहां प्रति वर्ष लगभग 40 छात्र (चार विभागों में दस-दस छात्र) निकलते हैं। प्रत्येक विभाग में 3 छात्र बढ़ाए गए हैं। इस प्रकार कुल छात्र संख्या 48 हो गई है।

भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थान, निर्देशन और पटकथा लेखन, चलचित्र छायांकन, संपादन और ध्वन्यांकन में तीन साल का स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स कराता है। फिल्म तथा टेलीविजन से जुड़े अन्य क्षेत्रों में बुनियादी डिप्लोमा कोर्सों के अतिरिक्त समाजशास्त्र, संस्कृति और फिल्म तथा टेलीविजन टेक्नोलाजी के बारे में अनुसंधान और खोजी अध्ययनों पर भी यह संस्थान ध्यान देता है।

बुनियादी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अलावा संस्थान, विभिन्न संगठनों और फिल्म उद्योग की मांग पर विभिन्न अल्पावधि पाठ्यक्रम और विभिन्न परियोजनाएं हाथ में लेता है।

## योजना स्कीम

संस्थान को बढ़ते छात्रों की जरूरतों और नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार भूत ढांचा तैयार करने के विचार से विभिन्न परियोजनाएं हाथ में ली हैं। 11वीं योजना की प्रमुख पहल एनीमेशन तथा प्रोडक्शन डिजाइन के नए विभाग का सृजन है जो पूरा होने को है और 2012-13 से पाठ्यक्रम शुरू हो जाएगा। 12वीं योजना के दौरान गर्ल्स होस्टल और टीवी सेंटर जैसी अतिरिक्त सुविधाएं प्रस्तावित हैं।

# मुख्य सचिवालय की फिल्म विंग स्कीमें

## ( क ) एंटी पाइरेसी पहल ( नई स्कीम )

पाइरेसी किसी भी सृजनात्मक क्षेत्र विशेषकर फिल्म क्षेत्र में एक बड़ा खतरा है। इसलिए स्कीम का मुख्य उद्देश्य सभी हितधारकों के बीच पाइरेसी के खिलाफ जागरूकता फैलाने और इससे पार पाने के लिए शिक्षित करना है। स्कीम में उन कदमों को ही आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है जिन्हें मंत्रालय पहले ही उठा चुका है। स्कीम के तहत फिल्म, प्रसारण और संगीत उद्योग से सभी को शामिल कर मल्टी-मीडिया अभियान शुरू करने का विचार है। फिल्म और मीडिया से कई हस्तियों को अनुरोध किया जाएगा जो पाइरेटेड सामान खरीदने से मना करने का लोगों से अनुरोध करेंगे। ये अभियान दूरदर्शन/एआइआर, निजी टी वी चैनलों और निजी एफएम पर चलाए जाएंगे। कॉपीराइट अधिनियम के बारे में जागरूक करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में पुलिस,न्यायिक तथा प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। पाइरेसी से लड़ने के लिए पाइरेसी के प्रभाव पर शोध कराया जाएगा ताकि विकास के साथ साथ सार्वजनिक निजी रणनीतियों को कारगर बनाया जा सके।

## ( ख ) भारतीय सिनेमा के 100 वर्षों ( 1913-2013 ) पर आयोजन

भारत में दादा साहब फालके ने 1913 में पहली फीचर फिल्म राजा हरिशचंद्र बनाई जो 13 अप्रैल 1913 को प्रदर्शित हुई। भारत में बनने वाली यह पहली देसी फिल्म थी। इसके बाद देश भर में फिल्मों का निर्माण शुरु हो गया। ध्वनि की खोज के बाद विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्म निर्माण की बाढ सी आ गई और क्षेत्रीय, स्थानीय तथा राष्ट्रीय फ्लेवर की फिल्में बनने लगीं। समय बीतने के साथ, फिल्में न केवल मनोरंजन का स्रोत बनी हैं बल्कि आजादी के बाद लोगों और सांस्कृतिक स्वरूप तथा संवेदनशीलताओं की सामाजिक-आर्थिक अभिलाषाओं को परलिक्षित करती हैं। इस स्कीम के तहत भारत में सिनेमा के 100 वर्षों पर आयोजन करने का विचार है। इसके तहत विभिन्न गतिविधियां चलाने का प्रस्ताव है जिसमें भारतीय सिनेमा के विभिन्न पहलुओं पर गैर-फिक्शन फिल्मों का निर्माण, गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सिनेमा के 100 वर्षों पर एक झांकी का प्रदर्शन तथा एक कॉफी टेबल बुक का मुद्रण, भारतीय सिनेमा के भूले बिसरे नायकों पर टीवी सीरियल, छात्रों के लिए फिल्म क्लब की शुरुआत, स्मारक डाक टिकट जारी करना, टी-शर्ट, मग, उच्च स्तरीय थीम गीत, सबसे पुराने चालू थिएटरों पर वृत्तचित्र निर्माण, फिल्मोत्सव आदि आयोजित करना शामिल है। स्कीम को लागू करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर कार्य किया जा रहा है।

## ( ग ) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन

स्कीम के तहत प्रिजर्वेशन विदाउट एरर्स, एकसेज विदाउट एंड के लक्ष्य के साथ फिल्म विरासत के संरक्षण का प्रस्ताव है। योजना स्कीम में प्रस्तावित गतिविधियां इस प्रकार है- (क) 1500 फीचर फिल्म और 1500 लघु फिल्मों का पुनरुद्धार, (ख) 1000 फीचर फिलमों और 2000 लघु फिल्मों का डिजिटलीकरण, (ग) अभिलेखीय उद्देश्य के लिए 1500 फीचर फिल्मों तथा 1500 लघु फिल्मों के इंटर-निगेटिवों की स्ट्राइकिंग, (घ) पुनरुद्धार की गई वॉलट निर्माण, (ड़) पुनरुद्धार और संरक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन। संपूर्ण परियोजना सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सीधी देखरेख में।

## ( घ ) भारत और विदेशों में फिल्म समारोहों और फिल्म बाजारों के जरिए भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना

देश में अच्छी फिल्मों के निर्माण में मदद करने और इन फिल्मों की विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों और फिल्म बाजारों में पहुंच को बढ़ावा देने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक योजनागत स्कीम तैयार की थी। उक्त उद्देश्य के लिए विभिन्न मीडिया इकाइयों की गतिविधियों में बेहतर तालमेल, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जैसी गतिविधियों के सुचारू आयोजन, भारत और विदेशों में फिल्म बाजारों और विभिन्न फिल्म समारोहों में भागीदारी, वित्त चित्रों के लिए मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह का आयोजन तथा देश भर में बच्चों के फिल्मों के प्रर्दशन की गतिविधियों को 12वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य सचिवायल की एक ही योजना स्कीम में शामिल कर लिया गया, जिसका शीर्षक है 'भारत और विदेशों में फिल्म समारोहों और फिल्म बाजारों के जरिए भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना'।

स्कीम का क्रियान्वयन मुख्य सचिवालय की देखरेख में संयुक्त रूप से फिल्म समारोह निदेशालय, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, फिल्म प्रभाग और बाल फिल्म समिति, भारत द्वारा किया जाएगा।

| क्र. सं. | स्कीम के भाग | क्रियान्वयन एजेंसी |
|---|---|---|
| 1. | डीएफएफ के अधिकारियों की विदेश यात्रा सहित भारत तथा विदेशों में फिल्म समारोहों में भागीदारी और आयोजन, कलात्मक मूल्यों वाली फिल्मों के प्रदर्शन के लिए एनजीओ/राज्य सरकार के संगठनों तथा एफएफएसआई को अनुदान सहायता, फिल्म चेतना का प्रचार, फिल्म एप्रेसिएशन पर पत्रिका प्रकाशन तथा सेमिनार/संगोष्ठियों आदि का आयोजन | फिल्म समारोह निदेशालय |
| 2. | भारत का अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोह (आइएफएफआई) का आयोजन भारतीय पेनोरमा के अंतर्गत फिल्मों का चयन, आईएफएफआई के लिए एसपीवी की स्थापना आदि | आईएफएफ के लिए एसवीपी की स्थापना |
| 3. | भारत तथा विदेशों में फिल्म बाजारों में भागीदारी | एनएफडीसी |
| 4. | एफआईएफएफ का द्विवार्षिक आयोजन | फिल्म प्रभाग |
| 5. | द्विवार्षिक आधार पर (वैकल्पिक वर्ष में) राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोहों का आयोजन | बाल फिल्म समिति, भारत |
| 6. | देश भर के स्कूलों में बाल फिल्मों का प्रदर्शन | |

## ( ड़ ) विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों तथा वृत्तचित्रों का निर्माण

नई 12वीं योजना स्कीम विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों तथा वृत्तचित्रों का निर्माण एनएफडीसी, सीएफएसआई और फिल्म प्रभाग द्वारा संयुक्त रूप से लागू की जाएगी। विवरण इस प्रकार है:-

| क्रं. सं. | स्कीम के भाग | क्रियान्वयन एजेंसी |
|---|---|---|
| i | विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्म निर्माण | एनएचडीसी |
| ii | बाल फिल्मों का निर्माण | सीएफएसआई |
| iii | वृत्तचित्र और लघु फिल्मों का निर्माण | फिल्म प्रभाग |

विभिन्न भारतीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को सहयोग और प्रोत्साहन देकर उत्कृष्ट सिनेमा के बढ़ावा देने का अधिदेश एनएफडीसी के प्राप्त है। योजना स्कीम के पहले भाग का उद्देश्य नई प्रतिभा, भारतीय सिनेमा की बहुयामी अनेकता और अंतर्राष्ट्रीय सह-निर्माताओं को प्रोत्साहित कर उन्हें बढ़ावा देने के विचार से फिल्मों का निर्माण करना है। सीएफएसआई को भारत में बनने वाली बाल फिल्मों के विश्वभर में प्रचार और बाल फिल्म आंदोलन को बढ़ावा देने का जिम्मा दिया गया है। स्कीम के दूसरे भाग का उद्देश्य देश में बाल सिनेमा का विकास, बच्चों को स्वस्थ और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान कर उनकी दुनिया के प्रति समझ विकसित करना और आधुनिक भारत के जिम्मेवार नागरिक बनने में मदद करना है।

फिल्म प्रभाग का उत्तरदायित्व जनसूचना, शिक्षा, प्रेरणा तथा शैक्षिक तथा सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए भारत सरकार के लिए आवश्यक वृत्तचित्रों, एनीमेशन तथा लघु फिल्मों का निर्माण और वितरण करना है। स्कीम के तीसरे भाग का उद्देश्य ने केवल फिल्म प्रभाग बल्कि निजी निर्माताओं को अधिक से अधिक फिल्म निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना है।

## ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

तीव्र प्रौद्योगिकी विकास ने एनीमेशन, गेमिंग और विशेष दृश्य प्रभावों के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा दिया है। एनीमेशन सॉफ्टवेयर कार्यक्रमों का इस्तेमाल कंटेंट विकसित करने के लिए 2 डी सैल एनीमेशन तथा 3 डी एनीमेशन तकनीकों का इस्तेमाल होता है। 3 डी मोशन केप्चर एनीमेशन तकनीकों का इस्तेमाल लो रिजोल्युशन गेम, इंटरनेट करेक्टर्स, विशेष प्रभाव इत्यादि में होता है। इसी तरह, गेमिंग उद्योग गेम डिजाइन, प्लेटफार्म डिजाइन तथा प्ले करेक्टरिस्टिक सिस्टम के लिए आधुनिक गेमिंग सॉफ्टवेयर पर निर्भर है। भारतीय गेमिंग उद्योग मोबाइल तथा ऑन लाइन गेमिंग क्षेत्रों में अवसरों का इस्तेमाल करना चाहता है। ऐनीमेशन, गेमिंग तथा दृश्य प्रभाव उद्योग प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी/व्यवसायिक दोनों मानवशक्ति की मांग वाला क्षत्र है। भारतीय उद्योग पहले से ही विरोध का सामना कर रहा है। ऐसे में जब इन उद्योगों में भारत का एक छोटा हिस्सा है, वैश्विक मांग और भारत में आईटी व्यावसायिकों का विशाल पूल होने के नाते इसमें अत्यधिक संभावनाएं हैं।

दृश्य प्रभाव एक अत्यंत कौशलपूर्ण गतिविधि है जो लगातार श्रव्य दृश्य उद्योग को व्यक्त करता है। इस संबंध में फिल्में जैसे मिशन इम्पॉसिबिल तथा हालीवुड की 'मैटिक्रस' और 'धूम-2' एवं 'डॉन' स्मरण में आती है। यह कौशल विकास का एनीमेशन तथा गेमिंग के अनुरूप है जिसमें राजस्व की संभावनाएं अधिक हैं।

तथापि, लगातार बढ़ती हुई एनिमेशन, गेमिंग एवं दृश्य प्रभाव उद्योग में प्रशिक्षित व्यवसायिकों का अभाव है। विभिन्न रिपोर्टों में अनुमानों के अनुसार लगभग 10,000 एनिमेशन व्यवसायिकों की आवश्यकता है जबकि वर्तमान में केवल 3000 ही उपलब्ध है। इसी प्रकार गेमिंग उद्योग में 6000 व्यवसायिक हैं जबकि मांग अधिक की है। उद्योग के विकास के बाद कुशल व्यवसायिकों की मांग और अधिक बढ़ सकती है। अत: एनीमेशन, गेमिंग और दृश्य प्रभाव सैक्टर में प्रशिक्षित व्यवसायिकों की मांग भारत में और बढ़ना अवश्यम्भावी है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस क्षेत्र हेतु मानव संसाधन योजना की आवश्यकता है जिससे प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या बढ़ सके। अत: उच्च शिक्षा में स्कूल पाठयक्रमों तथा एनीमेशन प्रशिक्षण में लक्ष्य के मद्देनजर एनीमेशन, गेमिंग तथा दृश्य प्रभाव सैक्टर के लिए एक विशेष प्रशिक्षण एवं सलाहकार संस्थान की स्थापना सरकारी/निजी भागीदारी में लिए जाने की परिकल्पना की गई है।

संस्थान इस क्षेत्र में अनुसंधान के अवसर भी उपलब्ध कराएगा। इससे और अधिक तकनीकी पहलों एवं सॉफ्टवेयर का विकास होगा। दूरगामी दृष्टिकोण से अनुसंधान से न केवल बौद्धिकता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि राजस्व अर्जित करने में भी सहायक होगा तथा संबंधित सैक्टर का नेतृत्व भी हो सकेगा।

संस्थान की स्थापना सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत करना प्रस्तावित है।

# प्रसारण क्षेत्र

## इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेल

अति आधुनिक इलेक्ट्रानिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) की स्थापना (क) केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (नियमन) अधिनियम 1995 में स्थापित कार्यक्रम तथा विज्ञापन संहिता तथा (ख) निजी एफएम रेडियो आदि के लिए लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के लिए निगरानी हेतु की गई है। 24 घंटे के 100 चैनलों की निगरानी सुविधा के साथ इस सेल ने जून 2008 में कार्य शुरू किया। 2008-09 में निगरानी चैनलों की संख्या 150 चैनल हो गई। 5 जनवरी 2011 से इसकी क्षमता 300 टीवी चैनलों की हो गई। चूंकि निजी चैनलों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ रही है अत: आगे भी इसकी क्षमता बढ़ने की संभावना है। निगरानी प्रणाली की शुरुआत के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। स्कीम की स्थापना और संवर्धन पूरी तरह सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

## एफएम सेल

सूचना और प्रसारण मंत्रालय रेडियो, टेलीविजन, फिल्मों, प्रेस प्रकाशनों, विज्ञापन और नृत्य और नाटक के पारंपरिक तरीकों जैसे जन संचार मीडिया के माध्यम से लोगों तक सूचना प्रवाह को पहुंचने में मदद कर रहा है। विभिन्न आयु समूहों की मनोरंजन और बौद्धिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मंत्रालय संलग्न है जिसमें राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल आदि पर विशेष ध्यान है। यह कार्य चार विंगों - सूचना, प्रसारण, फिल्म तथा एकीकृत वित्त विंग द्वारा संपन्न किया जाता है। योजना स्कीम 'प्राइवेट एफएम रेडियो' निजी एफएम प्रसारणकर्ताओं को बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए है जो उन्हें प्रभावी उपयोग के लिए सामान्य स्थल में प्रसारण सुविधाएं ढूंढने में सहायता करेगी।

## प्रसार भारती

### अधिदेश

अधिदेश प्रसार भारती नाम से भारतीय प्रसारण निगम की स्थापना के प्रावधान बनाए गए। प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 को 15 सितंबर 1997 से लागू किया गया। इस अधिनियम में प्रावधान है कि निगम सर्वसाधारण को जानकारी देने, शिक्षित करने और मनोरंजन के लिए सार्वजनिक सेवा प्रसारण का कार्य करेगा। यानी जो कार्य पहले आकाशवाणी और दूरदर्शन करते थे, वह कार्य अब यह निगम करेगा। निगम के सामान्य पर्यवेक्षण निर्देशन और प्रबंध के कार्य प्रसार भारती बोर्ड को सौंपे जाएंगे। यह बोर्ड अपने ऐसे सभी अधिकारों का इस्तेमाल और अपने ऐसे सभी कार्य उसी प्रकार करेगा जिस प्रकार इस अधिनियम के तहत निगम द्वारा किए जाते हैं।

निगम अपने कार्य सुचारू रूप से कर सके, इसके लिए अधिनियम में प्रावधान है कि संसद द्वारा कानूनी तौर पर इस बारे में विधिवत विनियोजन किए जाने के बाद केंद्र सरकार आवश्यकतानुसार निगम को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इक्विटी सहायता अनुदान या ऋण के रूप में धनराशि प्रदान कर सकती है। निगम का अपना कोष होगा और निगम की सारी प्राप्तियां इसी कोष में जमा की जाएंगी और निगम सभी भुगतान इसी कोष से करेगा।

1. इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निगम का प्राथमिक दायित्व सर्वसाधारण को जानकारी देने, शिक्षित करने और मनोरंजन के लिए सार्वजनिक प्रसारण सेवा को संचालन करना तथा रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करना होगा।

**स्पष्टीकरण**—शंका दूर करने के लिए एतद् द्वारा यह घोषणा की जाती है कि इस खंड के प्रावधान भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के अलावा होंगे, न कि अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध होंगे।

2. निगम अपने कार्यों के निर्वहन में निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखेगा :

(क) देश की एकता और अखण्डता तथा संविधान में निहित मूल्यों का संरक्षण।

(ख) सार्वजनिक हित, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में मुक्त, सच्ची तथा निष्पक्ष सूचना प्राप्त करने के नागरिक के अधिकार का संरक्षण तथा अपनी विचारधारा या किसी राय को जोड़े बिना विविध दृष्टिकोणों सहित सूचना की निष्पक्ष तथा संतुलित प्रस्तुति।

(ग) शिक्षा के क्षेत्र में एवं साक्षरता, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और विज्ञान एवं तकनीक पर विशेष ध्यान देना।

(घ) उपयुक्त कार्यक्रमों के प्रसारण द्वारा देश के विविध क्षेत्रों की सांस्कृतिक विविधता एवं भाषाओं को पर्याप्त कवरेज प्रदान करना।

(ङ) क्रीड़ा एवं खेल को पर्याप्त कवरेज प्रदान करना जिससे कि स्वस्थ प्रतियोगिता एवं खेल भावना को बढ़ावा मिले।

(च) युवाओं की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त कार्यक्रम प्रदान करना।

(छ) महिलाओं की स्थिति एवं समस्याओं के संबंध में राष्ट्रीय चेतना बढ़ाना तथा महिला उत्थान पर विशेष ध्यान देना।

(ज) शोषण, असमानता को दूर करने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने एवं छुआ-छूत जैसी बुराई को दूर करने तथा समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए काम करना।

(झ) कामगारों के अधिकारों की रक्षा करना एवं उनके कल्याण को बढ़ावा देना।

(ञ) कमजोर एवं ग्रामीण वर्ग तथा सीमावर्ती क्षेत्र, पिछड़े एवं सुदूर क्षेत्रों के लोगों की भलाई के लिए कार्य करना।

(ट) अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय समुदायों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त कार्यक्रम प्रदान करना।

(ठ) बच्चों, नेत्रहीनों, बूढ़ों, अपंगों एवं जनता के अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाना।

(ड) राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए, ऐसे प्रसारण करना जो भारत में विभिन्न भाषाओं के जरिए संवाद को बढ़ाते हों और हर राज्य में वहां की भाषा में क्षेत्रीय प्रसारण को बढ़ावा देना।

(ढ) उपयुक्त तकनीक द्वारा समग्र प्रसारण कवरेज प्रदान कराना तथा प्रसारण फ्रीक्वेंसी का सर्वोत्तम उपयोग एवं उच्च-स्तरीय उपलब्धियां सुनिश्चित करना।

(ण) रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण के निरंतर विकास के क्रम में शोध एवं विकास कार्य को आगे बढ़ाना।

(त) विभिन्न स्तरों पर प्रसारण के विभिन्न चैनलों की स्थापना द्वारा प्रसारण सुविधाओं का विस्तार।

3. विशेष रूप से एवं बिना पूर्वाग्रह के सामान्य रूप से, वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप, निगम कुछ कदम उठा सकता है :

(क) कार्यक्रमों के निर्माण एवं उपलब्धता को लोकसेवा के रूप में संचालित करने के लिए प्रसारण को सुनिश्चित करना।

(ख) रेडियो एवं टेलीविजन के लिए समाचार एकत्र करने के लिए एक व्यवस्था की स्थापना।

(ग) खेल प्रतियोगिताओं, अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं, फिल्मों, सीरियलों, समारोहों, बैठकों तथा जनहित की अन्य घटनाओं के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए खरीद अथवा प्राप्ति के लिए बातचीत करना और ऐसे कार्यों की प्रक्रिया निर्धारित करना।

(घ) रेडियो, टेलीविजन या अन्य सामग्री के लिए लाइब्रेरी की स्थापना एवं देखभाल।

(ङ) समय-समय पर कार्यक्रम, दर्शक शोध, बाजार या तकनीकी सेवाओं को संचालित या प्रारंभ करना, जो उपयुक्त व्यक्तियों को उपयुक्त तरीकों और नियमों एवं शर्तों के अनुसार कार्य किए जा सके।

(च ) नियमों द्वारा विर्निदिष्ट हो सकने वाली अन्य सेवाओं को प्रदान करना।

4. उपखंड (2) और (3) निगम की कोई बात निगम को, ऐसे नियमों एवं शर्तों के अनुसार जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हों, विदेशी सेवाओं के प्रसारण और ऐसे विदेशी प्रसारण की निगरानी से नहीं रोक सकती जिनके प्रसारण के लिए केंद्र सरकार से भुगतान किया जाना हो।

5. इस खंड में स्थापित उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराया गया है, इनकी सुनिश्चितता के उद्देश्य के लिए विज्ञापन के संबंध में केंद्र सरकार को प्रसारण समय की अधिकतम सीमा के निर्धारण की शक्ति होगी।

6. निगम की मात्र इस आधार पर कोई भी सिविल जवाबदेही नहीं होगी कि वह इस खंड के किसी भी प्रावधान को पूरा करने में असफल रहा है।

7. निगम को विज्ञापन या ऐसे कार्यक्रम, जो नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट हो, के संबंध में फीस या अन्य सेवा शुल्क निर्धारित करने का अधिकार होगा।

इस खंड के अधीन इकट्ठा की गई फीस या अन्य सेवा शुल्क समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वैसी सीमाओं से बाहर नहीं हो।

## लक्ष्य तथा उद्देश्य

आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो), प्रसार भारती का एक अभिन्न भाग है, जो उपरोक्त दिए गए आदेशों को निरंतर पूरा कर रहा है। आकाशवाणी अपने विभिन्न स्टेशनों से प्रसारित कार्यक्रमों द्वारा लोगों को सूचना देता है, शिक्षित करता है और उनका मनोरंजन करता है। यह पूरे देश की जनता को सरकारी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की सूचना श्रव्य-प्रसारण के माध्यम से देता है और संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित करता है। यह पूरे देश की जनता को महत्वपूर्ण समाचार तथा सम-सामयिक घटनाओं की जानकारी देता है। यह विचारों के विभिन्न बिंदुओं को प्रस्तुत करता है ताकि इसके द्वारा प्रसारित कार्यक्रम संतुलित एवं निष्पक्ष हों। यह शिक्षा एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। यह प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अपने तीव्र प्रसार के द्वारा जनता एवं सरकारी विभागों को समय पर सूचना प्रदान करता है। यह एक व्यवसायिक सेवा (विविध भारती) भी संचालित करता है जो कि वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री के विज्ञापन भी देता है। इसका विदेश सेवा प्रभाग विदेशी श्रोताओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित करता है। इसका समाचार सेवा प्रभाग 24 घंटे ताजा समाचार उपलब्ध कराता है। इसके अलावा आकाशवाणी का एफएम और डीटीएच चैनल दिन-रात संगीत, गाने आदि के जरिये लोगों का मनोरंजन करते हैं।

## नीति वक्तव्य

सार्वजनिक सेवा प्रसारक के रूप में प्रसार भारती के उद्देश्य हैं

- गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम बनाना और
- महिलाओं, बच्चों, सुविधाविहीन, विशिष्ट भाषाई समूहों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से सूचना प्रदान करने, शिक्षा देने और मनोरंजन करने के प्रयोजन को पूरा करना।

प्रसार भारती के अंतर्गत आकाशवाणी, प्रसार भारती के अधिदेश को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयत्न करता है। अनेक प्रकार की नई पहल की जा रही है, जैसे 86 चुने हुए आकाशवाणी स्टेशनों से खेत और घर से जुड़े कार्यक्रम– किसान वाणी कार्यक्रम, पर्यावरण, परिवार कल्याण, ग्रामीण बच्चों और छोटे बच्चों को केंद्र में रखकर बनए गए विशेष कार्यक्रम, महिला कार्यक्रम, शैक्षिक प्रसारण (इग्नू/एसीईआरटी/सीआईईटी) दिखाए जा रहे हैं। एचआईवी/एड्स पर जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रम और दूसरे स्वास्थ्य कार्यक्रमों, इग्नू के सहयोग के साथ कार्यक्रम, राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका (विज्ञान भारती), सीसेम स्ट्रीट कार्यक्रमों को आकाशवाणी पर प्रसारित किया गया है, साथ ही संगीत और नाटक से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण भी किया जाता है। पहल के इंजीनियरिंग पक्ष की ओर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व और द्वीपीय क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज कार्यक्रम चलाए गए हैं और एफएम सेवाओं का विस्तार, प्रोडक्शन कार्यक्रमों और ट्रांसमिशन सुविधाओं का डिजिटलीकरण एवं नई तकनीक को प्रस्तावित किया गया है। समाचार सेवा प्रभाग और अनुसंधान एवं विकास से संबंधित गतिविधियों को भी संचालित किया गया है।

सभी प्रकार की पहल के उचित एवं समयाबद्ध कार्यान्वयन को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

भारतीय क्लासिक योजना का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता के कार्यक्रम का निर्माण और देश की समृद्ध संस्कृति तथा साहित्यिक विरासत को संरक्षित रखना है। योजना के अंतर्गत सभी कार्यक्रम सभी भारतीय भाषाओं में बनाए गए हैं और इन साहित्यिक रचनाओं को अन्य भाषाओं में डब किया गया है जिससे देश के सभी दर्शकों को लाभ प्राप्त हो।

**कार्यक्रम :** दूरदर्शन में, महाराणा रंजीत सिंह की ऐतिहासिक गाथा पर 52 एपीसोड की शृंखला निर्माणाधीन है। फोर्ट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, कॉमन वरशिप सेंटर्स जैसे चुनींदा विषयों पर विशेष कार्यक्रम निर्माणाधीन हैं।

दूरदर्शन सार्वजनिक सेवा प्रसारण कोष के सहयोग से व्यापक स्तर के विषयों पर वृत्तचित्रों का निर्माण कर रहा है। इसके अंतर्गत हर वर्ष चार वृत्तचित्रों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं।

## डीडी उर्दू

पांच करोड़ 20 लाख उर्दू भाषी आबादी की जरूरतों को देखते हुए और उर्दू की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए 15 अगस्त 2006 को डीडी उर्दू अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य इस चैनल पर अच्छे विषय और लक्षित दर्शकों के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रमों को प्रसारित करना है। इसके लिए डीडी की अधिग्रहण परियोजना के माध्यम से सॉफ्टवेयर खरीदा गया है और डीडी में इसे तैयार भी किया गया है।

## डीडी न्यूज

डीडी न्यूज पहला और एकमात्र स्थलीय न्यूज चैनल है जो देश की लगभग आधी आबादी तक पहुंचता है। इस चैनल की शुरुआत नवंबर 2003 में हुई थी। डीडी न्यूज बिना सनसनी के, संतुलित समाचारों के प्रसारण को सुनिश्चित करते हुए सत्य, सर्वत्र, संपूर्ण (पूरा सच, हमेशा) का आदर्श वाक्य देता है।

आज के मीडिया परिदृश्य में, जहां 24 घंटे के अनेक निजी समाचार चैनल मौजूद हैं, डीडी न्यूज जैसे 24 घंटे के क्षेत्रीय सेटेलाइट राष्ट्रीय समाचार चैनल की मजबूत उपस्थिति की जरूरत है। सरकारी दृष्टिकोण, विशेष रूप से विकास नीतियों और कार्यक्रमों को प्रदर्शित करने के लिए यह अनिवार्य है। डीडी न्यूज एकमात्र भारतीय न्यूज चैनल है जो देश के 50 प्रतिशत लोगों तक पहुंचता है, विशेष रूप से समाज के सुविधाविहीन और अभावग्रस्त तबकों तक जो केबल सेटेलाइट के जरिए देश से जुड़े हुए नहीं हैं। राष्ट्रीय आपदा, विनाश आदि की स्थिति में, सार्वजनिक प्रसारक की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

## श्रोता अनुसंधान खंड

श्रोता अनुसंधान खंड अनुसंधान और आंकड़ा एकत्रीकरण के विभिन्न तरीकों के माध्यम से चैनलों पर कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनकी गुणवत्ता सुधारने में महत्पूर्ण भूमिका निभाता हैं। श्रोता अनुसंधान डीटीएच पेनेट्रेशन और कृषि कार्यक्रमों की नेरोकास्टिंग की मदद से देश भर में सर्वेक्षण करता है। श्रोता अनुसंधान खंड देश के विभिन्न हिस्सों

में स्थित अपनी 18 इकाइयों के सहयोग से शहरी और ग्रामीण इलाकों में डार्ट सर्वेक्षण भी करता है। वर्तमान वर्ष में भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों के प्रभाव पर सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज द्वारा किया गया है।

इन हाउस सर्वेक्षणों के अतिरिक्त दूरदर्शन ने टैम मीडिया रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड से रेटिंग डेटा और एमआरयूसी से बेसलाइन डेटा प्राप्त करेगा और उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में चैनल प्रबंधकों एवं मार्केटिंग विभाग को प्रदान करेगा।

**डीडी भारती**

डीडी भारती एक सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने वाला चैनल है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तावित, प्रोत्साहित और संरक्षित रखने में निर्णायक भूमिका निभाता है। चैनल संगीत, नृत्य, विरासत, स्वास्थ्य, बच्चों पर केंद्रित है और भारतीय जीवन शैली, दर्शन, कला और संस्कृति पर बल देता है। चैनल संगीत और नृत्य, पर्व, विशेष घटनाओं, मुशायरा, कवि सम्मेलन आदि के लाइव कवरेज को भी प्रसारित करता है। फिक्स प्वाइंट चार्ट्स में परिवर्तन के साथ, दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए चैनल ने नए कार्यक्रमों को भी प्रस्तावित किया है। कार्यक्रमों में वैविध्य तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए नए कार्यक्रम भी खरीदे गए हैं। कार्यक्रमों, विशेष रूप से सांस्कृतिक विरासत से संबंधित कार्यक्रमों में सुधार के लिए फिर कमीशनिंग प्रस्तावित है।

## क्षेत्रीय प्रसारण

देश की सामाजिक सांस्कृतिक और भाषाई विभिन्नता के मद्देनजर दूरदर्शन देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, विशेष रूप से प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएं –तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, बांग्ला, असमी, पंजाबी, गुजराती, मराठी और कश्मीरी – बोलने वाले लोगों के हित के लिए क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में भी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। मुख्य भाषा के कार्यक्रमों के अतिरिक्त, क्षेत्रीय भाषाओं के 11 सेटेलाइट चैनल भी उर्दू, सिंधी, संस्कृत, टुलु, कोंकणी, डोगरी, हिमाचली, हरियाणवी, नेपाली और उत्तर पूर्व की सभी भाषाओं और बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं।

क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम राज्य में विभिन्न एचपीटी और एलपीटी के क्षेत्रीय सहयोग के साथ सेटेलाइट पर, जमीनी ट्रांसमीटरों के माध्यम से डीडी 1 की क्षेत्रीय विंडो के रूप में दोपहर तीन बजे से शाम आठ बजे तक उपलब्ध रहते हैं। तमिलनाडु में यह क्षेत्रीय सहयोग रात 11 बजे तक रहता है।

इन क्षेत्रीय भाषाओं के चैनलों पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित विभिन्न कार्यक्रम और फॉरमेट उपलब्ध कराए जाते हैं और इन्हें संबंधित राज्य के राजधानी केंद्र से फीड और प्रसारित किया जाता है। इन चैनलों पर फीचर फिल्में, फिल्मी गाने, धारावाहिक, शास्त्रीय–सुगम–लोक संगीत, नृत्य, समाचार और समसामयिक कार्यक्रम, कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि प्रसारित किए जाते हैं जोकि श्रोता विशेष की रुचि के कार्यक्रमों के साथ समाज के सभी तबकों, महिलाओं, बच्चों और युवाओं का रंजन करते हैं।

## राज्य नेटवर्क

दूरदर्शन के क्षेत्रीय सेवा प्रसारण भी हैं जिन्हें राज्य नेटवर्क कहा जाता है। ये नेटवर्क उत्तर भारत के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए है। एचपीटी और एलपीटी के इन सभी राज्य नेटवर्कों के माध्यम से डीडीके, दिल्ली से सोमवार से शनिवार को दोपहर तीन से चार बजे तक एक घंटे के लिए उत्तरी नेटवर्क धारावाहिक आधारित मनोरंजन कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं और रविवार को हिंदी फीचर फिल्म प्रसारित की जाती है। इसलिए संबंधित राज्य की राजधानी से दोपहर चार से शाम आठ बजे के बीच कार्यक्रम बीम किए जाते हैं और उस राज्य के जमीनी ट्रांसमीटर से रिले किए जाते हैं जिससे क्षेत्र की प्रमुख स्थानीय बोली में आयोजित होने वाली गतिविधियों को कनेक्ट किया जा सके।

शिक्षा, सूचना और मनोरंजन के अतिरिक्त वर्ष भर सबसे ज्यादा बल फ्लैगशिप कार्यक्रमों को दिया जाता है। अपनी क्षमता का ध्यान न करते हुए क्षेत्रीय केंद्रों ने फ्लैगशिप कार्यक्रमों और लोक सेवा कार्यक्रमों को प्रमुखता देने में बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

## डीडी अभिलेखागार

डीडी अभिलेखागार 40 वर्षों से सृजित मीडिया कन्टेंट का परिरक्षक है। किसी भी मीडिया संगठन का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपनी परिसंपत्ति को कैसे प्रबंधित करता है। ब्रॉडकास्टिंग चैनल के रूप में वह मौजूदा घटनाओं की प्रासंगिकता के अधिक से अधिक फाइल फुटेज पर निर्भर रहता है। इसके अतिरिक्त डीडी अभिलेखागार का सांस्कृतिक कन्टेंट बहुत मूल्यवान है, चूंकि डीडी अभिलेखागार ऐसा एकमात्र माध्यम है जो विभिन्न सांस्कृतिक प्रवृत्तियों, जिसमें शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत और लोक नृत्य, आदिवासी संगीत और नृत्य शैलियां, परंपरागत और आधुनिक रंगमंच आदि शामिल है, के संरक्षण के उत्तरदायित्व को मान्यता देता है। यह बहुमूल्य कन्टेंट उस देश के स्पंदमान सांस्कृतिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है जो पूरे विश्व में अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। डीडी अभिलेखागार ने अपने कन्टेंट को संरक्षण का अभियान चलाया है जो भविष्य और देश की समृद्धि के लिए अतीत और वर्तमान का प्रतिनिधित्व करता है। अगले चार वर्षों में डीडी अभिलेखागर विश्व के सर्वश्रेष्ठ ब्रॉडकास्टिंग अभिलेखागारों में से एक हो जाएगा।

## स्व वित्त कमीशनिंग ( एसएफसी )

दूरदर्शन ने देश के प्रतिष्ठित निर्माताओं से अपने फ्लैगशिप चैनल डीडी 1 के लिए गुणवत्तापूर्ण मनोरंजक कन्टेंट आउटसोर्स करने के लिए स्व वित्त कमीशनिंग की नई योजना प्रतिपादित की है। इस योजना के तहत वरिष्ठ फिल्मकारों और टेलीविजन निर्माताओं द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर को दूरदर्शन की ओर से वितरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के स्वामित्व वाले कन्टेंट को दूसरे चैनलों द्वारा प्रसारित किया जा सकता है। यह योजना दूरदर्शन के प्राइम टाइम के दौरान अच्छा राजस्व अर्जित कर रही है।

डीडी एसएफसी कार्यक्रमों द्वारा सभी प्राइम टाइम और मिड प्राइम स्लॉट्स को अधिग्रहित करने को प्रतिबद्ध है। प्राइम टाइम और मिड प्राइम स्लॉट्स के अतिरिक्त एसएफसी कार्यक्रमों के लिए नॉन प्राइम टाइम स्लॉट्स को लेने की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। यहां यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि हर वर्ष निर्माण की लागत बढ़ रही है और गुणवत्ता के लिहाज से दूसरे सेटेलाइट चैनलों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए हमें एपीसोड के मूल्य को बढ़ाना चाहिए।

इस योजना के तहत निर्मित कार्यक्रम केवल दूरदर्शन की संपत्ति हैं। डीडी इस संपत्ति को बिना किसी अतिरिक्त मूल्य के, दूरदर्शन के किसी दूसरे चैनल पर जब चाहे प्रयोग कर सकता है। एक समय निवेश और बहुउपयोग का यह अधिकार, बिना किसी आवर्ती व्यय के, दूरदर्शन को प्रायोजित कार्यक्रमों के साथ नहीं मिलता। राजस्व में बढ़ोतरी के अतिरिक्त, डीडी मार्केटिंग एजेंसियों/प्रायोजकों के देय की समस्या से भी निजात पा लेता है क्योंकि डीडी सीधा ग्राहकों के संपर्क में होता है। अदालती मामलों/पंचाट से भी छुटकारा मिलता है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, प्राइम टाइम पर दैनिक धारावाहिक को प्रस्तावित करने का प्रयोग भी किया गया जो दर्शक संख्या बढ़ाने के साथ-साथ दूरदर्शन का राजस्व भी बढ़ाएगा।

### सॉफ्टवेयर की कमीशनिंग

- हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई, पटना, जयपुर, श्रीनगर, जम्मू स्थित केंद्रों के माध्यम से इन हाउस प्रोडक्शन गतिविधियों का संचालन

इंडियन क्लासिक्स स्कीम का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रमों का निर्माण और देश की समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को संभालना है। इस स्कीम में सभी कार्यक्रम भारतीय भाषाओं में बनाए जा रहे हैं और देश के सभी दर्शकों के लाभ के लिए ये साहित्यिक कार्यक्रम अन्य भाषाओं में डब किए जा रहे हैं। इंजीनियरिंग पक्ष पर काफी पहल की गई हैं। अधिकतर कार्यक्रम मौजूदा नेटवर्क के डिजिटल स्वरूप वाले हैं। जम्मू और काश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में एचपीटी/एलपीटी की स्थापना और ई-गवर्नेंस का क्रियान्वयन किया गया है। भारत सरकार ने 11वीं योजना के दौरान एमआईआर को 1718 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं जिनमें से 466.80 करोड़ रुपये 10वीं योजना को 11वीं योजना में भी चालू रखने और 1251.20 करोड़ रुपये शुरू की जाने वाली नई स्कीमों के लिए हैं।

जैसी कि योजना है 2017 तक एआईआर नेटवर्क के डिजिटलीकरण का कार्य पूरा हो जोगा। प्रथम चरण में 11वीं योजना के दौरान 924.20 करोड़ रुपये आबंटित किए थे। 54.78 करोड़ रुपये की आंशिक स्कीमें 2008 में स्वीकृत हुई थीं और बाकी स्कीमें (843.54 करोड़ रुपये) अप्रैल 2010 में स्वीकृत हुईं। 2011-12 के दौरान 133.77 करोड़ रुपये डिजिटलीकरण के लिए आबंटित किए गए। प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए 10 के डब्ल्यू एम डब्लू डीआरएम मोबाइल ट्रांसमीटर (कुल 6) 5 क्षेत्रों में स्थापित किए जा चुके हैं। 105 करोड़ रुपये के उपकरणों की खरीद आर्डर हो चुके हैं और 200 करोड़ रुपये के आर्डर दिए जाने प्रस्तावित हैं। 2011-12 की इन गतिविधियों के अलावा डिजिटलीकरण का प्रथम चरण 2013-14 में पूरा होने की आशा है। जे एंड के के सीमावर्ती क्षेत्रों में एचपीटी/एलपीटी स्थापना की स्कीम 100 करोड़ रुपये की लागत पर अगस्त 2011 में स्वीकृत हुई थी और अब यह क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है।

इस स्कीम के तहत, 10 के एम तथा 10 के डब्लू टीवी ट्रांसमीटर जे एंड के तीन क्षेत्रों में स्थापित किए जाने हैं। दो स्थलों का अधिग्रहण हो चुका है, तीसरे के लिए प्रक्रिया जारी है। इसके अतिरिक्त, 100 डब्लू एफएम ट्रांसमीटर मौजूदा 4 स्थानों पर स्थापित किए जाने हैं 10 के डब्लू के 2 टीवी ट्रांसमीटर मौजूदा एमआईआर स्थल पर स्थापित होने हैं। इस स्कीम से जे एंड के के सीमावर्ती क्षेत्रों में कवरेज को मजबूती मिलेगी।

ईआरपी क्रियान्वित ई-गवर्नेंस स्कीम इस योजना की अवधि में शुरू की गई थी। स्कीम केवल एमआईआर के लिए ही है। योजना आयोग दूरदर्शन की आवश्यकताएं शामिल करने का इच्छुक है। संशोधित स्कीम बनने की प्रक्रिया में है लेकिन चालू वित्तीय वर्ष में इस स्कीम की स्वीकृति की आशा नहीं है।

अप्रैल 2012 से 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होगी। यह योजना प्रसारण के प्रभावी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि डिजिटलीकरण के द्वितीय चरण का इस योजना में पूरा होना प्रस्तावित है। इसके साथ ही प्रसारण सेवाओं की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार आएगा। 11वीं योजना दौरान शुरू की गई स्कीमें भी इसकी पूरक होंगी। प्रसारण को और अधिक प्रभावी और सक्षम बनाने के लिए 12वीं योजना में प्रस्तावित स्कीमें इनके अधीन कवर होंगी -1. प्रसारण ढांचा नेटवर्क विकास, 2. 4811 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कांटेंट विकास, 3. विशेष परियोजनाएं। प्रसारण ढांचा नेटवर्क विकास के तहत विभिन्न स्कीमें प्रस्तावित हैं। ये हैं - 1. प्रसारण नेटवर्क का डिजिटलीकरण, 2. एफएम प्रसारण का विस्तार और बदलाव, 3. सीमावर्ती क्षेत्रों में कवरेज मजबूत करना, 4. वैकल्पिक प्लेटफार्म पर प्रसारण, 5. मौजूदा ढांचे को समेकित करना और 6. ई-गवर्नेंस।

11वीं योजना की अवधि में भारत सरकार ने दूरदर्शन को 2932 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, इनमें से 1078 करोड़ रुपये 10वीं योजना में जारी स्कीमों के लिए और 1854 करोड़ रुपये नई स्कीमों के लिए। दूरदर्शन के डिजिटलीकरण एचडीटीवी की शुरूआत तथा मौजूदा टीवी नेटवर्क के आधुनिकीकरण और संवर्धन पर जोर है। डिजिटलीकरण के लिए 11वीं योजना में 620 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था। कुल 67 स्टूडियो केंद्रों में 33 का पूरी तरह तथा 31 का आंशिक डिजिटलीकरण हो चुका है। 11वीं योजना पूरी होने तक चार केंद्रों को छोड़कर सभी केंद्रों का डिजिटलीकरण हो जाएगा। ये केंद्र 12वीं योजना में डिजिटलीकृत होंगे। स्थलीय नेटवर्क के डिजिटलीकरण के लिए 40 ट्रांसमीटर प्राप्त होने की प्रक्रिया में हैं। प्रथम चरण में, 19 डिजिटल ट्रांसमीटरों के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। 12वीं योजना में 490 ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण प्रस्तावित है। एचडीटीवी स्कीम के तहत 12वीं योजना में 165 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत हुआ था। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में स्थापित होने के लिए एचडीटीवी ट्रांसमीटरों की प्राप्ति के लिए टेंडरों की जांच जारी है। एचडी फार्मेट प्ले-आउट सुविधा दिल्ली में प्राप्त कर ली गई है। डीडी डायरेक्ट के डीटीएच प्लेटफार्म में एचडी फार्मेट सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। ईएनजी आधारित स्टूडियो से बाहर निर्माण के लिए एचडी उपकरण, पोस्ट प्रोडक्शन, ओबी वैन प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया जारी है। 49 से 97 चैनलों को डीटीएच प्लेटफार्म पर लाने की प्रक्रियाधीन है। 11वीं योजना के एक हिस्से के रूप में आधुनिकीकरण, संवर्धन, स्टूडियो अपग्रेडेशन, ट्रांसमीटर और सेटेलाइट प्रसारण उपकरणों का क्रियान्वयन विभिन्न स्तरों पर जारी है। अपनी विस्तार योजनाओं में दूरदर्शन सीमावर्ती क्षेत्रों में टीवी कवरेज मजबूत करने को प्राथमिकता दे रहाहै। उत्तर पूर्व और जे एंड के में दूरदर्शन सेवाओं के विस्तार तथा सुधार के लिए विशेष पैकेज लागू किए गए हैं। जे एंड के में टीवी कवरेज में और सुधार के लिए 12वीं योजना अवधि में 5वीं एचपीटी स्वीकृत किए गए हैं।

**डीडी का डिजिटलीकरण**

सभी 35 सेटेलाइट चैनल डिजिटल मोड में चल रहे हैं। डीटीएच प्लेटफार्म का भी डिजिटलीकरण हो गया है। इस स्कीम के तहत स्वीकृत मुख्य परियोजनाएं इस प्रकार हैं :

39 स्टूडियो केंद्रों का पूर्ण डिजिटलीकरण (31 आंशिक तथा 3 एनलॉग केंद्र) 40 स्थानों पर डिजिटल एचपीटी की स्थापना। 2012 तक सभी केंद्र पूरीतरह डिजिटल मोड में आ जाएंगे जबकि 2014 तक डिजिटल एचपीटी स्थापित हो जाएंगे। ट्रांसमीटर तथा स्टूडियो उपकरणों का आधुनिकीकरण, संवर्धन तथा बदलने की स्कीम फरवरी 2011 में 299 करोड़ रुपये में परिव्यय के साथ स्वीकृत हुई थी। इसकी मुख्य परियोजनाएं इस प्रकारहैं :

14 स्थानों पर मौजूदा पुराने एचपीटी को बदलना 60 एलपीटी को आटोमोड 500 वाट एलपीटी से बदलना, 20 स्टूडियो केंद्रों के कैमरा चेन, प्रोडक्शन स्विच, लोगो जेनेरेटर तथा कलर मॉनिटर आदि का आधुनिकीकरण उपर्युक्त परियोजनाएं क्रियान्वयाधीन हैं।

# मुख्य सचिवालय के प्रसारण विंग की स्कीमें

## इंटरनेशनल चैनल

भारत के वैश्विक शक्ति केरूप में उभरने से यह अनिवार्य हो गया है कि संवेदनशील मुद्दों पर भारत की स्थिति और विचार कम से कम समय में अधिक से अधिक देशों में पहुंचने चाहिए। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य अल-जजीरा, बीबीसी, सीएनएन, सीसीटीवी आदि की तरह विश्व भर में भारतीय स्थिति को प्रसारित करना है। इसमें मौजूदा डीडी न्यूज चैनल को डीडी इंडिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज और कार्यक्रम शुरू करने होंगे। डीडी इंडिया के काफी देशों में दर्शक हैं।

## भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग

भारत सरकार ने 2002 में मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की स्थापना के लिए नीति दिशा निर्देशों को मंजूरी दी। ये दिशानिर्देश 2006 में बदले गए और नए दिशानिर्देशों को मंजूरी दी गई। इनमें पात्रताका दायरा बढ़ाकर नागरिक समितियों और स्वैच्छिक संगठनों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू), आईसीए संस्थाएं, कृषि विज्ञान केंद्रों, पंजीकृत समितियों/स्वायत्त निकायों सोसायटीज एक्ट के तहत पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट आदि को भी शामिल कर लिया गया। प्रामाणिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय ने कार्य समूह का गठन किया है, ताकि ये संस्थाएं अपने रेडियो स्टेशन स्थापित कर सकें। कार्य समूह ने सुझाव दिया है कि प्रामाणिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार के पेशेवर रूप से कार्य करने वाली सामुदायिक रेडियो सहयोग स्कीम (सीआरएसएस) स्थापित करनी चाहिए।

# अध्याय-2

## परिव्यय और परिणाम/लक्ष्य का विवरण

## सूचना क्षेत्र

## विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

*(करोड़ रुपये में)*

| क्र. स. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य परिणाम | परिव्यय 2012-13 | | | परिमाणनीय/ हस्तांतरणीय/ वास्तविक प्रतिफल | परिमाणनीय/ हस्तांतरणीय वास्तविक प्रतिफल | प्रक्रिया/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | प्लान योजना का नाम | | 4 (i) गैर-योजना बजट | 4 (ii) योजना बजट | 4 (iii) पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन | | | | |
| 1 | विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम अवधारणा और प्रसार | 1. स्थापना<br>2. प्रदर्शनी<br>3. डिस्प्ले वर्गीकृत<br>4. रेडियो स्पॉट<br>5. मुद्रित प्रचार वितरण<br>6. बाह्य प्रचार | 27.66<br>1.85<br>32.42<br>2.00<br>2.40<br>-<br>1.00 | —<br>4.00<br>38.00<br>45.00<br>7.00<br>-<br>6.00 | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | —<br>500<br>15000<br>4800<br>180<br>—<br>250 | सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक आर्थिक उत्थान के बारे में विभिन्न माध्यमों-बाह्य प्रचार, रेडियो, दूरदर्शन, समाचारपत्र और पोस्टर/ पुस्तिकाओं के जरिए प्रचार करने से जन समुदाय में जागरूकता पैदा होगी और विकास में उनकी भागीदारी को प्रेरित किया जा सकेगा। | आवश्यकता अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य किए जाएंगे। | |
| | | **कुल (1)** | **67.33** | **100.00** | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | डीएवीपी का आधुनिकीकरण | 1.कम्प्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण<br>2.कार्यालय ढांचा<br>3.मानव संसाधन विकास<br>**कुल ( 2 )** | | —<br>10.00<br>—<br>**100.00** | —<br>—<br>— | —<br>—<br>— | कंप्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण, कार्यालय ढांचा और मानव संसाधान विकास | | |
| | | कुल **( 1 और 2 )** | **67.33** | **110.00** | | | | | |

# क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय
## बजट परिव्यय 2011-12 की तालिका

*(लाख रुपये में)*

| क्र. सं. | योजना/ कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/ परिणाम | परिव्यय 2011-12 | | | मात्रात्मक लाभ/उत्पादन वास्तविक भौतिक | प्रदर्शित परिणाम | प्रक्रिया/ समयबद्धता | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4(i) | 4(ii) | 4(iii) | | | | |
| | | | गैर योजना बजट | योजना बजट (अनुमोदित) राजस्व | पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन वित्त | | | | |
| I. | विशेष आउटरीय कार्यक्रम | स्कीम का उद्देश्य नेताओं/ संसाधन व्यक्तियों की राय से परिचित कराना जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों से युवा सम्मिलित हैं जो देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे विकास कार्यों से सम्बद्ध हैं। (1 कार्यक्रम में 2 क्षेत्रीय यूनिट प्रत्येक में कार्यरत इस ग्रुप में सामाजिक कार्यकर्ता, गैर-सरकारी संगठन, किसान, दस्तकार, स्कूलों के अध्यापक और छात्र आदि शामिल हैं। | | 1.62 | — | 600 कार्यक्रम | आयोजित यात्रा में सम्मिलित सदस्य केन्द्रीय सरकार की नीतियों और योजनाओं के संदेश वाहक हो जाते हैं। आयोजित यात्रा के सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में संचालन में विभिन्न कल्याण स्कीमों के बारे में स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाने में सहायक सिद्ध होते हैं। 10 फीडबेक प्रति कार्यक्रम लगभग। | 2 एवं आधा 2012-13 | |
| II. | | विभिन्न कल्याण स्कीमों के बारे में स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाने में सहायक सिद्ध होते हैं। | | 3.14 | | | | 2 एवं आधा 2012-13 | |

*(लाख रुपये में)*

| क्र. सं. | स्कीम/ कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/ परिणाम | परिव्यय 2011-12 | | | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम | अनुमानित परिणाम वास्तविक प्रतिफल | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4(i) | 4(ii) | 4(ii) | | | | |
| | | | गैर-योजना बजट | योजना बजट | पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन | | | | |
| | | हाल ही में लागू सूचना का अधिकार के तहत देश में प्रत्येक नागरिक सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों की जानकारी पा सकता है। | | | - | फिल्म प्रभाग से 60 मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, 12 डी.वी.डी. प्लेयर तथा 34 डिजिटल वीडियो कैमरे, 26 वायरलैस पीए सिस्टम से अधिक से अधिक फिल्में प्राप्त करना। यथासंभव 1 प्रोग्रामर, 1 सहायक प्रोग्रामर तथा 100 डी.ई.ओ., 30 डिजिटल कैमरे, 26 वाहनों को कार्य में लगाए रखना। | उपकरणों का इस्तेमाल लोगों के बीच सूचना संप्रेषण तथा सामाजिक मुद्दों पर शिक्षित करने में होगा। | 2 एवं आधा 2012-13 | |
| III. | | 2013 में 11 कार्यक्रमों का आयोजन, लागत 5 लाख प्रत्येक का | | 0.55 | 0.00 | 45 प्रतिष्ठानों से सूचना प्रदान | सरकार द्वारा गाइड लाइन प्रदान। | 2 एवं आधा 2012-13 का | |
| IV. | 500 गावों में 30,000 भागीदार आउट सोर्स द्वारा | क्षेत्रीय प्रचार विगत 23 वर्षों में पुन: कई गावों का दौरा किया है। | | 1.04 | | राज्य-1 जिला-1 गांव-1,000 कुल 1200 क्षेत्रों का दौरा | 10 फीडबैक लगभग 2400 जमा किया गया | वही | |
| V. | बुनियादी सहयोग सीधे मिलने पर | डी.वी.डी. प्लेयर तथा 34 डिजिटल वीडियो कैमरे, 26 वायरलैस पीए सिस्टम से अधिक से अधिक फिल्में प्राप्त करना। | | 1.66 | | डी.वी.डी. प्लेयर तथा 34 डिजिटल वीडियो कैमरे, 26 वायरलैस पीए सिस्टम से अधिक से अधिक फिल्में प्राप्त करना। | उपकरणों का इस्तेमाल लोगों के बीच सूचना संप्रेषण तथा सामाजिक मुद्दों पर शिक्षित करने में होगा। | वही | |
| | | | | | | | | | |

*(लाख रुपये में)*

| क्र. सं. | योजना/ कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/ परिणाम | परिव्यय 2011-12 | | | मात्रात्मक लाभ/उत्पादन वास्तविक भौतिक | प्रदर्शित परिणाम | प्रक्रिया/ समयबद्धता | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4(i) | 4(ii) | 4(iii) | | | | |
| | | | गैर योजना बजट | योजना बजट ( अनुमोदित ) राजस्व | पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन वित्त | | | | |
| II. | केन्द्रीय सूचना सदन मीडिया के बुनियादी विकास कार्यक्रम | सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और राज्य की राजधानी मिलकर 12वीं पंच वर्षीय योजना के लिए केन्द्रीय सूचना सदन में पिछड़े इलाके 2012-13 में दो क्षेत्र का चिह्नित किया है। | | 0.00 | 2.00 | 600 कार्यक्रम | | | |
| | | कुल | | 8.00 | 2.00 | अनुमति एवं अन्य कार्यों के लिए विगत वर्ष में प्रारूप बना। | | | |
| 1. | लघु कार्य | निर्माण/रिपेयर कार्य पूर्वोत्तर क्षेत्र | 44.00 | — | — | उपकरण के रिपेयर का प्रावधान | यह अवाध कार्य करने में सहायक | | |
| 2. | अन्य चार्ज | सरकार के विभिन्न कार्यों का प्रचार करना | 74.50 | — | — | 46,500 फिल्म शो, 4,968 विशेष कार्यक्रम | कार्यक्रम जागरूकता लाने के लिए | एक्शन प्लॉन कार्यक्रम संगठित और फीडबॅक कार्यक्रम का क्रियावयन पूरे वर्ष चला | |
| 3. | पेट्रोल तेल और लिबरीकेन्ट | ऊपर के अनुसार | 176.35 | — | — | पिछड़े/आदिवासी और सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित | ऊपर के अनुसार | सामान्य कार्यक्रम | |
| 4. | घरेलु यात्रा खर्च | ऊपर के अनुसार | 158.00 | — | — | ऊपर के अनुसार | ऊपर के अनुसार | 0.10 | |

# एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार

*(करोड़ रुपये में)*

| क्र. सं. | स्कीम/ कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/ परिणाम | परिव्यय 2012-13 | | | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता संबंधी | टिप्पणी/ जोखिम घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4(i) | 4(ii) | 4(iii) | | | | |
| | | | गैर-योजना बजट | योजना बजट | पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन | | | | |
| 1. | वेतन ओवरटाइम स्वास्थ्य-व्यय देश में यात्रा भत्ता दफ्तर व्यय | रोजगार समाचार / एम्पलायमेंट न्यूज का प्रकाशन | 26.90 | शून्य | शून्य | अंग्रेजी, हिन्दी तथा उर्दू में एम्पलायमेंट न्यूज/ रोजगार समाचार के 52 साप्ताहिक अंक निकालना | एम्पलायमेंट न्यूज प्रकाशित करके यह एकक निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्ति का उद्देश्य रखता है। (i) केंद्र तथा राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में नौकरियां, यूपीएससी, एसएससी, राष्ट्रीयकृत बैंकों, रेलवे भर्ती बोर्ड तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के परिणामों तथा प्रवेश अधिसूचनाओं/परीक्षा | वार्षिक आधार पर | |

*(करोड़ रुपये में)*

| क्र. सं. | स्कीम/ कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/ परिणाम | परिव्यय 2011-12 | | | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4(i) | 4(ii) | 4(ii) | | | | |
| | | | गैर-योजना बजट | योजना बजट | पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन | | | | |
| | ऑफिस किराया दर और कर<br>अन्य प्रशासनिक व्यय<br>वितरण और सामग्री<br>विज्ञापन और प्रचार<br>व्यवसायिक सेवा<br>अन्य खर्च<br>सूचना तकनीक और ऑफिस व्यय | | | | | | अधिसूचनाओं की जानकारी देना।<br>(ii) स्व-उद्यमिता तथा विभिन्न उभरते क्षेत्रों तथा परम्परागत क्षेत्रों में कैरियर पर लेखों की शृंखला निकालकर रोजगार के आयामों की जानकारी लोगों को देना।<br>(iii) एम्पलायमेंट न्यूज की वेबसाइट के जरिए सरकारी क्षेत्र में रिक्तियों की जानकारी उपलब्ध की जा रही है। वेबसाइट के जरिए आधुनिकतम मूल्य-संबंधित सेवाएं जैसे ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग तथा पाठकों को सीधे ई-मेल पर जानकारी आदि प्रदान की जा रही हैं। | | |
| | **कुल** | | 26.90 | | | | | | |

# भारतीय जनसंचार संस्थान
## परिणाम बजट 2012-13

*(करोड़ रुपये में)*

| क्रम सं | योजना/ कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2012-13 | | | वितरण योग्य/ परिणाम/भौतिक परिणाम | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम का घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 4(i) गैर-नियोजित बजट | 4(ii) योजना बजट | 4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन | | | | |
| 1. | जनसंचार में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान<br><br>भारतीय जन संचार संस्थान | पत्रकारिता/जनसंचार के क्षेत्र में आईआईएमसी द्वारा आयोजित किए गए शोध अध्ययन और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम देश के सामाजिक आर्थिक विकास के साथ गति बनए रखने के लिए उपयोगी है। | 11.42 | — | 04.25 | निम्नलिखित में पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करना :<br>नई दिल्ली और ढेंकानाल में पत्रकारिता (अंग्रेजी); नई दिल्ली में पत्रकारिता (हिन्दी),<br>नई दिल्ली में रेडियो व टीवी पत्रकारिता, विज्ञापन व पब्लिक रिलेशंस और ढेंकानाल में ओड़िया पत्रकारिता (325); पुरुष 155, महिला 170 विकास पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम पुरुष 20, महिला 25;<br>(मंत्रालय की जरूरत के अनुसार)आई आई एस के ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रम (13) पु. 11, म. 2 अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (600-700) पु. 700, म. 100 | निम्नलिखित में पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करना :<br>-पत्रकारिता (हिन्दी) 62<br>- पत्रकारिता (अंग्रेजी) 124 (62+62)<br>-पत्रकारिता (ओड़िया) (23)<br>-एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस (70)<br>-रेडियो व टीवी पत्रकारिता (46)<br>-विकास पत्रकारिता में दो डिप्लोमा कोर्स (40-45)<br>**अल्पकालीन कार्यक्रम**<br>-अल्पकालीन कोर्स/ कार्यशालाएं (600-700)<br>-आई आई एस अधिकारियों के चल रहे कोर्सों को पूरा करना।<br>-शोध अध्ययन (4 से 5 अध्ययन)।<br>**प्रकाशन :**<br>अंग्रेजी में कम्यूनिकेटर और हिंदी में संचार माध्यम जैसी अर्द्धवार्षिक पत्रिकाओं का, वार्षिक रिपोर्ट और छात्रों के लै जर्नलों को प्रकाशित करना। | दो वर्ष के सभी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रियाएं (अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर) जुलाई 2012 तक पूरी हो जायेगी और इसके तुरंत बाद ये पाठ्यक्रम शुरू हो जायेंगे।<br>समय-समय पर अनुसंधान अध्ययन किए जायेंगे।<br>पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जायेगा। | एन आर आई, शारीरिक रूप से विकलांग और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति जैसे कुछ आरक्षित श्रेणियों में 100 प्रतिशत सीटों का नहीं भरना था अन्य संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिलने के कारण या व्यक्तिगत कारणों से आई आई एम सी को छोड़ देने की संभावना भी रहती है। |

*(करोड़ रुपये में)*

| क्रम सं. | योजना/ कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2012-13 | | | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम का घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 4(i) गैर-नियोजित बजट | 4(ii) योजना बजट | 4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन | | | | |
| 2. | अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आईआईएमसी का उन्नयन | अंतर्राष्ट्रीय मानदंडो की स्थापना से जनसंचार में आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जा सकेगा। इससे यह संस्थान मीडिया उद्योग के क्षेत्र में वैश्विक नियुक्तियों के लिए योग्य पेशेवर तैयार किए जा सकेंगे। प्रस्तावित उन्नयन में आईआईएमसी के चार नये केन्द्रों का खोला जाना भी शामिल है। आईआईएमसी उपलब्ध करायेगा:<br>देश के विभिन्न क्षेत्रों में जन संचर के पाठ्यक्रमों के अध्ययन के विसंगतियों को दूर करेगा।<br>योजना आयोग, एसएफसी सूचना और प्रसारण मंत्रालय से 51.50 करोड़ रुपये के सरकारी अनुदान के साथ 62.00 करोड रुपये के कुल परिव्यय के लिये योजना को मंजूरी मिल गई है। यह योजना तीन वर्ष की अवधि अर्थात् मार्च 2013 तक पूरी हो जायेगी | — | 10.00 | — | जनसंचार के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान अध्ययन का संचालन (3-4 अध्ययन) और अर्द्धवार्षिक पत्रिका- अंग्रेजी में कम्युनिकेटर तथा हिन्दी में संचार माध्यम का प्रकाशन।<br>दिल्ली में आईआईएमसी परिसर में मौजूदा इमारत पर अतिरिक्त मंजिल का 100 प्रतिशत निर्माण नई दिल्ली और ढेंकानाल में आईआईएमसी परिसरों में अतिरिक्त भवन में निर्माण ।<br>जम्मू एवं कश्मीर में क्षेत्रीय केन्द्र खोला जाएगा क्षेत्रीय शाखा केरल में भी खुलेगा।<br>आइजोल में पहले लागत के तहत नक्शा, सर्वे, जमीन का समतल करने का काम हो गया है।<br>महाराष्ट्र के अमरावती में भी पहले लागत के तहत नक्शा, सर्वे इत्यादि का कार्य प्रगति पर है। | अक्टूबर 2012 में आरंभ होगा (डीडीए की अनुमति अगर मिल गई)।<br>जून 2012 में आरंभ होगा।<br>अगस्त 2012 में आरंभ होने पर स्थायी कैम्पस का निर्माण।<br>मार्च 2013 में कार्य पूरा होगा।<br>मार्च 2013 में कार्य पूरा होगा। | इमारत के निर्माण के लिए जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार यह प्रक्रियाएं पूरी हो गई है और दिल्ली में आईआईएमएसी परिसर में अतिरिक्त मंजिल पर निर्माटा 2012-13 में पूरा होगा और जून 2012 तक पूरा हो जायेगा। मार्च 2012 तक परियोजना प्रबंधन, इंजीनियरिंग, संरचनात्मक डिजाइन के लिए कंसल्टेंटों तथा कंट्रैक्टर की नियुक्ति हो जायेगी<br>मार्च 2013 में कार्य पूरा होगा।<br>2013 में कार्य पूरा होगा। | डीडीए की मंजूरी से अतिरक्ति मंजिल का निर्माण कार्य आरंभ होगा।<br>स्थान मिलने पर अस्थायी घर और स्थायी कैम्पस जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा।<br>स्थान मिलने पर अस्थायी घर और स्थायी कैम्पस केरला में बनाया जाएगा।<br>सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से उचित फंड उपलब्ध करवाना। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जमीन के हस्तांतरण होने पर स्थाई केम्पस का निर्माण होगा। |
| | | **कुल** | **11.42** | **11.00** | **4.25** | | | | |

* कोष्ठक के अंक छात्रों के दाखिले बताते हैं।

# फोटो प्रभाग

## गैर-योजना

*(करोड़ रुपये में)*

| क्र. सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2012-13 | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | प्रलेखन, प्रचार तथा अन्योन्य संदर्भ, फोटो द्वारा सरकारी विकास कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार | फोटो द्वारा सरकार के विकास कार्य को संग्रहित करना हैं। | गैर योजना 4.06 | नियमित फोटो प्रलेखन भावी पीढ़ियों के लिए परिवर्तन की दृश्य रिपोर्ट होगा। संभवत: ये अत्यधिक मूल्यवान प्रलेख होंगे जिन्हें जब जरूरत होगी दूबारा प्रयोग किया जाएगा। | यह प्रलेखन अन्योन्य संदर्भ द्वारा देश के सही इतिहास को जानने में मदद करेगा। | 2012-13 के दौरान | — |

*(करोड़ रुपये में)*

**योजना**

| क्र. सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2012-13 | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समय सीमा | टिप्पणी/ जोखिम घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | फोटोग्राफी की राष्ट्रीय केन्द्र उत्तर-पूर्व, के लिए विशेष अभियान | सरकार की फोटो डक्यूमेंटेंशन कार्यक्रम के तहत डिजिटल डाटा को अपलोड करना ताकि पूरी फोटो का लेखा जोखा ऑनलाइन उपलब्ध है साथ ही राष्ट्रीय फोटो पुरस्कार नए और उपरते हुए फोटोग्राफर हैं। | 0.50 | डिटिजल डाटा को अपलोड करना ताकि पूरी फोटो का लेखा जोखा ऑन लाइन उपलब्ध हो। साथ ही कार्यशाला कांफ्रेस इत्यादि का आयोजन करते रहते हैं और डिजिटलाइजेशन उच्च श्रेणी का करना और फोटो का डक्यूमेंटेशन पूर्वोत्तर राज्यों में। | भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम के साथ अभिलेखागार के फोटो को रिवाइवल करना | वार्षिक | — |

# भारतीय प्रेस परिषद

*(रुपये करोड़ में)*

| क्र. सं. | योजना एवं कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/ परिणाम | परिव्यय 2012-13 | | | मात्रात्मक/निष्पादन प्रतिफल | अनुमानित परिणाम | प्रक्रिया/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4(i) | 4(ii) | 4(iii) | | | | |
| | | | गैर-योजना बजट | योजना बजट | पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन | | | | |
| 1. | एक अर्द्ध-न्यायिक संस्था होने के कारण परिषद कोई स्कीम नहीं चला रही है। | प्रेस की आज़ादी का संरक्षण और भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेन्सियों के स्तर को बनाए रखते हुए उसमें सुधार लाना | 5.32 | उपलब्ध नहीं क्योंकि योजना बजट के लिए प्रस्ताव नहीं आया। | परिषद पंजीकृत समाचारपत्रों, पत्रिकाओं और समाचार एजेन्सियों से प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत शुल्क वसूल करती है और जमाराशियों पर ब्याज कमाती है। वर्ष 2011-12 में परिषद का लक्ष्य लेवी और अन्य प्राप्तियों के शुल्क के रूप में 119.50 लाख रुपए इकट्ठा करके भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता को कम करना है। | चूंकि प्रेस परिषद् के कार्य अर्द्धन्यायिक प्रकृति के हैं और यह प्रेस के आचरण संबंधी स्तर का नियामन करती है, अत: इसके भौतिक प्रतिफल/परिणामों को आंकना संभव नहीं है। | चूंकि प्रेस परिषद् के कार्य अर्द्धन्यायिक प्रकृति के हैं और यह प्रेस के आचरण संबंधी स्तर का नियामन करती है, अत: इसके भौतिक प्रतिफल/परिणामों को आंकना संभव नहीं है। | यह वादियों द्वारा आवश्यक शर्तें पूरा करने और परिषद द्वारा जांच पूरी करने पर निर्भर करता है। | शिकायतों के निपटारे में कोई जोखिम शामिल नहीं है। |

# पत्र सूचना कार्यालय

योजना

## परिव्यय तथा परिणाम/लक्ष्य का विवरण

*(करोड़ रुपये में)*

| क्र. सं. | कार्यक्रम योजना का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2012-13 योजना बजट | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र की स्थापना | राष्ट्रीय पत्र केन्द्र का निर्माण राईसेना रोड, 7-E नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के साथ निर्माण हो रहा है जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों को एक स्थान देगा। | 9.00 | परियोजना अगस्त 2012 तक समाप्त कर अधिग्रहण हेतु तैयार किया जायेगा। | परियोजना अगस्त 2012 तक समाप्त कर अधिग्रहण हेतु तैयार किया जायेगा। | 31.8.12 |
| | | | **नई योजना** | | | |
| 2. | मीडिया आउटरीच कार्यक्रम और विशेष घटना का प्रचार। यह योजना 3 भागों में शामिल किया गया है। | | 9.00 | | | |
| i | मिडिया आउटरीच कार्यक्रम | सार्वजनिक सूचना अभियान चलाकर प्रेस वार्ताएं आयोजित कर सफलती की कहानियां जारी और प्रेस दौरे आयोजित | 11.90 | 136 जनसूचना अभियान 5 मिडिया से बातचीत का 10 प्रेस दौरा आयोजित करना | 100 % | अंतिम प्रारुप देना |

*(करोड़ रुपये में)*

| क्र. सं. | कार्यक्रम योजना का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2010-11 योजना बजट | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ii | प्रवासी भारतीय दिवस समारोह | पीआईबी विशेष प्रत्यायन हेतु अधिकारी भेजता है। वे पत्रकारों के लिए तैयार मीडिया सेंटर के लिए कंप्यूटर आदि सुविधाएं भी जुटाते हैं। | 0.01 | प्रवासी दिवस समारोह में पीआईबी विशेष प्रत्यायन के लिए अधिकारी भेजता है। वे पत्रकारों के लिए तैयार मीडिया सेंटर के लिए कंप्यूटर आदि सुविधाएं भी जुटाते हैं। | प्रवासी दिवस समारोह में पीआईबी विशेष प्रत्यायन के लिए अधिकारी भेजता है। वे पत्रकारों के लिए तैयार मीडिया सेंटर के लिए कंप्यूटर आदि सुविधाएं भी जुटाते हैं। | **चौथी तिमाही** कालम 5 में वर्णित सभी गतिविधियां चौथी तिमाही में की जाएंगी क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस समारोह हर वर्ष नई दिल्ली में जनवरी में होता है। |
| iii | भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह | मौके पर मीडिय केंद्र की स्थापना करके पत्रकारों को विशेष प्रत्यायन, प्रेस वार्ताएं, विज्ञाप्तियां, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन, अखबार, फोटोकापी आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना। | 0.09 | मौके पर मीडिया केंद्र खोलना, सुविधाओं की व्यवस्था करना और पत्रकारों को विज्ञप्तियों, इंटरनेट, फोन, कंप्यूटर, फोटो कॉपी आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना | मौके पर मीडिया केंद्र खोलना, सुविधाओं की व्यवस्था करना और पत्रकारों को विज्ञप्तियों, इंटरनेट, फोन, कंप्यूटर, फोटो कॉपी आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना | **तीसरी तिमाही** कालम 5 में वर्णित सभी गतिविधियां तीसरी तिमाही में शुरू की जाएंगी। फिल्म समारोह हर साल नवंबर-दिसंबर में गोवा में आयोजित होता है। |
| 3 | संचार का आधुनिकीकरण और सुचना डिसमिशन प्रणाली | पीआईबी में आई टी को मजबूत करना | 2.50 | (क) विडियो कॉफ्रेसिंग बेवसाइड प्रबंधन संबंधी सेवाओं को अपग्रेड करना<br>(ख) पंजीकरण साफ्टवेयर को बनाना<br>(ग) मोबाइल उपकरण की सुविधा ऑफिस में<br>(घ) आधुनिक एचआर की सुविधा ऑफिस में<br>(ड: सामाजिक मीडिया सेल की स्थापना और आईटी बुनियादी सुविधा ऑफिस में हो इसकी पहल | आईटी का अधिकार अझिकारियों को दिया गया ताकि वह सूचना पहुंचाने और समन्वय स्थापित करने में सक्षम हों।<br><br>आईटी की मूलभूत सुविधा को अपग्रेड करना।<br><br>वेबसाइड का तकनीकी अपग्रेड और साफ्टवेयर | **चौथी तिमाही** कालम 5 में वर्णित सभी गतिविधियां चौथी तिमाही में की जाएंगी क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस समारोह हर वर्ष नई दिल्ली में जनवरी में होता है। |

*(करोड़ रुपये में)*

| क्र. सं. | कार्यक्रम योजना का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2012-13 योजना बजट | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ii | आपातकाल के लिए 24X7 मीडिया कंट्रोल रूम | आपातकाल के लिए 24X7 फीडबैक सिस्टम शुरू किया गया है जिसमें राष्ट्रीय डायरी वेबसाइड, राष्ट्रीय रेडियो, राष्ट्रीय टीवी चैनल समाचार पत्रों पर अपनी 24 घंटे नज़र रखते हैं। यहां 3 शिफ्टों में कार्य होता है। | 2.50 | आपातकाल के लिए 24X7 मीडिया कंट्रोल रूम<br>आपातकाल के लिए 24X7 फीडबैक सिस्टम शुरू किया गया है जिसमें राष्ट्रीय डायरी वेबसाइड, राष्ट्रीय रेडियो, राष्ट्रीय टीवी चैनल समाचार पत्रों पर अपनी 24 घंटे नज़र रखते हैं। यहां 3 शिफ्टों में कार्य होता है। | - | पूरे वर्ष भर |
| | **कुल** | | **26.00** | | | |

# प्रकाशन विभाग

**गैर योजना**

*(करोड़ रुपये में)*

| क्र. सं. | योजना/ कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/ परिणाम | परिव्यय 2012-13 | | परिमाणात्मक कार्य/ भौतिक उत्पादन | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4 (I) | 4 (II) | | | | |
| | | | गैर-योजना बजट | पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन | | | | |
| 1. | - | पत्रिकाओं व पुस्तकों को निकालना | 22.70 | - | 20 पत्रिकाएं और 100 से अधिक पुस्तकों को निकालना। दिल्ली में और दिल्ली के बाहर 150 पुस्तक प्रदर्शनियां/मेले आयोजित किए जाएंगे। | प्रकाशन विभाग का लक्ष्य है निम्नलिखित परिणामों को प्राप्त करना :<br>1. राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषयों पर पुस्तक छापना जिन पर अन्य प्रकाशन भवनों ने ध्यान नहीं दिया हो ऐसी पुस्तकों को कम कीमतों पर आम लोगों को उपलब्ध कराना।<br>2. विविधता में एकता, साम्प्रदायिक सद्भावना, राष्ट्रीय अखंडता इत्यादि की विचारधारा को मजबूत करना और बढ़ावा देना। | वार्षिक आधार पर | — |

# वित्तीय अपेक्षण—प्रयोजननुसार वर्गीकरण

*(करोड़ रुपये में)*

| क्र.सं. | योग भाग | 2010-2011 की वास्तविकता | | | 2011-12 के लिए बजट प्राप्ति | | | 2011-12 पुनरावृत्ति आगमन | | | 2012-13 के बजट आगणन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल |
| 1 | वेतन | - | 1329.11 | 1329.11 | - | 1350. 00 | 1350.00 | - | 1280.00 | 1280.00 | - | 1380.00 | 1380.00 |
| 2 | मजदूरी | - | Nil | Nil | - | NIL | NIL | - | NIL | NIL | - | NIL | NIL |
| 3 | ओवरटाइम भत्ता | - | 3.27 | 3.27 | - | 6.00 | 6.00 | - | 4.00 | 4.00 | - | 6.00 | 6.00 |
| 4 | स्वास्थ्य व्यय | - | 15.92 | 15.92 | - | 15.00 | 15.00 | - | 15.00 | 15.00 | - | 15.00 | 15.00 |
| 5 | घरेलू यातायात व्यय | - | 12.50 | 12.50 | - | 15.00 | 15.00 | — | 16.00 | 16.00 | 22.00 | 17.00 | 39.00 |
| 6 | विदेश यात्रा भत्ता | Nil | NIL | NIL | Nil | 15.00 | 15.00 | - | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 27.00 |
| 7 | दफ्तर व्यय | 9.82 | 171.49 | 181.31 | 10.00 | 140.00 | 150.00 | 10.00 | 130.61 | 140.61 | 155.00 | 140.00 | 295.00 |
| 8 | किराया, दर और कर | - | 10.95 | 10.95 | - | 19.00 | 19.00 | - | 80.39 | 80.39 | - | 15.00 | 15.00 |
| 9 | प्रकाशन | - | 403.00 | 403.00 | - | 353.00 | 353.00 | - | 353.00 | 353.00 | 6.00 | 355.00 | 361.00 |
| 10 | अन्य प्रशासनिक व्यय | - | 25.26 | 25.26 | - | 25.00 | 25.00 | - | 25.00 | 25.00 | 10.00 | 30.00 | 40.00 |
| 11 | वितरण और सामग्री | - | 15.95 | 15.95 | - | 14.00 | 14.00 | - | 10.00 | 10.00 | - | 14.00 | 14.00 |
| 12 | विज्ञापन और प्रचार | - | 210.77 | 210.77 | - | 163.00 | 163.00 | - | 163.00 | 163.00 | 9.00 | 165.00 | 174.00 |
| 13 | व्यावसायिक सेवा | - | 41.58 | 41.58 | - | 45.00 | 45.00 | - | 45.00 | 45.00 | 6.00 | 50.00 | 56.00 |
| 14 | अन्य खर्च | - | 89.42 | 89.42 | - | 55.00 | 55.00 | - | 56.00 | 56.00 | - | 60.00 | 60.00 |
| 15 | सूचना तकनीक आफिस व्यय | - | 7.98 | 7.98 | - | 8.00 | 8.00 | - | 8.00 | 8.00 | - | 8.00 | 8.00 |
| 16 | मशीन एवं उपकरण | 13.80 | __ | 13.80 | 85.00 | - | 85.00 | 44.00 | - | 44.00 | - | - | - |
| | **कुल** | **23.60** | **2337.20** | **2360.82** | **95.00** | **2223.00** | **2318.00** | **54.00** | **2196.00** | **2250.00** | **220.00** | **2270.00** | **2490.00** |

# परिणाम बजट 2012-13

*(करोड़ रुपये में)*

| क्रं. सं. | स्कीम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | 2012-13 के लिए अनुमोदित परिव्यय (रुपया करोड़ में) योजना बजट | 4i बजट | वास्तविक प्रतिफल | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/समयबद्धता | टिप्पणियां/ जोखिम घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रकाशन विभाग एवं रोजगार समाचार का आधुनिकीकरण स्वचालन तथा उन्नतिकरण | | 2.00 | पूरक एवं अन्य बजट स्त्रोत | | | | |
| | विशेष विषय पर किताबों को जारी करना | हमारे प्रकाशन में विषय की उत्कृष्टता और स्तर बढ़ाना | | | 5 किताबों की व्यवस्था | वास्तविक शोधपरक विशेष विषयों की किताबें | वार्षिक आधार | |
| | डिजिटल अभिलेखागार और प्रकाशन विभाग की ई-बुक की तैयारी | डिजिटिलाइजेशन और प्रकाशन विभाग की ई-बुक प्रकाशन विभाग की | | | डिजिटिलाईजेशन 60 पुस्तकों का | डिजिटल अभिलेखागार और प्रकाशन विभाग की पुस्तकों का ई-बुक बनाने की तैयारी | वार्षिक आधार | |
| | प्रभाग के प्रबंधन हेतु कम्प्यूटरीकरण, रायल्टी एवं अन्य गतिविधियां, साथ ही व्यापारिक कार्य के प्रबंधन हेतु आधुनिकीकरण | आधुनिकीकरण कम्प्यूटरीकरण स्वचलन तथा उन्नतिकरण द्वारा रायल्टी प्रबंधन | | | सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का समावेश इससे रॉयल्टी प्रबंधन में सहायता | कर्मचारी की कमी के कारण पुस्तकों का मुद्रण/पुनर्मुद्रण संबंधी निर्णय लेने में प्रभावी तीव्रता एवं प्रभावी लेखा। | वार्षिक आधार | |

*(करोड़ रुपये में)*

| क्रं. सं. | स्कीम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | 2012-13 के लिए अनुमोदित परिव्यय (रुपया करोड़ में) 4i नॉन प्लान बजट | प्लान बजट | वास्तविक प्रतिफल | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/समयबद्धता | टिप्पणियां/ जोखिम घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ऑफिस सुविधाएं एवं प्रबंधन का आधुनिकीकरण | अपग्रेड एवं आधुनिकीकरण की सुविधाएं | | | 3-5 विभाग/रूम का अपग्रेड और आधुनिकीकरण | अंतिम परिव्यय का विकास, मजबूती प्रदान कर वर्तमान प्रतियोगिता का सामना कर रहा है। | वार्षिक आधार | |
| | रोजगार समाचार का आधुनिकीकरण स्वचालन तथा उन्नतिकरण | डिजिटल और डिजिटल अभिलेखागार का निर्माण | | | एप्लॉइमेंट न्यूज को समर्पित वेबसाइट के जरिये हिंदी और अंग्रेजी में रोजगार अवसरों संबंधी सूचना का प्रसार | विदेश के प्रकाशकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाजार प्रकाशन विभाग की उपस्थित मुख्य प्रकाशन रूप में है खासकर गांधी साहित्य में। | वार्षिक आधार | |
| | अंतर्राष्ट्रीय बुक मेले में भागीदारी | प्रकाशन ही शो केस इस विभाग का है | | | 5 मुख्य अंतरराष्ट्रीय बुक-मेले में भागीदारी | कार्यक्रम का आयोजन अधिकतम आयाम प्रदान करता है साथ ही लोगों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देता है। | वार्षिक आधार | |
| | पूर्वोत्तर भाग-किताब प्रदर्शनी और आयोजन और विशेष कार्यक्रम किताबों को प्रोत्साहन, सेमिनार और कार्यशाला, छात्राओं और लेखकों, विद्वानों के लिए | किताब की प्रदर्शनी और किताब मेला आयोजन और विशेष कार्यक्रमों का आयोग | | | तीन कार्यक्रम का प्रदर्शनी और आयोजन दो सेमिनार, कार्यशाला का कार्यक्रम, छात्राओं, लेखकों और विद्वान के लिए | कर्मचारी की कमी के कारण पुस्तकों का मुद्रण/पुनर्मुद्रण संबंधी निर्णय लेने में प्रभावी तीव्रता एवं प्रभावी लेखा। | वार्षिक आधार | |
| | | **कुल** | **2.00** | **शून्य** | | | | |

# भारत के समाचारपत्र पंजीयक का कार्यालय
## वित्तीय परिव्यय, वास्तविक प्रतिफल तथा अनुमानित परिणाम

**गैर-योजना**

*(करोड़ रुपये में)*

| क्र. सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | लक्ष्य/ उपलब्धिां | परिव्यय 2012-13 | | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | गैर योजना बजट | पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | वेतन, ओवर टाइम, चिकित्सीय व्यय, यात्रा व्यय, कार्यालय खर्च, प्रकाशन | कार्यालय के विभिन्न कार्यों को पूरा करना जैसे—शीर्षक जारी करना, पंजीयक प्रमाणपत्र जारी करना, अखबारी कागज के आयात के लिए योग्यता प्रमाणपत्र जारी करना, रियायती शुल्क पर प्रिंटिंग मशीनरी के आयात के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करना, प्रिंट मीडिया के विकास पर वार्षिक रिपोर्ट 'प्रेस इन इंडिया' का प्रकाशन इत्यादि। | 4.17 | शून्य | शीर्षक सत्यापन,* पंजीकरण मामले,* समाचार पत्र प्रमाणपत्र,* अखबारी कागज के आयात के लिए प्रकाशकों को पात्रता प्रमाणपत्र*, प्रिंटिंग मशीन के आयात के लिए प्रकाशकों को अनिवार्यता प्रमाणपत्र*, प्रसार के दावों की समीक्षा* प्रकाशकों से प्राप्त आवेदन पत्रो/प्रार्थनाओं पर आधारित* | इन गतिविधियों से पीआरबी अधिनियम 1867 में निर्धारित प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। इसके अतिरिक्त मीडिया परिदृश्य के प्रभाव का आकलन किया जा सकता है। प्रसार दावों की समीक्षा के बाद आरएनआई द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के आधार पर इन प्रकाशनों को डीएवीपी द्वारा सरकारी विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इससे प्रिंट मीडिया द्वारा सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार करने में मदद मिलेगी। | सिटीजन चैप्टर में तय मानकों के अनुसार | लागू नहीं |

# भारत के समाचारपत्र पंजीयक का कार्यालय

## योजना

*(करोड़ रुपये में)*

| क्र. सं. | स्कीम/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2012-13 | | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | गैर योजना बजट | पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आरएनआई का सुदृढ़ीकरण | पीआरबी कार्य में सक्षमता, लोगों के त्वरित कार्य करवाने के लिए पीआरबी अधिनियम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। डिजिटल द्वारा ई-फाइल कर वार्षिक स्टेटमेंट और पंजीकरण किया जा रहा है। ताकि पीआरबी अधिनियम का सुचारू रुप से कार्यान्वयन हो सके। इसके साथ ही लोगों को त्वरित, सक्षम पारदर्शी सेवा उपलब्ध हो और प्रसार संख्या की जांच कड़ाई से हो। | 0.30 | शून्य | ई-फाइलिंग द्वारा समय की बचत और ऑन लाइन पंजीकरण से लाभ प्राप्त कर रहे है। | शीर्षक सत्यापन, शीर्षक पंजीकरण, प्रसार दावों के सत्यापन आदि के लिए लोग आर एन आई के मुख्यालय नई दिल्ली आते थे, अब वे लोग आरएनआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में ये कार्य करा सकते हैं। | जैसा कि नियम है। | लागू नहीं |

# गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग
## ( परिणाम बजट 2011-12 )

*(करोड़ रुपये में)*

| क्र. सं. | योजना/ कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/ परिणाम | परिव्यय 2012-13 | | | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4(i) | 4(ii) | 4(iii) | | | | |
| | | | गैर-योजना बजट | योजना बजट | पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन | | | | |
| 1. | **गैर-योजना** | | 200.00 | | | | | | |
| | अ) मास मीडिया के विविध पहलुओं से सम्बंधित प्रलेखन सेवाओं को प्रदर्शित करना | मास मीडिया में इसकी सावधिक सेवाओं के माध्यम से इसकी घटनाओं और प्रवृत्तियों की सूचना एकत्रित, व्याख्यायित और प्रचार-प्रसारित करना | बजट में अलग से प्रावधान नहीं। व्यय सामान्य तौर पर कार्यालय खर्च से पूरा किया जाता है (0.28 लाख रुपये) | - | - | इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 के दौरान प्रभाग का लक्ष्य 56 प्रलेखन सेवाओं को लाने का है। | इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 के दौरान प्रभाग का लक्ष्य 56 प्रलेखन सेवाओं को लाने का है। | समयावधि के अनुसार | कोई विशेष जोखिम नहीं है। |
| | ब) भारत में मास मीडिया का संकलन और संपादन—एक वार्षिक प्रकाशन | मास मीडिया पत्रकारिता से संबंधित मीडिया कर्ताओं, मीडिया नीति-निर्धारकों, | - वही - | - | - | भारत में मास मीडिया-इन इंडिया का **23वां** संस्करण प्रकाशित करना। | भारत में मास मीडिया-इन इंडिया का **23वां** संस्करण प्रकाशित करना। | समयावधि के अनुसार | - वही - |

*(करोड़ रुपये में)*

| क्र. सं. | योजना/ कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/ परिणाम | परिव्यय 2012-13 | | | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4(i) | 4(ii) | 4(iii) | | | | |
| | | | गैर-योजना बजट | योजना बजट | पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन | | | | |
| | | अध्यापकों और छात्रों को सूचना का बहुमूल्य स्रोत प्रदान करता है | | | | | | | |
| | स) इंडिया एक वार्षिक संदर्भ का संकलन और संपादन | देश के विविध पहलुओं इसके भौगोलिक और जन सांख्यिकीय आकारों, राज्य व्यवस्था, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों को सूचना का बहुमूल्य स्रोत प्रदान करता है। | - वही - | - | - | इंडिया — एक वार्षिक संदर्भ - 2013 को निकालना | - वही - | - वही - | - वही - |

*(लाख रुपये में)*

| क्र. सं. | योजना/ कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/ परिणाम | परिव्यय 2011-12 | | | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4(i) | 4(ii) | 4(iii) | | | | |
| | | | गैर-योजना बजट | योजना बजट | पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन | | | | |
| | द) घटनाक्रमों की पाक्षिक डायरी तैयार करना | मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दैनिक महत्वपूर्ण विकास की जानकारी देना। | - वही - | - | - | इस योजना के अंतर्गत कार्यालय ने 24 पाक्षिक 'डायरी ऑफ इवेंट्स' निकालने का लक्ष्य रखा है। | - वही - | कार्यक्रम के अनुसार | - वही - |
| | **योजना** | | | 0.25 | | | | | |
| 1. | राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार | किसी विशेष मीडिया संबंधी मुद्दे पर शोध किया जाएगा और जनता की राय ली जाएगी। ताकि नई नीति बनाई जा सके, जिसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अपनी मीडिया यूनिटों के माध्यम से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर लागू कर सके। | - | 0.25 | - | इस योजना के तहत विभाग ने 14 राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार एक हिन्दी और सात अंग्रेजी प्रिंट मीडिया में पाया है। | प्रलेखन सेवाओं के प्रकाशन से मीडिया यूनिट जैसे हितधारकों को विविध प्रकार की जानकारी हासिल करने में लाभ होगा। | - वही - | - वही - |

# गीत एवं नाटक प्रभाग

## वार्षिक योजना 2012-13

### वर्ष 2010-11 के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां

परिव्यय और परिणामों/लक्ष्यों का विवरण (2010-11) (परिणाम बजट 2010-11 के अनुसार) तथा वास्तविक उपलब्धि (योजना और गैर योजना)

*(लाख रुपये में)*

**वित्तीय**

| बजट अनुमान 2010-101 | | | वास्तविक | व्यय | 2010-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल |
| 627.00 | 2224.00 | 2851.00 | 599.18 | 2187.85 | 2787.03 |

* पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 150.00 लाख रुपये का समावेश वास्तविक कार्य निष्पादन इस प्रकार है।

# गीत एवं नाटक प्रभाग

## वार्षिक योजना 2011-12

### योजना

*(लाख रुपये में)*

| क्र. सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/ परिणाम | वर्ष 2010-11 का परिव्यय | मात्रात्मक / वास्तविक परिणाम | 31-3-11 को उपलब्धियां डब्ल्यू आर टी कॉल (5) | टिप्पणी/ जोखिम घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| 1. | ग्रामीण भारत के लिए जीवंत कला एवं संस्कृति | प्रचार कार्यक्रम | 627.00 | 8585.00 | 11639.00 | 599.18 |
| | **घटकवार विवरण** | | | | | |
| | अ. पर्वतीय/जनजातीय/रेगिस्तानी/ संवेदनशील और सीमा क्षेत्रों में आईसीटी गतिविधियां | - वही - | 271.00 | 4200.00 | 4971.00 | 262.33 |
| | ब. 76 चिन्हित जिलों में गतिविधियां | - वही - | 44.00 | 880.00 | 1680.00 | 43.31 |
| | स. न्यूनतम साझा कार्यक्रम का प्रचार | - वही - | 40.00 | 620.00 | 1274.00 | 39.78 |
| | द. जम्मू-कश्मीर व पूर्वोत्तर में विशेष गतिविधियां | - वही - | 156.00 | 2920.00 | 3678.00 | 155.87 |
| | ध. राष्ट्रीय/सामाजिक मुद्दों पर रंगमंचीय कार्यक्रम | - वही - | 100.00 | 65.00 | 36.00 | 94.38 |
| | च. अनुसंधान/विकास एवं प्रशिक्षण | | 07.00 | - | - | - |
| | छ. आईआईएमसी द्वारा प्रभाव मूल्यांकन | | 04.00 | - | | - |
| | ज. गीत एवं नाटक प्रभाग का आधुनिकीकरण (पूंजी) | - वही - | 05.00 | - | | 03.51 |
| | **कुल** | | **627.00** | **8685.00** | **11639.00** | **599.18** |

## योजना/गैर योजना/अन्य मंत्रालय/विभाग

**2010-11 के दौरान भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :**

| क्र.सं. | विवरण | लक्ष्य कार्यक्रम | कार्यक्रम उपलब्धियां | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| **(क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय कोष के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रम** | | | | |
| 1. | गैर योजना | 5100.00 | 5415+1051 कार्यक्रम मतदाताओं की जागरुकता हेतु | |
| 2. | योजना | 8685.00 | 11639.00 | |
| **(ख) अन्य मंत्रालयों/विभागों के कोष से चलाए जा रहे कार्यक्रम** | | | | |
| 3. | (i) व्यापार मेला, नई दिल्ली<br>(ii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | 82.00 | 82.00 | |
| 4. | आयोडीन युक्त नमक | 3015.00 | 4526.00 | |
| 5. | नेको (राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रम) रेड रिबन एक्सप्रेस सहित | 856.00 | 1127.00 | |
| 6. | एन एफ एस एम | 2060.00 | 2097.00 | |

## (ii) वर्ष 2011-12 (सं.अ.) के लिए बजट आवंटन

| योजना | गैर योजना | कुल (लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| 600.00* | 2274.00 | 2874.00 |

* पूर्वोत्तर राज्यों के 115.00 लाख रुपये समेत

# भौतिक कार्यनिष्पादन योजना

परिव्यय और परिणाम/लक्ष्यों का विवरण (परिणाम बजट 2011-12 के अनुसार) और वास्तविक उपलब्धि

*(करोड़ रुपये में)*

| क्र. सं. | योजना/ कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/ परिणाम | वित्तीय परिव्यय (बी ई 2011-12) | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | 31-12-10 को कॉलम (4) और (5) के अनुसार उपलब्धि | टिप्पणी/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | सजीव कला और संस्कृति कार्यक्रम गरीबों के लिए | प्रचार कार्यक्रम | 600.00 | 8800.00 | 2011-12 | 11524.00 | |

# वार्षिक योजना
## घटकवार विवरण

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | आईसीटी का पहाडी/ आदिवासी/रेगिस्तान/ संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों मे गतिविधि | प्रचार कार्यक्रम | 277.00 | 4400.00 | 2011-2012 | 5934 |
| B | एलडब्ल्यूई क्षेत्रों/ चिह्नित 83 जिलों में गतिविधि | वही | 46.00 | 920.00 | वही | 1631 |
| C | कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत प्रचार | वही | 43.00 | 670.00 | वही | 861 |
| D | विशेष गतिविधि पूर्वोत्तर एवं जम्मू कश्मीर राज्य में | वही | 100.00 | 65.00 | वही | 56 |
| E | शोध विकास एवं प्रशिक्षण | वही | 10.00 | - | वही | - |
| F | आइआइएमसी के द्वारा प्रभावी एससिमेंट | वही | 04.00 | - | वही | - |
| G | एंडडीडी का आधुनिकीकरण | वही | 05.00 | - | वही | - |
| | कुल | प्रचार | 600.00 | 8800.00 | वही | 11524 |

योजना/गैर योजना/अन्य मंत्रालय/विभाग ( 2011-12 ) ( फरवरी 2012 तक )
( ख )

| क्र.सं. | विवरण | लक्ष्य कार्यक्रम | कार्यक्रम उपलब्धि |
|---|---|---|---|
| **क. सूचना और प्रसारण कोष के अन्तर्गत चलाई जा रही गतिविधियां** | | | |
| 1. | गैर योजना | 5100 | 5483 |
| 2. | योजना | 8800 | 11524 |
| 3. | आबादी स्थिरीकरण | 7065 | 9908 |
| 4. | आयोडाइज नमक | 1600 | 1778 |
| 5. | वत्सल्य मेला | 30 | 30 |
| 6. | आईआईटीएफ | 164 | 164 |
| 7. | एस डब्ल्यूई (छत्तीसगढ़ राज्य केवल) | 1400 | 1778 |
| 8. | ग्रामीण विभाग (आर डी) | 1091 | 1217 |

## वित्तीय वर्ष 2011-12 का उद्देश्य

| योजना | गैर योजना | कुल ( लाख रुपये में ) |
|---|---|---|
| 600.00 | 2274.00 | 2874.00 |

*# 115.00 लाख रुपये पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष*

## योजना/गैर योजना/अन्य मंत्रालय/विभाग ( 2011-12 )

| क्र.सं. | विवरण | वित्त ( लाख रुपये में ) |
|---|---|---|
| 1. | गैर योजना | 2224.00 |
| 2. | योजना | 600.00 |
| 3. | आबादी स्थिरीकरण | 420.25 |
| 4. | वत्सल्य मेला | 01.45 |
| 5. | आईआईटीएफ | 14,09.360 |
| 6. | आयोडाइज नमक | 120.00 |
| 7. | एस डब्ल्यू ई (छत्तीसगढ़ के लिए) | 73.50 |
| 8. | ग्रामीण विभाग | 82.00 |

ग्रामीण भारत के लिए सजीव कला और संस्कृति। इस योजना के निम्नलिखित अवयव हैं :

1. **पर्वतीय, आदिवासी, रेगिस्तानी, संवेदनशील और सीमावर्ती इलाकों में आई सी टी गतिविधियां और मूल्यांकन :** सीमा पार से दुष्प्रचार का जवाब देने के लिए प्रभाग जम्मू-कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर क्षेत्र के संवेदनशील और अंदरूनी सीमावर्ती इलाकों में विशेष प्रचार अभियान चलाता है। इस तरह के अभियानों का उद्देश्य इन इलाकों के लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ना भी है। सभी सीमा केन्द्र अपने क्षेत्रों में विशेष सेवा ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल और अन्य रक्षा एजेंसियों के सहयोग से विभागीय और पंजीकृत निजी दलों, कैजुअल कलाकारों और भाड़े के वाहन लेकर विशेष प्रचार अभियान चलाते हैं।

   प्रभाग आदिवासी, पर्वतीय और रेगिस्तानी इलाकों में वहां के लोगों को उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही विकास गतिविधियों की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम करता है। कार्यक्रम ऐसे बनाए जाते हैं जिन्हें वे समझा सकें। इन कार्यक्रमों का मकसद लोगों में देश के प्रति निकटता की भावना जगाना और विकास योजनाओं में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है। कार्यक्रमों के लिए दल स्थानीय कलाकारों के बीच से बनाए जाते हैं। वे अपने कार्यक्रमों में स्थानीय बोलियों, मुहावरों और कला स्वरूपों का इस्तेमाल करते हैं। प्रभाग की योजना 2012-13 में ऐसे 7270 कार्यक्रम करने वाली है। निर्धारित रकम में निगरानी, परिवहन, संपर्क, आकलन और मूल्यांकन तथा इकाई मुख्यालय और क्षेत्र में अन्य व्यवस्थाओं का खर्च शामिल है।

2. **राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों पर नाटकों का प्रदर्शन :** संगीत एवं नाटक प्रभाग ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम सचल है जिसे प्रदर्शनों के लिए जगह-जगह से लाया जाता है। इसमें थिएटर प्रोडक्शन की विभिन्न विधाओं से संबंधित 25 से 30 तकनीशियन और भाड़े के वाहन भी शामिल होते हैं। यह माध्यम जनता और खास तौर से युवाओं को देश की सांस्कृतिक विरासत, जनजीवन, महान हस्तियों के विचारों और ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए बेहद असरदार है। इसका एक अहम पहलू 100 से 120 स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों की भागीदारी है। प्रभाग का दिल्ली और बंगलुरू में स्थित अपनी दो ध्वनि एवं प्रकाश इकाइयों के जरिए 60 ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का विचार है।

3. **संगीत एवं नाटक प्रभाग का आधुनिकीकरण :** प्रभाग की गतिविधियों को और प्रभावी बनाने के लिए मौजूदा क्षेत्रीय इकाइयों के अलावा 11वीं योजना के दौरान खोली गई या प्रस्तावित केन्द्रों को भी अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों से लैस किए जाने की जरूरत है। प्रभाग ने इन उपकरणों और प्रौद्योगिकी की खरीद के लिए 5.00 लाख रुपए का प्रावधान किया है।

4. **83 चिह्नित जिलों में गतिविधियां :** योजना आयोग ने 85 चिह्नित जिलों में 880 लाइव शो आयोजित करने के लिए 75 लाख रुपए प्रदान किए हैं। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द्र, आतंकवाद का विरोध और देशभक्ति पर केन्द्रित होंगे। सजीव कार्यक्रम के विषय 15 पाउंट प्रधानमंत्री कार्यक्रम को लिया जाता है।

5. **साझा न्यूनतम कार्यक्रम का प्रचार :** प्रभाग 2012-13 में साझा न्यूनतम कार्यक्रम के प्रचार के लिए 1000 कार्यक्रम करेगा। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, ग्रामीण विकास और रोजगार के मुख्य मुद्दों पर केन्द्रित होंगे। इस काम के लिए 70.00 लाख रुपए का आवंटन किया गया है।

6. **जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष गतिविधियां :** इसके तहत प्रभाग 2012-13 में 1600 कार्यक्रम आयोजित करेगा जिनके लिए 80.00 लाख रुपए का आवंटन किया गया है।

| क्र. सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/ परिणाम | वर्ष 2012-13 का परिव्यय (योजना) | मात्रात्मक / वास्तविक | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ग्रामीण भारत के लिए जीवंत कला एवं संस्कृति | प्रचार कार्यक्रम | 8.00 | 12000 | 2012-13 | |
| | **घटकवार विवरण :** | | | | | |
| | (अ) पर्वतीय/जनजातीय/रेगिस्तानी/संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में आईसीटी गतिविधियां के तहत प्रचार एवं प्रभाव | -do- | 4.20 | 7270 | 2012-13 | |
| | (B) 83 चिन्हित जिलों में गतिविधियां | -do- | 0.75 | 2070 | 2012-13 | |
| | (C) न्यूनतम साझा कार्यक्रम का प्रचार | -do- | 0.70 | 100 | 2012-13 | |
| | (D)जम्मू-कश्मीर व पूर्वोत्तर में विशेष गतिविधियां | -do- | 0.80 | 1600 | 2012-13 | |
| | (E) राष्ट्रीय/सामाजिक मुद्दों पर रंगमंचीय कार्यक्रम | -do- | 1.40 | 60 | 2012-13 | |
| | (F) गीत एवं नाटक प्रभाग का आधुनिकीकरण (पूंजी) | -do- | 0.00 | | 2012-13 | |
| | (G) अनुसंधान/विकास एवं प्रशिक्षण | -do- | 0.10 | - | 2012-13 | |
| | (H) आईआईएमसी द्वारा प्रभाव मूल्यांकन | -do- | 0.05 | - | 2012-13 | |

## योजना

*(लाख रुपये में)*

| क्र. सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/ परिणाम | वर्ष 2012-13 का परिव्यय (योजना) | | | मात्रात्मक / वास्तविक परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| | | | 4(i) | 4(ii) | 4(iii) | | | |
| | | | गैर-योजना बजट | योजना बजट रुपये में | पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन | | | |
| | | | 23.24 | | | | | |
| | लाइव कला और संस्कृति कार्यक्रम ग्रामीण भारत में | प्रचलित कार्यक्रम | - | 8.00 | - | 12000 | 2012-13 | |
| | कुल | | 23.24 | 8.00 | | | | |

# गीत एवं नाटक प्रभाग

## वार्षिक योजना 2010-11 के अनुमानित परिणाम

**अनुलग्नक**

1. 63,100 व्यक्ति दिवसों के लिए रोजगार उपलब्ध कराए जायेंगे जिससे 31,55,000 व्यक्तियों तक सूचना/संदेश पहुंच सकेगा।

2. i. 42,000 व्यक्ति दिवसों के लिए रोजगार सृजन होगा 21,00,000 व्यक्तियों तक सूचना/संदेश पहुंचेगा।

   ii. 8800 व्यक्ति दिवसों के लिए रोजगार सृजित होंगे, 4,40,000 व्यक्तियों तक सूचना/संदेश पहुंचेगा।

   iii. 6200 व्यक्ति दिवसों के लिए रोजगार का सृजन होगा 3,10,000 व्यक्तियों तक सूचना/संदेश पहुंचेगा।

   iv. 5,600 व्यक्ति दिवसों के लिए रोजगार का सृजन होगा 2,80,000 व्यक्तियों तक सूचना/संदेश पहुंचेगा।

   v. 10,000 व्यक्ति दिवसों के लिए रोजगार का सृजन होगा, 1,50,000 व्यक्तियों तक सूचना/संदेश पहुंच सकेगा।

   vi.&vii. कार्यक्रमों की गुणवत्ता में कई गुणा वृद्धि होगी।

# मुख्य सचिवालय सूचना क्षेत्र योजना

## सूचना भवन का निर्माण

*(करोड़ रुपये में)*

| क्र. सं. | योजना/ कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/ परिणाम | परिव्यय 2012-13 | | | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4(i) | 4(ii) | 4(iii) | | | | |
| | | | गैर-योजना बजट | योजना बजट (करोड़ रुपये में) | पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन | | | | |
| | सीजीओ कॉम्प्लैक्स लोधी रोड, नई दिल्ली में सूचना भवन फेज-V का निर्माण | सिविल एवं विद्युतीय कार्यों का निष्पादन | - | 15 | - | 1. बुनियाद के साथ-साथ ढांचागत कार्यों का निष्पादन<br>2. सिविल प्रगति के साथ-साथ विद्युतीय कार्य भी जारी।<br>3. ब्रिक कार्य, फ्लोरिंग, फिनिशिंग एवं अन्य विविध लकड़ी, स्टील, वाशबेसिन/ सिंक एवं सैनिटरी का कार्य | **सिविल कार्य**<br>1. शेष पाइल कैप्स तथा बेसमेंट कार्यों का निष्पादन।<br>2. पाकेट्स में सुपर स्ट्रक्चर कार्य<br>3. ब्रिक कार्य, फ्लोरिंग, लकड़ी, स्टील वाशबेसिन/ सिंक, सैनिटरी तथा फिनिशिंग सामग्री<br>**विद्युतीय कार्य**<br>1. फायर फाइटिंग एवं फायर अलार्म<br>2. लिफ्ट<br>3. सब स्टेशन<br>4. विविध विद्युतीय सामग्री | फ्लो चार्ट के अनुसार | (क) यदि आवश्यक अनुमानित विधि की आवंटन नहीं होता है तो कार्य चालू पंचवर्षीय योजना के भीतर पूरा नहीं हो पाएगा।<br>(ख) यदि स्वीकृत कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी शामिल किया जाता है तो कार्य आगामी पंचवर्षीय योजना में चला जाएगा।<br>(ग) सभी ढांचात्मक/ वास्तुकला की ड्राइंग/ विवरणों को समय से जारी किए जाने की आवश्यकता है। |

**वित्तीय परिव्यय, भौतिक परिणाम परियोजना और परियोजना का परिणाम**

**योजना का नाम :** पूर्वोत्तर/जम्मू और कश्मीर और अन्य चिह्नित क्षेत्र का विकास

**11वीं पंचवर्षीय योजना का परिव्यय :** 25 करोड़ रुपये और वार्षिक योजना 2012-13 में 2 करोड़ रुपये

| वर्ष | 11वीं योजना परिव्यय |
|---|---|
| 2012-2013 | 2 |
| 2013-2014 | 6 |
| 2014-2015 | 6 |
| 2015-2016 | 6 |
| 2016-2017 | 5 |
| **कुल** | **25** |

*(करोड़ रुपये में)*

| क्रम सं | योजना/ कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2011-12 | | | निर्धारित/ वितरणीय भौतिक परिव्यय | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम का घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 4(i) गैर-योजना बजट | 4(ii) योजना बजट | 4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन | | | | |
| 1. | पूर्वोत्तर/जम्मू कश्मीर और अन्य चिह्नित क्षेत्र का विकास | 1. बुनियादी विकास पूर्वोत्तर राज्यों जम्मू कश्मीर सीमाक्षेत्र और एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्र केन्द्रीय सूचना सदन, प्रेस सेन्टर का आधुनिकीकरण राज्य सूचना विभाग को वित्तीय सहायता उपकरण हेतु दिया जाता है वित्तीय सहयोग मिडिया यूनिट सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रों को प्रदान किया जाता है।<br>2. सामान्य कार्यक्रम पर पीआईबी, डीएवीपी, डीएफपी और संगीत नाटक एकेडमी को उनके क्षेत्रों में बढ़ावा देना है। | — | 2.00 | — | संचार ढांचा का इन क्षेत्रों में विकास मूलभूत ढांचा और मीडिया यूनिट का सहयोग क्षेत्रीय स्तर पर मुश्किल | संचार की पहुंच और ढांचा विकास सहयोग | यह नई योजना मंत्रालय में प्रस्तावित है जो आरंभिक दौर और योजना समय में समयबद्धता दर्शाता है। | |
| | | **कुल** | — | **2.00** | — | | | | |

# अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम

**योजना का नाम :** अंतरराष्ट्रीय मीडिया विनिमय कार्यक्रम

**11वीं पंचवर्षीय योजना का परिव्यय :** 2.50 करोड़ रुपये और वार्षिक योजना 2012-13 रुपये 0.20 करोड़ रुपये

| वर्ष | 12वीं योजना परिव्यय |
|---|---|
| 2012-2013 | 0.20 |
| 2013-2014 | 0.60 |
| 2014-2015 | 0.60 |
| 2015-2016 | 0.60 |
| 2016-2017 | 0.60 |
| **कुल** | **2.50** |

*(करोड़ रुपये में)*

| क्रम सं | योजना/ कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2012-13 | | | निर्धारित/ वितरणीय भौतिक परिव्यय | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम का घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 4(i) गैर-योजना बजट | 4(ii) योजना बजट | 4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन | | | | |
| 1. | अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम | मुख्य लक्ष्य संस्कृति मजबूत और मीडिया संबंधों का विनियम, विचार बृहद रोल की पहचान जिससे मीडिया की उन्नति बेहतर राष्ट्रीय समझ सूचना के साथ क्षेत्र में रहना | — | 0.20 | — | समझौता पत्र में संस्कृति आदान-प्रदान हेतु किया गया यह प्रिंट और प्रसारण मिडिया के लिए किया गया मिडिया के सदस्य और गणमान्य विभिन्न मीडिया स्थापन में दौरा करते हैं। सूचना और मास मीडिया के बीच संयुक्त कार्य समूह का समझौता अंतर्राष्ट्रीय मिडिया और सेमिनार कार्यशाला का आयोजन | बेहतर भागीदारी और मीडिया से संबंधित विषय में सीख भारत और अन्य देशों के बीच | यह नई योजना मंत्रालय की पहल और योजनावधि में समयबद्ध निर्धारित की गई। | |
| | | **कुल** | — | 0.20 | — | | | | |

# नीति संबंधित अध्ययन, सेमिनार, पर्यवेक्षण इत्यादि

## नीति संबंधित अध्ययन, सेमिनार, पर्यवेक्षण इत्यादि तीनों की क्षेत्र में मीडिया यूनिट के साथ ( प्रचार-भारती समाहित नहीं )

### नई योजना

*(करोड़ रुपये में)*

| क्रम सं | योजना/ कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2012-13 | | | निर्धारित/ वितरणीय भौतिक परिव्यय | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम का घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 4(i) गैर-योजना बजट | 4(ii) योजना बजट | 4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन | | | | |
| 1. | नीति संबंधी अध्ययन सेमिनार पर्यवेक्षण इत्यादि सभी तीन क्षेत्रों में मीडिया यूनिट के साथ (प्रसार-भारती समाहित नहीं) नई योजना | प्रबंधन प्रणाली का विकास करना (एम आई एस) फिल्म सूचना प्रसारण क्षेत्र अध्ययन और पर्यवेक्षण व्यवस्था और विकास का असर निति का फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्र में सेमिनार और कार्यशाला आयोजित करना।<br>राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का कार्यशाला और मनोरंजन के क्षेत्र में।<br>मनोरंजन और मिडिया के क्षेत्र में बढ़ावा देना। | 1.00 | — | — | समझौता पत्र में संस्कृति आदान-प्रदान हेतु किया गया यह प्रिंट और प्रसारण मिडिया के लिए किया गया मिडिया के सदस्य और गणमान्य विभिन्न मिडिया स्थापन में दौरा करते हैं। सूचना और मास मीडिया के बीच संयुक्त कार्य समूह का समझौता अंतराष्ट्रीय मिडिया और सेमिनार कार्यशाला का आयोजन | - एम आई एस विकास<br>- नीति संबंधी अध्ययन का आयोजन<br>- सेमिनार करना<br>-बढ़ोत्तरी/गणना<br>पर्यावेक्षण/नई योजना/ (मध्यावधि बढ़ोत्तरी) | 1. यह वर्तमान ज्ञान पर आधारित मिडिया और मनोरंजन विभाग यह कार्य, विकास प्रगति इत्यादि<br>2. मंत्रालय के नीति बनाने में मदद करता है।<br>3. आम आदमी के लिए सूचना को बढ़ावा देना | |
| 2. | | सार्वजनिक सूचना अभियान चलाकर प्रेस वार्ताएं चलाकर प्रेस वार्ताएं आयोजित करके सफलता की कहानियां जारी करके और प्रेस दौरे आयोजित करके केन्द्र सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी देना | | — | — | | | अभी अंतिप प्रारूप तैयार नहीं | |
| | | कुल | — | — | — | | | | |

# मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण

## परिणाम बजट 2011-12 में परिणाम लक्ष्य

*(लाख रुपये में)*

| क्र.सं. | स्कीम का नाम | परिव्यय | वास्तविक आउटपुट | प्रक्षेपित परिणाम | टिप्पणी/जोखिम तत्व |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मानव संसाधन विकास के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण | 1.50 | अभी तक विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए कुल 57 (46 देश और 11 विदेश) अधिकारियों को नामित किया गया है। | विभिन्न मीडिया एककों के प्रभावशाली संचालन के लिए क्षमता का विकास, अधिकारियों की क्षमता तथा कौशल का उन्नयन। | कोई विशिष्ट जोखिम नहीं। |

# मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण

इस स्कीम के लिए वर्ष 2012-13 हेतु अनुमानित वार्षिक योजना परिव्यय 2 करोड रुपए है। मंत्रालय के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु विशिष्ट होने के कारण इसका (i) जेंडर बजट, (ii) अजजा बजट, और (iii) पूर्वोत्तर बजट संबंधी कोई विशिष्ट भाग नहीं है। हालांकि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अधिकारियों को नामित करते समय महिलाओं, अजा/अजजा अधिकारियों और पूर्वोत्तर के प्रतिनिधित्व का पूरा ध्यान रखा जाता है।

*(लाख रुपये में)*

| क्र. सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/ परिणाम | परिव्यय 2012-12 योजना | बजट | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आईआईएस अधिकारियों के लिये विदेश स्थित संस्थानों में मानव संसाधन विकास के लिये प्रशिक्षण | 1. मानव संसाधन विकास के अंतर्गत मंत्रालय के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना ताकि उनकी योग्यता में इजाफा हो।<br>2. मंत्रालय के अधिकारियों को मीडिया/प्रशासन से संबंधित कई क्षेत्रों में विदेशी संस्थानों में प्रशिक्षण देना।<br>3. अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और जरूरतों को समझने के लिए विदेशों में स्थित संस्थान जैसे बीबीसी, थॉमसन फाउंडेशन, यूके, रेडियो नीदरलैंड, हार्वड यूनिवर्सिटी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना।<br>4. आईआईएस अधिकारियों को विभिन्न मीडिया इकाइयों में भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उनके कैरियर के निरंतर विकास के लिये तैयार कार्यक्रमों का प्रशिक्षण। | 0.00 | 2.00 | (क) 11वीं पंचवर्षीय योजना के पांचवें वर्ष 2012-13 में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं :<br>* मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों के 100-150 अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।<br>* कैरियर के दौरान<br>* प्रशिक्षण के लिए सुव्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना।<br>* भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। | कौशल उन्नयन सुधार के जरिए संगठन के प्रभाव को सुधारना | विभिन्न संस्थानों / संगठनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार इसे वर्ष भर में बांटा जाएगा। | कोई विशिष्ट जोखिम नहीं |

**नोट :** (1) कॉलम 2 के सामग्री 2012-13 के लिए परिव्यय के लिए पारित वार्षिक योजना से है।
(2) 4(i) और 4(ii) के कॉलम में दिए गए आंकडे पारित परिव्यय वर्ष 2012-13 के लिए है।

# फिल्म क्षेत्र

# केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

## योजना

*(लाख रुपये में)*

| क्र. सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | लक्ष्य/परिणाम | परिव्यय 2011-12 | | | परिमाणनीय/ वितरण योग्य/ भौतिक नतीजे | अनुमानित परिणाम | प्रक्रिया/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4 (i) | 4 (ii) | 4 (iii) | | | | |
| | | | **गैर-योजना बजट** | **योजना बजट** | **पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन** | | | | |
| 1. | कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली की स्थापना और सीबीएफसी में बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन (पूंजी) | क्षेत्रीय कार्यालयों व सीबीएफसी मुख्यालयों और मंत्रालय के बीच डाटा के तीव्र ट्रांसमिशन के लिए लीज्ड लाइन संपर्क स्थापित किया गया है। | 6.50 | 1.50 | शून्य | सीबीएफसी के क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालयों एवं मंत्रालय को लीज्ड लाइन संपर्क द्वारा जोड़ा जाएगा। (इंट्रानेट) लोगों को दिखाने के लिए आरटीआई अधिनियम के संदर्भ में जानकारी देने के लिए प्रमाणित फिल्मों और कटों की विस्तृत जानकारी को वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। | देश के सभी क्षेत्र में प्रमाणन में समरूपता लाने के लिए ऑडियो व वीडियो डाटा का तीव्र प्रसार। | वार्षिक आधार | विभिन्न हितधारकों द्वारा काम का क्रियान्वयन करवाना |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | प्रमाणन प्रक्रिया की निगरानी (राजस्व) | प्रमाणन प्रक्रिया में सुधार आने के लिए | — | 1.50 | — | सीबीएफसी व परामर्शदाता पैनल के सदस्यों के लिए कार्यशालाओं, सम्मेलनों और बोर्ड बैठकों का आयोजन किया जाएगा। | प्रमाणन दिशा-निर्देशों की बेहतर समझ के लिए प्रमाणन प्रक्रिया में सुधार। | वार्षिक आधार | वार्षिक बजट आबंटन का उपयोग करना |
| | **कुल** | | **6.50** | **3.00** | **शून्य** | | | | |

# बाल फिल्म समिति, भारत

*(करोड़ रुपये में)*

| क्र. सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम (चालू योजनाएं) | ग्यारहवीं योजना के लिए उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2012-13 | | | वास्तविक प्रतिफल/ मात्रात्मक परिणाम (2010-11) | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/जोखिम संबंधी घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 4(i) | 4(ii) | 4(iii) | | | | |
| | | | गैर-योजना बजट | योजना बजट | पूरक अतिरिक्त बजट स्त्रोत | | | | |
| 1 | सीएफएसआई को सरकार से अनुदान | 1. लक्ष्य : फिल्मों के माध्यम से शिक्षा तथा संस्कृति को बेहतर बनाना और स्वस्थ मनोरंजन के लिए बच्चों में फिल्म समालोचना को प्रोत्साहन देना।<br>2. परिव्यय निर्माण 12 फीचर फिल्म स्टैन्ड दो लघु/एनिमिशन फिल्म और डब 134 शीर्षक भारत के प्रमुख भाषाओं में। | | 10.00 | शून्य | 5 फीचर फिल्में, 2 लघु फिल्में, 14 डबिंग, 6 उपशीर्षक, 22 फिल्में खरीदी जाएंगी। | राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों की बाल फिल्में उपलब्ध कराई जाएंगी। | योजना के अंतिम प्रारूप पर अनुमति का इंतजार और 31.3.2013 तक कार्य खत्म। | बच्चों के फिल्मीं कला को बढ़ावा देना और अधिक से अधिक दर्शक तक पहुंचने के लिए विभिन्न भाषाओं में 55 बिग सबटाइटिल करना। |
| | | 1. लक्ष्य : अभिलेख के उद्देश्य से डिजिटल रूप में सीएफएसआई की फिल्मों का रूपांतरण<br>2. (170 घंटे की फिल्मों का डिजटिलीकरण किया जाएगा) | | | | सीएफएसआई की सभी फिल्में अभिलेख हेतु डिजिटल फॉरमेट में रूपांतरित की जाएंगी। | | | बाल फिल्म निर्माताओं के लिए तकनीकी स्रोत का विस्तार |
| | | 1. लक्ष्य : सीएफएसआर फिल्म (निर्माण, डब, और उपशीर्षक के लिए) डिजिटल लाइब्रेरी में बनाया जा रहा है। | 2.00 | शून्य | | लाइब्रेरी के रूप में सीएफएसआई की सभी फिल्मों की वेबकास्टिंग तथा सीएफएसआई की फिल्मों की इंटरनेट पर उपलब्धता। | सीएफएसआई की सभी फिल्मों की वेबकास्टिंग तथा सीएफएसआई की वेबसाइट पर उनका प्रदर्शन। | 31.03. 2012 | फंड पर निर्भर |
| | | 2. परिव्यय बाल फिल्मों को ऑनलाइन उपलब्ध कराना | | शून्य | | 25 लाख दर्शकों को लाभांवित करने के लिए 5000 प्रदर्शनों का आयोजन। | देश के दूर-दराज के क्षेत्रों के ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचना। | 31.03. 2012 | फंड पर निर्भर |
| | | 1. लक्ष्य : राज्य और जिला प्रशासन, नेहरू युवा केंद्रों तथा गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से देश के सभी बच्चों तक पहुंचना।<br>2. परिव्यय लगभग 30 हजार शो का आयोजन | | | | | | | |

*(लाख रुपये में)*

| क्र. सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम (चालू योजनाएं) | ग्यारहवीं योजना के लिए उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2012-13 | | | वास्तविक प्रतिफल/ मात्रात्मक परिणाम (2010-11) | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/जोखिम संबंधी घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 4(i) | 4(ii) | 4(iii) | | | | |
| | | | गैर-योजना बजट | योजना बजट | पूरक अतिरिक्त बजट स्त्रोत | | | | |
| | सीएफएस आईसीएफएफ संगठन | भारतीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के विचार विनिमय के लिए मंच तैयार करना। | 1.55 | | | कोई प्रदर्शन नहीं 2012-13 में सीएफएस आईसीएफएफ के तहत | | | |
| | आईसीएफएफ में भागीदारी | सीएफएसआई फिल्मों को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भागीदारी और मार्केटिंग के आयाम ढूढ़ने का प्रयास। | | | | 15 प्रसिद्ध आईसीएफएफ में भागीदारी | बाजार और सह निर्माण के नए आयाम खोलने | | |
| | कुल | | 1.55 | 13.00 | | | | | |

# फिल्म समारोह निदेशालय

## गैर-योजना

*(करोड़ रुपये में)*

| क्र. स. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य परिणाम | *प्रस्तावित* परिव्यय 2012-13 | | | परिमाणनीय/ हस्तांतरणीय/ वास्तविक प्रतिफल | परिमाणनीय/ हस्तांतरणीय वास्तविक प्रतिफल | प्रक्रिया/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4 (i) | 4 (ii) | 4 (iii) | | | | |
| | | | गैर-योजना बजट | योजना बजट | पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन | | | | |
| 1 | लघु कार्य | वेतन भत्ते, ओई, डीटीई आदि | 2.45 | | शून्य | | | - | |
| 2 | प्रतिस्थापना संबंधी खर्चे | सीरीफोर्ट सांस्कृतिक परिसर का रख-रखाव | 4.00 | | शून्य | कला संस्कृति तथा सिनेमा के क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए सभागार सुज्जित करना तथा किराए पर देना | किराए से उच्च आय की उम्मीद | एक वर्ष | |
| 3 | सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत फिल्म समारोह | विश्वभर में समृद्ध और विविध संस्कृति को फैलाना और विदेशों की उपस्थिति बढ़ाना | 0.22 | | शून्य | सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत भारत और विदेशों में 06 फिल्म समारोहों का आयोजन। | भारतीय सिनेमा को प्रोत्साहन तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत देशों के साथ संबधों को मजबूत बनाना। | सीईपी का वर्ष भर आयोजन | |
| 4 | राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार | भारत में निर्मित फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित कर अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देना | 2.50 | | शून्य | 3 मई 2013 को 59वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया जायेगा और 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2012 को 59 राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जूरी के लिए स्क्रीनिंग हुआ। | भारतीय कला और संस्कृति के क्षेत्र में सुधार लाना तथा बेहतर प्रतिभाओं को मान्यता प्रदान करना ताकि भारतीय सिनेमा को बेहतर बनाया जा सके। | एक वर्ष | |
| | | कुल | 9.20 | | | | | | |

# फिल्म समारोह निदेशालय

## योजना

*(लाख रुपये में)*

| क्र. सं. | योजना का नाम | उद्देश्य/परिणाम | प्रस्तावित परिव्यय 2012-13 | | | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| 1. | सिरीफोर्ट में फेरबदल और अतिरिक्त निर्माण-प्रमुख कार्य (योजना पूंजी) | सीरीफोर्ट परिसर का नवीनीकरण और सुविधाओं में सुधार ताकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के परिसर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। | गैर-योजना | योजना | *पूरक अति.ब.सं.* | सिरीफोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नवीनीकृत ऑडिटोरियम बनाना और कला, संस्कृति तथा सिनेमा के क्षेत्र में आडिटोरियम/परिसर को अन्य पार्टियों को किराए पर देकर अधिक राजस्व अर्जित करना। | जैसा ऊपर दिया गया है। | |
| | | | | 1.00 | शून्य | | | |
| | **कुल** | | 9.20 | 1.00 | | | | |

# भारतीय फिल्म एवं टेलिविजन संस्थान पुणे

*(करोड़ रुपये में)*

| क्रम सं. | योजना/ कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2012-13 | | | निर्धारित/ वितरणीय भौतिक परिव्यय | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम का घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 4(i) गैर-योजना बजट | 4(ii) योजना बजट | 4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन | | | | |
| 1. | भारतीय फिल्म एवं टेलिविजन संस्थान पुणे को अनुदान राशि | गैर योजना के उद्देश्य अध्यापक, तकनीकी और प्रशासनिक स्टॉफ को भत्ता देना और प्रोजेक्ट वर्क और दिन-प्रतिदिन का खर्च आता है। स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स फिल्म और टेलिविजन में उच्च प्रशिक्षित व्यक्ति इस संस्थान से मिलते हैं। प्रत्येक वर्ष लगभग 275 छात्र उत्तीर्ण होते हैं। डिप्लोमा कोर्स डायरेक्टर, सिनेमोटोग्राफर (फिल्म और टीवी) संपादक (फिल्म और टीवी) ऑडियोग्राफी (फिल्म और टीवी) अभिनय, कला-निदेशक, प्रोडक्शन डिजाइन और सर्टिफिकेट कोर्स एनिमेशन, कम्प्यूटर ग्राफिक्स, विडियो एडिटिंग और ऑडियोग्राफी और टीवी इंजिनियर | 13.50 | — | 1.5 (वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान) | संस्थान डिप्लोमा कोर्स आयोजित करता है जिसका नाम निर्देशन,. तिनमोटोग्राफी (फिल्म एवं टीवी) संपादन (फिल्म एवं टीवी) ओडियोग्राफी (फिल्म एवं टीवी) अभिनय, कला निर्देशन और निर्माण डिजाइन और सर्टिफिकेट कोर्स एनिमेशन एवं कम्प्यूटर ग्राफिक, विडियो संपादन और ऑडियोग्राफी और टीवी इंजिनियरिंग है। कई गतिविधियों में छात्रों की परियोजना जैसे लगातार लघु फिल्म, वृत्तचित्र, प्लेबैक और डिप्लोमा फिल्म इत्यादि। 2 से 3 वर्ष का (सार्टिफिकेट कोर्स) था 1 वर्ष का प्रशिक्षण (सार्टिफिकेट कोर्स) संस्थान द्वारा आयोजित किए जाते हैं। प्रतिवर्ष 275 छात्र | 3 वर्ष के डिप्लोमा कोर्स में 275 छात्रों को संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त होते हैं। 2 साल पीजी (डिप्लोमा कोर्स और 1 वर्ष सर्टिफिकेट कोर्स का पाठ्यक्रम है। इसके अतिरिक्त कुछ लघु कोर्स विभिन्न संस्थानों द्वारा करवाये जाते हैं। संस्थान सिर्फ फिल्म उद्योग को ही प्रशिक्षित तकनिशियन प्रदान नहीं करता बल्कि उद्योग को सृजनात्मक लोग भी प्रदान करता है। | संस्थान से पास हुए छात्र।<br>3 वर्ष का स्नोतकोत्तर डिप्लोमा<br>1. 2006 सत्र के 42 छात्र मार्च 2012 में अपना अध्ययन पूरा करेंगे।<br>2. 2007 सत्र के 43 छात्र दिसम्बर 2012 में अपना पाठ्यक्रम पूरा करेंगे।<br>3. 50 छात्र 2008 सत्र का 3 वर्ष के कोर्स के लिए 27 फरवरी 2012 को आरंभ हुआ।<br>2 वर्ष स्नातकोत्तर डिप्लोमा<br>21 छात्राओं का 2009 का सत्र जुलाई 2012 में आरंभ होगा। | परियोजना का परिणाम परिव्यय वित्तीय सहयोग की उपलब्धता पर निर्भर।<br>2 अन्य सैक्टर संस्थान की पहुंच से बाहर। |

*(करोड़ रुपये में)*

| क्रम सं | योजना/ कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2012-13 | | | निर्धारित/ वितरणीय भौतिक परिव्यय | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम का घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 4(i) गैर-योजना बजट | 4(ii) योजना बजट | 4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन | | | | |
| | | | | | | (लगभग) यहां से पास होकर निकलते हैं। जो अपने क्षेत्र में उच्चतम प्रशिक्षित हैं जैसे निर्देशन सिनेमेटोग्राफी, संपादन, ध्वनि मुद्रण इत्यादि। | | | |
| 2. | भारतीय फिल्म एवं टेलिविजन संस्थान पुणे को अनुदान राशि-अपग्रेड और आधुनिकीकरण | मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे के सेटअप में फिल्म और तकनीक का विकास करना यह छात्रों को शारीरिक सुविधा और आधुनिक तकनीक का उपयोग पाठ्यक्रम में प्रगति लाने के लिए किया जाता है। अध्यापकों एवं कर्मचारियों को नए विकास के लिए प्रशिक्षण देते हैं। | — | 7.00 | — | एक आधुनिक संसाधन तथा ज्ञान केन्द्र की योजना है। जैसे पुस्तकालय, ई, पुस्तकालय, इंटरनेट, विद्यार्थी केन्द्र, फैकल्टी के लिए विचार विमर्श कक्ष तथा वीडियो कांफ्रेंसिंग केन्द्र का समन्वय नई मशीनरी और उपकरणों के लिए ढ़ाँचागत बदलाव तथा इमारतों के नवीकरण के लिए भी अतिरिक्त विधियों की जरूरत है। | | 1. एसएफसी अनुमोदित अंतिम प्रारूप<br>2. डिजाइन और योजना निर्माण और पुर्नस्थान कार्य<br>3. नागरिक निर्माण और विधुतिकरण कार्य | जोखिम<br>1. लक्ष्य को प्राप्त करना वित्तीय सहयोग पर निर्भर।<br>2. केस दर केस के हिसाब से सेटेशनरी प्राप्ति<br>3. संस्थान के अन्य फैक्टर नियंत्रण से बाहर |
| | | **कुल** | **13.50** | **7.00** | **1.50** | | | | |

# फिल्म प्रभाग

## परिव्यय बजट 2012-2013 ( गैर योजना )

### गैर योजना

*(करोड़ रुपये में)*

| क्र. सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/उपलब्धियां | वित्तीय परिव्यय ( यो.ब. ) 2012-13 | वास्तविक/मात्रात्मक उपलब्धियां | अनुमानित परिणाम | प्रक्रिया/अवधि | टिप्पणी/ जोखिम के घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उत्पादन | लोगों को सूचित करने जागरूक करने, प्रोत्साहित करने तथा सांस्कृतिक उन्नयन के मद्देनजर भारत सरकार की जरूरतों के अनुसार डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन तथा लघु फिल्में बनाना मुख्य उद्देश्य। देश भर के लोगों तथात संस्थाओं को उनकी जरूरत के अनुसार वीसीडी फॉरमेट में लघु फिल्मों, एनिमेशन, डाक्यूमेंट्री की बिक्री तथा वितरण सुनिश्चित करना। | 13.42 | 36 फिल्म | सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, विकास कार्यों के बारे में लोग जानकारी पा सकेंगे इससे उन्हें जानकारी मिलेगी तथा वे प्रोत्साहित होंगे। | 01.04.12 से 31.03.2013 | अनुमान है कि अधिकाधिक डॉक्यूमेंट्री का निर्माण होगा। बाहर के निर्मात और इन हाउस निर्माता इसमें भागीदारी करेंगे। किराए में 1% कमी का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसलिए संभवत किराया न हो। हालांकि फिल्म प्रभाग की फिल्में काफी संख्या में फिल्म थिएटर वाले लेते हैं तथा उन्हें पर्दे पर दिखाते हैं। |
| 2 | थिएटरों में डॉक्यूमेंट्री का वितरण | दस शाखा कार्यालयों के नेटवर्क के द्वारा डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का वितरण। स्टॉक शॉट्स की बिक्री केवल मुंबई स्थित मुख्यालय से। | 19.01 | 13000 थियेटर में वितरण | वही | 01.04.2012 से 31.03.2013 | |

# परिव्यय बजट 2012-2013

*(लाख रुपये में)*

## योजना

| क्र. सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/उपलब्धियां | वित्तीय परिव्यय (यो.ब.) 2012-13 | वास्तविक/मात्रात्मक उपलब्धियां | अनुमानित परिणाम | प्रक्रिया/अवधि | टिप्पणी/ जोखिम के घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अन्तर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु और एनिमेशन फिल्म समारोह | मुंबई में दो-वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु एवं एनीमेशन फिल्म समारोह आयोजित करना। 11वीं योजना अवधि में 3 फिल्म समारोह | 0.05 | 2012 के पुरस्कार प्राप्त फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। योजना का अंतिम प्रारूप वित्तीय सहायता पर निर्भर करता है। | 2012 का मिफ्फ पुरसकार प्राप्त के फिल्मों का प्रदर्शन | द्विवार्षिक मिफ्फ समारोह में विश्व भर से फिल्मकारों द्वारा आवेदन पत्र/प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं और प्रतिष्ठित ज्यूरी की सिफारिश पर भागीदारों को पुरस्कार। | |
| 2 | प्रभाग की फिल्मों का डिजीटलीकरण तथा वेबकास्टिंग | इंटरनेट के माध्यम से फिल्म प्रभाग की डॉक्यूमेंट्री, लघु तथा एनिमेशन फिल्मों का दुनियाभर में प्रचार। इसके लिए आर्काइव की सभी 6 फिल्मों का डीवीडी में ट्रांसफर 1 हाई डेफिनिशन तकनीक का प्रयोग। फिल्म प्रमाग की फिल्में वेबसाइट www.filmsdivision.org पर उपलब्ध हैं। | 0.90 | फिल्म प्रभाग की फिल्मों की, वेबकास्टिंग के लिए इसे स्वातंत्र्योत्तर भारत की ऑडियो-वीजुअल इनसाइक्लोपिडिया से जोड़ना तथा प्रभाग की फिल्मों को डिजिटल फॉरमेट में हस्तांतरण। | इससे इंटरनेट के माध्यम से लोग फिल्म प्रभाग की फिल्मों से जुड़ सकेंगे और इस तरह फिल्में सुरक्षित रहेंगी। | 1.4.2012 से 31.3.2013 | |

| क्र. सं. | योजना/कार्यक्रम | उद्देश्य/उपलब्धियां | वित्तीय परिव्यय (ब.अ.) 2012-13 | वास्तविक मात्रात्मक उपलब्धियां | अनुमानित परिणाम | प्रक्रिया/अवधि | टिप्पणी/ जोखिम के घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण | समय की जरूरत को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर तथा जम्मू-कश्मीर के फिल्म निर्माताओं तथा जनता को मुख्य धारा में लाना।<br>उनके लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना प्रस्तावित है। ये फिल्में सामाजिक मुद्दों पर होंगी तथा समाधानपरक होंगी। | 8.00 | योजना को अंतिम प्रारूप दे दिया गया है और वित्तीय सहायता का इंतजार है। | इन क्षेत्रों में लोगों को डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के माध्यम से जागरूक बनाना और नए टेलेंट को आगे लाना है। | बाहरी एजेंसी द्वारा फिल्मों का वेबसाइट पर इनकोड किया गया है। फिल्मों का डीवीडी में हस्तांतरण के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। वेबकास्टिंग एक सतत प्रक्रिया है। फिल्मों का डिजीटलीकरण का कार्य 11वीं योजना अवधि के दौरान पूरा कर लिया जाएगा। | |
| 4. | मूविंग इमेज संग्रहालय की स्थापना। इसका वैकल्पिक नाम होगा - नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा (एनएमआईसी) | आंगुतकों/फिल्म प्रेमियों के लाभार्थ प्रख्यात निर्देशकों, निर्माताओं, संस्थानों, आदि की कृतियों का प्रदर्शन और फिल्म निर्माण से संबंधित सामग्री दर्शाने के लिए एक स्थाई संग्रहालय की स्थापना करना। इसके बाद फिल्म निर्माताओं तथा फिल्म छात्रों के लिए सेमिनार, कार्यशाला आदि आयोजित करना। | 1.00 | फिल्म प्रभाग, मुम्बई में एक संग्रहालय की स्थापना करना, जिसमें दृश्य-श्रव्य माध्यम से भारतीय सिनेमा का इतिहास और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फिल्म निर्माण सामग्री दर्शाई जाएगी। | एनबीसीसी द्वारा तैयार परियोजना रिपोर्ट के आधार पर फिल्म प्रभाग, मुम्बई में एमओएमआई नामक संग्रहालय की स्थापना करना। | परियोजना 2013 के अन्त तक पूरी हो जाएगी। | निश्चित अवधि से अधिक समय लगने का जोखिम, क्योंकि यह प्लान स्कीम एनबीसीसी द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और उसके द्वारा ठेके देने से सीधे संबंधित है। |

# राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

*(करोड़ रुपये में)*

| क्र. सं. | योजना/ कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/ परिणाम | वित्तीय परिव्यय ( बी ई 2012-13 ) | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों का उत्पादन | भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने और फिल्म निर्माण में नई प्रतिभाओं को लाना | 17.00 | 5 फिल्में | यह क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों और भारतीय सिनेमा के दर्शक को बढ़ायेगा और इस क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करेगा | फिल्में करीब एक साल में निर्मित होंगी | फिल्म के प्रति दर्शक की प्रतिक्रिया काफी लचीली और गैर अनुमान वाली है। |
| 2. | इक्विटी भागीदारी | एनएफडीसी का प्राधिकार तथा प्रदत्त पूंजी आधार बढ़ाना ताकि अपने अधिदेश को पाने के लिए निगम के पास फंड उपलब्ध रहे। | 4.00 | 5 बाजार | फिल्म निर्माण को प्रभावी बनाने के अधिदेश का पालन करने के लिए यह निगम को पर्याप्त कोष उपलब्ध करायेगा। | एनएफसीडी ने इसके रिवाइवल को मापने के लिए बी आर पी एस ई को अधिकार दिया है और इसके लिए कुछ समय लगेगा। हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है | यह योजना अभी स्वीकृत होनी है। केबिनेट द्वारा एनएफडीसी की इक्विटी में निवेश के प्रस्ताव की मंजूरी के बाद ही फंड जारी किया जा सकता है। |

# सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

## परिणाम/लक्ष्य 2012-13 ( प्लॉन ) परिणाम बजट के

*(करोड़ रुपये में)*

| क्रं. सं. | स्कीम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | 2012-13 के लिए अनुमोदित परिव्यय ( रुपया करोड़ में ) 4i | | | वास्तविक प्रतिफल | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/समयबद्धता | टिप्पणियां/ जोखिम घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | नॉन प्लान बजट | | प्लान बजट | | | | |
| 1. | सत्यजीत रे फिल्म एवं टीवी विजन संस्थान कोलकाता को अनुदान राशि | गैर योजना का उद्देश्य अध्यापक, कर्मचारीओं तकनीकी का दिन प्रतिदिन का खर्च देना संस्थान का मूल उद्देश्य फिल्म एवं टीवी उद्योग के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों को मुहैया कराना है, संस्थान निर्देशन तथा पटकथा लेखन, चलचित्र फोटोग्राफी, संपादन और साउंड रिकार्डिंग में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। कुल 120 छात्रों की क्षमता संस्थान के तीन समवर्ती बैचों में फैली है। | 7.00 | | 0.87 पूरक अतिरिक्त बजट स्रोत 2012-13 | फिल्म उद्योग में सारी विधाओं के जानकार लोगों को वार्षिक तौर पर निकलते हैं। यह संस्था से प्रतिवर्ष छात्र फिल्म उद्योग के लिए निकलते हैं। | संस्था फिल्म एवं टेलीविजन उद्योग को उच्च दर्जे का फिल्मों का ज्ञान प्राप्त लोगों को मुहैय्या करवाता है। लगभग 40 छात्र 3 वर्ष के स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स और इसके अलावा शॉट टर्म कोर्स करते हैं इस संस्थान से प्रतिवर्ष 40 उच्च दर्जे के प्रशिक्षित छात्र निकलते हैं। जो संपादन, निर्देशन पटकथा लेखन, चलचित्र, फोटोग्राफी में निपूर्ण होते हैं। यह छात्र उद्योग में ही नहीं सिनेमा और टीवी में सृजनात्मक कार्य करते हैं। | **माध्यमिक/अंतिम**<br>अंतिम वर्ष बैच (2008-11 सत्र का छठा बैच) के 39 छात्र अपनी अंतिम परियोजनाएं पूरी कर रहे होंगे। परियोजना अवधि में 30 मिनट अवधि की 10 लघु फिल्में (डिप्लोमा फिल्में) निर्मित की जाती हैं।<br>9वां बैच तथा 2009-13 का 10वां बैच (जूनियर) परियोजना कार्य सहित निर्धारित समयसीमा के मुताबिक अपने पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहा होगा।<br>इस अवधि में 2013 के 10वें नए बैच के प्रवेश का कार्य शुरू किया जाएगा।<br>नए दाखिले (11वीं पंचवर्षीय योजना 2012-15) में लिए गए | 1. अनुमानित परिणाम/प्रतिफल की उपलब्धि धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है।<br>2. संस्थान के नियंत्रण से बाहर का कोई कारक |

*(करोड़ रुपये में)*

| क्रं. सं. | स्कीम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | 2011-12 के लिए अनुमोदित परिव्यय | वास्तविक प्रतिफल | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/समयबद्धता | टिप्पणियां/ जोखिम घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | एस आर एफ टी आई कोलकाता में केप्टिव टीवी चैनल स्कीम | स्कीम एसआरएफटीआई, कोलकाता में ''ए फीडर टेलीविजन सॉफ्टवेयर बेस'' के विकास के विचार से शुरू की गई। | 0.01 | स्कीम समाज तथा सामुदायिक विकास के लक्ष्य के साथ नए उभरते स्थानीय टी वी नेटवर्क की आवश्यकताओं को पूरा करने के ऑन लाइन टीवी के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए नए रास्ते खोलेगी। | स्कीम का उद्देश्य प्रशिक्षण की गुणवत्ता में नए मूल्य जोड़ना है जिससे छात्रों को भविष्य में रोजगार के अवसर बढ़ सकें तथा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। | | 1. स्कीम के लक्ष्य की उपलब्धि धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है।<br>2. लाइसेंस के लिए सरकारी अनुमति की प्राप्ति<br>3. संस्थान के नियंत्रण से बाहर का कोई कारक |
| 2. | एस आर एफ टी आई में सामुदायिक रेडियो | स्कीम का मुख्य उद्देश्य रेडियो के क्षेत्र में छात्रों को ऑन-लाइन प्रशिक्षण देना है। | 0.08 | स्कीम परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय रुचि खासकर मनोरंजक कार्यक्रमों जैसी जन जागरूकता के लिए है। | स्कीम का उद्देश्य प्रशिक्षण की गुणवत्ता में नए मूल्य जोड़ना है जिससे छात्रों को भविष्य में रोजगार के अवसर बढ़ सकें तथा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें।<br>एक बार परियोजना समेकित हो जाए तो सरकारी विभागों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों से रेडियो कार्यक्रम प्रायोजित होने लगेंगे जिससे निर्माण लागत आंशिक या पूरी निकल आएगी। | बेसिल ने परियोजना चालू करने का कार्य पूरा कर लिया है और प्रसारण लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। 24 मई 2008 को सी आर सी का प्रसारण शुरू हो चुका है। तब से कार्यक्रम नियमित प्रसारित हो रहे हैं।<br>लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, कार्यक्रमों की विषयवस्तु को विविधता प्रदान की जाएगी, प्रसारण समय 3 घंटे (सुबह) से +2 घंटे पुनः प्रसारण कर बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। | 1. लक्ष्य उपलब्धि धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है।<br>2. संचालन लाइसेंस का नवीनीकरण तथा फ्रीक्वेंसी लाइसेंस<br>3. संस्थान के नियंत्रण से बाहर के कारक |

*(करोड़ रुपये में)*

| क्रं. सं. | स्कीम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | 2011-12 के लिए अनुमोदित परिव्यय | वास्तविक प्रतिफल | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/समयबद्धता माध्यमिक/अंतिम | टिप्पणियां/ जोखिम घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | एस एआर एफ टी आई में छात्रवृत्ति तथा आदान-प्रदान कार्यक्रम सहित एच आर डी पहलू | स्कीम की परिकल्पना फिल्म निर्माण में उभरते चलन तथा प्रौद्योगिकी पर ज्ञान की आपसी समझ साझा करने के उद्देश्य से प्रतिष्ठित विदेशी फिल्म स्कूलों के साथ निरंतर छात्र/संकाय-आदान प्रदान करना है। | 0.20 | 1. छात्र आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित करना<br>2. छात्रवृत्ति अनुदान<br>3. राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में भागीदारी आयोजित करना | स्कीम का उद्देश्य नए मूल्यों के साथ प्रशिक्षण में गुणवत्ता बढ़ाना है जिससे भविष्य में रोजगार के अवसर बढ़ सकें। | छात्र आदान प्रदान कार्यक्रम का अगला चरण शुरू किया जाएगा, छात्रवृत्ति/इंटर्नशिप कार्यक्रम जअंतराष्ट्रीय आदान-प्रदान कार्यक्रम जारी रहेंगे। | 1. लक्ष्य उपलब्धि धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है।<br>2. संचालन लाइसेंस का नवीनीकरण तथा फ्रीक्वेंसी लाइसेंस<br>3. संस्थान के नियंत्रण से बाहर के कारक |
| 4. | प्रशिक्षण और कौशल विकास डब्ल्यु. आर. टी. सामाजिक सुसंगत फिल्म निर्माण | परियोजना अनिवार्य रूप से संस्थान द्वारा फिल्म एवं टीवी के क्षेत्र में नौजवान छात्रों को दिए जा रहे प्रशिक्षण में वांछित मूल्य वर्धन करना है। स्कीम के तहत प्रस्तावित तत्वों से संस्थान की मौजूदा प्रशिक्षण गतिविधियों को और बढ़ाएंगी जिससे उद्योग की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो रहे छात्रों को सहायता मिल सके। | 1.00 | 1. फिल्म और टी वी के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी विकास के साथ परिचय कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना<br>2. सामाजिक रूप से सुसंगत फिल्मों का निर्माण<br>3. न्यूज लैटर का प्रकाशन | सिनेमा और टीवी के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकीय बदलावों से परिचय में स्कीम संकाय सदस्यों की मदद करेगी। स्थानीय कार्यक्रम में कलाकार प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ विचारों के आदान प्रदान में सहायता करेंगे। छात्रों को भी इस अवसर पर बातचीत का मौका मिलेगा फिल्म निर्माण के प्रावधान से निर्माण में छात्रों को सीधा अनुभव मिलेगा जो उनके कैरियर की चुनौतियों से निपटने में मददगार साबित होगा अपनी फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन | 1. संकाय चक्रानुक्रम में फिल्म निर्माण और उससे संबंधित पहलुओं पर लघु पाठ्यक्रम शुरू करेगा। उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, सेमिनारों, महोत्सवों में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।<br>2. स्थानीय कार्यक्रमों में अंतराष्ट्रीय-राष्ट्रीय कलाकार होंगे जिनसे छात्र-संकाय को बातचीत का मौका मिलेगा।<br>3. छात्रों की भागीदारी से योजना वर्षों में संकाय पूरी फीचर फिल्म तथा वृत्त | 1. लक्ष्य उपलब्धि धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है।<br>2. संचालन लाइसेंस का नवीनीकरण तथा फ्रीक्वेंसी लाइसेंस |

*(करोड़ रुपये में)*

| क्रं. सं. | स्कीम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | 2012-13 के लिए अनुमोदित परिव्यय | वास्तविक प्रतिफल | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/समयबद्धता माध्यमिक/अंतिम | टिप्पणियां/ जोखिम घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | से उन्हें संस्थान के छात्र के रूप में अपनी प्रतिभा आकलन का अवसर मिलेगा। | चित्र का निर्माण करेगा।<br>4. स्कीम में छात्र फिल्मोत्सव 'क्लेप्स्टिक' तथा 'डोसेज' छात्रों तथा फिल्मकारों के बीच फिल्म जागरूकता फैलाएंगे।<br>5. संस्थान अपनी अकादमिक तथा अन्य गतिविधियों को प्रमुखता से द्विवार्षिक न्यूज लैटर (टेकवन) में प्रकाशित करेगा। | |
| 2. | संस्था को अनुदान | 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार नए स्टूडियो का निर्माण | 8.00 | • नए फिल्म स्टूडियो तथा फिल्म अभिलेखागार का निर्माण 50 प्रतिशत पूर्ण | संस्थान स्थापित करने का उद्देश्य पूरा होगा और संस्थान आत्मनिर्भर बनेगा। छात्र समुदाय लाभांवित होगी और अपने पाठ्यक्रम समय से पूरा कर सकेगी। नियमित गतिविधियों को व्यवस्थित करने पर, संस्थान का और विकास होगा और भारतीय मीडिया की गुणवत्ता में सुधार होगा। | • आर्किटेक डिजाइन और योजना<br>• विद्युतिकरण और सिरिल कार्य (सी सी डब्ल्यू द्वारा किया गया)<br>• उपकरण का खरीद और इस्टॉल करना | 1. लक्ष्य उपलब्धि धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है।<br>2. संचालन लाइसेंस का नवीनीकरण तथा फ्रीक्वेंसी लाइसेंस<br>3. संस्थान के नियंत्रण से बाहर के कारक |

# मुख्य सचिवालय फिल्म विंग योजना

## ( क ) एंटी पायरेसी पर पहल

*(करोड़ रुपये में)*

| क्रम सं | योजना/ कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2012-13 | | | निर्धारित/ वितरणीय भौतिक परिव्यय | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम का घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 4(i) गैर-योजना बजट | 4(ii) योजना बजट | 4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन | | | | |
| 1. | एंटी पायरेसी पहल | पाइरेसी किसी भी सृजनात्मक क्षेत्र विशेषकर फिल्म क्षेत्र में एक बड़ा खतरा है। इसलिए स्कीम का मुख्य उद्देश्य सभी हितधारकों के बीच पाइरेसी के खिलाफ जागरूकता फैलाने और इससे पार पाने के लिए शिक्षित करना है। स्कीम में उन कदमों को ही आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है जिन्हें मंत्रालय पहले ही उठा चुका है। स्कीम के तहत फिल्म, प्रसारण और संगीत उद्योग से सभी को शामिल कर मल्टी-मीडिया अभियान शुरू करने का विचार है। फिल्म और मीडिया से कई हस्तियों को अनुरोध किया जाएगा जो पाइरेटड सामान खरीदने से मना करने का लोगों से अनुरोध करेंगे। ये अभियान दूरदर्शन/ एआईआर, निजी टीवी चैनलों और निजी एफएम पर चलाए जाएंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कॉपीराइट अधिनियम के बारे में जागरूक करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सो में पुलिस, न्यायिक तथा प्रशसनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। पाइरेसी से लड़ने के लिए पाइरेसी के प्रभाव पर शोध कराया जाएगा ताकि विकास के साथ-साथ सार्वजनिक निजी रणनीतियों को कारगर बनाया जा सके। | — | 0.10 | — | 1. परियोजना रिपोर्ट विवरण अंतिम प्रारूप<br>2. अधिकृत अधिकारियों से अनुमति<br>3. सार्वजनिक निजी मजबूतीकरण मल्टी मीडिया के द्वारा | एंटी पायरेसी के प्रति जागरूकता लाने के लिए पहल | एसपीसी और फंड के लिए अनुमति लक्ष्य कॉलम 5 में 2012-2013 के लिए है। | |

# फिल्मों का शताब्दी समारोह—1913 से 2013

*(करोड़ रुपये में)*

| क्रम सं. | योजना/ कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2012-13 | | | निर्धारित/ वितरणीय भौतिक परिव्यय | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम का घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 4(i) गैर-योजना बजट | 4(ii) योजना बजट | 4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन | | | | |
| 1. | फिल्मों का शताब्दी समारोह (1913-2013) | भारतीय सिनेमा की 100वीं वर्षगांठ | — | 3.00 | — | 1. विस्तार परियोजना का अंतिम प्रारूप<br>2. अधिकृत अधिकारी की मंजूरी<br>3. कार्य और विभिन्न गतिविधियों का शताब्दी समारोह | अंतिम गतिविधियों का फिल्मों का शताब्दी समारोह | एसएफसी और फंड जारी लक्षित सीटी कॉलम 5 के अनुभाग 2012-13 | |

# राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन

*(करोड़ रुपये में)*

| क्र. सं. | योजना/ कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/ परिणाम | परिव्यय 2011-12 | | | परिमाणकीय/ हस्तांतरणीय वास्तविक प्रतिफल | लक्षित परिव्यय | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4(i) | 4(ii) | 4(iii) | | | | |
| | | | गैर-योजना बजट | योजना बजट | पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन | | | | |
| 2. | राष्ट्रीय फिल्म विरासत | फिल्म का निर्माण का लक्ष्य संरक्षित बिना किसी चूक के अंत तक | - | 20.00 | - | (i) परियोजना का अंतिम विस्तार<br>(ii) अधिकृत अधिकारी से अनुमति<br>(iii) डिजिटल भविष्य का कार्य आरंभ फिल्मों एवं छोटी फिल्मों का | डिजिटिलाइजेशन का आरंभ। पुन-संरक्षित पुराने फीचर फिल्म का | ईएफसी के द्वारा पारित। कालम 5 की तरह योजना आरंभ वित्तीय सहायता मिलने के बाद होगा। | |

# भारत और विदेशों में आयोजित फिल्म बाजारों में भागीदारी

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय फिल्म विंग की मुख्य सचि. स्कीम

*(करोड़ रुपये में)*

| क्रं. सं. | योजना कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2012-13 | | | परिमाणनीय/वितरण योग्य वास्तविक आउटपुट | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणियां/ जोखिम घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | (i) नॉन प्लान बजट | (ii) प्लान बजट | (iii) | | | | |
| 1. | विदेशी फिल्म समारोहों/ बाजारों में भागीदारी | भारतीय फिल्मों के निर्यात को प्रोत्साहित करना और भारतीय फिल्मों के लिए बाजार का विस्तार करने के लिए फिल्मों को एक उद्योग के रूप में मजबूती प्रदान करना | | 15.00 | शून्य | भारतीय फिल्मों को विश्वस्तर पर बढावा देने के लिए फिल्म समारोहों में भागीदारी<br>(i) अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोतसवों में भागीदारी<br>(ii) एसपीवी की स्थापना आईएफएफआई के द्वारा<br>(iii) फिल्मों का चयन भारतीय पैनोरमा 2012<br>(iv) भागीदारी/20 फिल्म महोत्सव का भारत एवं विदेश में आयोजित | भारतीय फिल्मों के विश्व बाजार में अधिक से अधिक दिखाने तथा भारतीय फिल्मों को बढावा देने के लिए अंतराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन<br>(iii) इफ्फी में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का अलग एसपीवी<br>(iv) गांवो के बच्चे के लिए अच्छी फिल्म को प्रदर्शित किया जाए।<br>(v) फिल्म निर्माता एवं निर्देशक के लिए अपने फिल्मों को दर्शाने हेतु प्लेटफार्म। | कॉलम 5 में दिए गए वितरण योग्य परिणामों के अतिरिक्त दृश्यता बढ़ाने की अन्य पहलों के लिए व्यय हो सकता है। | |

*(लाख रुपये में)*

| क्र. सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2012-13 | निर्धारणीय/वितरणीय भौतिक परिव्यय | प्रक्षिप्त परिणाम | प्रक्रिया/समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (v) 5 फिल्मी बाजार में भागीदारी<br><br>(vi) 5000 शो का आयोजन और 25 लाख बच्चे लाभांवित<br><br>(vii) बच्चों के लिए फिल्म महोत्सव का आयोजन | एसपीसी का अंतिम प्रारुप और वित्त के जारी होने का इंतजार ताकि कार्य को पूरा किया जाए | | |
| | | **कुल : (क)** | **15.00** | | | | |

# फिल्म एवं वृत्तचित्र का विभिन्न भाषाओं में निर्माण

*(करोड़ रुपये में)*

| क्र. सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2012-13 | निर्धारणीय/वितरणीय भौतिक परिव्यय | प्रक्षिप्त परिणाम | प्रक्रिया/समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (i) | फिल्म एवं वृतचित्र का विभिन्न भाषाओं में निर्माण (योजना) | (i) फिल्म निर्माण विभिन्न भारतीय/ क्षेत्रीय भाषा में नये टेलेंट को बढ़ावा देना और इससे विदेश सह-निर्माण को बढ़ावा देना<br><br>(ii) एडवांस शिक्षा और संस्कृति फिल्मों के माध्यम और स्वस्थ वातावरण में बच्चों को फिल्मों द्वारा बढ़ावा देना।<br><br>(iii) बाहर के ज्यादा से ज्यादा निर्माता को बुनियादी सूचना की जानकारी देकर वृतचित्र बनाने के लिए बढ़ावा | 35 | (i) एनएफडीसी द्वारा 5 क्षेत्रीय भाषा में फिल्मों का निर्माण<br><br>(ii) 03 फीचर फिल्में और 02 लघु फिल्म 14 डबिंग इत्यादि बाल चित्र समिति द्वारा<br><br>(iii) फिल्म प्रभाग द्वारा 100 फिल्मों का निर्माण | (i) नए टेलेंट को प्रोत्साहन।<br>(ii) अपनी समृद्ध संस्कृति से दुनियां को परिचित कराना।<br>(iii) बच्चों के लिए स्वस्थ्य वातावरण बनाने के लिए फिल्मों का निर्माण।<br>(iv) बाहर के ज्यादा से ज्यादा निर्माता को बुनियादी सूचना की जानकारी देकर वृतचित्र बनाने के लिए बढ़ावा | एसएफसी का अंतिम प्रारूप और वित्त जारी होने पर लक्ष्य की प्राप्ति का इंतजार | |

# राष्ट्रीय एनीमेशन गेमिंग और विशेष प्रभाव के लिए उत्कृष्टता केन्द्र

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना संबंधी नई योजना | उच्च प्रौद्योगिकी विषयवस्तु उद्योग में कार्मिकों की समस्या के समाधान के लिए ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव में उत्कृष्टता के लिए सरकारी-निजी भागीदारी में केंद्र की स्थापना। | – | 1.00 | – | (i) एम/एस पीडब्ल्युसी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उत्कृष्टता केंद्र और बीएफएक्स की स्थापना के लिए सिफारिश की है।<br>(ii) एम/एस पी डबल्यु सी द्वारा सौंपे गए विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।<br>(iii) संपूर्ण स्कीम के लिए योजना आयोग का अनुमोदन | विस्तृत डीपीआर के आधार पर तथा नई स्कीम पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करना। | परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 'उत्कृष्टता केंद्र' की स्थापना के लिए अपेक्षित धन की व्यवस्था और स्थापना में लगने वाले समय के मुद्दे स्पष्ट होंगे। | यह योजना सरकारी-निजी भागीदारी में लागू की जानी है। इसलिए निजी पार्टियों के योगदान की पहचान करनी होगी। |

# प्रसारण क्षेत्र

## इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानिटरिंग केंद्र

**2.18 करोड़ रुपये का वार्षिक योजना 4.50 करोड़ 2011-12 में आवंटन, परिव्यय 2012-13 को 10.00 करोड़ (योजना) औ्र 4.38 करोड़ (गैर-योजना) ब्यौरा निम्नलिखित है :**

**बजट (2012-13) योजना/गैर योजना** *(करोड़ रुपये में)*

| क्र. सं. | स्कीम का नाम | उद्देश्य/ परिणाम | परिव्यय 2012-13 | | | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयसीमा | टिप्पणी/ जोखिम घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4(i) | 4(ii) | 4(iii) | | | | |
| | | | गैर-योजना बजट | योजना बजट | पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन | | | | |
| 1. | इलेक्ट्रानिक मीडिया अनुश्रवण केन्द्र (ई एम एम सी) की स्थापना। | निजी/विदेशी टी वी चैनलों के कार्यक्रमों की मानिटरिंग ताकि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में निर्धारित विज्ञापनों और कार्यक्रमों के कोड का अनुपालन निश्चित किया जा सके।<br>निजी एफएम चैनलों की भी लाइसेंस जारी किया जाएगा। | 4.38 | 10.00 करोड़ (स्वीकृत परिव्यय) | शून्य | चूंकि यह एक मानिटरिंग सुविधा है इसलिए लाभ की मात्रा निश्चित नहीं की जा सकती। वास्तविक आउटपुट 9 जून 2008 से लगभग 300 चैनलों की निगरानी की जा रही है। आवश्यक मशीनरी और उपकरण लगा दिए गए हैं। एफएम में निगरानी हेतु मशीन लगाई जा रही है। | ईएमएमसी द्वारा 9.6.2008 से 100 टीवी चैनलों की मानिंटरिंग शुरु की गई थी बाद में 2008-09 के दौरान इसे बढ़ाकर 150 टीवी चैनल कर दिया गया। इसे 5.1.2011 से फिर से बढ़ाकर 300 टीवी चैनल कर दिया गया है। योजना आवंटन के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। आगे इसमें एफएम की निगरानी की मशीन लगाई जाएगी। | ईएमएमसी की मानिटरिंग क्षमता बढ़ाकर 300 चैनल कर दी गई है। निजी एफएम चैनलों की मानिटरिंग कार्यविधि के लिए प्रक्रिया चल रही है जो 31 मार्च 2012 तक पूरी हो जाने की संभावना है। | ईएमएमसी 300 टी वी चैनलों की मानिटरिंग कर रहा है। निजी एफएम चैनलों की मानिटरिंग कार्यविधि का कार्य प्रक्रियाधीन है लगभग 700 लाइसेंस जारी किए गए है। |

# एफएम सैल

मेसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लिमिटेड (बेसिल) मंत्रालय की तरफ से छह शहरों में एफएम टावरों की स्थापना के लिए निजी एफएम रेडियो परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है। इस परियोजना के लिए मंत्रालय की ओर से धन उपलब्ध कराया जा रहा है।

बेसिल ने मंत्रालय की तरफ से 6 शहरों में निजी एफएम चैनल की स्थापना की। इस कार्य के लिए वित्तीय सहायता मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।

*(रुपये करोड़ में)*

| क्र. सं. | योजना कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2012-13 | | | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4(i) | 4(ii) | 4(iii) | | | | |
| | | | गैर-योजना बजट | योजना बजट | अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन | | | | |
| 1. | निजी एफएम रेडियो (6 शहरों जैसे दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता और देहरादून) में नए टावरों को लगाने का कार्य | निजी एफएम प्रसारकों के लिए ट्रांसमिशन उपकरणों को सह-स्थापित करने के लिए नए ट्रांसमिशन टावरों को लगाने का कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद और देहरादून में पांच टावरों के लगाने का कार्य पूरा हो गया है। कोलकाता में टावर लगाने का काम अभी शुरू होना है क्योंकि वहां बिना बाधा वाली कोई जगह उपलब्ध नहीं है। | शून्य | लागू नहीं | |

# मुख्य सचिवालय प्रसारण विंग योजना
## अंतर्राष्ट्रीय चैनल

### वित्तीय परिव्यय, अनुमानित वास्तविक आउटपुट तथा अनुमानित परिणाम

चूंकि योजना आरंभिक चरण में है, इसके लिए वर्ष 2011-12 के बजट में 1.0 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

| क्र. सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/ परिणाम | परिव्यय 2011-12 | | | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4(i) गैर-योजना बजट | 4(ii) गैर-योजना बजट | कांम्पली-मेंटरी अतिरिक्त बजटीय संसाधन | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | अंतर्राष्ट्रीय चैनल | प्रमुख उद्देश्य दुनिया भर में भारत की स्थिति को उसी प्रकार प्रस्तुत करना है, जैसा अलजज़ीरा बीबीसी, सीएनएन, सीसीटीवी, आदि पर किया जाता है। | - | .01 | - | इसके लिये डीडी इंडिया जिसे बहुत से देशों में देखा जाता है, पर प्रसारण के साथ-साथ वर्तमान डीडी न्यूज़ चैनल के जरिये अंतर्राष्ट्रीय समाचारों और कार्यक्रमों की शुरुआत करनी होगी। | संवेदनशील मसलों पर भारत की स्थिति और दृष्टिकोण को संभवत: अधिकतम देशों में यथाशीघ्र पहुंचाना। | प्रस्ताव प्रतिपादन के चरण में है। | |

# सामुदायिक रेडियो के लिए आईईसी गतिविधियां

**भारत में सामुदायिक रेडियो क्रांति का सहयोग**

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अनुदान के पुरस्कार को प्रस्तावित किया है। इसके अंतर्गत सक्रिय और नए रेडियो स्टेशन जिसमें बुनियादी सुविधा/उपकरण/प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/रचनात्मक विभाग और ऑपरेशन मूल्य इत्यादि। स्टेशन को 1 से 15 लाख रुपये स्थितिनुसार अनुदान दिया जायेगा। 5 साल में 500 नए सामुदायिक रेडियो स्टेशन और 300 सामुदायिक रेडियो को सहयोग किया जाता है।

मंत्रालय ने अपनी नीति के प्रति जागरूकता लाने का प्रस्ताव है और संगठन में क्षमता निर्माण की अनुमति जागरूकता/क्षमता निर्माण वर्कशाप और राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी इत्यादि। देश के विभिन्न भागों में है। इसके अतिरिक्त आईईसी का डिजाइन और सीआर ऑपरेटर द्वारा तकनीकी प्रशिक्षण, सामुदायिक रेडियो का भारत और विदेशी ढ़ांचे में प्रसारण प्रणालियों के संचालन की उर्वर भूमि की मौजूदगी दर्शाती है। सामुदायिक रेडियो का विकास एवं रखरखाव ऑन लाइन पोर्टल द्वारा किया जाता है। सामुदायिक प्रबंधन प्रणाली एवं सामग्री का आदान-प्रदान प्रचार/आईईसी की प्रिंटिंग सामग्री/पंचायत में किड वितरण और रेडियो के लिए सहयोगी संसाधन का क्षेत्र है।

बीई 2012-13 में 5 करोड़ रुपये भारतीय सामुदायिक रेडियो प्रबंधन सहयोग की योजना है, 3 करोड़ रुपये सीआरएसएस, 2 करोड़ रुपये आईईसी गतिविधि के लिए रखा है। परिणाम बजट (2012-13) की योजना भारतीय सामुदायिक रेडियो प्रबंधन सहयोग का टेबल नीचे हैं -

*(करोड़ रुपये में)*

| क्र. सं. | योजना/ कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/ परिणाम | परिव्यय 2012-13 | | | परिमाणकीय/ हस्तांतरणीय वास्तविक प्रतिफल | लक्षित परिव्यय | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4(i) | 4(ii) | 4(iii) | | | | |
| | | | गैर-योजना बजट | योजना बजट | पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन | | | | |
| 1. | सामुदायिक रेडियो सहयोग योजना | नए कार्यरत सामुदायिक रेडियो का स्रोत/क्षमता और तकनीकी द्वारा सामुदायिक दायित्व को पूरा करते है। | - | 3.00 | - | सामुदायिक रेडियो का विशेषकर सुदूर, ग्रामीण और गरीबी रेखा के आसपास का क्षेत्र में कार्यरत है। | सामुदायिक रेडियो की संख्या बढ़ी। | प्रबंधन एवं कागज पत्री के लिए सामुदायिक रेडियो को अनुदान हेतु नीति। | |

*(करोड़ रुपये में)*

| क्र. सं. | योजना/ कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/ परिणाम | परिव्यय 2012-13 | | | परिमाणकीय/ हस्तांतरणीय वास्तविक प्रतिफल | लक्षित परिव्यय | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी/ जोखिम घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4(i) | 4(ii) | 4(iii) | | | | |
| | | | गैर-योजना बजट | योजना बजट | पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन | | | | |
| 2. | सामुदायिक रेडियो के लिए आई ई सी गतिविधियां | सामुदायिक रेडियो प्रसारण के लिए अनुदान | - | 2.00 | - | एनजीओ/सीएसओ के बीच नीति के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा वर्तमान में कार्य कर रहे सामुदायिक रेडियो स्टेशनों संचालकों की क्षमता निर्माण करना। | समाज और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता, सांस्कृतिक एवं सामाजिक एकात्मकता के जरिए सामुदायिक विकास। | देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यशालाएं/ परामर्श और प्रचार का आयोजन। | |

# दूरदर्शन

**परिव्यय तथा परिणाम/लक्ष्यों का वक्तव्य ( 2011-12 )**

*(करोड़ रुपये में)*

| क्र. सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/ परिणाम | स्वीकृत परिव्यय ( 2011-12 ) | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता ( तिमाही लक्ष्य ) | | टिप्पणी/ जोखिम घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | 7. |
| | **चालू स्कीम** | | | | | | |
| 1. | जम्मू-कश्मीर विशेष योजना चरण-I तथा II (पूंजी) | जम्मू-कश्मीर में दूरदर्शन कवरेज प्रसारण में सुधार। अमृतसर में टावर निर्माण के अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर विशेष पैकेज का पहला चरण कार्यान्वित हो गया है, टावर निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इसके परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर में दूरदर्शन प्रसारण की गुणवत्ता तथा कवरेज एरिया में सुधार होगा। योजना के द्वितीय चरण में कंटेंट के सुधार पर जोर दिया गया है। | 2.20 | अमृतसर में 300 एमटीआर टावर<br>अमृतसर में 300 मीटर ऊंचे टावर पर लगे एंटिना से डीडी-1 तथा डीडी-न्यूज एचपीटी का आरंभ | सीमापारीय क्षेत्रों में टीवी कवरेज में वृद्धि<br>सीमापारीय क्षेत्रों में डीडी-1 तथा डीडी-न्यूज चैनल उपलब्ध कराना | नई साइट पर डीडी-1 और डीडी (न्यूज) ट्रांसमीटर का संस्थापन और उन्हें चालू करना-तीसरी तिमाही | - शून्य - |
| | राजस्व | डीडी कशीर चैनल के लिए कार्यक्रमों का निर्माण/अधिग्रहण/कमीशनिंग और डीडीके श्रीनगर, जम्मू व लेह के लिए क्षेत्रीय सेवा | 53.89 | 8000 एपीसोड का कार्यक्रम | डीडीके श्रीनगर, जम्मू और लेह की डीडी कशीर/क्षेत्रीय सेवा के लिए नए और बेहतर सॉफ्टवेयर | वार्षिक आवंटन के अनुसार | वर्तमान वित वर्ष का 70 रुपये का दायितव आगे ले जाया गया |
| 2. | निर्माण सुविधाओं (स्टूडियो/ओबी) का आधुनिकीकरण तथा डिजिटलीकरण | कार्यक्रमों की तकनीकी गुणवता बढ़ाना | 3.00 | स्टूडियो केंद्र, केंद्रीकृत रिकार्डिंग, संपादन तथा प्लेबैक का सभी 17 मुख्य दूरदर्शन केंद्रों में आधुनिकीकरण। ओ बी सुविधाओं का विस्तार तथा तीव्र न्यूज डिलीवरी प्रणाली | स्टूडियो का डिजिटलीकरण | कार्य चालू है | |

| क्र. सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/ परिणाम | परिव्यय 2011-12 | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | पूर्वोत्तर विशेष पैकेज चरण-II (पूंजी) | पूर्वोत्तर तथा अंडमान-निकोबार क्षेत्र में दूरदर्शन कवरेज का सुदृढ़िकरण। पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप के द्वीपीय इलाकों में दूरदर्शन सेवाओं के विस्तार तथा सुधार के लिए सरकार ने एक विशेष पैकेज (द्वितीय चरण) को मंजूरी दी। | 1.91 | पूर्वोतर के लिए डीएसएनजी की चार यूनिट और अंडमान निकोबार के लिए एक यूनिट | पूर्वोतर और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में समाचार एकत्र करने की सुविधा बढाना | डीएसएनजी की एक यूनिट की आपूर्ति | डीजीएनजी की तीन यूनिट की आपूर्ति की गई |
| | राजस्व | डीडी नार्थ ईस्ट के सैटेलाइट चैनल के लिए प्रोडकशन और सॉफटवेयर को चालू करना और उत्तर पूर्व के 11 क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए कार्यक्रमों का निर्माण अधिग्रहण कमीशनिंग | 20.00 | 6880 एपीसोड के इनहाउस और कमिशनड कार्यक्रम | उत्तर पूर्व में डीडी चैनलों और 11 क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए नए और गुणवत्तावान कार्यक्रम | | |
| 4. | डीटीएच | इस योजना का उद्देश्य शेष बचे क्षेत्रों में टीवी कवरेज उपलब्ध कराना है। | 0.00 | | | | डीटीएच सेवा शुरू हो चुकी है |
| 5. | एचडीटीवी | यह वह तकनीक है जो उत्कृष्ट पिक्चर तथा वाइड स्क्रीन इमेज के कार्यों में अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इस तकनीक से 35 मी.मी. फिल्म जैसी पिक्चर क्वालिटी मिलती है। यह तकनीक डिजिटल सराउंडिंग साउंड भी उपलब्ध कराती है। एचडीटीवी फिल्ड प्रोडक्शन के लिए प्रायोगिक परियोजना का कार्य चालू है। | 0.40 | एचडीटीवी प्रोडक्शन के लिए पायलट परियोजना चालू करना । | प्रायोगिक योजना एचडीटीवी फार्मेट में निर्माण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। | | फील्ड निर्माण वैन खरीद ली गई है |
| **6.** | **दसवीं योजना की अन्य अनुमोदित योजना** | | 25.00 | | | | |

| क्र. सं. | स्कीम/कार्यक्रम | उद्देश्य/ परिणाम | परिव्यय 2012-13 (योजना बजट) | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | मौजूदा नेटवर्क का डिजिटलीकरण<br>पूंजी<br>राजस्व | ट्रांसमीशन, रिकार्डिंग आदि का सुधार | 225.60<br>27.00 | | | |
| 1.1 | ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण | | | | | |
| क. | एमडब्लू ट्रांसमीटर | | 95.00 | | | |
| i | राजकोट में ट्रांसमीटर बदलना | | 2.00 | कार्य पूरा | परियोजना मंजूरी | |
| ii | कावारती में ट्रांसमीटर बदलना | | 0.50 | | स्थापन पूरा | |
| | | | 0.60 | कावारती में होस्टल | कार्य प्रगति पर -कार्य पूरा | |
| iii | चिन्सुरा में ट्रांसमीटर बदलना | | 2.30 | ट्रांसमीटर स्थापन पूरा | कार्य प्रगति पर परियोजना मंजूर | |
| iv | दिल्ली बीबी, बाड़मेर, बीकानेर, चेन्नई, गुवाहाटी, तवांग | | 11.00 | प्राप्ति स्थापन | उपकरणों की प्राप्ति, परीक्षण, मंजूरी | |
| | | | 1.00 | सिविल कार्य पूरा | सिविल कार्य पूरा | |
| | | | 3.00 | विभागीय कार्य पूरा | विभागीय कार्य पूरा | |

| क्र. सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/ परिणाम | परिव्यय 2011-12 | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम | प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) | टिप्पणी/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **नई योजना** | | | | | |
| v | विजयवाड़ा, पटना, पणजी, रांची, मुंबई, पुणे, तिरुचिरापल्ली, वाराणसी, कोलकाता, मुंबई, पासी घाट | | 8.00 | प्राप्ति, स्थापन | सिविल कार्य पूरा | |
| | | | 2.50 | सिविल कार्य पूरा | विभागीय कार्य पूरा | |
| | | | 5.00 | उपकरण प्राप्ति, विभागीय कार्य पूरा | विभागीय कार्य पूरा | |
| vi | दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलुरू तथा धारवाड, जबलपुर, अजमेर, चेन्नई, सिलीगुड़ी, ईटानगर | | 15.00 | प्राप्ति स्थापन | उपकरणों का निरीक्षण, प्राप्ति | |
| | | | 2.00 | सिविल कार्य पूरा | सिविल कार्य प्रगति पर, कार्य पूरा | |
| | | | 5.00 | उपकरण प्राप्ति, विभागीय कार्य पूरा | जोनल उपकरणों की प्राप्ति और विभागीय कार्य शुरू | |
| vii | डिब्रूगढ़, राजकोट, जम्मू, जालंधर, सूरतगढ़, लखनऊ | | 12.00 | उपकरण प्राप्ति, विभागीय कार्य पूरा | उपकरणों का निरीक्षण, प्राप्ति | |
| | | | 2.00 | सिविल कार्य पूरा | सिविल कार्य प्रगति पर, कार्य पूरा | |

| क्र. सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/ परिणाम | | परिव्यय 2011-12 | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम | प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) | टिप्पणी/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | |
| | एस डब्लयू ट्रांसमीटर | | | 24.00 | | | |
| i | एस डब्लयू डीआरएम ट्रांसमीटर बदलना 5 एस डब्ल्यू ट्रांसमीटर (दिल्ली 2, अलीगढ़ 2, बंगलूरू 1 | | | 14.50 | 500 केवी एस डब्ल्यू ट्रांसमीटर की प्राप्ति आर्डर लागत 16.33 करोड़ | निगरानी, प्राप्ति, स्थापन | |
| (ग) | एफएम ट्रांसमीटर | | | 40.10 | | | |
| i | विस्तार | | | 35.25 | | | |
| | 10वीं योजना स्कीम के तहत एफ एम विस्तार | | | 0.10 | हल्द्वानी, रायबरेली और चंपावत में स्थल अधिग्रहण | हल्द्वानी, रायबरेली और चंपावत में स्थल अधिग्रहण | |
| | | | | 0.10 | फाजिल्का, अमृतसर, चौटान हिल तथा रायबरेली | उपकरणों के लिए आदेश निगरानी | |
| | | | | 2.00 | सिलचर और गंगटोक के लिए पैनल एंटीना की प्राप्ति | उपकरण निगरानी, प्राप्ति, स्थापन | |
| | 11वीं योजना के तहत मौजूदा 24 एआईआर/टीवी स्थलों का एफएम विस्तार | | | 1.74 | 12 स्थानों पर ट्रांसमीटरों का स्थापन | प्राप्ति, स्थापन, शुरूआत | |

| क्र. सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/ परिणाम | परिव्यय 2011-12 | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम | अनुमानित परिणाम प्रक्रियाएं/ (तिमाही लक्ष्य) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ii | | | | | | |
| | एफएम/एम डब्लू ट्रांसमीटरों को बदलना | | 4.85 | | | |
| | 11वीं योजना के तहत मौजूदा 40 स्टेशनों पर उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों का बदलना | | 0.10 | 27 ट्रांसमीटरों की प्राप्ति | Q1 - तकनीकी मूल्यांकन,<br>Q2 - उपकरण का आदेश,<br>Q4 - उपकरण निगरानी | |
| | | | 0.10 | 13 स्थानों पर बदलाव | Q1 - तकनीकी मूल्यांकन,<br>Q2 - उपकरण का आदेश,<br>Q4 - उपकरण निगरानी | |
| | | | 1.00 | भवन कार्य पूरा | Q1 - 27 जगह कार्य पूरा, 13 जगह जारी<br>Q2 - सभी जगह कार्य पूरा | |
| | | | 0.10 | जोनल उपकरणों की प्राप्ति और सिविल कार्य शुरू | जोनल उपकरणों की प्राप्ति और सिविल कार्य शुरू | |
| | | एफएम विस्तार के तहत अन्य प्राप्तियां | 0.10 | आदिलाबाद तथा क्योंझार में 100 मीटर स्व-सहायक टावर | तकनीकी मूल्यांकन, उपकरण का आदेश, उपकरण निगरानी | |
| | | | 1.40 | | Q1 - उपकरण प्राप्ति<br>Q2 - स्थान | |
| | | | 2.00 | एफएम मोन और स्टीरियो मॉनिटर | Q1 - उपकरण प्राप्ति<br>Q2 - स्थान | |

| क्र. सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/ परिणाम | परिव्यय 2010-11 | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| | स्टूडियो और नेटवर्किंग | | 46.20 | | | | |
| i | 10वीं योजना के तहत 49 स्थानों पर उच्चशक्ति सर्वरों की स्थापना | | 12.00 | 10वीं योजना के तहत 49 स्थानों पर उच्चशक्ति सर्वरों की स्थापना | Q1 - उपकरण के लिए आर्डर<br>Q2 - कुछ स्थानों पर उपकरण प्राप्ति | | |
| ii | एक्स प्लान के अंतर्गत 4 स्टूडियो की स्थापना | | 0.50 | 4 स्टूडियो पर कार्य लंबित | Q1 - परियोजना पूरी | | |
| 1.3 | संपर्क | | 15.10 | | | | |
| 1.4 | स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान को मजबूत करना | | 3.10 | | | | |
| 2 | सीमावर्ती क्षेत्रों की मजबूती | | 11.00 | | | | |
| i | जम्मू और कश्मीर में 3 एचपीटी/एलपीटी की स्थापना | | 0.50 | 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर की प्राप्ति | Q1 - उपकरण प्राप्त<br>Q2 - स्थापन | | |

| क्र. सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/ परिणाम | परिव्यय 2011-12 | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| III साइट | | | | | | | |
| | | | 0.50 | III साइट | III साइट | | |
| | | | 0.10 | 10 किलोवाट एफएम नौशेरा में | Q1 - आर्डर<br>Q2 - निगरानी | | |
| | | | 5.80 | 5 किलोवाट के 2 टीवी ट्रांसमीटर राजकोट में | Q1 - आर्डर<br>Q2 - निगरानी | | |
| | | | 0.10 | 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर और 10 किलोवाट टीवी ट्रांसमीटर डीडी में | Q1 - आर्डर<br>Q2 - निगरानी | | |
| | | | 2.00 | | कार्य प्रगति पर | | |
| | | | 01.00 | | कार्य प्रगति पर | | |
| | | | 0.50 | 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर की प्राप्ति | Q1 - उपकरण प्राप्त<br>Q2 - स्थापन | | |

| क्र. सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/ परिणाम | परिव्यय 2011-12 | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/ समयबद्धता | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| | 12वीं योजना के तहत एफएम ट्रांसमीटरों की निम्न स्थानों पर स्थापना<br>भारत – बंगलादेश<br>भारत – म्यांमार<br>भारत – चीन<br>भारत – भूटान<br>भारत – नेपाल<br>भारत – पाकिस्तान<br>लक्ष्यद्वीप तथा अंडमान और निकोबार | | 1.0 | स्कीम अनुमोदन, बजट स्वीकृति, उपकरण प्राप्ति | Q1 - स्कीम स्वीकृत<br>Q2 - स्वीकृत<br>Q3 - सिविल कार्य दिया गया<br>Q4 - एनआईटी जारी | | |
| 5. | ई-गवर्नेंस | मीडिया यूनिटों को तीव्र सूचना प्रसार, ऑन-लाइन प्रबंधन तथा ईआरपी समाधान | 0.10 | स्कीम की स्वीकृति, सिविल आकलन, उपकरण प्राप्ति तथा एनआईटी | स्कीम की स्वीकृति, सिविल आकलन, उपकरण प्राप्ति तथा एनआईटी | | |
| | स्कीम-II कंटेट विकास और प्रसार | | 25.00 | | | | |
| | स्कीम-III मानव संसाधन विकास | | 0.10 | | | | |
| | स्कीम-IV विशेष परियोजनाएं | | 247.0 | | | | |
| | कुल पूंजी | | 52.00 | | | | |
| | कुल (राजस्व) डीबीएसास | | 299.00 | | | | |

# प्रसार भारती
# दूरदर्शन - वार्षिक योजना ( 2012-13 )

*(करोड़ रुपये में)*

| क्रं. सं. | स्कीम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | 2012-13 के लिए अनुमोदित परिव्यय | वास्तविक प्रतिफल | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/समयबद्धता माध्यमिक/अंतिम | टिप्पणियां/ जोखिम घटक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **जारी स्कीम** | | | | | | |
| 1. | जारी X वीं योजना (XI तथा XII तक) | XI वीं योजना से पहले स्वीकृत परियोजनाओं का पूरा होना | 45.00 | | | | |
| | | | | टॉवर पर अमृतसर में डीडी-1, डीडी नयूज एचपीटी की शुरुआत | पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में कवरेज बढ़ाना | | टॉवर कार्य पूर्ण |
| | | | | स्टाफ क्वार्टर पटना | | तीसरी तिमाही का कार्य पूर्ण | |
| | | | | मुंबई में स्टाफ क्वार्टर | | चौथी तिमाही का कार्य पूर्ण | |
| | | | | ऑटोमोड एलपीटी-50 | स्थलीय प्रसारण में सुधार | | |
| | | | | महबूब नगर में एचपीटी (आंतरिक) | लक्षित क्षेत्रों में टीवी कवरेज बढ़ाना | | ट्रांस्मीटर उपकरण की आपूर्ति |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | स्थलीय प्रसारण नेटवर्क का डिजिटलीकरण | | **69.79** | | | | |
| 3. | ट्रांस्मीटर और स्टूडियो उपकरणों का आधुनिकीकरण, बदलना | | **26.00** | | | | |
| 4. | डीटीएच का विस्तार | | **25.00** | | | | |
| 5. | सेटेलाइट प्रसारण उपकरणों का आधुनिकीकरण | सेटेलाइट प्रसारण उपकरणों का आधुनिकीकरण | **25.00** | | | | |
| 6. | एचडीटीवी | एचडीटीवी निर्माण, पोस्ट निर्माण सुविधा तथा प्रसारण | **25.00** | दिल्ली और मुंबई में एचडीटीवी निर्माण सुविधा | | कार्य प्रगति पर | टेंडर आमंत्रित और मूल्यांकन जारी |
| 7. | स्टाफ क्वार्टर और अन्य विविध स्कीम | स्टाफ के लिए आवास सुविधा | **10.00** | 7 स्थलों पर स्टाफ क्वार्टर, 2 गेस्ट हाउस, 3 सामुदायिक केंद्र | | 4 स्थानोंपर स्टाफ कवार्टर निर्माण, 4 गेस्ट हाउस | |
| | **नई स्कीम** | | **0.19** | | | | |
| | स्कीम-I प्रसारण ढांचा नेटवर्क विकास | | | | | | 12 वीं योजना आबंटन स्वीकृत होना है |
| | स्कीम-IV विशेष परियोजनाएं | | **0.02** | | | | |
| | **कुल ( पूंजी )** | | **226.00** | | | | |
| | **कुल ( राजस्व )** | | **60.00** | | | | 12 वीं योजना आबंटन स्वीकृत होना है |
| | **डीडी का कुल** | | **286.00** | | | | |

# अध्याय-3

## सुधार, उपाय तथा नीतिगत पहल

# सूचना क्षेत्र

## विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

### सुधार उपाय तथा नीतिगत पहलें

पारदर्शिता, सशक्तिकरण, विकेंद्रीकरण तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए डीएवीपी के सुधार तथा नीतिगत पहलें नीचे दी गई हैं -

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) भारत सरकार की नोडल विज्ञापन एजेंसी की भूमिका को मजबूत करने के लिए बदलाव एवं पहल करता है। डीएवीपी भारत सरकार की अधिकृत विज्ञापन ऐजेंसी है जो विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं का प्रचार करती है, जिसमें सामाजिक आर्थिक उत्थान, राष्ट्रीय सद्भावना, आतंकवाद के विरुद्ध संप्रभुता और स्वास्थ्य संबंधी प्रदर्शनी, समाचारपत्र, सेटलाइट, टीवी चैनल, रेडियो, डिजिटल कैमरा, आउटडोर प्रचार और प्रिंटेड प्रचार सामग्री इत्यादि शामिल हैं।

**मीडिया-लिस्ट सॉफ्टवेयर का सृजन :** विज्ञापनों को क्रमबद्ध तरीके से समाचारपत्रों, साफ्टवेयर जारी करने के लिए डीएवीपी ने स्वंय एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो विज्ञापनों को प्रसार, कीमत, शामिल विज्ञापनों की संख्या जैसे विविध आधारों पर विज्ञापन आवंटित करेगा।

**इलेक्ट्रानिक तरीके से भुगतान जारी करना :** डीएवीपी ने नेशनल इलेक्ट्रानिक फाइल ट्रांसफर सिस्टम के जरिये भुगतान जारी करना शुरु किया है। डीएवीपी की वेबसाइट www.davp.nic.in पर बिलों की स्थिति देखी जा सकती है।

**समाचार पत्रों का नया पैनल तथा दर समीक्षा :** प्रसार के साथ ही समाचार पत्रों को बेहतर पारिश्रमिक देने के लिए दरों की समीक्षा की गई और चालू वित्तीय वर्ष में नया पैनल तैयार किया जाएगा।

**दृश्य-श्रव्य विंग के लिए एंपैनलमेंट एडवायजरी समिति का गठन :** एक समान फार्मूला पर आधारित टीवी और रेडियो चैनलों के लिए नई दरें सुधारने के लिए एक समिति बनाई गई है।

**सार्वजनिक-निजी भागीदारी :** एक और क्षेत्र जिसमें एक प्रमुख पहल की गई वह है सृजनात्मकता, चाहे मुद्रित या दृश्य-श्रव्य माध्यम में हो। डीएवीपी ने अपने ग्राहक मंत्रालयों के लिए सृजनात्मक डिजाइन करने के लिए रिकार्ड संख्या में निजी विज्ञापन एजेंसियों का पैनल बनाया है। मल्टीमीडिया अभियानों के लिए क वर्ग में 5 एजेंसियां, ख वर्ग में 1 तथा ग वर्ग में 22 एजेंसियों का पैनल तैयार किया है। 62 एजेंसी को इन पैनल किया है। प्रोग्रामरों, डाटा एंट्री आपरेटरों की आउट सोर्सिंग की गई।

प्रधानमंत्री के भाषण की पुस्तिका की नई डिजाइन और प्रधानमंत्री के भाषणों के लिए एक नया टेम्पलेट बनाया गया। विभिन्न विषयों को अलग-अलग रंग से चित्रित किया गया।

# क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

निदेशालय अपने कार्मिकों की संख्या को उचित स्तर पर लाकर स्वयं को नया स्वरूप दे रहा है ताकि इसकी कार्यक्षमता में सुधार हो। निदेशालय का मुख्य जोर जनजातीय, सीमावर्ती क्षेत्र, दूरदराज तथा पिछड़े क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ाने पर है जो अन्य मीडिया की पहुंच से बाहर हैं। पारदर्शिता के मद्दे नजर निदेशालय अपनी बेवसाइट को समय-समय पर अद्यतन करता रहता है।

# एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार

## गैर-योजना

### i) कुल राजस्व एवं शुद्ध अधिशेष

रोजगार समाचार ने 2010-11 में 5425.33 लाख रुपये का कुल राजस्व कमाया। खर्च निकालने के बाद शुद्ध अधिशेष 2010-11 के दौरान 2865.32 लाख रुपये हो गया। दिसंबर 2011 तक राजस्व 3994.77 लाख रुपये तथा शुद्ध अधिशेष 2414.00 लाख रुपये है।

### ii) राजस्व

रोज़गार समाचार ने नौकरी बाजार में अपनी सर्वोच्च स्थिति को बरकरार रखा हुआ है तथा वर्ष 2010-11 के दौरान अधिक विज्ञापन लेने में सफल रहा है। विज्ञापन राजस्व 2010-11 में बढ़कर 3432.64 लाख रुपये हो गया है। 2010-11 में प्रचार से राजस्व 3432.64 लाख और वितरण से राजस्व 92.69 लाख रुपए प्राप्त किये।

### iii) पेजों की औसत संख्या

रोज़गार समाचार में छापे जाने वाले पृष्ठों की औसत संख्या 2000-01 में 39.55 पृष्ठों से बढ़कर 2010-11 में 65.23 पृष्ठों तक पहुंच गई।

### iv) नेटवर्क में विस्तार

रोजगार समाचार अपने पाठकों तक पहुंचने के लिए ज्यादातर अपने नेटवर्क पर निर्भर करता है। दूर-दराज के क्षेत्रों में कवरेज सुनिश्चित करने के लिए पाठकों के पास सीधे ग्राहक बनने की भी सुविधा है। विभाग की देशभर में अपने नेटवर्क विस्तार की योजना है।

### v) इंटरएक्टिव वेबसाइट

रोजगार समाचार की सबसे बड़ी सफलता इसकी वेबसाइट- www.employmentnews.gov.in को शुरू करना है जिसे प्रतिदिन 20,000 से अधिक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यह वेबसाइट सरकारी क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयोग हो रही है।

# प्रकाशन विभाग

## सुधार के उपाय व नीतिगत पहल

एम्पलॉयमेंट नयूज द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी अलग से दी गई है जबकि विभाग के संपादकीय, प्रशासनिक कारोबार, उत्पादन और योजना शाखाओं में की गईं नीतिगत पहलें निम्नलिखित हैं :-

**प्रशासन :** इस विभाग के लिए जरुरी वस्तुओं और सेवाओं की मंजूरी और खरीदने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाया और इनको जीएफआर के नियमों के अनुरुप बनाया गया।

प्रशासनिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए और अगर कोई समस्या है तो इसके समाधान के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ नियमित टेलीफोन संपर्क शुरु किया गया।

**उत्पादन :** - मुद्रण गुणवत्ता सुधारने और लागत घटाने के लिए प्रिंटरों का नया पैनल तैयार किया गया है।

- किताबों के लिए प्रयुक्त होने वाले कागज की गुणवत्ता के संबंध में विनिर्देशों में कड़ाई करने के बाद इसमें काफी सुधार हुआ।

**संपादकीय :** किताबों के चयन में पारदर्शिता लाने के लिए एक पुस्तक समिति गठित की गई जिसने किताबों के प्रस्तावों की जांच की और सहमति के आधार पर उनको मंजूरी दी।

2011-12 में हिन्दी के कीर्ति स्तंभ साहित्यकारों की जन्मशताब्दी के अवसर पर पुस्तकों की शृंखला लाई गई है। इसमें अज्ञेय, गोपाल सिंह नेपाली, फैज अहमद फैज, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल कुछ ऐसी शख्सियत हैं जिन पर 2011-12 में पुस्तकें आई हैं।

कलाकारों को इंटरनेट से विचार लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया और किताबों के आवरणों के डिजायन को बिल्कुल नया रूप दिया गया।

**व्यापार :** विशिष्ट पुस्तकों के प्रकाशन, विज्ञापन, पुस्तक समीक्षाओं, महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों और पुस्तक मेलों में भागीदारी द्वारा विभाग इसकी पुस्तकों और पत्रिकाओं के स्वरुप में सुधार लाने के लिए जोर-शोर से प्रयास किए गए।

घरेलू पुस्तकालय सदस्यता में विस्तार और नए सदस्य जोड़े गए।

ऑन लाइन बुक स्टोर से समझौता करने की पहल कर प्रकाशन विभाग ने अपनी पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया है।

**योजना :** मानवीय पहलुओं पर केंद्रित कर 'योजना' और 'कुरुक्षेत्र' दोनों के आवरण पृष्ठों को सुधारा गया।

# भारतीय जन संचार संस्थान

संस्थान विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ जुड़ने को इच्छुक युवकों एवं युवतियों को बुनियादी कौशल/आवश्यक तकनीकी ज्ञान से सुसज्जित करता है तथा क्षेत्र के विभिन्न आयामों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। संस्थान की ओर से यह प्रयास किया जाता है कि वह अपने छात्रों को समाज के लिए उपयोगी सदस्य बनाये। सामान्यत: यह पाया गया है कि 60 प्रतिशत छात्र विभिन्न डिप्लोमा कोर्स में महिलाएं हैं। इस तरह भारतीय जन संचार संस्थान संचार माध्यम और संचार में महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रहा है।

विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देते हुए भारतीय जनसंचार संस्थान ने दो नए क्षेत्रीय केन्द्र आइजोल (मिजोरम), अमरावती (महाराष्ट्र) में खोले हैं। दो नए क्षेत्रीय केन्द्र खोलने की प्रक्रिया जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर) और कोट्टायम (केरल) जारी है। ढेंकनाल (उड़ीसा) में क्षेत्रीय केन्द्र कार्य कर रहा है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है।

पूरे देश में प्रवेश परीक्षा में और प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता रखने के लिए सभी लिखित परीक्षा के परिणाम, साक्षात्कार और अंतिम दाखिला सूची संस्थान के वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाती है।

# फोटो प्रभाग

फोटो प्रभाग का प्रमुख कार्य विभिन्न सरकारी संगठनों के लिए प्रगति और विकास के लिए फोटोग्राफ्स और दृश्य प्रलेखन तैयार करना तथा राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों से संबंधित दृश्यों को उपलब्ध कराना है। संदर्भों की जांच-पड़ताल करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने, तस्वीरों को एक स्लाइड में रखने ताकि चित्रों तक पहुंचने की सुविधा मिल सके। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास संबंधित कार्यकलापों तथा जम्मू और कश्मीर जैसे स्थानों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप जैसे योजना कार्यक्रमों से संबंधित स्थानों के दृश्य प्रलेखों को प्राप्त किया जा सके। डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम (अंकीय पुस्तकालय प्रणाली) को और प्रभावी बनाने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा समय तक अंकीय तस्वीरों को सुरक्षित रखकर प्रभावी प्रणाली बनाए रख सके और ऐतिहासिक महत्व की गुणवत्ता सम्पन्न तस्वीरों को प्राप्त किया जा सके और ऐसे क्षेत्रों जिन्होंने विकास किए हैं, लेकिन उनके दृश्य अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, उनके भी फोटो अभिलेख व्यापक रूप से प्राप्त किए जा सकें।

# भारतीय प्रेस परिषद

प्रेस परिषद ने अर्द्ध न्यायिक संस्था होने और प्रेस के आचरण संबंधी मानदंडों के नियमन का उत्तरदायित्व संभालते हुए निम्नलिखित सुधार के उपाय और नीतिगत पहलें की हैं :

## 1. सुधारात्मक उपाय

प्रेस परिषद अधिनियम में संशोधन के लिए सूचना एवं प्रसारण मंलालय से विचार विमर्श

प्रेस परिषद अधिनियम (वित्तीय पावर के प्रतिनिधि), अनुच्छेद, 1983

**2. नीतिगत उपाय :**

परिषद के गठित चार उच्च समिति के सिफारिशों के सर्वेक्षण के दौरान निम्नलिखित नीति के फ्रेम पर काम चल रहा है –

(क)

(ख) पत्रकारों की ड्यूटी पर तैनाती के समय सुरक्षा व्यवस्था।

**3. पारदर्शिता**

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू करना

2 भारतीय प्रेस परिषद का नागरिक चार्टर्ड इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

3. प्रेस परिषद की पूरी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

4. फैसलों और परिषद की अन्य संदर्भित रिपोर्टों को वेबसाइट पर डालना।

5. पत्रकारिता के मानदंड संबंधी मानक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

6 पत्रकारों के लिए आचरण संहिता वेबसाइट पर।

7. परिषद की वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट पर है।

8. पीआरएबी के आदेशों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है।

# पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए पत्र सूचना कार्यालय सरकार की नोडल एजेंसी है। ब्यूरो मीडिया प्रतिनिधियों को मीडिया सुविधाएं प्रदान करता है। सरकार के आम आदमी तक पहुंचने के प्रयासों के एक हिस्से के रुप में पी आई बी राष्ट्रीय स्तर पर जनसूचना अभियान (पी आई सी) आयोजित कर रहा है। पी आई बी का मुख्य उद्देश्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी अधिनियम (नरेगा), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, सूचना का अधिकार अधिनियम, अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतू प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई सी डी एस) स्कीम, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक बनवासी कल्याण इत्यादि के बारे में जागरुकता पैदा करने तथा सूचना पहुंचाना है।

ब्यूरो एक ही स्थान पर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को मीडिया सुविधाएं प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र स्थापित कर रहा है। ईएफसी ने पहले ही परियोजना को मंजूरी दे दी है और एनबीसीसी को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है। परियोजना लागत 60 करोड़ रुपये तक पहुंचने के कारण ईएफसी का नया अनुमोदन 15 सिंतबंर 2009 को प्राप्त किया गया। निर्माण कार्य भूतल पर आरसीसी स्लैब ईंट और प्लास्टर का काम चौथी मंजिल तक पूरा हो गया है। जमीन, आंतरिक विद्युत कार्य, एवीएसी, पानी सप्लाई/शौचालय का कार्य प्रगति पर है।

इसके अतिरिक्त, स्कीम में भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह तथा प्रवासी भारतीय दिवस हिस्सा बन गया है। ये भारत सरकार के प्रतिष्ठित कार्यक्रम हैं जो मिली जुली संस्कृति की झलक प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार, पीआईबी इन दोनों कार्यक्रमों के लिए मीडिया सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

12वीं पंच वर्षीय योजना में पत्र सूचना कार्यालय के आधुनिकीकरण के लिए नई योजनाओं का प्रस्ताव है। इसका मुख्य लक्ष्य आधुनिकीकरण और संचार का अपग्रेड और सूचना का डिसमेंशन प्रणाली को संपूर्ण रूप से आधुनिक तकनीक के साथ उपयोग करना और सूचना पत्र कार्यालय के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय एवं शाखाओं दफ्तर में कार्यक्षमता में

बदलाव दर्शनीय हैं। उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित विभागों का प्रस्ताव योजना के तहत आरंभ होगा :-

**( क ) आधुनिक संचार और सूचना डिसमिनेशन सिस्टम** - आधुनिक एवं अपग्रेड आईसीटी की मूलभूत सुविधा और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल उच्च सक्षमता, मजबूत संचार सूचना डिसमिनेशन प्रणाली और सेवा प्रदान करने में सुधार करना है।

**( ख ) 24x7 आपातकालीन मीडिया कंट्रोल रूम** - 24X7 आपातकालीन फीडबैक और प्रतिउत्तर व्यवस्था पत्र एवं सूचना कार्यालय में किया गया है। यह समाचार चैनलों पर रात-दिन नजर रखते हैं और इसका फीडबैक भारत सरकार के मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को देनी है। इस तरह वह अपनी जिम्मेदारी विकास की विषय/वास्तविक समय के आधार पर समाचार कहानी द्वारा निर्वाहन करती है।

## गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग

गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग ने 11 वीं पंचवर्षीय योजना में समाविष्ट करने के लिए अपने महतवपूर्ण कार्य क्षेत्र में नई नीतिगत पहल शुरु की हैं। इन पहल का उद्देश्य जन कल्याण में मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करना तथा पत्रकारिता में उच्च आदर्शों को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार नामक योजनाएं आम जनता की भलाई के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी का एक उदाहरण हैं।

वर्चुअल पुस्तकालय में पुस्तकालय का उन्नयन ऐतिहासिक संस्थान के निर्माण की पहल है जो शोधकर्ताओं और नीति नियामकों के लिए स्रोत साम्रगी एवं सूचना के भंडार का कार्य करेगी।

मास मीडिया में अनुसंधान मीडिया-संबंधी विशिष्ट मुद्दों पर शोध करने, फीडबैक लेने और जनता की राय हासिल करने की स्कीम है जिससे सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तरों पर इसकी मीडिया इकाइयों द्वारा नीति निर्धारण और कार्यान्वयन में मदद मिलेगी।

## भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक

पिछले कुछ वर्षों में प्रिंट मीडिया का जिस तरह से विस्तार हुआ है उससे वह प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम 1867 के दायरे के भी बाहर निकल गया है। पी.आर.बी. अधिनियम 1867 के अनुसार और इस अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा की गई है ताकि उन्हें प्रिंट मीडिया के वर्तमान परिदृश्य के अनुसार प्रासंगिक बनाया जा सके। समाचार पत्रों के त्वरित, कुशल और पारदर्शी सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पी आर बी संशोधित अधिनियम 2011 को अंतिम प्रारूप दिया जा रहा है> प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना और समाचार पत्रों की प्रसार संख्या की कड़ी जांच करने जैसे कार्य किए जा रहे हैं और 2007-12 तक की 11वीं योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी और मध्य क्षेत्र भोपाल में दो नये क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की जा रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017 के तीन मुख्य उद्देश्य हैं : (1) रिकार्डों का डिजिटिलाइजेशन (2) कम्प्यूटर द्वारा पंजीकरण और (3) फाईलिंग का वार्षिक सूचकांक आरंभ करना।

# गीत एवं नाटक प्रभाग

प्रभाग को स्थापना संचार उद्देश्यों के लिए प्रचुर लोक कला और पारंपरिक रूपों का दोहन करने के लिए लघु प्रायोगिक इकाई के रूप में 1954 में की गई थी। लाइव इंडिया जिसे अब इस नाम से व्यापक प्रसिद्धि हासिल है, बहुत प्रभावी सिद्ध हुआ है क्योंकि जनता से तत्काल संपर्क करने का लाभ इसमें निहित है तथा इसमें समकालिक मुद्दों, विचारों और समझाने की विधियों का लचीलापन है। इसलिए प्रभाग का कार्यक्षेत्र और आकार बढ़ाया गया ताकि इसे व्यापक पहुंच और सुगमता प्रदान की जा सके तथा दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, रेगिस्तानी और सीमा क्षेत्रों सहित वास्तविक धरातल पर संचार करने के इसके प्रयासों के प्रभाव को बढ़ाया जा सके।

प्रभाग का मुख्य कार्य, जैसा कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट में बताया गया है, आम जनता में सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक आदर्शों (जो राष्ट्र की प्रगति के लिए अनुकूल हों), के बारे में जागरूकता और भावनात्मक आत्मीयता पैदा करना, सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में रक्षा तैयारियों और शेष देश के साथ सांस्कृतिक एकता की भावना पैदा करना तथा सुदूर क्षेत्रों में तैनात सेना के जवानों का नैतिक बल लाइव मनोरंजन मीडिया जिसमें शहरी थियेटर के रूप और देश के सभी क्षेत्रों की लोक कला के जरिए कला को प्रोत्साहित करते हैं।

अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रभाग लोक तथा पारंपरिक नाटकों, नृत्य रूपकों, ओपेरा, नृत्य नाटकों, लोक एवं पारंपरिक काव्य, कठपुतली और सदियों पुरानी परंपरा के जादूगरों के सैंकड़ों कौशल जैसे व्यापक लोक एवं पारंपरिक रूपों का उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त प्रभाग साम्प्रदायिक सामंजस्य, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक विरासत के संवर्द्धन, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आधुनिक तकनीकों और सैंकड़ों कलाकारों के साथ ध्वनि एवं प्रकाश साधनों का भी उपयोग करता है।

देश के विभिन्न भागों में उपलब्ध असंख्य लोक और पारंपरिक रूपों के इस्तेमाल के जरिए गीत एवं नाटक प्रभाग एक तरफ तो इन रूपों के जीर्णोद्धार और टिकाऊपन का महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है तथा दूसरी तरफ हजारों कलाकारों की अपनी भाषा, मुहावरों तथा सोद्देश्यपूर्ण और सार्थक संवाद के लिए उनकी बोलियों में उनके कौशल का उपयोग करके उनको आजीविका उपलब्ध कराने में सक्षम हुआ है।

ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिकीकरण के शीर्ष के तहत कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव है।

कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुधारने के मद्देनजर शोध एवं विकास तथा प्रभाव आकलन कराया जाएगा।

# सूचना भवन का निर्माण चरण-V

वर्ष 2006 के दौरान, सूचना भवन के चरण-V के निर्माण का एक प्रस्ताव मंत्रालय के नीति योजना एकांश को इस आशय के साथ भेजा गया कि इसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में शामिल किया जाए। योजना आयोग से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद सूचना भवन के पांचवें चरण के निर्माण के लिए 12 मार्च, 2008 को व्यय वित्त समिति की बैठक आयोजित की गयी थी। व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने 74.60 करोड़ रुपये लागत की सीमा निर्धारित करते हुए इस परियोजना को इस शर्त पर मंजूरी दे दी कि लागत सीमा को पार नहीं किया जाएगा। परियोजना की कुल लागत 72,88,55,919 पारित है।

पंचवर्षीय योजना वर्षानुसार वर्ष 2007-12 के लिए अनुमानित बजट में निधि का ब्यौरा निम्नानुसार है :

| क्रम संख्या | परियोजना का नाम | आबंटित बजट | उपयोग की गई निधि | वार्षिक योजना |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सूचना भवन के (नई दिल्ली, लोधी रोड सीजीओ काम्पलेक्स) पांचवें चरण का निर्माण | 1.00 करोड़ रुपये | 1.00 करोड़ | 2007-08 |
| 2 | - वही - | 3.53 करोड़ रुपये | 1.76 करोड़ रुपये | 2008-09 |
| 3 | - वही - | 10.00 करोड़ रुपये | 10.00 करोड़ रुपये | 2009-10 |
| 4. | - वही - | 18.00 करोड़ रुपये | 18.00 करोड़ रुपये | 2010-11 |
| 5 | - वही - | 31.30 करोड़ रुपये | 21.30 करोड़ रुपये | 2011-12 फरवरी 2012 तक |
| | कुल | 63.83 करोड़ रुपये | 52.06 करोड़ रुपये | |

फेज V का कार्य विस्तारित कर अगामी वर्ष 2012-13 तक कर दिया गया है और कुल वित्तीय लागत 31.30 करोड़ रुपये 2011-12 तक जारी की जाएगी।

## पूर्वोत्तर राज्यों/जम्मू एवं कश्मीर एवं अन्य चिह्नित क्षेत्रों में विकास

एक नई योजना की कल्पना पूर्वोत्तर राज्यों/जम्मू एवं कश्मीर एवं अन्य चिह्नित क्षेत्रों के विकास एवं संचार हेतु की गछई है।

## अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम

जैसा कि योजना नई है और इसका उद्देश्य अपने अनुभवों को भारत एवं अन्य देशों के मीडिया और विकासक के साथ विनिमय करना है।

नीति संबंधी अध्ययन, सेमिनार, पर्यवेक्षण इत्यादि तीनों ही क्षेत्र में मीडिया यूनिट (प्रसार भारती के साथ)।

### नई नीति

इस योजना के तहत नीति संबंधी अध्ययन, सेमिनार और लगातार पर्यवेक्षण। नई (मध्यावधि कीमत लगाना) मीडिया सेक्टर मंत्रालय के नियोजित योजना में आते हैं। यह अध्ययन आकर्षक विकास को समझने में इस सेक्टर के उचित नीति पहल पर सहायक होता है।

# फिल्म क्षेत्र

## केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

वर्तमान समय की आवश्यकतानुसार प्रमाणन प्रक्रिया को सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत संशोधन प्रस्तावित है।

प्रमाणन प्रक्रिया को ऑन-लाइन किया गया है। यह प्रमाणन संबंधी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाता है।

## बाल फिल्म समिति, भारत

सीएफएसआई के पूर्व अध्यक्ष ने फिल्म सिटी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भूमि आवंटित करने के लिए अनुरोध किया। महाराष्ट्र फिल्म, स्टेज तथा सांस्कृतिक विकास निगम लिमिटेड ने फिल्म सिटी, गोरेगांव में 1600 व.मी. जगह का प्रस्ताव दिया है। सीएफएसआई अब वित्तीय जरुरतों के साथ महाराष्ट्र सरकार के अनुमोदन का इंतजार कर रही है।

सीएफएसआई का उद्देश्य यहां एक राष्ट्रीय महत्व के आधुनिक बाल फिल्म परिसर का निर्माण करना है, जिसमें फिल्म निर्माण के सभी पहलुओं सहित एक एनीमेशन तथा कठपुतली स्टूडियो का निर्माण शामिल है। इसका उद्देश्य अच्छी फिल्मों का निर्माण करना है। इस परिसर में बाल फिल्म अभिलेखागार स्थापित करने की भी योजना है।

## फिल्म समारोह निदेशालय

भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 2011 का आयोजन तथा 2010 के लिए 59वें राष्ट्रीय पुरस्कार 3 मई, 2012 को नई दिल्ली में प्रदान किए गए। 60वीं 2012 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हेतु जूरी के लिए फिल्मों की स्क्रीनिंग करवाई गई।

भारतीय पेनोरमा वर्ष 2012 के फिल्मों का चयन किया गया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2012 और भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए विशेष प्रस्तावित वाहन (एसपीबी) की प्रक्रिया आरंभ की है।

डीएफएफ वर्ष भर भारत में भारतीय पेनोरमा फिल्मों के प्रदर्शन तथा विश्व भर में फिल्म महोत्सवों में भागीदारी जैसी अपनी नियमित गतिविधियां चलाता रहेगा।

# भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के डिप्लोमा कोर्स को मान्यता दिलवाने के लिए संसद में नए अनुच्छेद का प्रस्ताव पारित किया गया है।

मशीनरी और उपकरणों की खरीद अत्यधिक पारदर्शी ढंग से खुली निविदाओं के आमंत्रण तथा वेबसाइट एवं मुद्रित मीडिया पर व्यापक प्रचार के जरिए की जाती है।

संस्थान के बुनियादी ढांचे का वैश्विक स्तर के अनुरूप उन्नयन करने के लिए वैश्विक फिल्म स्कूल नामक नई स्कीम विचाराधीन है।

संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा बताई गई फिल्मों को नियमित रूप से विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में प्रविष्टि दी जाती है ताकि विद्यार्थियों के काम को भारत और विदेशों में पहचान प्रदान की जा सके।

वर्ष के दौरान संस्थान ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों/आयोजनों में भाग लिया।

# फिल्म प्रभाग

### सुधार, उपाय तथा नीतिगत पहल

बाहरी निर्माताओं/एनजीओ से डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनवाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि फिल्म सामाजिक मुद्दों पर हों तथा उनमें समाधान भी हो ताकि राष्ट्र निर्माण में ऐसी फिल्मों की महती भूमिका हो। इसके साथ ही नये टेलेन्ट को प्रोत्साहित करना है।

# भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार

2012-13 से राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार में फिल्मों को इंटर-नेगेटिव में संयोजित करने की योजना है। 'नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया' सिनेमा फिल्मों का संग्रह भर नहीं होगा बल्कि यह फिल्म निर्माताओं, फिल्म छात्रों को फिल्म विकास के विविध आयामों की जानकारी देगा। विश्व भर के लोगों के लिए यह जानकारी का यह अच्छा केंद्र होगा।

# राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

1. बारहवीं योजना अवधि के दौरान क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण के लिए एनएफडीसी को सरकारी मदद देने का निर्णय लिया गया है।

2. यह प्रस्ताव है कि एनएफडीसी सहनिर्माण के क्षेत्र में भी काम करेगा और संभावनाशील अंतर्राष्ट्रीय एवं स्वदेशी सहनिर्माताओं को बुनियादी पूंजी मुहैया करायेगा। इसके लिए जरूरी पूंजी की पूर्ति कंपनी के आईईबीआर से की जाएगी।

3. एनएफडीसी ने 12वीं योजना अवधि में विदेशी फिल्म और टेलीविजन बाजार में भागीदारी करने की निर्यात रणनीति बनायी है।

4. भारतीय फिल्म परियोजनाओं की गुणवत्ता, उसके दायरे तथा उसकी आकांक्षाओं में विस्तार करने के उद्देश्य से एनएफडीसी फिल्म उद्योग को विभिन्न तरह की पटकथा की उपलब्धता को व्यापक बनाने के अपने प्रयास के तहत उसने पटकथा विकसित करने के लिये हर साल खास संख्या में भारतीय लेखकों को सहायता देने का लक्ष्य बनाया है ताकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को उच्च गुणवत्ता वाली तथा बाजार में बिक सकने वाली सामग्रियां विकसित हो सके।

## सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

संसद के अनुच्छेद में प्रस्ताव है कि सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान माना जाए। यह अनुच्छेद संस्थान द्वारा दिया गया डिप्लोमा और अन्य की पहचान सामाजिक योगदान की तरह की जाए।

पारदर्शिकता का परिचय देने के लिए संस्थान में एक शिकायत प्रकोष्ठ है और नागरिक घोषणा पत्र का प्रकाशन भी किया जाता है। यह संस्थान के बेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

## एंटी पायरेसी में पहल

फिल्म क्षेत्र में बढ़ती पायरेसी को रोकने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नियोजित योजना के तहत स्टेकहोल्डर में जागरूकता लाने के लिए पहल की है।

## राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विरासत को संरक्षित करने का महत्त्वकांक्षी योजना का प्रस्ताव है।

## भारत और विदेशों के फिल्म बाजारों में भागीदारी

**( क ) फिल्म महोत्सव निदेशालय/आई एफ एफ आई**

(i) 20 भारतीय एवं विदेश में फिल्म महोत्सव में भागीदारी और आयोजन।

(ii) वर्ष 2012 के भारतीय पेनोरमा के लिए फिल्मों का चयन।

(iii) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2012 का आयोजन और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में विशेष प्रस्तावित वाहन (एस पी वी) की प्रक्रिया आरंभ की।

(ख) बाल फिल्म समिति ने राष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सव का आयोजन 2012-13 में किया।

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड ने 5 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाजारों में भागीदारी की और यह फिल्म निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु कार्यरत है।

(घ) बाल फिल्म समिति देशभर के स्कूलों में फिल्म प्रदर्शनी का आयोजन करती है।

## विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्म निर्माण

11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मंत्रालय व्यापारिक संगठन के द्वारा फिल्म निर्माण की गतिविधि की जिम्मेदारी अलग से दी गई है। क्षेत्रीय भाषाओं, बाल फिल्मों और वृत्तचित्र और नये टेलेंट को फिल्म निर्माण में प्रोत्साहित करना है। एनएफडीसी, बाल चित्र समिति और फिल्म प्रभाग एकल योजना के तहत 11वीं पंचवर्षीय योजना में 'विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्म निर्माण' किया जाता है।

## ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एनीमेशन फिल्म, गेमिंग, प्रदर्शन और लिपणन में प्रौद्योगिकी की प्रगति पर राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

# प्रसारण क्षेत्र

## इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानिटरिंग केंद्र (ईएमएमसी)

वर्ष 2007-08 के दौरान 19.65 करोड़ रुपये की कुल लागत से ईएमएमसी की स्थापना हेतु एसएफसी (आरसी) की योजना अनुमोदित की गई थी। 11वीं योजना के तहत ईएमएमसी परियोजना के कार्यान्वयन संवर्धन हेतु 16.75 करोड़ का अनुमान था। वार्षिक योजना 2010-11 के अन्तर्गत 2.18 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है। परियोजना का निष्पादन मंत्रालय के अधीन एक पीएसयू ब्रोडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टैंट्स इंडिया, लिमिटेड (बीईसीआईएल) द्वारा किया जा रहाहै। यह परियोजना दिनांक- 9 जून, 2008 से अस्तित्व में आई थी और इसकी मानीटरिंग क्षमता बढ़ाकर 300 टीवी चैनल कर दी गई है। केबल टेलीविजन वर्क (विनियम) अधिनियम 1995 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों से निहित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के अन्तर्गत की निगरानी के अलावा यह संदर्भ में मानीटरिंग विषयवस्तु के अलावा विभिन्न एजेंसियों जिनमें मंत्रिमंडल सचिवालय, पीएमओ, एमएचए आदि सम्मिलित है के लिए आवश्यक विषयपरक विशेष रिपोर्टें तैयार करतीहै। ईएमएमसी मंत्रालय का अधीनस्त कार्यालय है और इसकी स्थापना के लिए परियोजना पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्तपोषित है।

# एफ. एम. रेडियो

निजी एफ एम रेडियो का कार्य एफ एम चरण I नीति के माध्यम से 1999 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। प्रथम चरण में बड़े पैमाने पर हुई खामियों को ध्यान में रखते हुए और ट्राई की सिफारिशों और अन्य सार्थक कारकों को ध्यान में रखते हुए निजी एजेंसियों (चरण II) के माध्यम से एफ एम रेडियो प्रसारण सेवा का विस्तार करने की नीति को 30 जून 2005 में स्वीकृति दी गई और 13 जुलाई 2005 को इसकी अधिसूचना जारी की गई। एफएम रेडियो प्रसारण के चरण के कार्यान्वयन का कार्य पूरे जोरों पर चल रहा है। कुल 337 चैनलों को निजी एफएम रेडियो के दूसरे चरण में लगाने का कार्यक्रम शुरू किया गया और उनमें से 280 चैनलों के लिए बोलियां सफल रहीं। जांच पड़ताल के बाद 245 एफएम चैनलों के संचालन के लिए विभिन्न कंपनियों को आशय-पत्र भेजे गए। इस समय 254 चैनल चालू हैं जिनमें 21 चैनल विभिन्न चरण में अंतर्गत संचालन कर रहे हैं।

# प्रसार भारती

प्रसार भारती के पास प्रसारण और टेलीकास्टिंग के क्षेत्र में ढांचागत, श्रमशक्ति और तकनीकी विशेषज्ञता के संदर्भ में संसाधनों का व्यापक भंडार है। ढांचागत भंडार में, विशेष रूप से भूमि, इमारत, टावर, ट्रांसमीटर, स्टूडियो, सेटेलाइट अर्थ स्टेशनत, अभिलेखकरण की सुविधा, कर्मचारियों का प्रशिक्षण (तकनीकी)संस्थान, अनुसंधान और विकास आदि शामिल हैं। 500 डब्ल्यू मीडियम वेव ट्रांसमीटर से शुरुआत करते हुए आकाशवाणी आज प्रमुख प्रसारक संगठन बन गया है। 275 रेडियो ट्रांसमीटर के साथ यह 91.82 प्रतिशत क्षेत्र और 99.16 प्रतिशत आबादी के दायरे में फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त डीडी डायरेक्ट प्लस के फ्री टू एयर डीटीएच प्लेटफॉर्म पर 21 रेडियो लगभग पूरे देश में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। दूरदर्शन 31 चैनलों से बढ़कर 39 सेटेलाइट अर्थ स्टेशनों तक फैल गया है और विभिन्न क्षमताओं वाले इसके 1416 ट्रांसमीटर देश की 92 प्रतिशत आबादी को अपने दायरे में लिए हुए हैं।

अपनी क्षमता के सदुपयोग के लिए आकाशवाणी ने मई 2001 में अपने संसाधनों को स्वतंत्र केंद्र के रूप में स्थापित किया जिससे व्यापक ढांचे से राजस्व अर्जित किया जा सके। निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत, अगले 10 से 15 वर्षों में आकाशवाणी के संसाधनों द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से राजस्व उत्सर्जित किए जा सकते हैं :

- निजी प्रसारकों, मोबाइल सर्विस प्रदाताओं/इग्नू के साथ लाइसेंस फीस आधार पर प्रसार भारती (पीबी)के ढांचागत संसाधन, जैसे टावर (एसटीएल टावर, स्व सहायक एस डब्ल्यू टावर, एकीकृत टीवी/एफएम टावर)निर्माण और भूमि को बांटना। अभी पीबी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की निजी एफएम चरण 1 और चरण 2 योजना के तहत निजी एफएम प्रसारकों के साथ अपने ढांचागत संसाधनों को बांट रहा है। इस योजना के तहत वे अपने एंटीना को माउंट कर सकते हैं और अपने ट्रांसमीटर और दूसरे सहायक उपकरणों के इंस्टॉलेशन के लिए स्पेस खोल और बंद कर सकते हैं। भविष्य में, अगर पीपीपी के माध्यम से अपेक्षित हो, तो हम अपने ढांचागत संसाधन की व्यापक हिस्सेदारी कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त प्रसार भारती परिसर में लगे अपने उपकरण इंस्टॉल करने वाले निजी एफएम प्रसारकों को संचालन और रखरखाव सेवाएं भी प्रदान की जा सकती हैं। इस उद्देश्य के लिए एआईआर/डीडी स्टेशनों को श्रमशक्ति आउटसोर्स करने की अनुमति देने की जरूरत होगी क्योंकि श्रमशक्ति की पहले ही कमी है। पीबी निजी प्रसारकों के स्टूडियो और ट्रांसमीटरों को इंस्टॉल और कमीशन करने का काम भी कर सकता है।
- आकाशवाणी/डीडी सेटअप के साथ को साइट करने वाले चैनल/इग्नू ट्रांसमीटरों के संचालन और रखरखाव का काम भी आकाशवाणी/डीडी स्टेशन कर रहे हैं। प्रसार भारती की योजना है कि भविष्य में इग्नू के ट्रांसमीटरों के लिए भी यह कार्य किया जाएगा।

- मौजूदा समय में आकाशवाणी स्टूडियो और ट्रांसमीटरों का खाली समय इग्नू को किराए पर दिया गया है। जब भी कभी ऐसी आवश्यकता होगी और अगर भविष्य में ऐसा समय देना संभव होगा तो प्रसार भारती दूसरे शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों और आउटस्टेशन एजेंसियों को प्रतिस्पर्धात्मक दर पर, मौजूदा ट्रांसमिशन घंटों के लिए किराए पर ये सुविधाएं प्रदान करेगा।
- प्रसार भारती श्रोताओं को आईवीआरएस और एसएमएस आधारित सेवा जैसी मूल्य संवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए टेलीकॉम सेवाओं के साथ एक समझौता कर रहा है। इस प्रकार की लोकप्रिय सेवाएं प्रदान करके, टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को मिलने वाले राजस्व में से आकाशवाणी को भी राजस्व प्राप्त हो सकता है। दूरदर्शन पहले से दिल्ली से मूल्य संवर्धित सेवाएं प्रदान कर रहा है और जल्द इसे दूसरे शहरों में भी विस्तार देना चाहता है।
- आकाशवाणी के नेटवर्क में एमडब्ल्यू/एफएम/एसडब्ल्यू प्रसारक ट्रांसमीटर का एयर टाइम शैक्षणिक/कृषि संस्थानों को किराए पर दिया जा सकता है।
- विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/आवासीय स्कूलों में 50/100 वॉट के एफएम सामुदायिक रेडियो स्टेशन को स्थापित करने में भी प्रसार भारती मदद प्रदान कर सकता है।
- प्रसार भारती विभिन्न आकाशवाणी/दूरदर्शन केंद्रों पर ब्रॉडकास्टिंग के विभिन्न क्षेत्रों में ऑन साइट और संस्थात्मक प्रशिक्षण भी प्रदान कर सकता है। कुछ केंद्रों में यह प्रशिक्षण पहले से दिया जा रहा है जिसका आगे चलकर विस्तार किया जा सकता है।
- डेटा ऑडियो चैनल (डीएआरसी) सेवा के माध्यम से प्रसार भारती राजस्व अर्जित कर सकता है।

## लैंगिक बजट

वर्तमान वित्तीय वर्ष में, क्षेत्रीय केंद्रों/चैनलों पर लैंगिक बजट को प्रस्तावित किया गया है और अगले वित्तीय वर्ष में सभी केंद्रों/चैनलों में लैंगिक मुद्दों पर कार्यक्रम बनाने के लिए 20 प्रतिशत बजट आवंटित करना तय किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में दूरदर्शन केंद्रों पर कार्य करने वाली महिलाओं को अधिक सुविधाएं देने के प्रावधान किए जाएंगे, जैसे मनोरंजक क्लब, क्रेचेज, अलग शौचालय, रेस्ट रूम आदि।

## आकाशवाणी का डिजिटलीकरण

11वीं पंचवर्षीय योजना में आकाशवाणी नेटवर्क के डिजिटलीकरण और सीमांत क्षेत्रों में आकाशवाणी/डीडी के दायरे को बढ़ाना मौजूदा वित्तीय वर्ष की प्रमुख गतिविधियों में से एक था। इस वर्ष आकाशवाणी और दूरदर्शन में सॉफ्टवेयर प्रॉडक्शन/अधिग्रहण की एक नई योजना भी चलाई गई जिसका उद्देश्य गुणात्मक कन्टेंट प्रदान करना था। सरकार ने आकाशवाणी का डिजिटलीकरण ट्रांसमीटर, स्टूडियो और संचार जो आंतरिक प्रक्रिया में 98 स्टूडियो और समन्वय 100 वाट एफ एम क्षमता वाली ट्रांसमीटर जिसमें 100 लोकेशन डिजिटलीइजेशन आकाशवाणी नेटवर्क में किया गया 843.54 करोड़ रुपये की लागत आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र के सीमा क्षेत्र में मजबूत करने हेतू है जिसमें 100 करोड़ रुपये मुख्य गतिविधि को चालू वर्ष में वित्तीय सहायता है।

सभी 35 सेटेलाइट चैनल डिजिटल ढंग से काम कर रहे हैं। डीटीएच प्लेटफार्म भी डिजिटल है। 67 स्टूडियो सेंटर से 23 पूरी तरह डिजिटल बन गए हैं और 31 के कुछ भागों को डिजिटल किया गया है। अन्य 13 स्टूडियो केन्द्र में लाए जा रहे हैं। अप्रैल 2011 में 620 करोड़ रुपये का दूरदर्शन का डिजिटलाइजेशन और कुछ बड़ी परियोजनाएं पारित हो गई हैं।

पूरे 39 स्टूडियो केन्द्र का पूर्ण डिजिटलाइजेशन (31 कुछ और 8 एनलॉग स्टूडियो केन्द्र) एपीटी 40 स्थानों पर स्थापित। ऊपर के अन्य परियोजना पर भी काम हो रहे हैं। पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन का कार्य 2012 तक विस्तारित किया गया। 2014 तक डिजिटल एचपीटी चरणबद्ध रूप से स्थापित किया जायेगा।

## स्टूडियो का आधुनिकीकरण और ट्रांमीटर उपकरण

फरवरी 2011 में 299 करोड़ रुपये स्टूडियो के आधुनिकीकरण और ट्रांसमीटर उपकरण हेतु पारित हुये हैं। मुख्य परियोजना को मान्यता के साथ इस योजना

के निम्नलिखित भाग भाग हैं :

- 15 स्थानों पर पुराने उच्च ताप ट्रांसमीटर का बदलाव - 60 निम्न पावर ट्रांसमीटर का बदलाव ओटोमोड (1+1) 500 वाट एलपीटी में करना

- 20 स्टूडियो केन्द्र का आधुनिकीकरण पुराने उपकरण का बदलाव कर किया जायेगा जैसे कैमरा, चेन, निर्माण स्वीच, लोगो जेनरेटर और रंगीन मॉनिटर इत्यादि

इन परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

## एचडीटीवी

एचडीटीवी 5 गुणा अधिक उच्च पारंपरिक टेलीविजन प्रणाली (प्रमाणिक-परिभाषा टीवी) मुख्य कारक एचडीटीवी के हैं - कांच की तरह साफ और ध्वनि रहित तस्वीर, अधिक वास्तविक रंग, बड़ा स्क्रीन तस्वीर और देखने में ज्यादा वास्तविक लगे।

11वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित परियोजना लागू होने वाली है

- दिल्ली एवं मुंबई में एचडीटीवी स्टूडियो

- दिल्ली, कोलकाता, मुंबछई और चेन्नई में एचडीटीवी क्षेत्रीय निर्माण के बाद और देखने की सुविधा

- एचडीटीवी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में ट्रांसमीटर

- बहुत सारे कैमरे के साथ ओबी वेन (2 नंबर) दिल्ली और मुंबई में बाहर के निर्माण हेतु

ऊपर दिये सभी परियोजना विभिन्न स्तर पर हैं और इसके 2013 तक विभिन्न चरणों में पूरा होने वाला है।

## प्रशिक्षण

विगत दो वर्षों से दूरदर्शन में गहराई से परिवर्तन जारी है। टीवी तकनीक बहुत तेजी से बदल रहा है। एनलोग उपकरण, जो कई वर्षों तक शासन किया है जल्दी ही निष्प्रयोग हो जायेगा। आज चर्चा में डिजिलाइजेशन है। दूरदर्शन भी अपने नेटवर्क का डिजिटिलाइजेशन कर रहा है। दूरदर्शन अपने कर्मचारी को प्रशिकशम देने पर जोर डाल रहा है। विशेषकर प्रसारण तकनीक में होने वाले विकास को देखते हुए उसके अनुरूप प्रशिकि्शत किया जा रहा है। नये कर्मचारी और पुराने कर्मचारी को प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता को बढ़ाकर नए तकनीक की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा प्रबंधन कार्यक्रम का इन-हाउस प्रशिक्षण संस्थान जैसे एसटीआई(टी) दिल्ली, डीटीआई लखनऊ, आरएसटीआई(टी) शिलोंग, भुवनेश्वर और मनाड (मुंबई) में दिया जाता है। प्रशिक्षण पाठयक्रम का संचालन आईआईटी कानपुर, आईआईएम शिलांग और कुछ अन्य बाहर के संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त उपकरण का निर्माण कार्यस्थल पर देने प्रशिक्षम दिया गया है। अप्रैल से नवंबर 2011 में 760 इंजिनियर अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया और 440 इंजिनियर अधिकारियों को 1 दिसम्बर 2011 से 31 मार्च 2012 तक प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है। लगभग 75 इंजिनियर अधिकारियों को 2011 तक विभिन्न एटीएस के अंतर्गत ुपकरण निर्माण, नए उपकरण का परिचय नेटवर्क में करना है। विभिन्न भागों में खराब उपकरणों को बनाने का कार्यशाला आयोजित किया जाता है।

# मुख्य सचिवालय प्रसारण विंग

## अंतर्राष्ट्रीय चैनल

**सुधारात्मक उपाय तथा नीतिगत पहलें**

प्रारंभिक अनुमान के रूप में इसमें 100.00 करोड़ रुपये का व्यय है। इस उद्देश्य के लिए प्रसार भारती को एक स्कीम तैयार करने का निदेश दिया गया है।

## सामुदायिक रेडियो के लिए आईईसी गतिविधियां

दिसंबर, 2002 में, भारत सरकार ने आईआईटी/आईआईएम जैसे स्थापित शैक्षिक संस्थानों को सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएम) स्थापित करने के लिये लाइसेंस प्रदान करने की नीति को स्वीकृति प्रदान की। इसके अंतर्गत 104 संस्थानों से आवेदन प्राप्त किए गए। इनमें से 67 योग्य संस्थानों को जवाबी पत्र भेजे गये और 45 संस्थानों ने लाइसेंस समझौतों पर हस्ताक्षर किये। वर्तमान में 103 सामुदायिक रेडियो केंद्र देश के विभिन्न हिस्सों में चलाये जा रहे हैं।

मई 2004 में आयोजित कार्यशाला की सिफारिशों के साथ-साथ सांसदों की परामर्श समिति यदि आदि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद सरकार द्वारा इस मुद्दे पर पुन: विचार-विमर्श किया गया और दिसंबर, 2006 में विकास और सामाजिक परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर आम नागरिकों तथा अलाभकारी स्वयंसेवी संस्थानं जैसे संगठनों को इस नीति के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया।

# अध्याय 4
# पिछले कार्य प्रदर्शन की समीक्षा

## अध्याय IV

## पिछले कार्य प्रदर्शन की समीक्षा

## सूचना क्षेत्र

## विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

4.1 **वर्ष 2010-11 के लक्ष्य और उपलब्धियां :** लक्ष्य और उपलब्धियां वित्तीय और भौतिक दोनों ही संदर्भों में निम्नलिखित पैराग्राफ में दी जा रही हैं।

4.2 **वित्तीय प्रदर्शन :** पिछले वर्ष का वित्तीय प्रदर्शन योजना और गैर-योजना के आवंटन का लगभग पूरी तरह उपयोग कर लिया गया।

**वित्तीय**

*(लाख रुपये में)*

| (वित्तीय अनुमान 2010-11) | | | (वास्तविक व्यय 2010-11) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर योजना | कुल |
| 4949.00 | 6227.99 | 11176.99 | 4947.32 | 6663.75 | 11611.07 |

2010-11 की वार्षिक योजना के दौरान 4450.00 लाख रुपये का स्वीकृत प्रावधान संशोधित व्यय में बढ़कर 4949.00 लाख रुपये कर दिया गया।

वर्ष 2010-11 की वार्षिक योजना को एक जारी कार्यक्रम *विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम : अवधारणा एवं प्रसार* के लिए बनाया गया है। इसके अंतर्गत 4450.00 लाख रुपये के परिव्यय की मंजूरी दी गई है। हालांकि संशोधित अनुमान/अंतिम अनुदान के चरण में 4949.00 लाख रुपये का अतिरिक्त कोष दिया गया है। मार्च 2011 तक 4947.32 लाख रुपये की धन राशि व्यय हुई है तथा वित्तीय लक्ष्य के संदर्भ में शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल हुई है। यह योजना बाह्य प्रचार माध्यम, मुद्रित प्रचार माध्यम, प्रदर्शनी, डिसप्ले और वर्गीकृत विज्ञापन तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा सूचना के प्रसार द्वारा लागू किया गया है।

**4.3 वास्तविक उपलब्धियां :**वित्तीय लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए थे, वास्तविक उपलब्धियां भी उत्कृष्ट थीं जो इस प्रकार रहीं :

**4.3.1 प्रदर्शनी :** वर्ष 2010-11 की वार्षिक योजना के तहत देश भर में कई महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया जैसे कि 'स्वस्थ भारत', पुनरुत्थानशील भारत, कई फ्लैगशिप कार्यक्रम 'भारत निर्माण', एन 1 एच 1 प्रदर्शनी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), आजादी एक्सप्रेस-1857 क्रांति यात्रा, एड्स जागरूकता एवं स्वस्थ मां स्वस्थ बच्चा इत्यादि।

**4.3.2 मुद्रित विज्ञापन :** 'भारत निर्माण' और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवसों पर विज्ञापन जारी किए गए। डीएवीपी द्वारा विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा स्वायतशासी संगठनों के लिए 13829 मुद्रित विज्ञापन जारी किए गए जिनमें से 714 डिसप्ले तथा अन्य क्लासीफाइड इनमें 148 यूपीएससी के लिए थे।

**4.3.3 श्रव्य-दृश्य :** डीएवीपी के बजट से राष्ट्रीय एकता (भारत मेरी पहचान), भारतीय संविधान के 60 वर्ष,गांधी जयंती, शहीद दिवस, सद्भावना दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर अभियान।

**4.3.4 मुद्रित प्रचार माध्यम :** योजना प्रचार के लिए 13, गैर-योजना के लिए 67, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 4 तथा अन्य मंत्रालयों के लिए 86 पुस्तिकाएं मुद्रित की गईं।

**4.3.5 बाह्य प्रचार :** होर्डिंग्स, बस पैनल,कियोस्क, सार्वजनिक सुविधाओं इत्यादि के जरिए 239 अभियान चलाए गए।

**4.3.6 डीएवीपी का आधुनिकीकरण :** वित्तीय वर्ष के दौरान आधुनिकीकरण की योजना के तहत ऑनलाइन बिलिंग के लिए आवश्यक हार्डवेयर तथा कम्प्यूटर तथा सॉफ्टवेयर खरीदे डीएवीपी मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में ढांचागत सुविधाओं की व्यवस्था की गई। कान्फ्रेंस हाल के अद्यतन किया गया है तथा प्रदर्शनी खंड में डिजीटल लाइब्रेरी के लिए सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर प्रदान किया गया है और निदेशालय के कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया है।

**4.3.6** वर्ष 2010-2011 के दौरान लक्ष्य और उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं :

| क्र.सं. | ब्योरा | लक्ष्य | उपलब्धियां |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रदर्शनी | 650 | 422 |
| 2 | डिसप्ले/वर्गीकृत विज्ञापन | 15560 | 13829 |
| 3 | रेडियो/टेलीविजन पर विज्ञापन@ | 2182 | 3900 |
| 4 | मुद्रित प्रचार | 175 | 170 |
| 5 | बाह्य प्रचार | 250 | 239 |

@ इसके अंतर्गत 12 भाषाओं में 325 अभियान शामिल हैं।

**4.4 वर्ष 2011-12 के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां : 2011-12 के चालू वर्ष के लिए लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है :**

**वित्तीय लक्ष्य**

वर्ष का बजट प्रावधान नीचे दिया गया है। डीएवीपी ने अपने व्यय के लिए योजना और गैर-योजना दोनों के लिए अतिरिक्त राशि मांगी है।

*(करोड़ रुपये में)*

| योजना | गैर-योजना | कुल |
|---|---|---|
| 5500.00 | 67.33 | 122.33 |

## 4.6 वास्तविक प्रदर्शन

वर्ष 2011-12 में दो योजनाएं बनाई गई हैं : **( 1 ) विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम : अवधारणा एवं प्रसार** (चालू योजना) के लिए स्वीकृत परिव्यय 5400.00 लाख रुपये कर दिया गया है। **( 2 ) डीएवीपी का आधुनिकीकरण :** यह एक नई योजना है, 11वीं योजना में वर्ष 2011-12 के लिए 100.00 लाख रुपये अनुमोदित किए गए हैं। जिसके लिए योजना और गैर-योजना मदों के अन्तर्गत 31 दिसम्बर 2011 तक 10383.93 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं।**4.6.2 योजना :** विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम : अवधारणा एवं प्रसार

**( क ) प्रदर्शनियां :** वार्षिक योजना 2011-12 के दौरान महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों का देश भर में आयोजन हुआ जैसे कि 'स्वस्थ भारत', पुनरुत्थानशील भारत, फ्लैगशिप कार्यक्रम, 'भारत निर्माण', एच1 एन1-प्रदर्शनी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) आदि।

**( ख ) बाह्य प्रचार :** बाह्य प्रचार के अंतर्गत उपभोक्ता मामले, भारतीय नौसेना, आयकर, बी आई एस, जनगणना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, बीईई, डब्ल्यूसीडी, एमएचए (एनडीएमए) भारत निर्माण तथा सार्वजनिक सुविधाओं पर अभियान चलाए गए।

**( ख ) रेडियो स्पॉट :** सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बजट से भारत निर्माण अभियान चलाया गया। अन्य मंत्रालयों के लिए अतुल्य भारत, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रचार, सेना/नौसेना में भर्ती, उपभोक्ता जागरूकता, जनसंख्या नियंत्रण पर अभियान चलाए गए।

**( घ ) डिसप्ले तथा क्लासीफाइड :** कुल 12,693 विज्ञापन जारी किए गए। इनमें से 1120 डिसप्ले तथा बाकी क्लासीफाइड थे। 94 विज्ञापन यूपीएससी के थे।

**( ङ) मुद्रित प्रचार :** विभिन्न भाषाओं में 146 कार्य और 302 मदों की महत्वपूर्ण बुकलेट की छपाई करवाई गई।

### 4.6.3 योजना : डीएवीपी का आधुनिकीकरण

**कार्यालय खर्च :** आधुनिकीकरण की योजना तहत वित्तीय वर्ष के दौरान ऑन लाइन बिलिंग के लिए कम्प्यूटर तथा जरूरी हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर खरीदे गए। साथ ही डीएवीपी मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में ढांचागत सुविधाओं की व्यवस्था की गई।

**4.6.4** वर्ष 2011-12 की भौतिक उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :

## योजना/गैर-योजना/अन्य मंत्रालय/विभाग ( 2011-12 )

| क्र.स. | विवरण | लक्ष्य | 31.12.2011 तक उपलब्धियां | 31.3.2012 तक अनुमानित उपलब्धियां |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रदर्शनी | 500 | 462 | 130 |
| 2 | डिसप्ले/वगीकृत विज्ञापन | 15000 | 12693 | 16000 |
| 3 | रेडियो/टीवी के लिए विज्ञापन@ | 4800 | 3740 | 1200 |
| 4 | मुद्रित प्रचार | 189 | 146 | 38 |
| 5 | बाह्य प्रचार | 500 | 375 | 150 |

@ इन लक्ष्यों में विभिन्न भाषाओं में कार्यक्रम शामिल हैं।

## 4.6.5 वर्ष 2012-2013 के लक्ष्य

**वित्तीय**

(करोड़ रुपये में)

**बजट अनुमान**

| योजना | गैर-योजना | कुल |
|---|---|---|
| 110.00 | 67.33 | 177.33 |

**वित्तीय लक्ष्य**

**योजना/गैर-योजना/अन्य मंत्रालय/विभाग ( 2012-2013 )**

| क्र.सं. | विवरण | लक्ष्य |
|---|---|---|
| 1. | प्रदर्शनी | 500 |
| 2. | डिसप्ले/वर्गीकृत विज्ञापन | 15000 |
| 3. | रेडियो/टीवी विज्ञापन | 4800 |
| 4. | मुद्रित प्रचार | 180 |
| 5. | बाह्यय प्रचार | 250 |

## 4.6.6 2011-2012 की वार्षिक योजना

वर्ष 2011-2012 की वार्षिक योजना में : (1) *विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम : अवधारणा एवं प्रसार* के लिए 5500.00 लाख रुपये की योजना तथा (2) *डीएवीपी का आधुनिकीकरण* के लिए 100.00 लाख रुपए की मंजूरी वाली दो योजनाओं को शामिल किया गया है।

चल रही योजना अर्थात *विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम : अवधारणा एवं प्रसार* के तहत राष्ट्र के महत्वपूर्ण फ्लैगशिप अभियान तथा मल्टीमीडिया प्रचार जैसे कि प्रदर्शनी, बाह्यप्रचार, इलेक्ट्रानिक मीडिया पर सूचना प्रदान करना, डिसप्ले एवं वर्गीकृत विज्ञापन की सहायता से सरकार की नीतियों के प्रसार का कार्य है।

लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपर्युक्त योजनाओं में अर्थात *विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम : अवधारणा एवं प्रसार, डीएवीपी का आधुनिकीकरण* को योजना आयोग ने कम्प्यूटरीकरण और डिजीटलीकरण, आफिस का बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन के विकास सहित शामिल किया है।

# क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

## वार्षिक योजना 2010-11 के दौरान कार्य निष्पादन की समीक्षा

### वास्तविक कार्यक्रम गतिविधियां

| | 2010-11 | | 2011-12 | | 2012-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| **कार्यक्रम** | **लक्ष्य** | **उपलब्धियां (दिसम्बर, 11 तक)** | **लक्ष्य** | **उपलब्धियां** | **लक्ष्य** |
| दौरे वाले दिन | 23568 | 15972 | 23568 | 15917 | 23568 |
| फिल्म शो | 46500 | 28401 | 27900 | 22091 | 27900 |
| विशेष कार्यक्रम | 4968 | 7688 | 2484 | 4899 | 2484 |

वार्षिक योजना 2010-11 में केवल दो योजनाओं को मंजूरी मिली है-(i) दौरों का आयोजन/दक्षता उन्नयन तथा (ii) क्षेत्रीय कार्यालयों एवं क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन। इन योजनाओं की लागत 5.55 करोड़ रुपये है।

दौरों का आयोजन/दक्षता उन्नयन योजना के तहत 13 दौरे किए गए। दूसरी योजना के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यालय के लिए 15 मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर, 15 वायरलैस पी ए प्रणालियां, 16 डीवीडी प्लेयर, 6 डिजिटल वीडियो कैमरे, 100 स्टिल वीडियो कैमरे, 9 डिजिटल फोटोकापी मशीनें, एक प्रोग्रामर और सहायक प्रोग्रामर को इस कार्य में लगाया गया और फिल्म प्रभाग और सीएफएसआई से 35 फिल्मों की 4786 वीसीडी/डीवीडी, 5.73 लाख रुपये में खरीदी गईं।

### निदेशालय का वित्तीय कार्य निष्पादन

*(हज़ार रुपये में)*

| **योजना/गैर-योजना** | 2010-11 | | 2011-12 | | 2012-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **लक्ष्य** | **उपलब्धियां (दिसंबर, 11 तक)** | **लक्ष्य** | **उपलब्धियां** | **लक्ष्य** |
| योजना | 555.00 | 9048 | 40000 | 19022* | 100000 |
| गैर-योजना | 3572.00 | 312776 | 413500 | 295607** | 531855 |
| **कुल** | **412,700** | **3218.24** | **453500** | **314629** | **631855** |

* दिसंबर 2011 तक वास्तविक व्यय

** नवंबर 2011 तक वास्तविक व्यय

## 11वीं योजना परिव्यय

प्रस्तावित 11वीं योजना स्कीम का विवरण और औचित्य नीचे दिया गया है-

*( लाख रुपये में)*

| क्रम सं. | स्कीम का नाम | अनुमोदित 11वीं योजना परिव्यय | वार्षिक योजना 2012-13 के लिए व्यय |
|---|---|---|---|
| 1. | आयोजित दौरे/कौशल उन्नयन | 230.00 | 79.00 |
| 2. | क्षेत्रीय कार्यालयों और एफपीयूएस में सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर का आधुनिकीकरण और उन्नयन | 1102.67 | 200.00 |
| | **कुल** | **1332.67** | **279.00** |

## संगठन

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय ने 32 क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों तथा 4 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ 1953 में कार्य करना शुरू किया। उल्लेखनीय है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रण में इस निदेशालय ने पंचवर्षीय योजना प्रचार संगठन के रूप में अपना कार्य शुरू किया। 1959 में इसे क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय का रूप दिया गया। कुछ समय पश्चात् क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां तथा क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए। मौजूदा दौर में 22 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 207 क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों के माध्यम से यह निदेशालय ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार अभियान में लगा है। इस निदेशालय की पहुंच बहुत व्यापक है। दूर-दराजों के क्षेत्रों तथा उन गांवों तक इसकी पहुंच है जहां आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता।

क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां प्रचार के कई तकनीकों का प्रयोग करती हैं, जैसे-फिल्म शो, गीत तथा नाटक, फोटो प्रदर्शनी, ग्रुप डिसकशन, सेमिनार, संगोष्ठी, रैली तथा विविध प्रतिस्पर्धात्मक तरीके जैसे-वाद-विवाद, ड्राइंग, ग्रामीण खेल आदि। इन गतिविधियों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य होता है ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षित तथा जागरूक करना। डीएफपी (क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय) विकास गतिविधियों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि निम्न स्तर के लोगों को भी जागरूक बनाया जाए तथा विकास गतिविधियों से उन्हें जोड़ा जाए। डीएफपी एक ऐसा मंच प्रदान करता है ताकि लोग सरकार द्वारा जारी विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों तथा योजनाओं के बारे में अपनी प्रतिक्रिया (विचार) व्यक्त कर सकें।

## वार्षिक योजना 2011-12

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वर्ष 2011-12 के लिए 2.79 करोड़ रुपये का कोष उपलब्ध कराया है। इनमें से 79.00 लाख रुपये की राशि आयोजित दौरों/कौशल उन्नयन तथा 2.00 करोड़ रुपये की राशि क्षेत्रीय प्रचार कार्यालयों/इकाइयों के सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण स्कीम के लिए है। इसके तहत 17 आयोजित दौरों, 31 मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर, 10 डीवीडी प्लेयर, 15 वायरलेस पी.ए. सिस्टम, 8 डिजिटल वीडियो कैमरों का प्रावधान है। इसके अलावा फिल्म प्रभाग आदि से अधिक से अधिक वीएचएस कैसेट/सीडी/डीवीडी प्राप्त करने, एक प्रोग्रामर,दो सहायक प्रोग्रामर तथा 100 डेटा एंट्री आपरेटर, 25 डिजिटल कैमरे को किराये पर लेने तथा 26 वाहनों को प्राप्त करने का प्रावधान है।

# योजना स्कीम 2011-12

*(हजार रुपये में)*

| क्रम सं. | योजना का नाम | 2011-12 के लिए संशोधित परिव्यय | लक्ष्य 2011-12 | दिस. 11 तक खर्च | उपलब्धि | खाते का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आयोजित दौरे/कौशल उन्नयन | 79.00 | 17 आयोजित दौरे | 60.11 | 6 दौरे आयोजित हुए | मांग सं. 60, ''2220'' सूचना और प्रचार, 60.106 क्षेत्रीय प्रचार 01-क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, 01,00.21-वर्ष 2010-11 के लिए आपूर्ति और सामग्री (योजना) |
| 2. | क्षेत्रीय कार्यालयों/इकाइयों के सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर आधुनिकीकरण तथा उन्नयन | 200.00 | 3 मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर, 10 डीवीडी प्लेयर, 15 वायरलैस पी ए सिस्टम, 8 डिजिटल वीडियो कैमरे प्राप्त करना, 1 प्रोग्रामर, एक सहायक प्रोग्रामर, 100 डीईओ, 26 वाहन, 25 डिजिटल कैमरे | 130.11 | एक प्रोग्रामर और एक सहायक प्रोग्रामर तथा डाटा एंट्री आपरेटरों, 7 वाहनों और 31 मल्टी मीडिया प्लेयर के लिए एनआईसीएसआई को भुगतान | माँग सं. 60, ''4220'' सूचना और प्रचार (मुख्य शीर्ष) पर पूँजी परिव्यय, 60-अन्य (उप मुख्य शीर्ष), 60.052 मशीनरी और सामग्री (लघु शीर्ष), 02 डीईएफ के लिए सामग्री की प्राप्ति, 02.00.52 मशीनरी और सामग्री वर्ष 2011-12 के लिए (योजना)। |
| | **कुल** | 279.00 | | 190.22 | | |

## 2012-13 की वार्षिक योजना

2012-13 की वार्षिक योजना का वास्तविक वित्तीय ब्यौरा इस प्रकार है :

*(लाख रुपये में)*

| योजना का नाम | 2012-13 का वास्तविक लक्ष्य | 2012-13 के लिए प्रस्तावित आबंटन |
|---|---|---|
| (क) **प्रत्यक्ष कार्यक्रम** | | 788.60 |
| विकासात्मक संचार और प्रचार के अन्तर्गत | | |
| (1) विशेष पहुंच वाले कार्यक्रम | 600 विशेष कार्यक्रम | 150.00 |
| (2) लोगों की सुविधानुसार सूचना | क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के मौजूदा ढांचे में 95 सूचना/दिशानिर्देश केन्द्र स्थापित करना | 324.90 |
| (3) आयोजित दौरे/योग्यता उन्नयन | 11 आयोजित दौरे | 55.00 |
| (4) बाह्य स्रोतों के माध्यम से 5000 गांवों में 33000 दौरे किये गये | 1200 दौरों के माध्यम से एक राज्य, एक जिला और 1000 गांव कवर किये गए। | 103.88 |
| (5) प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने वाले कार्यक्रमों के लिए मूलभूत सुविधाएं | 60 मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर, 12 एचडी डीवीडी प्लेयर, 26 वायरलैस पीए सिस्टम, 40 जेनरेटर सेट, 30 डिजिटल स्टिल कैमरे, 34 डिजीटल वीडियो कैमरे, 40 बाक्स आफिस प्रोजेक्टर, 10 लैपटॉप, 3 फोटो कापी मशीनें, 10 वाहन और निदेशालय के अधिकारियों के लिए 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम | 166.22 |
| **केन्द्रीय सूचना सदन** | | 200.00 |
| मीडिया मूलभूत विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत | कुल | 1000.00 |

# एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोज़गार समाचार

2009-10 के दौरान उपलब्धियां अत्यंत संतोषजनक रहीं क्योंकि एम्प्लाइमेंट न्यूज को पूर्व वर्ष की तुलना में विज्ञापन से अधिक राजस्व तथा अधिक लाभ अर्जित हुआ। यह प्रवृत्ति मौजूदा वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान भी बनी रही और 4700.00 लाख रुपये के राजस्व के लक्ष्य की तुलना में कुल 7157.01 लाख रुपये का राजस्व अर्जित हुआ। यह 4887.33 अरब रुपये का अधिशेष है। 2010-11 के दौरान एम्पलाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार ने 4025.99 लाख रुपये अर्जित किए हैं और लक्ष्य प्राप्ति के करीब है। यह लक्ष्य 4887.33 अरब रुपये की डीएवीपी तथा अन्य सरकारी विभागों से वसूली से प्राप्त हुआ है।

**भारतीय जन-संचार संस्थान ( आई आई एम सी ) ( 2012-13 )**

| योजना/गतिविधि का नाम | वित्तीय वर्ष 2010-11 | | वित्तीय वर्ष 2011-12 | | वित्तीय वर्ष 2012-13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धियां | वास्तविक लक्ष्य | उपलब्धियां | अन्तर के कारण | वास्तविक लक्ष्य |
| जनसंचार में प्रशिक्षण/ शिक्षण और अनुसंधान | स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम का आयोजन | जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे किए गये | स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम का आयोजन | पाठ्यक्रम : | अन्य पिछड़ी जातियों के कम उम्मीदवारों के आने के कारण सभी पाठ्यक्रमों में शेष सीटें खाली रहीं। | पाठयक्रम |
| | हिंदी पत्रकारिता (62) | हिंदी पत्रकारिता (62) (एम-52 एफ-10) | हिन्दी पत्रकारिता (62) | हिन्दी पत्रकारिता (56) (एम-39 एफ-17) | | हिंदी पत्रकारिता (62) |
| | अंग्रेजी पत्रकारिता 129 (67+62) | अंग्रेजी पत्रकारिता (66+49) (एम-43, एफ 72) | अंग्रेजी पत्रकारिता 129 (67+62) | अंग्रेजी पत्रकारिता (102) (एम+49 एफ-53) | | अंग्रेजी पत्रकारिता 129 (67+62) |
| | उड़िया पत्रकारिता (23) | उड़िया पत्रकारिता (21) (एम-11 एफ-10) | उड़िसा पत्रकारिता (23) | उड़िया पत्रकारिता (16) | | उड़िया पत्रकारिता (23) |
| | विज्ञापन एवं जनसंपर्क (75) | विज्ञापन एवं जन संपर्क (73) (एम-27 एफ 46) | विज्ञापन एवं जनसंपर्क (75) | विज्ञापन एवं जनसंपर्क (71) एम 25 एफ-46) | | विज्ञापन एवं जन संपर्क (75) |
| | रेडियो एवं टी वी पत्रकारिता (51) | रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता (50) | रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता (51) | रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता | | रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता (51) |
| | विकास पत्रकारिता में दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम (40-45) | विकास पत्रकारिता में दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम (48) एम-20 एफ 28 | विकास पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (40-45) | विकास पत्रकारिता में दो डिप्लोमा पाठयक्रम (47) (एम 19 एफ 28) | | विकास पत्रकारिता में दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम (40-45) |
| | लघु अवधि कार्यक्रम - लघु अवधि पाठ्यक्रम | लघु अवधि पाठ्यक्रम/ कार्यशालाएं (470) | लघु अवधि कार्यक्रम लघु अवधि पाठ्यक्रम/ कार्यशालाएं | लघु अवधि कार्यक्रमु लघु अवधि पाठ्यक्रम/ कार्यशालाएं (435) | | लघु अवधि कार्यक्रम लघु अवधि पाठ्यक्रम/ कार्यशालाएं (400-500) |
| | भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और नये बैच का प्रारंभ | शोध एवं अनुसंधान को पूरा किया गया (4) | भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और नये बैंच का प्रारंभ | भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के लिए प्रसारण और नये बैच का प्रारंभ | | भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और नये बैच का प्रारंभ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | शोध और अनुसंधान (4-5)<br>'कम्यूनिकेटर' और अंग्रेजी संचार माध्यम हिंदी लैब पत्रिकाओं और वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन<br>तीसरे वर्ष के दौरान और अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के अंतिम चरण का कार्यान्वयन | पूरा किया गया<br>पूरा किया गया | शोध और अनुसंधान (4-5)<br>कम्यूनिकेटर (अंग्रेजी) और 'संचार माध्यम' (हिन्दी, लैब पत्रिकाओं और वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन) | शोध और अनुसंधान (5)<br>कम्यूनिकेटर (अंग्रेजी) 2007 का अंक प्रकाशित संस्थान के विभिन्न पाठयक्रमों छात्रों में 60 प्रतिशत महिलाएं | शोध और अनुसंधान (4-5)<br>कम्यूनिकेटर (अंग्रेजी) और 'संचार माध्यम' हिन्दी लैब पत्रिकाओं और वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन<br>महिला छात्रों का विभिन्न पाठ्यक्रमों में आना जारी |

कोष्ठक में दी गई संख्या में छात्रों की संख्या इंगित हैं।

## 11वीं पंचवर्षीय योजना में भरतीय जनसंचार संस्थान के योजनाबद्ध वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियां

*(करोड़ रुपये में)*

| | 2010-11 | | | | 2011-12 | | | | 2012-13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **योजना** | **बजट आंबटन 2010-11** | **वास्तविक व्यय 2010-11** | **लक्ष्य** | **वास्तविक उपलब्धियां** | **बजट आबंटन 2011-12** | **संशोधित व्यय 2011-12** | **लक्ष्य** | **वास्तविक उपलब्धियां** | **प्रस्तावित** | **लक्ष्य** |
| अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भारतीय जनसंचार संस्थान को पहुंचाना | 3.70 | 3.60 | मौजूदा बिल्डिंग के अलावा 50 प्रतिशत निर्माण कार्य को पूरा किया गया | 200.00 | 20.00 | 4.90 | दिल्ली में संस्थान के बिल्डिंग के अलावा शत प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा | दिसंबर 2011 तक नई दिल्ली के संस्थान के मौजूदा बिल्डिंग के अलावा निर्माण काम | 10.00 | संस्थान के निर्माण कार्य के लिए डीडीए और अन्य संस्थानों से स्वीकृति ली गई। |
| दो क्षेत्रीय कार्यलयों के लिए शिक्षण उपकरणों की खरीद | | पूरी की गई | | | | | नई दिल्ली एवं ढेनकनाल में संस्थान के एक और भवन का निर्माण कार्य शुरू | ढेनकनाल और नई दिल्ली में संस्थान के और भवन का निर्माण कार्य शुरू | | ढेनकनाल में भारतीय जन संचार संस्थान की बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू |
| | | | | | | | क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए शिक्षण उपकरणों की खरीद | शिक्षण उपरकरणों की खरीद मार्च 2012 तक पूरी की गई | | संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थाई परिसर के लिए आवास एंव भूमि |
| | | | | | | | मिजोरम और महाराष्ट्र (विदर्भ) में संस्थान के दो क्षेत्रीय केन्द्रों को खोला गया | अगस्त 2011 में आइजोल (मिजोरम) में और अमरावती (महाराष्ट्र में क्षेत्रीय केन्द्र शुरू किए गए | | |
| दो नये क्षेत्रीय केन्द्रों का प्रारंभ किया जाना | | | | | | | | | 01.00 | आइजोल और अमरावती में स्थाई परिसर के लिए निवेश पूर्ण गतिविधियों की शुरुआत की गई |

# फोटो प्रभाग

## 2010-11 के वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियां

### वित्तीय

*(लाख रुपये में)*

| स्वीकृत बजट अनुदान | | | वास्तविक परिव्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|
| योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल |
| 84.10 | 351.53 | 436.03 | 65.47 | 329.46 | 394.93 |

**2011-12**

*(लाख रुपये में)*

| | योजना | गैर-योजना | कुल |
|---|---|---|---|
| स्वीकृत बजट अनुदान | 210.00 | 396.00 | 606.00 |
| संशोधित अनुमानित (प्रस्तावित) | 175.00 | 394.00 | 569.00 |
| वास्तविक परिव्यय | 36.63 | 251.63 | 288.26 |

**बजट अनुमान 2012-13**

*(लाख रुपये में)*

| योजना | गैर-योजना | योग |
|---|---|---|
| 50.00 | 406.00 | 456.00 |

| | | 20011-12 | | 2012-13 |
|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | | लक्ष्य | उपलब्धियां | लक्ष्य |
| 1. | समाचार एवं फीचर अवसरों को कवर किया | 3500 | 2354 | 3500 |
| 2. | डिजीटल फोटो को विभाग में प्राप्त किया | - | 123250 | 125000 |
| 3. | फोटो डिवीजन की वेबसाइट पर डिजीटलीकरण करके फोटो को अपलोड किया गया | - | 7401 | 10000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4. | कुल तैयार प्रिंट उनकी आपूर्ति | 100000 | 73460 | 100000 |
| 5. | आर्काइव में फोटो को अपलोड किया | 100000 | 89,827 | 120000 |
| 6. | कुल फोटो एलबम, फोटो को तैयार किया और उनकी आपूर्ति | 200 | 217 | 250 |

# भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) का कामकाज अर्द्ध न्यायिक किस्म का है। वह इस बात पर नजर रखती है कि प्रेस नैतिक मानदंडों का पालन करे। इसलिए इसके कामकाज का लक्ष्य के हिसाब से आकलन करना सही नहीं होगा। अलबत्ता इसकी अर्द्ध न्यायिक गतिविधियों को आंकड़ों की नजर से देखा जा सकता है। वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान उसे मिली शिकायतों और उनके समाधान का ब्यौरा संलग्न है। उसने लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका पर सालों भर और राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोहों के दौरान चर्चाएं आयोजित कीं। इस साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस 'सार्वजनिक जवाबदेही के औजार के रूप में मीडिया' विषय पर केन्द्रित था। इस अवसर पर एक स्मारिका प्रकाशित की गई जिसमें इस विषय पर महत्वपूर्ण लेख थे। राज्यों में भी राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोहपूर्वक मनाया गया।

परिषद ने सलाहकार की अपनी भूमिका में सरकार और अन्य प्रतिष्ठानों को जिन मसलों पर अपनी राय मुहैया कराई उनमें से कुछ इस प्रकार हैं -

1. इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया में अश्लील कार्यक्रमों और समाचारों पर चिंता जताने वाला प्रस्ताव जिसे लोकसभा में नियम 189 के तहत स्वीकार किया गया।
2. ज्योतिष से संबंधित विज्ञापनों का मामला जिसे विधि एवं न्याय मंत्रालय, कानूनी मामला विभाग, भारतीय विधि आयोग की तरफ से परिषद को भेजा गया।
3. किसी समाचार को पेड न्यूज घोषित करने के मानदंड तय करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग से मिला अनुरोध। परिषद ने ऐसे चार मानदंड/दिशानिर्देश भेजने का निर्णय लिया जिनका इस्तेमाल पेड न्यूज पर कार्रवाई में किया जा सकता था।

## पेड न्यूज

पीसीआई ने 'अमर उजाला' और 'दैनिक जागरण' को पेड न्यूज के मामले में दोषी ठहराया था। निर्वाचन आयोग ने उसके फैसले के आधार पर उत्तर प्रदेश के संबंधित विधायक के खिलाफ कार्रवाई की। उसे समाचार/विज्ञापन पर हुए खर्च को अपने चुनाव व्यय में नहीं दिखाने के मामले में तीन साल तक संसद और विधान मंडल के किसी भी सदन का चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया। आयोग ने यह फैसला इस उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव हारने वाले एक प्रत्याशी की शिकायत पर किया।

परिषद ने किसी समाचार को पेड न्यूज घोषित करने के लिए तय मानदंडों/दिशानिर्देशों को आयोग के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और महाराष्ट्र के राज्य निर्वाचन अधिकारियों को भी भेजने का फैसला किया। इनमें से शुरुआती पांच राज्यों में 2012 के फरवरी और मार्च में विधानसभा चुनाव कराए गए हैं।

**मीडियाकर्मियों के अधिकारों के हनन और प्रेस की आजादी पर खतरे के निम्नलिखित मामलों में परिषद ने अपनी ओर से कार्रवाई की -**

1. 'मिड डे' मुंबई के खोजी पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या की।
2. पत्रकार डेविड देवदास पर जघन्य हमला।
3. जम्मू कश्मीर में सशस्त्र बलों द्वारा मीडियाकर्मियों की पिटाई और उन्हें अपना काम करने से रोका जाना। राज्य सरकार ने परिषद को इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने का आश्वासन दिया।

## अन्य देशों के प्रेस संस्थानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श

पीसीआई विभिन्न देशों की प्रेस परिषदों और अन्य ऐसी संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय संगठन वर्ल्ड एसोसिएशन आफ प्रेस काउंसिल्स (डब्ल्यूपीसी) का सक्रिय सदस्य है। डब्ल्यूएपीसी की कार्यकारी परिषद की बैठक 26 अप्रैल 2011 को नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसमें हुए विचार विमर्श से सभी सदस्य लाभान्वित हुए।

पीसीआई ने प्रेस की आजादी और उसके नैतिक मानदंडों को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों की संबंधित संस्थाओं से विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू की। उसके एक प्रतिनिधिमंडल ने मलेशिया में प्रेस परिषद के गठन के लिए 7 से 9 अप्रैल 2011 तक उस देश का दौरा किया। इसके अलावा पिछले साल 27 से 30 नवंबर तक हांगकांग और 7 और 8 दिसंबर को इंडोनेशिया का दौरा किया गया। अफगानिस्तान के एक प्रतिनिधिमंडल ने 26 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका के एक दल ने 23 नवंबर को पीसीआई का दौरा किया।

पीसीआई ने पिछले साल 28 और 29 अप्रैल को नई दिल्ली में 'मानवाधिकारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इसमें भारत के अलावा आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, तुर्की, इजरायल, तंजानिया, नेपाल और इंडोनेशिया जैसे विभिन्न देशों के मीडियौ संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

**सतर्कता और सूचना अधिकार ढांचों का कामकाज संतोषजनक रहा।**

**हिन्दी भाषा को बढ़ावा**

परिषद ने अपने अधिकारिक कामकाज में हिन्दी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर खास ध्यान दिया। खंड 10(4) में पहले से ही अधिसूचित उसके सभी कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए उत्साहित किया जाता है। कर्मचारियों के लाभ के लिए राजभाषा पर एक अनिवार्य कार्यशाला के अलावा अन्य तिमाही कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं।

पीसीआई के फैसलों और अन्य घोषणाओं को द्विभाषी स्वरूप में सार्वजनिक किया गया।

**प्रकाशन**

1. हिन्दी और अंग्रेजी में तिमाही गृह पत्रिका का प्रकाशन जिसमें परिषद की गतिविधियों के अलावा प्रेस जगत की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी दी जाती है।
2. वार्षिक रिपोर्ट को द्विभाषी स्वरूप में प्रकाशित कर उसे समय पर संसद के दोनों सदनों में रखा गया।
3. 2010-11 के फैसलों का संकलन (हिन्दी और अंग्रेजी)
4. राष्ट्रीय प्रेस दिवस - स्मारिका 2011।

| क्रम संख्या | विवरण | 2010-11 | 2011-12 | 12 अप्रैल से 13 मार्च तक (संभावित) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | लांबित मामले | 1173 | 1047 | |
| 2. | दर्ज मामले | 900 | 550 | 950 |
| 3. | जिन मामलों पर परिषद ने फैसला किया | 225 | 50 | |
| 4. | अध्यक्ष द्वारा किए गए फैसले | 801 | 524 | |
| 5. | 31.3.2009 तक लंबित मामले | 1047 | 1023 | |

# पत्र सूचना कार्यालय

**1. वर्ष 2011-12 के दौरान पहले नौ महीनों के दौरान योजना और गैर योजना प्रदर्शन**
**2. वर्ष 2010-11 के दौरान योजना और गैर-योजना प्रदर्शन**

**वार्षिक योजना 2011-2012** *(करोड़ रुपये में)*

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना आबंटन | | अंतिम अनुदान | वास्तविक व्यय 31.3.11 तक | पूर्वोत्तर क्षेत्र | | कमी के कारण (यदि कोई हो) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | एसबीजी | संशोधित व्यय | | | 2010-11 का आंबटन | 31.3.2011 तक व्यय | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केंद्र की स्थापना | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | नई दिल्ली में स्थित भवन पूरे देश के लाभ के लिए है इसलिये पूर्वोत्तर के लिए अलग से प्रावधान नहीं। | | |
| 2. | मीडिया की पहुंच के कार्यक्रम | 14.50 | 14.00 | 11.00 | 10.06 | 2.00 | 1.60 | 50 जन सूचना अभियानों के लक्ष्य के मुकाबले 136 जन सूचना अभियान आयोजित किए गए। व्यय की स्थित संतोषजनक रही। |
| 3. | *विशेष अवसरों पर प्रचार। इसके अंतर्गत तीन घटक शामिल हैं जो इस प्रकार हैं :*<br>(i) भारतीय अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई) | 0.08 | 0.08 | 0.061 | 0.0609 | शून्य | शून्य | 41वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह 2 दिसंबर 2010 को समाप्त हुआ और इसमें 6.09 लाख रुपये योजना आंबटन के अन्तर्गत खर्च हुए। गैर योजना आंबटन में से 6.80 लाख रुपये अतिरिक्त रूप से व्यय हुए जिससे कंप्यूटर, फैक्स मशीनें, फोटोकापी मशीने और वाहन किराये पर लिए गए। |

*(करोड़ रुपये में)*

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना आबंटन | | अंतिम अनुदान | वास्तविक व्यय 31.3.11 तक | पूर्वोत्तर क्षेत्र | | कमी के कारण (यदि कोई हो) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | एसबीजी | संशोधित व्यय | | | 2010-11 का आंबटन | 31.3.2011 तक व्यय | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | (ii) प्रवासी भारतीय दिवस समारोह | 0.0125 | 0.018 | — | — | शून्य | शून्य | यह समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया इसलिए इसके लिए गैर योजना बजट आदि से व्यय किया गया। |
| | (iii) मीडिया आदान-प्रदान कार्यक्रम | 0.1575 | 0.1575 | — | — | 0.0440 | शून्य | अन्य देशों से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया न मिलने की वजह से कोई प्रगति नहीं हो सकी और अंतिम अनुदान स्तर पर सभी फंडों को लौटा दिया गया। |
| 4. | दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मुख्य प्रेस केन्द्र और अन्य मीडिया केन्द्र | 21.75 | 21.75 | 13.94 | 13.94 | यह खेल दिल्ली में आयोजित किए गए थे इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग से बजट प्रावधान नहीं किया गया। | | कुल आबंटन में से 1987 करोड़ रुपये जनवरी 2011 तक जारी किए गए। बाद में बेसिल ने 5.93 करोड़ रुपये लौटा दिए जिसे सरकारी लेखे में डाल दिया गया। इस प्रकार इस योजना के लिए 13.94 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। |
| | **कुल** | **46.50** | **46.00** | **35.01** | **34.07** | **2.00** | **1.60** | |

## दिसंबर 2011 तक पहले 9 महीनों का योजना व्यय ( 2011-12 की वार्षिक योजना )

*(करोड़ रुपये में)*

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना आबंटन | | अंतिम अनुदान | वास्तविक व्यय 31.12.11 तक | पूर्वोत्तर क्षेत्र | | कमी के कारण ( यदि कोई हो ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | एसबीजी | संशोधित व्यय | | | 2010-11 का आंबटन | 31.12.2011 तक व्यय | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र की स्थापना | 20.50 | 30.00 | — | 18.00 | नई दिल्ली स्थित भवन पूरे देश के लिए है इसलिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अलग से प्रावधान नहीं किया | | दिए गए समय के अनुसार निर्माण कार्य लगभग पूरा |
| 2. | मीडिया के लिए कार्यक्रम | 14.50 | 14.00 | — | 6.6573 | 2.00 | 1.0531 | दिसंबर 2011 तक 89 जन सूचना अभियान आयोजित किये गये। |
| 3. | विशेष अवसरों के लिए इस योजना में तीन घटक इस प्रकार हैं : | | | | | | | |
| | (i) भारतीय अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोह | 0.08 | 0.08 | — | 0.08 | — | — | गोवा में 23 नवंबर से 3 दिसंबर 2011 तक अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित किया गया। |
| | (ii) प्रवासी भारतीय दिवस समारोह | 0.0125 | 0.0125 | — | — | — | — | 7-9 जनवरी 2012 तक प्रवासी भारतीय दिवस समारोह आयोजित किया गया। |
| | (iii) मीडिया आदान-प्रदान कार्यक्रम | 0.1575 | 0.1575 | — | — | — | — | इस घटक पा कार्यान्वयन अन्य देशों पर निर्भर करता है। अन्य देशों से प्रतिक्रिया न प्राप्त होने की वजह से कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। |
| | **कुल** | **35.35** | **44.75** | **—** | **24.74** | **2.00** | **1.0531** | |

# प्रकाशन विभाग

## 2011-12 ( 31.12.2011 तक ) तथा 2012-13 के वर्ष के दौरान लक्ष्य और उपलब्धियां

**वित्तीय**

*(लाख रुपये में)*

| बजट आकलन 2010-11 | | | वास्तविक व्यय 2011-12 ( 31.12.2011 तक ) | | | बजट आकलन 2012-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर योजना | कुल | योजना | गैर योजना | कुल |
| 23.62 | 2337.20 | 2360.82 | 29.55 | 1772.94 | 1802.49 | 200.00 | 2270.00 | 2470.00 |

**वास्तविक**

| | 2010-11 | | 2011-12 | | 2012-13 ( लक्ष्य ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धियां | लक्ष्य | उपलब्धियां | लक्ष्य | उपलब्धियां |
| पत्रिकाएं | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
| पुस्तक | 90 | 93 | 90 | 33 (दिसंबर 2011 तक) | 100 | - |

### 4.2 अन्य सरकारी विभागों के साथ गठजोड़

विभाग डाक विभाग के साथ गठजोड़ की संभावना तलाश कर रहा है ताकि अपने नेटवर्क को बढ़ाकर विभाग की पुस्तकें/पत्रिकाएं जनता को बेची जा सकें।

### 4.4 सार्वजनिक निजी भागीदारी

प्रकाशन विभाग की किताबों को बेचने के लिए शीर्ष पुस्तक विक्रेताओं/प्रकाशकों को शामिल करके सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभाग में मानव संसाधन कम होने के कारण पांडुलिपि, प्रूफ रीडिंग, अनुवाद इत्यादि से संबंधित कार्य बाहर से करवाए जा रहे हैं। स्वचलन से संपूर्ण प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता आएगी और माऊस को क्लिक करके सारी सूचना प्राप्त की जा सकेगी। प्रकाशन विभाग की वेबसाइट www.publicationsdivision.nic.in के माध्यम से निविदा संबंधी सभी पूछताछ को इंटरनेट पर डाला जा रहा है।

**4.4 प्रकाशन विभाग ने वर्ष 2012-13 में योजना के तहत निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रस्ताव दिया है।**

*(लाख रुपये में)*

| | | |
|---|---|---|
| | **प्रकाशन विभाग और रोजगार समाचार पत्र का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण और उन्नयन योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित छह घटक इस प्रकार हैं :** | 200.00 |
| 1. | विशेष विषयों पर पुस्तकें लिखवाना। | |
| 2. | 1944 से अपने प्रकाशनों का डिजिटलीकरण। | |
| 3. | वाणिज्यिक विभाग के पुस्तकों के स्टॉक प्रबंधन, रायल्टी और अन्य गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण। | |
| 4. | कार्यालय के मूलभूत ढांचे का आधुनिकीकरण। | |
| 5. | अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भागीदारी। | |
| 6. | रोजगार समाचार इंटरनेट पर उपलब्ध कराना और रोजगार समाचारपत्र का डिजीटलीकरण। | |
| 7. | पूर्वोत्तर क्षेत्र घटक : पुस्तक प्रदर्शनियों और पुस्तक मेलों का आयोजन, पुस्तक को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों और लेखकों के लिए विशेष कार्यक्रम जैसे सेमिनार, कार्यशालाएं आदि आयोजित करना। | |
| | **कुल** | **200** |

## 5. विपणन और बिक्री को बढ़ावा

प्रकाशन विभाग की पुस्तकें बिक्री केन्द्रों/आउटलेटों, पुस्तक प्रदर्शनियों और एजेन्टों के नेटवर्क के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचती हैं। ये बिक्री केन्द्र नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई, पटना और तिरुअनंतपुरम में स्थित हैं। बंगलुरू और गुवाहाटी प्रकाशन विभाग ने जिन पुस्तक प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लिया, वह इस प्रकार हैं :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14वां नेयवेली पुस्तक मेला | नेयवेली (तमिलनाडु) | चेन्नई | 1.7.2011 से 10.7.2011 |
| 2. | श्रीनगर पुस्तक मेला 2011 | श्रीनगर (उत्तराखंड) | मुख्यालय | 16.7.2011 से 24.7.2011 |
| 3. | इरोड पुस्तक मेला | इरोड (तमिलनाडु) | चेन्नई | 29.7.2011 से 9.8.2011 |
| 4. | दिल्ली पुस्तक मेला-2011 | प्रगति मैदान, नई दिल्ली | मुख्यालय | 27.8.2011 से 4.8.2011 |
| 5. | 9वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला-2011 | लखनऊ (उ.प्र.) | लखनऊ | 15.9.2011 से 25.9.2011 |
| 6. | 23वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला-2011 | देहरादून | मुख्यालय | 24.9.2011 से 2.10.2011 |
| 7. | पुडुचेरी पुस्तक मेला-2011 | पुडुचेरी (तामिलनाडु) | चेन्नई | 15.10.2011 से 24.10.2011 |
| 8. | फैजाबाद पुस्तक मेला-2011 | फैजाबाद (उ.प्र.) | लखनऊ | 2.11.2011 से 6.11.2011 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9. | राष्ट्रीय पुस्तक मेला-2011 | वाराणसी | लखनऊ | 4.11.2011 से 13.11.2011 |
| 10. | राष्ट्रीय पुस्तक मेला-2011 | जयपुर | मुख्यालय | 5.11.2011 से 13.11.2011 |
| 11. | पुस्तक प्रदर्शनी | वसंतकुंज, नई दिल्ली | दिल्ली | 14.11.2011 से 16.11.2011 |
| 12. | उर्दू विरासत उत्सव | लाल किला, दिल्ली | दिल्ली | 16.11.2011 से 20.11.2011 |
| 13. | पुस्तक प्रदर्शनी | लक्ष्मी नगर, दिल्ली | दिल्ली | 18.11.2011 से 20.11.2011 |
| 14. | 12वां राजधानी पुस्तक मेला-2011 | भुवनेश्वर | कोलकाता | 1.2.2011 से 11.12.2011 |
| 15. | हैदराबाद पुस्तक मेला | हैदराबाद | हैदराबाद | 16.12.2011 से 25.12.2011 |
| 16. | सीकर पुस्तक मेला | सीकर (राजस्थान) | मुख्यालय | 28.12.2011 से 4.1.2012 |
| 17. | विजयवाड़ा पुस्तक मेला | विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) | हैदराबाद | 1.1.2012 से 11.1.2012 |
| 18. | 35वां चेन्नई पुस्तक मेला | चेन्नई | चेन्नई | 5.1.2012 से 17.1.2012 |

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों में विभाग द्वारा प्रस्तावित भागीदारी

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | कोलकाता पुस्तक मेला | कोलकाता | कोलकाता | 25.1.2012 से 5.2.2012 |
| 2. | विश्व पुस्तक मेला | प्रगति मैदान | नई दिल्ली, मुख्यालय | 25.2.2012 से 4.3.2012 |

अप्रैल 2011 से दिसंबर 2011 तक जन सूचना अभियानों (पीआईसी) के अवसर पर विभाग द्वारा आयोजित पुस्तक प्रदर्शनियां।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | जन सूचना अभियान के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी | झांसी, जनपथ (उ.प्र.) | लखनऊ | 2.6.2011 से 24.6.2011 |
| 2. | जन सूचना अभियान के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी | पुडुचेरी (तमिलनाडु) | चेन्नई | 5.7.2011 से 7.7.2011 |
| 3. | जनसूचना अभियान के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी | पोलाची, कोयंबटूर (तमिलनाडु) | चेन्नई | 27.8.2011 से 29.8.2011 |
| 4. | जनसूचना अभियान के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी | चेनगम तिरुवनामल्ली (तमिलनाडु) | चेन्नई | 10.9.2011 से 12.9.2011 |
| 5. | जनसूचना अभियान के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी | भदोही (उ.प्र.) | लखनऊ | 13.10.2011 से 15.10.2011 |
| 6. | जनसूचना अभियान के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी | पुनपुन (बिहार) | पटना | 22.10.2011 से 24.10.2011 |
| 7. | जनसूचना अभियान के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी | धडोडरीमलाई, करूर (तमिलनाडु) | चेन्नई | 19.11.2011 से 21.11.2011 |
| 8. | जनसूचना अभियान के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी | बेहराइच, जनपथ (उ.प्र.) | लखनऊ | 28.11.2011 से 30.11.2011 |
| 9. | जनसूचना अभियान के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी | नागरेओल, कन्याकुमारी (तमिलनाडु) | चेन्नई | 7.12.2011 से 19.12.2011 |

अप्रैल से दिसंबर 2011 तक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसरों पर विभाग द्वारा आयोजित पुस्तक प्रदर्शनियां

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | विश्व पुस्तक दिवस पर पुस्तक प्रदर्शनी | 18.4.2011 से 29.4.2011 | विभाग के 9 बिक्री केन्द्रों में |
| 2. | ग्रीष्म पुस्तक प्रदर्शनी | 13.6.2011 से 24.6.2011 | विभाग के 9 बिक्री केन्द्रों में |
| 3. | स्वतंत्रता दिवस पुस्तक प्रदर्शनी | 8.8.2011 से 18.8.2011 | विभाग के 9 बिक्री केन्द्रों में |
| 4. | शिक्षक दिवस पुस्तक प्रदर्शनी | 29.8.2011 से 8.9.2011 | विभाग के 9 बिक्री केन्द्रों में |
| 5. | हिंदी पखवाड़ा पुस्तक प्रदर्शनी | 14.9.2011 से 23.9.2011 | विभाग के 9 बिक्री केन्द्रों में |
| 6. | गांधी जयंती पुस्तक प्रदर्शनी | 29.9.2011 से 14.10.2011 | विभाग के 9 बिक्री केन्द्रों में |
| 7. | राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह पुस्तक प्रदर्शनी | 8.11.2011 से 18.11.2011 | विभाग के 9 बिक्री केन्द्रों में |
| 8. | क्रिसमस और नववर्ष पुस्तक प्रदर्शनी | 22.12.2011 से 4.1.2012 | विभाग के 9 बिक्री केन्द्रों में |

महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसरों पर वर्ष 2011-12 के वित्त वर्ष के दौरान विभाग अपने बिक्री केन्द्रों पर प्रस्तावित पुस्तक प्रदर्शनियां

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | गणतंत्र दिवस पुस्तक प्रदर्शनी | 23.1.2012 से 3.2.2012 | विभाग के 9 बिक्री केन्द्रों में |
| 2. | उपभोक्ता अधिकार दिवस पुस्तक प्रदर्शनी | 12.3.2012 से 23.3.2012 | विभाग के 9 बिक्री केन्द्रों में |

प्रकाशन विभाग ने राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों से प्राप्त आर्डरों को पूरा किया।

राजा राममोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन योजना, कोलकाता के अन्तर्गत राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से प्राप्त आर्डरों को पूरा किया। विभाग ने अप्रैल 2011 से दिसंबर 2011 तक अपनी पुस्तकों, पत्रिकाओं और विज्ञापनों के माध्यम से 390.04 लाख रुपये का (रोजगार समाचार पत्र सहित) कुल राजस्व अर्जित किया।

विभाग ने अपने प्रकाशनों और पत्रिकाओं के विपणन के अलावा अन्य सरकारी विभागों, राज्य सरकारों, स्वायत्त संस्थानों जैसे नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी, सीएसआईआर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय आदि के प्रकाशनों की भी बिक्री की।

# भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक

## वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 ( 31.3.2012 तक ) तथा 2012-13 के दौरान लक्ष्य और निष्पादन

### वित्तीय

*( लाख रुपये में)*

| गतिविधि का नाम | वर्ष | योजना | गैर-योजना | कुल |
|---|---|---|---|---|
| अनुमानित बजट | 2010-11 | 17.00 | 359.00 | 376.00 |
| वास्तविक बजट | 2010-11 | 16.99 | 377.39 | 394.38 |
| अनुमानित बजट | 2011-12 | 17.00 | 435.00 | 452.00 |
| संशोधित अनुमान | 2011-12 | 4.00 | 405.00 | 409.00 |
| अनुमानित बजट | 2012-13 | 30.00 | 417.00 | 420.50 |

आरएनआई के सुदृढ़ीकरण के लिए 88.06 लाख रु. के व्यय के लिए योजना आयोग के तहत मंत्रालय द्वारा एक योजना स्कीम मंजूर की गई। वर्ष 2012-13 के लिए 30.00 लाख रु. की राशि निर्धारित की गई है।

## भौतिक

| क्र. सं. | | 2010-11 | | 2011-12 | | 2012-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **कार्यक्रम/गतिविधियां** | **लक्ष्य** | **उपलब्धियां** | **लक्ष्य** | **उपलब्धियां** नवंबर 2011 तक | **लक्ष्य** |
| **अ.** | **गतिविधियां** | | | | | |
| 1. | शीर्षक देने का कार्य (आवेदन) | 25044 | 13233 | 17917 | 10275 | *** |
| 2. | शीर्षकों को मुक्त करना | *** | 8292 | *** | 7763 | *** |
| 3. | पंजीकरण | 28328 | 5763 | 20362 | 4881 | *** |
| 4. | प्रसार के दावों की जांच | *** | *** | 40 | 31 | *** |
| 5. | प्रिंटिंग मशीनों के आयात के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र जारी किए | *** | *** | *** | 0 | *** |
| 6. | एफसीआरए,1976 के अंतर्गत समाचार पत्रों को जारी प्रमाणपत्रों की संख्या | *** | 12 | *** | 4 | *** |
| 7. | अखबारी कागज के आयात के लिए प्रकाशकों को जारी किये गये योग्यता प्रमाणपत्रों की संख्या | *** | 775 | *** | 1091 | *** |
| 8. | सूचना के अधिकार के अन्तर्गत किये गये आवेदनों की संख्या | 963 | 911 | 955 | 845 | *** |
| **ख.** | **कार्यक्रम** | | | | | |
| 9. | आरएनआई की वार्षिक रिपोर्ट (भारत के समाचार पत्र) | 2009-10 रिपोर्ट | 2009-10 रिपोर्ट | 2010-11 रिपोर्ट | 2010-11 रिपोर्ट | 2011-12 रिपोर्ट |

**नोट :** प्रकाशकों द्वारा प्राप्त किये गये आवेदनों पत्रों/आवेदनों पर आधारित इस श्रेणी में इस तरह का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता।

| | | |
|---|---|---|
| वर्ष 2010–11 के संशोधित अनुमान के लिए योजनागत परिव्यय | : | 17.00 लाख रुपये |
| वर्ष 2010–11 के लिए योजनागत कार्य/उपलब्धियां | : | 16.99 लाख रुपये |

## 2011–12 के लिए योजनागत परिव्यय

| | | |
|---|---|---|
| 2011–12 के लिए स्वीकृत बजट सहायता | : | 17.00 लाख रुपये |
| 2011–12 के लिए संशोधित अनुमान | : | 4.00 लाख रुपये |
| 2012–13 के लिए बजट अनुमान | : | 30.00 लाख रुपये |
| 11वीं योजना के कार्यक्रमों का नाम | | |
| **कुल योजना परिव्यय** | : | **88.06 लाख रुपये का कुल बजट आंबटन और समाचार पंजीयक कार्यालय को सुदृढ़ बनाना** |

## 11वीं योजना स्कीम : आर एन आई का सुदृढ़ीकरण

वर्ष 2010–11 के दौरान 17.00 लाख रुपये के कुल परिव्यय के साथ स्वीकृत 11वीं योजना में आर एन आई में सुदृढ़ीकरण को शामिल किया गया। इसके अन्तर्गत आर एन आई के दो क्षेत्रीय कार्यालय एक गुवाहाटी में और एक भोपाल खोलने का प्रावधान रखा गया। 2011–12 के लिए बजट आबंटन में से 3.44 लाख रुपये की राशि 31.2012 तक व्य की गई। समाचार पत्र पंजीयक कार्यालय के अन्तर्गत 2011–12 के दौरान जिन गतिविधियों का कार्यान्वयन किया गया वह इस प्रकार है :

### कम्पयूटरीकरण

शीर्षकों के पंजीकरण और जांच की प्रक्रिया का कंप्यूटरीकरण के अलावा, सभी जांचे गये शीर्षकों को कार्यालय की वेबसाइट में डाला गया और इन्हें आवेदक डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस सुविधा के लिए करने से कोई भी व्यक्ति या प्रकाशक शीर्षकों को देखकर अपनी पसंद के शीर्षकों के लिए आवेदन कर सकता है। यह डाटा बेस राज्य/भाषा अनुसार है। 10वीं योजना के अन्तर्गत रेडियो फ्रीक्वेंसी लिंक शुरू किया किया गया जो अभी तक संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है।

## प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम ( पी आर बी अधिनियम )

प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम 1867 के अन्तर्गत अधिनियम की मौझूदा मीडिया परिदृश्य के अनुरूप समीक्षा की गई। अधिनियम–2011 के संशोधन के अनुसार तैयार किया गया और इसे अंतिम रूप दिया गया।

### राजभाषा

भारत के समाचार पंजीयक कार्यालय में 14–28 सितंबर 2011 को हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें हिंदी में कार्य करने को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगितायें आयोजित की गई।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत इस वर्ष 'पंजीयन आरती' को 5वां पुरस्कार दिया गया। पंजीयक कार्यालय में एक सहायक निदेशक (राजभाषा) और दो अनुवादक कार्यरत हैं जो कार्यालय का अनुवाद कार्य और हिन्दी में किये जा रहे कार्य पर निगराती रखते हैं।

## लोक शिकायतें

कार्यालय का लोक शिकायत सैल भी कार्यरत है। कार्यालय के उप प्रेस पंजीयक आंतरिक शिकायतों को दूर करने के लिए बनाये गए सैल के प्रमुख के रूप में पदासीन हैं।

## पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कार्य

पूर्वोत्तर क्षेत्र और मध्य भारत के क्षेत्र के लिए कार्यालय ने विशेष कदम उठाये हैं। वर्ष 2007-08 में गुवाहाटी में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया और भोपाल में 2008/09 में भोपाल में मध्य क्षेत्र के लिए एक नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र और मध्य क्षेत्र के कार्य कोलकाता के पंजीयक कार्यालय तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत देखा जाता है। गुवाहाटी और भोपाल के पंजीयक कार्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र और मध्य क्षेत्र के समाचार पत्र/पत्रिकाओं के प्रकाशकों की जरूरतों को पूरा करने का कार्य करते हैं।

# गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग

## (क) गतिविधि के आधार पर वर्गीकरण

*(लाख रुपये में)*

| क्र. सं. | गतिविधि वर्गीकरण | 2010-11 के लिए वास्तविक | | | 2011-12 के बजट अनुमान | | | संशोधित अनुमान 2011-12 | | | बजट अनुमान 2012-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल |
| 1. | गवेषणा, संदर्भ और प्रलेखन तथा प्रशिक्षण | शून्य | 166.30 | 166.30 | 25.00 | 217.00 | 242.00 | 25.50 | 184.50 | 209.00 | 0.0 | 230.00 | 230.00 |
| | | **शून्य** | **166.30** | **166.30** | **25.00** | **217.00** | **242.00** | **25.50** | **184.50** | **209.00** | **0.0** | **230.00** | **230.00** |

## (ख) उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण

*(लाख रुपये में)*

| क्र. सं. | गतिविधि वर्गीकरण | 2010-11 के लिए वास्तविक | | | 2011-12 के बजट अनुमान | | | संशोधित अनुमान 2011-12 प्रस्तावित | | | 2011-12 के बजट अनुमान | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल |
| 1. | वेतन | – | 132.60 | 132.60 | – | 175.00 | 175.00 | – | 150.00 | 150.00 | – | 170.00 | 170.00 |
| 2. | चिकित्सा | – | 3.60 | 3.60 | – | 4.50 | 4.50 | – | 4.50 | 4.50 | – | 4.50 | 4.50 |
| 3. | ओवरटाइम भत्ता | – | – | – | – | 0.40 | 0.40 | – | 0.20 | 0.20 | – | – | – |
| 4. | घरेलू यात्रा व्यय | – | 0.25 | 0.25 | – | 1.50 | 1.50 | – | 1.50 | 1.50 | – | 2.00 | 2.50 |
| 5. | कार्यालय व्यय (ओ ई-आई आईएस प्रशिक्षण | शून्य | 28.00 | 28.00 | 25.00 | 28.00 | 53.00 | 25.00 | 25.50 | 50.50 | – | 35.50 | 35.00 |
| 6. | अन्य प्रशासनिक व्यय | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7. | बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टेक्स | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8. | प्रशिक्षण | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9. | सूचना प्रौद्योगिकी | – | 1.85 | 1.85 | – | 7.60 | 7.60 | – | 2.80 | 3.40 | – | 18.50 | 18.50 |
| | **कुल जोड़** | **शून्य** | **166.3** | **166.3** | **25.00** | **217.00** | **242.00** | **25.00** | **184.50** | **209.00** | **–** | **230.00** | **255.00** |

# भौतिक निष्पादन के लिए परिणाम बजट ( योजना ) 2012-13

| योजना का नाम | 2010-11 | | 2011-12 | | असमानता के कारण | 2012-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **लक्ष्य** | **उपलब्धि** | **लक्ष्य** | **जनवरी 2012 तक उपलब्धि** | | **लक्ष्य** |
| **1. गवेषणा इकाई** मास मीडिया में शोध। | अनुसंधान पत्र जारी करना | शून्य | शून्य | | विषय को अंतिम रूप नहीं दिया गया। | — |
| **2. अ ) संदर्भ इकाई** लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण करना। | बुक रैक, 500 किताबें ई-बुक और आवधिक पत्रिकाएं खरीदना। पिछले वर्ष खरीदे गए आई टी उपकरण के लिए वार्षिक रखरखाव समझौता करना। | योजना स्कीम के तहत कोई पुस्तक नहीं खरीदी जा सकी | 500 किताबें/ई-बुक, आवधिक पत्रिकाएं और पिछले वर्ष खरीदे गए आईटी उपकरण के लिए एएमसी खरीदना। | योजना स्कीम के तहत कोई पुस्तक नहीं खरीदी जा सकी | पुस्तकालय के लिए जगह की कमी। | |
| **2. ब संदर्भ इकाई** राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार। | राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार चयन समिति का गठन करना, पुरस्कारों के लिए चयन करना, स्मृति चिह्न का डिजाइन कास्टिंग और गढ़ायी करना, पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित करना। | शून्य | योजना के अंतर्गत विभाग ने अंग्रेजी के और आठवीं सूची के अंतर्गत सभी भाषाओं के 30 पुरस्कारों का चयन का प्रस्ताव। | शून्य | योजना को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। | |

## भौतिक निष्पादन के लिए परिणाम बजट ( गैर योजना ) 2012-13

**वास्तविक उपलब्धि ( गैर-योजना )**

| योजना का नाम | 2010-11 | | 2011-12 | | असमानता के कारण | 2012-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति जनवरी 2011 तक | | लक्ष्य |
| **1. एनडीसीएमसी** आवर्ती सेवाओं द्वारा मास मीडिया की प्रवृत्तियों और घटनाओं की जानकारी एकत्रित करना, विश्लेषण करना और उनका प्रसार करना। | 56 | 55 | 56 | 47 | स्टाफ की कमी | 56 |
| मास मीडिया इन इंडिया वार्षिक प्रकाशन का संकलन एवं संपादन करना। | 1 | 0 | 1 | 0 | प्रकाशन विभाग को प्रूफ भेजे गये | 1 |
| **2- संदर्भ एकांश** 'इंडिया-वार्षिक संदर्भ' ग्रंथ का संकलन एवं संपादन | 1 | 1 | 1 | 0 | शीघ्र ही पुस्तक का प्रकाशन | 1 |
| 'डायरी ऑफ इवेन्ट्स' पाक्षिक का प्रकाशन | 24 | 24 | 24 | 20 | - लागू नहीं - | 24 |

# गीत एवं नाटक प्रभाग

प्रभाग को स्थापना संचार उद्देश्यों के लिए प्रचुर लोक कला और पारंपरिक रूपों का दोहन करने के लिए लघु प्रायोगिक इकाई के रूप में 1954 में की गई थी। लाइव इंडिया जिसे अब इस नाम से व्यापक प्रसिद्धि हासिल है, बहुत प्रभावी सिद्ध हुआ है क्योंकि जनता से तत्काल संपर्क करने का लाभ इसमें निहित है तथा इसमें समकालिक मुद्दों, विचारों और समझाने की विधियों का लचीलापन है। इसलिए प्रभाग का कार्यक्षेत्र और आकार बढ़ाया गया ताकि इसे व्यापक पहुंच और सुगमता प्रदान की जा सके तथा दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, रेगिस्तानी और सीमा क्षेत्रों सहित वास्तविक धरातल पर संचार करने के इसके प्रयासों के प्रभाव को बढ़ाया जा सके।

प्रभाग का मुख्य कार्य (जैसा कि इसकी अधिकारिक वेबसाइट में बताया गया है) आम जनता में सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक आदर्शों (जो राष्ट्र की प्रगति के लिए अनुकूल हों), के बारे में जागरूकता और भावनात्मक आत्मीयता पैदा करना, सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में रक्षा तैयारियों और शेष देश के साथ सांस्कृतिक एकता की भावना पैदा करना तथा सुदूर क्षेत्रों में तैनात सेना के जवानों का नैतिक बल लाइव मनोरंजन मीडिया (जिसमें शहरी थियेटर के रूप और देश के सभी क्षेत्रों की लोक कला शामिल है) के जरिए ऊंचा बनाए रखना है।

अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रभाग लोक तथा पारंपरिक नाटकों, नृत्य रूपकों, ओपेरा, नृत्य नाटकों, लोक एवं पारंपरिक काव्य, कठपुतली और सदियों पुरानी परंपरा के जादूगरों के सैंकड़ों कौशल जैसे व्यापक लोक एवं पारंपरिक रूपों का उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त प्रभाग साम्प्रदायिक सामंजस्य, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक विरासत के संवर्द्धन, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आधुनिक तकनीकों और सैंकड़ों कलाकारों के साथ ध्वनि एवं प्रकाश साधनों का भी उपयोग करता है।

प्रभाग को स्थापना संचार उद्देश्यों के लिए प्रचुर लोक कला और पारंपरिक रूपों का दोहन करने के लिए लघु प्रायोगिक इकाई के रूप में 1954 में की गई थी। लाइव इंडिया जिसे अब इस नाम से व्यापक प्रसिद्धि हासिल है, बहुत प्रभावी सिद्ध हुआ है क्योंकि जनता से तत्काल संपर्क करने का लाभ इसमें निहित है तथा इसमें समकालिक मुद्दों, विचारों और समझाने की विधियों का लचीलापन है। इसलिए प्रभाग का कार्यक्षेत्र और आकार बढ़ाया गया ताकि इसे व्यापक पहुंच और सुगमता प्रदान की जा सके तथा दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, रेगिस्तानी और सीमा क्षेत्रों सहित वास्तविक धरातल पर संचार करने के इसके प्रयासों के प्रभाव को बढ़ाया जा सके।

प्रभाग का मुख्य कार्य (जैसा कि इसकी अधिकारिक वेबसाइट में बताया गया है) आम जनता में सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक आदर्शों (जो राष्ट्र को प्रगति के लिए अनुकूल हों), के बारे में जागरूकता और भावनात्मक आत्मीयता पैदा करना, सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में रक्षा तैयारियों और शेष देश के साथ सांस्कृतिक एकता की भावना पैदा करना तथा सुदूर क्षेत्रों में तैनात सेना के जवानों का नैतिक बल तथा सुदूर क्षेत्रों में तैनात सेना के जवानों का नैतिक बना लाइव मनोरंजन मीडिया (जिसमें शहरी थियेटर केरूप और देश के सभी क्षेत्रों की लोक कला शामिल है) के जरिए ऊंचा बनाए रखना है।

लोक कला और पारंपरिक मीडिया या ज्यादा प्रसिद्ध नाम से ज्ञात लाइव इंडिया का न सिर्फ भाषाई, भौगोलिक और सांस्कृतिक संबर्द्धता एवं पहचान के कारण बल्कि ग्रामीण भारत में वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में अत्यधिक प्रभावी हैं। यह बहुत फायदेमंद स्थिति भी है कि हमारे देश में लोककला और पारंपरिक रूपों का विशाल भंडार है जिसके जरिए संदेशों, सूचना या जागरूकता इस ढंग से पैदा की जा सकती है कि जनता उसे तत्काल मान्यता प्रदान करे, प्राप्त करे और उसके अनुरूप क्रिया करे। यह राष्ट्रीय एकीकरण और सांप्रदायिक सामंजस्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में ग्रामीण जनता के सामान्य कल्याण और गरीबी उन्मूलन के लिए लक्षित विकास योजनाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

इसलिए लोककला और पारंपरिक मीडिया को विशेषरूप से ग्रामीण एवं अविद्युतीकृत तथा दुर्गम क्षेत्रों में आम आदमी के हित में विशेष रूप से गरीबों के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे विविध कार्यक्रमों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए सभी मीडिया रणनीति का प्रभावी और एकीकृत घटक के रूप में उपयोग जारी रहेगा।

विभागीय दलों, पैनल में शामिल कलाकारों और प्रभाग के साथ स्पष्ट रूप से नियमित आधार पर काम करने वाली प्राइवेट पंजीकृत मंडलियों सहित लगभग 10,000 लोक और पारंपरिक कलाकार हैं। संभवत: गीत एवं नाटक प्रभाग मॉडल सरकारी संगठनों में से एक है जिसमें अपने परिचालन के क्षेत्रों के साथ-साथ अपनी गतिविधि को भी गैर योजना व्यय बढ़ाए बिना स्थायी दीर्घावधि दायित्व निभाने के लिए विस्तार के लिए जबरदस्त लचीलापन है। प्रभाग की सिर्फ करीब 8 प्रतिशत कार्यकारी शक्ति प्रभाग के नियमित रोल पर है। इसके अतिरिक्त यह निर्विवाद तथ्य है कि पारंपरिक मीडिया या लाइव मीडिया इसकी पहुंच, प्रभाव और लचीलेपन के मद्देनजर आईईसी गतिविधियों के लिए सर्वाधिक किफायती माध्यम है।

निदेशक की अध्यक्षता में प्रभाग तीन स्तरों पर कार्य करता है अर्थात (i) दिल्ली में मुख्यालय, (ii) बंगलुरू, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, पुणे और रांची में दस क्षेत्रीय केन्द्र, (iii) सहायक निदेशकों की अध्यक्षता में सात सीमा केन्द्र दरंभगा, गुवाहाटी, जम्मू, जेबापुर, इंफाल, नैनीताल और शिमला में, (iv) प्रबंधकों की अध्यक्षता में छह विभागीय नाटक मंडली भुवनेश्वर, दिल्ली, हैदराबाद, पटना, पुणे और श्रीनगर (जम्मू) में स्थित है।

# मुख्य सचिवालय की सूचना विंग स्कीमें

## सूचना भवन का निर्माण

अब तक सूचना भवन के निर्माण के लिए आबंटित 63.83 करोड़ रुपये (11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान) की राशि में से 52.06 करोड़ रुपये सिविल कंस्ट्रक्शन विंग, आकाशवाणी को जारी किए जा चुके हैं। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से पांचवें चरण का कार्य 11वीं योजना के अंत तक समाप्त नहीं हो सका। इसी कारण V के चरण का कार्य अगले वर्ष 2012-13 में पूरा किया जायेगा। अगले वित्त वर्ष (2012-13) के दौरान इस परियोजना को पूरा करने के लिए 15 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

# विकास संबंधी पहलों का आर्थिक विश्लेषण ( नई योजना )

**निम्नलिखित अध्ययन कार्य किए गए हैं :**

1. **वार्षिक योजना 2007-08**
   ''उत्तर पूर्व तथा जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में जनसंचार मीडिया का प्रभाव और पहुंच'' : रिपोर्ट भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) द्वारा सौंपी गई।

2. **वार्षिक योजना 2008-09**
   ''भारत में अंत:मीडिया स्वामित्व'': प्रारूप रिपोर्ट भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद (एएससीआई) द्वारा सौंपी गई।

3. फिल्म खंड की दो चालू स्कीमों का मूल्यांकन, तथा; (i) फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा ''फिल्म समारोहों के जरिए निर्यात संवर्द्धन'' और (ii) मुख्य सचिवालय द्वारा ''देश और विदेश में फिल्म बाजारों में भागीदारी'' प्रारूप रिपोर्ट भारतीय जन प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा 2009-10 में जमा की जानी है।

4. 2009-10 के दौरान निम्नलिखित दो अध्ययनों को पूरा किया जाना है :-

   I. ''एफएम पर संगीत के लिए मॉडल आईपीआर व्यवस्था''। यह अध्ययन 2008-09 में मंजूर किया गया था। लेकिन इसके बाद एजेंसी ने इसे पूरा करने में असमर्थता जता दी। इसलिए यही अध्ययन 2009-10 में पूरा किया जा रहा है।

   II. ''प्रसारण उद्योग के कॉपीराइट तथा संबंधित अधिकार'' भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को प्रदान किया गया।

5. **2010-11 की वार्षिक योजना**

   I. ''एफएम पर संगीत मॉडल आईपीआर व्यवस्था'' को इंडियन्स एनालीटिकल लिमिटेड नई दिल्ली को दिया गया। इसकी अंतिम रिपोर्ट शीघ्र आने वाली है।

   II. ''प्रसारण उद्योग के कॉपीराइट तथा संबंधित अधिकार'' भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के दिए गए। इसकी अंतिम रिर्पोट अभी तक नहीं आई है।

6. **2011-12 की वार्षिक योजना**
   सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जुलाई 2011 में राष्ट्रीय प्रर्वतक परिषद की तर्ज पर क्षेत्रीय प्रवर्तक परिषद बनाई है। इस परिषद के सदस्य कई विशेषज्ञ हैं जो अपने क्षेत्र के महारथी हैं। यह परिषद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करेगी।

# मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण

**वर्ष 2012 के लिए निष्पादित बजट के लक्ष्य**

**मीडिया इकाई का नाम :**

*(करोड़ रुपये में)*

| क्र.सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | आवंटन 2011-12 | परिणात्मक हस्तांतरणीय/ वास्तविक उत्पादन | टिप्पणी/जोखिम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | मानव संसाधन विकास (प्रसार भारती सहित) मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण | 1.50 | वर्ष के दौरान कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 57 अधिकारियों को नामांकित किया गया | कोई जोखिम नहीं |

# फिल्म क्षेत्र

## केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

### वास्तविक उपलब्धियां

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने 3548 भारतीय और विदेशी फिल्मों को प्रमाणपत्र जारी किये हैं। बोर्ड ने 9637 भारतीय और विदेशी वीडियो फिल्मों को प्रभाव पत्र दिए।

बोर्ड ने 341 डिजीटल भारतीय और विदेशी फिल्मों को प्रमाणपत्र जारी किए।

**( योजनावाट वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां 2010-11 और 2011-12 )**

| योजना का नाम | वास्तविक लक्ष्य ( 2010-11 ) | वास्तविक उपलब्धियां ( 2010-11 ) | वास्तविक लक्ष्य ( 2011-12 ) | वास्तविक उपलब्धियां ( 2011-12 ) | कमी के कारण |
|---|---|---|---|---|---|
| केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में मूलभूत सुविधाओं के कम्पयूटरीकरण प्रबन्धन की स्थापना | सभी 9 क्षेत्रीय कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण | छह क्षेत्रीय कार्यालय का कम्पयूटरीकरण लिया गया। | सभी व क्षेत्रीय कार्यलयों कम्पयूटरीकरण किया गया। | सभी व क्षेत्रीय कार्यालयों का कम्पयूटरीकरण किया गया और जनवरी 2012 से कम्पयूटरीकृत प्रमाणपत्र जारी करने शुरू किए गए। | |
| प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया का आधुनिकीरकण और निगरानी | 4 बोर्ड की बैठकें और कार्याशालायें आयोजित की गईं। | 4 बोर्ड की बैठकें और कार्याशालालयें आयोजित की गईं। | तिमाही बैठक/संवाद सदस्यों के लिए और कार्यशाला का आयोजन | 4 बोर्ड की बैठकें। संवाद और उद्योग के विशेषज्ञों और दर्शकों के साथ वार्तालाप | |
| दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना | | | अपने क्षेत्रों के फिल्म प्रमाणन का कार्य। | सभी 3 क्षेत्रीय कार्यालय पूरी तरह से स्थापित किए गए और फिल्म प्रमाणन का कार्य कर रहे हैं। | |

# बाल फिल्म समिति, भारत

## वास्तविक उपलब्धियां

| | उपलब्धियां 2010-11 | लक्ष्य 2011-12 | उपलब्धियां | | लक्ष्य 2012-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | वास्तविक | अनुमानित | |
| | | | अप्रैल 2011 से दिसंबर 2011 तक | अप्रैल 2011 से दिसंबर 2011 तक | |
| क. निर्माण | 3 फीचर फिल्में और एक लघु फिल्म का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। | 3 फीचर फिल्में + 2 लघु फिल्में | 2 फीचर फिल्में पूरी की गईं। | 1 फीचर, 1 लघु फिल्म 31.3.2012 तक पूरी होने की आशा है। | 3 फीचर + 2 लघु |
| ख. डबिंग | 20 रूपान्तर | 14 फिल्में | 20 फिल्मों के 20 रूपान्तरण | प्रतिक्रिया पर निर्भर | 12 फिल्में |
| ग. सब टाइटल | — | 10 फिल्में | 3 फिल्मों और 6 वीडियो फिल्मों का सब टाइटल दिये गये। | 2 फीचर फिल्मों को सब टाइटल के लिए लिया गया। | 16 फिल्में |
| घ. खरीद | कोई उपयुक्त फिल्म नहीं प्राप्त हुई | 1 फीचर और 2 लघु फिल्में | | | 2 फिल्में |
| ड. प्रिंट लागत | 31 फिल्मों को पुर्न स्थापन | आवश्यकता के अनुरूप | — | — | 2 फिल्में |

## डिजीटलीकरण और वेबकास्टिंग : योजना

| | उपलब्धियां 2010-11 | लक्ष्य 2011-12 | उपलब्धियां | | लक्ष्य 2012-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | वास्तविक | अनुमानित | |
| | | | अप्रैल 2011 से दिसंबर 2011 तक | अप्रैल 2011 से दिसंबर 2011 तक | |
| क. डिजीटलीकरण | — | आवश्यकतानुसार | आवश्यकता अनुरूप | | |
| ख. वेबकास्टिंग | बाल फिल्म समिति की वेबसाईट लगातार अपडेट की जाती है | आवश्यकता अनुरूप | आवश्यकता अनुरूप | | बाल फिल्म समिति की वेबसाइट का रख रखाव |
| ग. खराब फिल्मों को पुर्नस्थापन | 31 फिल्में पुनस्थापित की गईं। | | | | लगभग 15 शीर्षकों को पुर्नस्थापित करने के लिए चुना गया। |

## नगर निगम के विद्यालयों में फिल्म प्रदर्शनी : योजना

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| विद्यालयों में फिल्म प्रदर्शनी | 6370 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया 27 लाख बच्चों ने देखा। | 5000 फिल्म शो आयोजित किये गए जिन्हें 25 लाख बच्चों ने देखा | 5832 फिल्म शो आयोजित किए गए जिन्हें 25 लाख बच्चों ने देखा | अनुमानतया 850 फिल्म शो आयोजित किये गए जिन्हें 2.50 बच्चों ने देखा। | 5000 फिल्म शो आयोजित किये गए जिन्हें 25 लाख बच्चों ने देखा। |

## फिल्म समारोह

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17वें बाल फिल्म समारोह का आयोजन | — | 1 | 1 | अनुमानतया 850 फिल्म शो आयोजित किये गए जिन्हें 2.50 बच्चों ने देखा। | 5000 फिल्म शो आयोजित किये गए जिन्हें 25 लाख बच्चों ने देखा। |
| अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोह में भागेदारी | 19 | 15 | 7 | फिल्म समारोह की प्रतिष्ठा और स्तर के अनुरूप | 15 |

# फिल्म समारोह निदेशालय

## योजना शीर्ष के तहत 2010-10 तथा 2012-13 ( 31.12.2011 तक ) के वास्तविक प्रदर्शन की समीक्षा

| क्र. सं. | स्कीम का नाम | 2009-10 के लिए लक्ष्य | उपलब्धियां 2009-10 | कमी के कारण | 2010-11 के लिए लक्ष्य | उपलब्धियां 2010-11 ( 31.12.10 तक ) | वास्तविक प्रदर्शन की समीक्षा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) |
| 1. | विदेशी यात्रा खर्च | - | - | - | - | - | प्रशासनिक खर्च |
| 2. | (i) भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह सहित भारत तथा विदेश में फिल्म समारोहों के जरिए निर्यात संवर्धन | 01 | 01 | शून्य | 01 | 01 | शून्य |
| 3. | (i) विदेशी फिल्म समारोहों में भागीदारी | 45 | 45 | शून्य | 45 | 48 | - |
| | (ii) भारतीय पैनोरमा | 01 | 01 | शून्य | 01 | 01 | शून्य |
| 4. | फिल्म समारोह परिसर— फेरबदल और संयोजन | सीरीफोर्ट आडिटोरियम का सुधार | कार्य प्रगति पर | शून्य | राष्ट्रमंडल खेल 2010 को ध्यान में रखकर सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम में सुविधांए | कार्य प्रगति पर | शून्य |
| 5. | प्रिंट यूनिट का उन्नयन | 2010-11 तक स्वीकृत कार्य को अगस्त तक पूरा किया जाना। | सीरीफोर्ट आडिटोरियम का सुधार कार्य | शून्य | शून्य | सभी प्रमुख योजनाओं को पिछले वित्त वर्ष में पूरा कर लिया गया। | आडिटोरियम से संबंधित |

| क्र. सं. | स्कीम का नाम | 2009-10 के लिए लक्ष्य | उपलब्धियां 2009-10 | कमी के कारण | 2010-11 के लिए लक्ष्य | उपलब्धियां 2010-11 (31.12.10 तक) | वास्तविक प्रदर्शन की समीक्षा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | सीरीफोर्ट आडिटोरियम का सुधार कार्य | इस आडिटोरियम के इलैक्ट्रिक स्टोर रूम को केन्द्रीय रूम में इसके किचन को सुधार कार्य और 31.3.2013 तक दीमक रोधी काम को पूरा करने का प्रस्ताव है। | कार्यों के 2010-11 में पूरा होने के बाद एक करोड़ रुपये संशोधित बजट अनुमान के स्तर पर लौटाये गए। नये कान्फ्रेन्स रूम के निर्माण कार्य को 2010-12 में संभव नहीं पाया गया। इसलिये इस राशि को वापिस लौटा दिया गया। |
| 4 | प्रिंट इकाईयों का पुनर्स्थापन | उपकरणों की खरीद | स्टीन बैंक एडिटिंग मशीन, प्रिंट इकाई को लाने ले जाने वाले वाहन और अन्य उपकरणों की खरीद | शून्य | उपकरणों की खरीद | विभिन्न उपकरणों की खरीद के लिए 2900 लाख रुपये की राशि स्वीकृत | 'राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन' योजना को फिल्म के डिजीटलीकरण में सम्मिलित कर लिया गया जिससे 70 लाख रुपये की राशि को वापिस लौटा दिया गया। |

## गैर योजना के अंतर्गत 2010-11 और 2011-12 के वास्तविक प्रदर्शन की समीक्षा

| क्र. सं. | योजना का नाम | 2010-11 के लिए लक्ष्य | उपलब्धियां 2010-11 | कमी के कारण | 2011-12 के लिए लक्ष्य | उपलब्धियां 2011-12 ( 31.12.11 तक ) | वास्तविक प्रदर्शन की समीक्षा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) |
| 1. | वेतन | - | - | - | - | - | # |
| 2. | समयोपरि भत्ता | - | - | - | - | - | # |
| 3. | घरेलू यात्रा | - | - | - | - | - | # |
| 4. | कार्यालय व्यय | - | - | - | - | - | # |
| 5. | किराया, दर और कर | - | - | - | - | - | # |
| 6. | लघु कार्य | - | - | - | - | - | # |
| 7. | भत्ते | - | - | - | - | - | # |
| 8. | अन्य प्रभार | - | - | - | - | - | # |
| 9. | सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत फिल्म समारोह | 12 | 12 | शून्य | 12 | 13 | - |
| 10. | राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार | 1 | 1 | शून्य | 1 | 1 | - |
| 11. | बैंकिंग नकदी लेन-देन कर | - | - | - | - | - | - |
| 12. | चिकित्सा व्यय | - | - | - | - | - | - |

# प्रशासनिक खर्चे होने के कारण कोई लक्ष्य नहीं

# फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे

## पिछले प्रदर्शन की समीक्षा

| क्रम संख्या | योजना/कार्यक्रम का नाम | 2010-11 के दौरान वास्तविक प्रदर्शन |
|---|---|---|
| क. | **भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे की अनुदान राशि** | |
| 1. | **मशीनरी और उपकरण** | |
| | फिल्म और टीवी पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक उपकरणें और उनके कलपुर्जों की खरीद | वास्तविक लक्ष्य को पूरा किया गया। |
| 2. | **सिविल/इलेक्ट्रीकल निर्माण कार्य (सी सी डब्ल्यू)** | |
| | इसके तहत दो प्रमुख परियोजनायें हैं। (i) 100 कमरों वाले नये छात्रावासों का निर्माण, (ii) एकीकृत ज्ञान संसाधन केन्द्र का निर्माण/वार्षिक मांग निर्माणकार्य की प्रगति के अनुसार रहेगा। | इस कार्य को वर्ष के लक्ष्य के अनुसार शुरू किया जायेगा। |
| 3. | **कम्पयूटरीकरण और आधुनिकीकरण** | |
| | शैक्षणिक लाइसेंस और ऑपरेटिंग प्रणाली को अपग्रेड करना। | साफ्टवेयर और हार्ड वेयर के अपग्रेड किया गया। |
| 4. | **सामुदायिक रेडिये की स्थापना** | |
| | छात्रों के विकास, दर्शकों और रेडियो कार्यक्रमों के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने और अनुसंधान कार्य के लिए इस योजना को जारी रखा गया।<br>रेडियो टोप/कैसेट/सीडी/एनडीडी जैसे सॉफटवेयर उपकरणों का रखरखाव संसाधन सामग्री, अतिथ्य, दौरों और अन्य कार्य। | वास्तविक लक्ष्य को पूरा किया गया। |
| 5. | **कैप्टिव चैनल की स्थापना**<br>यह योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना में जारी है। इसका उद्देश्य छात्रों में कार्यक्रमों और प्रसारण के क्षेत्र में शोध, अनुसंधान, विकास और नए प्रयोगों को बढ़ावा देता है। | वास्तविक लक्ष्य लगभग प्राप्त किया गया। |

| क्रम संख्या | योजना/कार्यक्रम का नाम | 2010-11 के दौरान वास्तविक प्रदर्शन |
|---|---|---|
| 6. | एचआरडी पक्ष जिसमें छात्रों के लिए छात्रवृत्ति तथा विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ कार्यक्रमों का आदान-प्रदान शामिल है। परियोजना व्यय में छात्रों/शिक्षकों के भत्ते शामिल हैं। यह कुछ संस्थानों द्वारा किए गए ज्ञापन समझौतों पर आधारित है। 11वीं योजना के एचआरडी योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियों को शामिल किया गया:<br>1. विभिन्न कार्यों के लिए स्टॉक और फैकल्टी को प्रशिक्षण देना<br>2. संस्थान की पत्रिका 'लैंससाइट' का प्रकाशन काफी समय से इसका प्रकाशन बंद था।<br>3. फिल्मों और एचआरडी से संबंधित सभी क्षेत्रों के सांस्कृतिक समारोहों, सेमिनार और परिचर्चाओं पर होने वाला व्यय।<br>4. संस्थान की लाईब्रेरी के लिए पुस्तकों की खरीद।<br>5. संस्थान में चल रहे कई पाठ्यक्रमों में आने वाले विशेषज्ञों की कार्यशालाएं।<br>6. अन्य प्रासंगिक कार्य। | लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त किया। |
| (ख) | **नई योजना**<br>ग्लोबल फिल्म स्कूल | इस योजना को कई कारणों से प्राप्त नहीं किया जा सका। इस योजना को 12वीं योजना के दौरान व्यापक स्तर पर शुरू किया जायेगा। |

# फिल्म प्रभाग

## डॉक्यूमेंट्री ( न्यूज मैगजीन सहित )

| | उपलब्धि 2010-11 | लक्ष्य 2011-12 | प्रत्याशित उपलब्धि 2011-12 | | लक्ष्य 2012-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | अप्रैल, 2011 से दिसं., 2011 तक | जन., 2012 से मार्च, 2012 तक | |
| **( 1 ) इन हाउस निर्माण**<br>(ए) गैर योजना<br>(i) थिएटर/गैर थिएटर के लिए न्यूज मैगजीन | 22 | * | 9 | 11 | * |
| (ii) डॉक्यूमेंट्री जारी-थिएटर | 19 | 26 | 9 | 12 | 26 |
| (iii) डॉक्यूमेंट्री जारी-गैर थिएटर | 5 | 10 | 5 | 9 | 10 |
| (iv) संस्थागत शिक्षण और प्रशिक्षण फिल्म | - | - | - | - | - |
| (2) बाहरी निर्माताओं से निर्माण | 9 | - | 2 | 4 | - |
| **कुल** | 55 | **36** | **25** | **36** | **36** |
| अन्य मंत्रालयों द्वारा अनुदानित फिल्मों का निर्माण | - | - | - | - | - |
| बाहरी निर्माताओं द्वारा प्रत्यक्ष | 3 | - | 1 | 5 | - |
| भुगतान के आधार पर फिल्म निर्माण | | | | | |
| **योजना** | 84 | 75 | 2 (टीआर)<br>23 (एनटीआर) | 50 | - |
| **कुल** | **87** | **75** | **25** | **55** | **36** |

*(*) फिल्म प्रभाग वीवीआईपी के विदेश जाने तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं पर ही न्यूज मैगजीन का निर्माण करता है। इसलिए न्यूज मैगजीन के निर्माण का कोई विशेष लक्ष्य नहीं है।*

## वितरण

फिल्म प्रभाग डॉक्यूमेंट्री तथा न्यूज मैगजीन का वितरण थिएटर तथा गैर-थिएटर वर्ग के लिए करता है। थिएटर के लिए वितरण देश के सिनेमा हाउस के जरिए होता है जो मान्य फिल्मों (609 मीटर से अधिक नहीं) को प्रदर्शित करते हैं। इसकी वास्तविक उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

### ( भौतिक )

| प्रिंट्स और कैसेट की संख्या | उपलब्धियां 2010-11 | लक्ष्य 2011-12 | उपलब्धियां दिसं., 2011 तक | उपलब्धियां मार्च, 2012 तक | लक्ष्य 2012-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| थिएटर के लिए जारी | 13289 | 13300 | 9666 | 3334 | 13300 |
| गैर थिएटर जारी | 88 | - | - | - | निर्धारित नहीं |
| क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय को वीएचएस कैसेट तथा वीसीडी की आपूर्ति | - | - | - | - | निर्धारित नहीं |
| डीएफपी को प्रिंट्स की आपूर्ति | - | - | - | - | निर्धारित नहीं |
| प्रिंट की बिक्री | | | | | |
| 35एमएम/16 एमएम (कलर) | 3 | 5 | 8 | - | निर्धारित नहीं |
| 35एमएम/16 एमएम (बी एंड डब्ल्यू) | | | | | |
| वीटा (कलर) | | | | | |
| डीवीडी (कलर) | 1764 | 1000 | 1400 | 500 | 2000 |
| वीसीडी (कलर) | 1470 | 2500 | 270 | 150 | 500 |

फिल्म प्रभाग द्वारा प्रति सप्ताह सिनेमा हाउसों को अनुमोदित फिल्मों की आपूर्ति का ब्योरा इस प्रकार है।

| | |
|---|---|
| 2009-10 | 8219 |
| 2010-11 | 6967 |
| 2011-12 | 8305 |

गैर थिएटर वितरण के तहत फिल्म प्रभाग प्रति सप्ताह एक डॉक्यूमेंट्री या एक न्यूज मैगजीन (बारी-बारी से) जारी करता है। इसके लिए पूरे देश को एक सर्किट माना जाता है। वर्ष 2011-12 के दौरान थिएटर वितरण के तहत प्रति सप्ताह 290 प्रिंट्स तैयार किए जाते हैं।

फिल्म प्रभाग एनएफडीसी तथा अन्य एजेंसियों के माध्यम से विदेशों में फिल्मों के व्यावसायिक वितरण की कोशिश करता है। इसके अलावा फिल्म प्रभाग स्टॉक शॉट्स, व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक फिल्मों की बिक्री सरकार द्वारा तय दर पर करता है।

फिल्म प्रभाग की डॉक्यूमेंट्री तथा न्यूज मैगजीन की आपूर्ति विदेश मंत्रालय के विदेश स्थित मिशनों की आपूर्ति की जाती है जो सरकारी, अर्ध सरकारी तथा शैक्षिक संस्थों को प्रदर्शन के लिए नि:शुल्क देते हैं। विदेश में गैर व्यावसायिक प्रयोग के लिए भी फिल्म प्रिंट्स की बिक्री होती है। कुछ डॉक्यूमेंट्री तथा न्यूज रील का विदेशों में रॉयल्टी आधार पर टीवी पर व्यावसायिक उपयोग फिल्म प्रभाग तथा नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा किया गया।

| **माइनर हैड** | **वास्तविक** | **प्रत्याशित प्रस्तावित आरई-2011-12** | **अनुमानित 2011-12 ( प्रस्तावित )** |
|---|---|---|---|
| 1. किराया | 492.00 | 505.00 | 555.00 |
| 2. प्रिंट्स की बिक्री तथा स्टॉक शॉट्स | 25.00 | 25.00 | 27.00 |
| 3. अन्य प्राप्ति | 22.00 | 20.00 | 23.00 |
| **कुल** | **539.00** | **550.00** | **605.00** |

* 1. सम्बद्ध राज्यों के हाई कोर्ट में दायर डब्ल्यू पीएस/डब्ल्यू एएस मामले के मद्देनजर वर्ष 1995-1999 के लिए बकाया क्लीयर नहीं किया गया है।

2. उ.प्र.,नई दिल्ली, पंजाब तथा मं.प्र. के 500 से अधिक सिनेमा हाउसों ने फिल्म प्रभाग से अनुमोदित फिल्में लेना बंद कर दिया है।

# विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भागीदारी

| | **समारोह की संख्या** | **प्राप्त फिल्मों की संख्या** |
|---|---|---|
| राज्य फिल्म समारोह | — | — |
| राष्ट्रीय फिल्म समारोह | 16 | 93 |
| अन्तरराष्ट्रीय फिल्म समारोह | 04 | 09 |
| **कुल** | **20** | **102** |

# भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार ( एन एफ ए आई )

**वास्तविक उपलब्धियां**

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अज्ञिभलेखागार की 1 अप्रैल 2011 से 31 जनवरी 2012 तक की उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

| | |
|---|---|
| फिल्में | 454 फिल्में (नई 63, डुप्लीकेट-7 और 384 एल टी एल आधारित) |
| पुस्तकें | 114 |
| फिल्म फोल्डर/पुस्तिकायें | 75 |
| अचल चित्र | 1397 |
| गीत | 403 |
| पोस्टर | 949 |
| डीवीडी | 141 |
| डिजीटलीकृत फिल्में | 214 |
| खराब फिल्मों के नये प्रिंट | 130 |

## योजनाबद्ध वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां ( 2010-11 और 2011-12 )

| योजना/कार्यक्रम का नाम | वास्तविक लक्ष्य 2010-11 | वास्तविक उपलब्धियां 2010-11 | वास्तविक लक्ष्य 2011-12 | वास्तविक उपलब्धियां 2010-11 | कमी के कारण अगर हैं तो |
|---|---|---|---|---|---|
| **परियोजनायें** अभिलेखागार में 22वीं फिल्मों को प्राप्त करना और उनका प्रदर्शन | 600 (फिल्मों) डीवीडी को प्राप्त किया गया। जिनमें 300 फिल्मों का डिजटलीकरण किया गया और 1100 फिल्मों और संबंधित सामग्री को फिर से नया बनाया गया। | प्राप्त की गई 343 फिल्मों/ डीवीडी में से 245 फिल्मों का डिजीटलीकरण किया गया। 152 फिल्मों को और 19329 फिल्म सामग्री को नया बनाया गया। | प्राप्त की गई 600 फिल्मों/डीवीडी में से 400 फिल्मों का डिजीटलीकरण करके और 100 फिल्मों और पटकथा जैसी सहायक फिल्म सामग्री को फिर से नया बनाया गया। | प्राप्त की गई 595 फिल्मों/ डीवीडी से 214 फिल्मों का डिजीटलीकरण किया गया और 130 फिल्मों को नया बनाया गया | उपलब्ध बजट आंबटन के अनुरूप उपलब्धियां रहीं। |

# राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम

## योजनाबद्ध कार्यक्रम

2010-11 के दौरान योजनाबद्ध स्कीमों का निष्पादन इस प्रकार है :

| क्र.सं. | योजना का नाम | 2010-11 के लक्ष्य | 2010-11 की उपलब्धियां | 2011-12 के लक्ष्य | 2011-12 ( 31 दिसंबर 2011 तक ) उपलब्धियां | वास्तविक निष्पादित कार्य की समीक्षा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण | 7 फिल्में | 5 फिल्में | 4 फिल्में | 3 फिल्में | एक फिल्म 31.3.2012 तक पूरी हो जाएगी। |
| 2. | फिल्मों का जीर्णोद्धार और | 38 फिल्में | 38 फिल्में | 39 फिल्में | 41 फिल्में | 2010-11 के दौरान 79 फिल्मों का डिजीटलीकरण और उनका जीर्णोद्धार किया गया। |

## सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

वर्ष 2011 के दौरान, 2011–2014 के अकादमी सत्र के लिये तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अन्तर्गत 42 छात्रों (प्रत्येक क्षेत्र में 12 की क्षमता के साथ) ने प्रवेश लिया। बैच के अनुसार छात्रों की संख्या नीचे दी जा रही है।

| | **बैच** | **7वां** | | **8वां** | | **9वां** | | **10वां** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **वर्ष** | **2007–10** | | **2008–11** | | **2009–12** | | **2011–14** | | **कुल** | |
| | | **पुरुष** | **महिलाएं** | **पुरुष** | **महिलाएं** | **पुरुष** | **महिलाएं** | **पुरुष** | **महिलाएं** | **पुरुष** | **महिलाएं** |
| 1. | निर्देशन | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 28 | 12 |
| 2. | सिनेमाटोग्राफी | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 47 | 2 | 27 | 27 | |
| 3. | संपादन | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 30 | 5 |
| 4. | ऑडियोग्राफी | 10 | 0 | 8 | 2 | 9 | 1 | 11 | 0 | 38 | 3 |
| | **कुल** | **31** | **7** | **31** | **8** | **26** | **10** | **35** | **7** | **123** | **32** |

**योजनागत स्कीम**

| क्रम.सं. | योजनागत स्कीम का नाम | 2011-12 के दौरान वास्तविक प्रदर्शन ( 31.12.2011 तक ) |
|---|---|---|
| 1. | नये शैक्षिक विभाग का सृजन : फिल्म और टेलीविजन में निर्माण प्रबन्धन | 1. निर्माण के लिये बुनियादी योजना तैयार, कोलकाता नगर निगम से अनुमति मिलने के बाद मार्च 2012 से निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा<br>2. नये विभाग के लिये मंत्रालय से स्वीकृत भर्ती की प्रक्रिया अभी पूरी की जा रही है जो मार्च 2012 तक पूरी होने की संभावना है ताकि अगले शैक्षिक सत्र 2012-13 में इसकी कक्षायें शुरू की जा सकें। |
| 2. | नये शैक्षिक विभाग का सृजन : एनिमेशन और इलेक्ट्रॉनिक इमेजिंग | 1. नये भवन का निर्माण कार्य अभी जारी है और इसके मार्च 2012 तक पूरा होने की संभावना है।<br>2. इस विभाग में की जाने वाली भर्ती की प्रक्रिया अभी जारी है प्रक्रिया मार्च 2012 तक पूरी होने की संभावना है ताकि अगले शैक्षिक सत्र 2012-13 में कक्षाएं शुरू की जा सकें। |
| 3. | कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण | 1. कुछ नये अति आधुनिक तकनीकी उपकरण खरीदे गये और संस्थान में लगाये गये।<br>2. ई-बिजनेस स्यूट का इस्तेमाल करते हुये ईआरपी के क्रियान्वयन के लिये सॉल्यूशन डिजाइन पूरा किया गया और दूसरे चरण का कार्य शुरू किया गया।<br>3. मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 22 कर्मियों की भर्ती की गई।<br>4. नये फिल्म स्टूडियो तथा फिल्म अभिलेखागार की डिजाईन तथा योजना तैयार करने के लिये जादवपुर विश्व विद्यालय के वास्तु विभाग द्वारा अनुमति के बाद निर्माण कार्य शुरू। |
| 4. | एचआरडी पहलू/छात्रवृत्ति/छात्र आदान प्रदान कार्यक्रम/इंटर्नशिप | 1. 8 छात्रों को एसआरएफटीआई की मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई।<br>2. एसआरएफटीआई के छात्र और शिक्षक ईडन वर्ग नैपियर यूनिवर्सिसिटी के साथ छात्रों के आदान-प्रदान कार्यक्रम में भाग लिया।<br>3. गोवा में आयोजित 42वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में संस्थान के छात्रों द्वारा तैयार फिल्में दिखाई गईं |
| 5. | प्रशिक्षण और कौशल विभाग | 1. डाक्यूमैंटरी, प्लैबैक और डिप्लोमा की कई छात्र फिल्म परियोजनायें शुरु की गई<br>2. विभिन्न संगठनों द्वारा फिल्म और टेलीविजन संबंधी सेमिनार/कार्यशालाओं में संस्थान के कुछ संकाय सदस्यों ने हिस्सा लिया<br>3. संस्थान की पत्रिका टेकवन का प्रकाशन<br>4. संस्थान के छात्रों ने भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लिया<br>5. संस्थान में फिल्म समारोह आयोजित किया गया |
| 6. | एसआरएफटीआई में सामुदायिक रेडिया (सीआरएस) की स्थापना | 1. सीआरएस का सफलतापूर्वक उद्घाटन तथा 90.4 मेगा हटर्ज फ्रीक्वेंसी पर प्रसारण<br>2. प्रसारण की गुणवता सुधारने के लिए तकनीकी अपग्रेडेशन किया गया। |
| 7. | एसआरएफटीआई में केप्टिव टीवी चैनल (सीटीवीसी) की स्थापना | 1. खरीदे गए उपकरण संस्थान में लगाये गये।<br>2. कैप्टिव चैनल को शुरु किया गया और संस्थान द्वारा तैयार कार्यक्रम प्रसारित किये गये। |

# राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन

## योजनागत बजट के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान और 2011-12 ( 31.12.2011 ) के वास्तविक कार्यों की समीक्षा

| क्र. सं. | योजना का नाम | 2010-11 के लिए लक्ष्य | उपलब्धियां 2010-11 | कार्य कमी के कारण | 2011-12 के लिए लक्ष्य ( 31.12.11 तक ) | उपलब्धियां 2011-12 ( 31.12.11 तक ) | वास्तविक कार्यों की समीक्षा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) |
| | राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन | नहीं लाया गया<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 2011-12 में शुरु किया गया लक्ष्य -शून्य<br>योजना आयोग से उसकी स्वीकृति ले ली गई है।<br>है। | सैद्धांतिक रुप से मसौदे को अंतिम रुप दे दिया गया है के लिए<br>प्रकिया पूरी कर ली गई | संबंधित अधिकारियों की स्वीकृति |

# भारत और विदेशों में फिल्म समारोहों और फिल्मों की बिक्री के माध्यम से भारतीय सिनेमा को प्रोत्साहन

## योजनागत बजट के अंतर्गत 2010-11 और 2011-12 ( 31.12.2011 ) के वास्तविक कार्यों की समीक्षा

| क्र. सं. | योजना का नाम | 2010-11 के लिए लक्ष्य | उपलब्धियां 2010-11 | कमी के कारण | 2011-12 के लिए लक्ष्य | उपलब्धियां 2011-12 ( 31.12.11 तक ) | वास्तविक प्रदर्शन की समीक्षा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) |
| 1. | विदेश यात्रा व्यय | - | - | - | - | - | प्रसासनिक व्यय |
| 2. | अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह | 1 | 1 | शून्य | 1 | 1 | गोवा में 23.11.11 से 3.12.11 तक सफलतापूर्वक संपन्न |
| . | (ii) विदेशी फिल्म समारोहों में भागीदारी फिल्म समारोह | 45 | 79 | शून्य | 50 | 52 | शुन्य |
| | (iii) भारतीय पैनोरमा | 1 | 1 | शून्य | 1 | 1 | अक्टूबर 2011 में भारतीय पैनोरमा के |

| क्र. सं. | योजना का नाम | 2010-11 के लिए लक्ष्य | उपलब्धियां 2010-11 | कमी के कारण | 2011-12 के लिए लक्ष्य | उपलब्धियां 2011-12 ( 31.12.11 तक ) | वास्तविक प्रदर्शन की समीक्षा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) |
| 3. | अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह | शून्य | शून्य | शून्य | 1 | 1 | अंतर्गत 24 फीचर फिल्में और गैर 21 फीचर फिल्में चुनी गईं<br><br>दो वर्षों में बार आयोजित किया जाता है और नवंबर 2011 में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया |

| क्र. सं. | स्कीम का नाम | 2009-10 के लिए लक्ष्य | उपलब्धियां 2009-10 | कमी के कारण | 2010-11 के लिए लक्ष्य | उपलब्धियां 2010-11 (31.12.10 तक) | वास्तविक प्रदर्शन की समीक्षा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 4. | मुंबई अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह | शून्य | शून्य | शून्य | 1 | 1 | दो वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। इस बार 2-9 फरवरी 2012 को सफलता-पूर्वक संपन्न। |
| 5. | नगर निगम के विद्यालयों में फिल्मों का प्रदर्शन | 5000 शो | 6370 शो | शून्य | 5000 | 5832 | शून्य |

# विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों का निर्माण

**योजनागत बजट के अन्तर्गत 2010-11 और 2011-12 ( 31.12.2011 ) वास्तविक कार्यों की समीक्षा**

| क्र.सं. | योजना का नाम | 2010-11 के लक्ष्य | 2010-11 की उपलब्धियां | 2011-12 के लक्ष्य | 2011-12 ( 31 दिसंबर 2011 तक ) उपलब्धियां | वास्तविक कार्यों की समीक्षा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा विभिन्न भाषाओं में फिल्मों का निर्माण | 7 फिल्में | 5 फिल्में | 4 फिल्में | 3 फिल्में | एक फिल्म 31.3.2012 तक पूरी होने की संभावना |
| 2. | बाल फिल्मों का निर्माण | 3 फीचर फिल्में एक लघु फिल्म | 3 फीचर फिल्में एक फिल्म का निर्माण कार्य लगभग पूरा | 3 फीचर फिल्मे 2 लघु फिल्में | 2 फीचर फिल्में | 1 फीचर फिल्म 1 लघु फिल्म 31.3.2012 तक पूरी होने की आशा |
| 3. | डाक्यूमेंटरी और लघु फिल्मों का निर्माण | 70 फिल्में | 87 फिल्में | 95 फिल्में | 63 फिल्में | 31.3.2010 तक लक्ष्य पूरा होने की संभावना। |

# राष्ट्रीय एनीमेशन गेमिंग और स्पेशल इफैक्ट उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना

## योजना गत बजट के अन्तर्गत 2010-11 और 2011-12 ( 31.12.2011तक ) वास्तविक कार्यों की समीक्षा

| क्र. सं. | स्कीम का नाम | 2010-11 के लिए लक्ष्य | उपलब्धियां 2010-11 | कार्यों की कमी के कारण | 2011-12 के लिए लक्ष्य ( 31.12.11 तक ) | उपलब्धियां 2010-11 ( 31.12.11 तक ) | कार्यों की वास्तविक समीक्षा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) |
| 1. | राष्ट्रीय एनीमेशन गेमिंग और स्पेशल इफैक्ट उत्कृष्ट केन्द्र स्थापित करना | - | - | - | मसौदा तैयार कर लिया गया है आवश्यक स्वीकृतियां ली जा रही हैं। | मसौदा तैयार कर लिया गया है और इ एफ सी प्रस्ताव पर कार्य किया जा रहा है। | संबंधित अधिकारी द्वारा योजना स्वीकृति ली जानी है। |

# इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानिटरिंग केन्द्र

यह परियोजना अनुसंधान एवं विकास भवन 14-बी रिंग रोड इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली में 9.6.2008 को शुरू की गई। इस समय केन्द्र 300 टी वी चैनल को मॉनीटर कर रहा है। प्राइवेट एफ एम चैनल को भी मानीटर करने की भी व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जा रही है।

# एफएम प्रकोष्ठ

**यह परियोजना अप्रैल 2006 में शुरू हुई। दिसंबर 2011 तक परियोजना का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :**

| क्र. सं. | स्थान का नाम | स्थिति | | टावर के पूरा करने का लक्ष्य | पूरा होने का समय |
|---|---|---|---|---|---|
| | | नींव | टावर | | |
| 1. | जयपुर | पूर्ण | पूर्ण | मार्च, 2007 | समाप्त |
| 2. | हैदराबाद | पूर्ण | पूर्ण | मार्च, 2007 | समाप्त |
| 3. | नई दिल्ली | पूर्ण | पूर्ण | मार्च, 2007 | समाप्त |
| 4. | चेन्नई | पूर्ण | पूर्ण | मार्च, 2007 | समाप्त |
| 5. | कोलकाता | नींव का काम शुरू | ढांचे का कार्य प्रगति पर | मार्च, 2007 | ... |
| 6. | देहरादून | पूर्ण | पूर्ण | मार्च, 2007 | समाप्त |

* कोलकाता में आकाशवाणी द्वारा स्थल की अनापत्ति निलंबित

छह शहरों में इस परियोजना पर हुए व्यय का ब्योरा निम्नलिखित है :

| क्र.सं. | शहर का नाम | स्वीकृत लागत | पहले से व्यय हो चुकी राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | जयपुर | 166.12 लाख रुपये | 1081.89 लाख रुपये |
| 2. | हैदराबाद | 166.12 लाख रुपये | |
| 3. | चेन्नई | 220.83 लाख रुपये | |
| 4. | नई दिल्ली | 439.05 लाख रुपये | |
| 5. | कोलकाता | 220.83 लाख रुपये | |
| 6. | देहरादून | 98.29 लाख रुपये | |
| | **कुल** | **1311.24 लाख रुपये** | **1081.89 लाख रुपये** |

परियोजना की प्रगति की समीक्षा मंत्रालय द्वारा मासिक एवं त्रैमासिक छमाही और वार्षिक आधार पर की जाती है।

## आकाशवाणी - वार्षिक योजना ( 2011-12 )

### परिणाम बजट में परिणाम/लक्ष्य

करोड़ रु. में

| क्र.सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2011-12 | | मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम | प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | चालू स्कीमें | | | | | | |
| | पूंजी | | | | | | |
| | राजस्व | | | | | | |
| 1 | जम्मू कश्मीर विशेष पैकेज (चरण I और II) | जम्मू-कश्मीर में रेडियो कवरेज के विस्तार के लिए | 2.50 | 1.92 | जम्मू-कश्मीर पैकेज चरण-I पूरा हो चुका है। जम्मू-कश्मीर पैकेज चरण-II स्कीम में शामिल डीजी सेट और यूपीएस खरीदे जा चुके हैं। अल्प लंबित कार्य 2011-12 में पूरा हो जाएगा। | Q1 - लंबित संस्थापन कार्य को पूरा करना | |
| | पूंजी | | 0.50 | 0.04 | | | |
| | राजस्व | | 2.00 | 1.88 | | | |
| 2 | MW सेवाओं का विस्तार | प्राथमिक कवरेज क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए ट्रांसमीटरों का उन्नयन | 0.40 | 0.01 | पूरा | पूरा | |
| 3 | FM सेवाओं का विस्तार | | 20.52 | | 10KW FM के 41 ट्रांसमीटरों का संस्थापन पूरा | Q1- साइट पर ट्रांसमीटरों की प्राप्ति, Q2- संस्थापन शुरू, Q3- संस्थापन पूरा, Q4- जांच और मापन | नए स्टेशनों और अतिरिक्त चैनलों को चालू करने के लिए O&M स्टाफ की जरूरत होगी। |
| | | | | | 20 KW FM के 4 ट्रांसमीटरों की खरीद | | |
| | | | | | 3. अमृतसर में निर्माण कार्य पूरा (20 KW FM Tr.) | Q1- लोक निर्माण कार्य शुरू<br>Q2- लोक निर्माण कार्य जारी<br>Q3- ट्रांसमीटर भवन का निर्माण पूरा<br>Q3- ट्रांसमीटर का संस्थापन | 300 M TV टॉवर पूरा होने के बाद (जो 11 मार्च तक होने की संभावना है) अमृतसर में FM tr. शुरू होगा। |
| | | | | | हल्द्वानी, रायबरेली और चम्पावत में जगह का अधिग्रहण | Q1- हल्द्वानी और चम्पावत में साइट का अधिग्रहण यदि मांग नोट प्राप्त हो जाता है तो रायबरेली साइट के लिए भुगतान<br>Q3- रायबरेली में साइट का अधिग्रहण | चम्पावत ओर हल्द्वानी साइटों के लिए डिमांड नोट की प्रक्रिया जारी है। रायबरेली में पहचानी गई साइट को अभी राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया जाना है। |
| | | | | | बर्दमान, धनबाद और दार्जिलिंग में निर्माण कार्य पूरा | Q1- लोक निर्माण कार्य शुरू<br>Q2- लोक निर्माण कार्य जारी<br>Q3- ट्रांसमीटर भवन का निर्माण पूरा<br>Q4- ट्रांसमीटर का संस्थापन | ट्रांसमीटर भवन के लिए अनुमान प्रक्रियाधीन है तथा 11 मार्च तक काम प्रदान किए जाने की संभावना है। |
| | | | | | बागेश्वर 5 KW FM Tr., करीमनगर 5 KW FM Tr., उज्जैन 5 KW FM Tr का संस्थापन पूरा | Q1- ट्रांसमीटर का संस्थापन शुरू<br>Q2- संस्थापन का काम पूरा<br>Q3- जांच और मापन | बागेश्वर और उज्जैन में ट्रांसमीटर के लिए आदेश दे दिए गए हैं तथा 11 मार्च तक प्राप्त हो जाने की संभावना है। पहले |

| क्र.सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2011-12 | | मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम | प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | हैदराबाद की ओर परिवर्तित करीमनगर ट्रांसमीटर को वापस लाया गया है क्योंकि वहा 10 KW FM का Tr. संस्थापित हो गया है। स्टेशन चालू करने के लिए O&M स्टाफ की मंजूरी की जरूरत है। |
| | | | | | श्रीकाकुलन 1 KW FM Trs., नई टिहरी 1 KW FM Trs. ओर गैरषेण 1 KW FM Tr. का संस्थापन पूरा | Q1- ट्रांसमीटर का संस्थापन शुरू<br>Q2- संस्थापन का काम पूरा<br>Q3- जांच और मापन | श्रीकाकुलन 1 KW FM Tr., नई टिहरी 1 KW FM Tr. और गैरषेण 1 KW FM का ट्रांसमीटर स्थापित होने के बाद वहां से वापस लाया गया है। श्रीकाकुलम में लोक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा गैरषेण और नई टिहरी में 11 मार्च तक पूरा हो जाएगा। स्टेशनों को चालू करने के लिए O&M स्टाफ की मंजूरी की जरूरत है। |
| | | | | | कूचविहार ओर बलूरघाट में 10 KW FM Trs. का संस्थापन पूरा और बर्दमान, धनबाद और दार्जिलिंग में संस्थापन कार्य प्रगति पर | Q1- ट्रांसमीटरों की प्राप्ति<br>Q2- कूचविहार और बलूरघाट में ट्रांसमीटर का संस्थापन शुरू<br>Q3- कूचविहार और बलूरघाट में ट्रांसमीटर का संस्थापन पूरा<br>Q4- बर्दमान, धनबाद और दार्जिलिंग में संस्थापन | ट्रांसमीटरों के लिए निविदा की प्रक्रिया जारी है तथा 11 फरवरी तक आदेश जारी होने की संभावना है। स्टेशनों को चालू करने के लिए O&M स्टाफ की मंजूरी की जरूरत है। |
| | प्रोडक्शन सुविधाओं का डिजिटलाइजेशन | विषय सामग्री की तकनीकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए | 0.18 | 0.15 | ट्रांसमिशन (16) और रिकार्डिंग (17) कंसोल का संस्थापन पूरा | Q1- साइटो पर कानसोल प्राप्त होने की संभावना<br>Q2- कनसोल का संस्थापन प्रगति अधीन होने की संभावना<br>Q3- संस्थापन कार्य पूरा होने वाला है। | |
| | स्टूडियो सुविधाओं और विविध स्कीमों का ऑटोमेशन | | 5.00 | 5.00 | राजकोट में 1000 KW MW Trs. का संस्थापन पूरा | Q1- संस्थापन प्रगति पर<br>Q2- संस्थापन पूरा<br>Q3- जांच और मापन<br>Q4- ट्रांसमीटर चालू | ट्रांसमीटर का प्रेषण पूर्व निरीक्षण पूरा हो गया है तथा 10 दिसंबर तक प्राप्त हो जाने की संभावना है। |
| | | | | | 48 केंद्रों पर हाई एंड सर्वरों का संस्थापन पूरा | Q1- कुछ स्टेशनों पर उपकरण की प्राप्ति और SITC कार्य शुरू<br>Q2- शेष स्टेशनों के उपकरण की प्राप्ति, उन स्टेशनों पर SITC कार्य पूरा जहां Q1- में उपकरण प्राप्त हो गए थे तथा शेष स्टेशनों में कार्य प्रगति पर<br>Q3- SITC कार्य पूरा<br>Q4- जांच और मापन | हाई एंड सर्जरी के लिए खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। |

| क्र.सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2011-12 | | मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम | प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | सिल्चर और देहरादून में कैप्टिव भू-केंद्रों का संस्थापन पूरा | Q2- उपकरण की प्राप्ति<br>Q3- संस्थापन कार्य शुरू<br>Q4- संस्थापन कार्य पूरा | निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन पर है। 11 मार्च तक अग्रिम A/T दिया जाने की संभावना है। |
| 6 | पूर्वोत्तर विशेष पैकेज | पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेडियो कवरेज बढ़ाने के लिए | 45.00 | 34.27 | अनिनी (अरूणाचल), तमेन्लोंग और उखरूल (मणिपुर) में 1 KW FM के 19 ट्रांसमीटरों के लिए 3 लंबित साइट का अधिग्रहण | साइटों को राज्य सरकारों द्वारा आवंटन मिलना है। मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। | अनिनी में प्रस्तावित की जा रही वैकल्पिक साइट के विवरण की राज्य सरकार से प्रतीक्षा है। तमेंगलोंग और उखरूल जोनल कार्यालय की टीम कानून व्यवस्था में सुधार होते ही साइट की विजिट करेगी। मामला आगे बढ़ाया जा रहा है। |
| | पूंजी | | 45.00 | 34.27 | 16 जगहों पर जिन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है, लोक निर्माण काम पूरा | Q1- चंफाई, लम्डिंग, खोनसा और चांगलांग में लोक निर्माण कार्य पूरा करना। करीमगंज, चेरापूंजी, बोमडिला, फेक और दोखा में लोक निर्माण कार्य शुरू करना तथा जुनेहबोतो में लोक निर्माण कार्य सौंपना<br>Q2- करीमगंज, चेरापूंजी, बोमडिला, फेक और दोखा में लोक निर्माण कार्य जारी रखना तता जुनेहबोतो में लोक निर्माण कार्य शुरू करना।<br>Q3- करीमगंज, चेरापूंजी, बोमडिला, फेक और दोखा में ट्रांसमीटर निर्माण कार्य पूरा करना। जुनेहबोतो में लोक निर्माण कार्य जारी रखना।<br>Q4- जनेहबोतो में लोक निर्माण कार्य पूरा करना। | छह स्थानों तुईपांग, नूतन बाजार, उदयपुर, ग्वालपाड़ा दापारजियो और कोलासिव में ट्रांसमीटर भवन तैयार हैं। चार स्थानों चम्फाई, लम्डिंग, खोनसा औरचांगलांग में लोक निर्माण कार्य प्रगति पर है। पांच स्थानों करीमगंज, चेरापूंजी, बोमडिला, फेक और दोखा में भवन निर्माण का अनुमान कार्य प्रगति पर है तथा 11 मार्च तक कार्य सौंपने की संभावना है। जुनेहबबोतो में साइट शीघ्र ही अधिग्रहीत होने की संभावना है। संबंधित राज्य सरकारों ने चंफाई, फेक, ग्वालपाड़ा, कोलासिब, चांगलांग, खोनसा और दारपेरिजो में आकाशवाणी की साइट के लिए संपर्क मार्ग का निर्माण कर दिया है। मामला आगे बढ़ाया जा रहा है। |
| | राजस्व | | 0.00 | 0.00 | 6 जगहों पर 1 K FM Trs. संस्थापन का काम पूरा | Q2- चम्फाई, लम्डिंग, खोनसा और चांगलांग में संस्थापन कार्य शुरू करना<br>Q3- चम्फाई, लम्डिंग, खोनसा और चांगलांग में संस्थापन कार्य शुरू करना और करीमगंज एक चेरापूंजी, बोमडिला, फेक और दोखा में कार्य शुरू<br>Q4- करीमगंज एवं चेरापूंजी, बोमडिला, फेक और दोखा में संस्थापन कार्य पूरा करना | O&M स्टाफ की मंजूरी के लिए स्टेशन चालू करने की जरूरत है। |

| क्र.सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2011-12 | | मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम | प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | 2. सिल्चर -5 KW FM Tr. - संस्थापन का काम पूरा | Q1- ट्रांसमीटर का संस्थापन शुरू करना<br>Q2- संस्थापन पूरा करना<br>Q3- परीक्षण और मापन | ट्रांसमीटर के लिए आर्डर दिया गया और 11 मार्च तक प्राप्त होने की संभावना है। O&M स्टाफ की मंजूरी के लिए अतिरिक्त चैनल चालू करने की जरूरत है। |
| | | | | | 3. गंगतोक - 10 KW FM Tr. - संस्थापन का काम पूरा | Q1- साइट पर ट्रांसमीटरों की प्राप्ति<br>Q2- संस्थापन शुरू करना<br>Q3- संस्थापन शुरू करना<br>Q4- परीक्षण और मापन | ट्रांसमीटर के लिए आर्डर दिया गया और 11 मार्च तक प्राप्त होने की संभावना है। O&M स्टाफ की मंजूरी के लिए अतिरिक्त चैनल चालू करने की जरूरत है। |
| | | | | | 4. चिनसुरा - 1000 KW MW Tr. संस्थापन का काम पूरा | Q1- ट्रांसमीटर का संस्थापन शुरू करना<br>Q2- संस्थापन पूरा करना<br>Q3- परीक्षण और मापन | ट्रांसमीटर के लिए आर्डर दिया गया तथा 11 मार्च तक प्राप्त होने की संभावना है। O&M स्टाफ की मंजूरी के लिए अतिरिक्त चैनल चालू करने की जरूरत है। |
| | | | | | 5. कावारत्ती - 10 KW MW Tr. संस्थापन का काम पूरा | Q1- ट्रांसमीटर का संस्थापन शुरू करना<br>Q2- संस्थापन पूरा करना<br>Q3- परीक्षण और मापन | ्टांसमीटर के लिए आर्ड दिया गया तथा 11 मार्च तक प्राप्त होने कीसंभावना है। |
| | | | | | 6. DSNG सिस्टम्स (3) - उपकरण की खरीद और तैनाती | Q1- खरीद प्रस्ताव का अनुमोदन और अग्रिम A/T का प्लेसमेंट<br>Q2- फर्म से कार्य निष्पादन बैंक गारंटी प्राप्त करना तथा औपचारिक A/T का प्लेसमेंट<br>Q3- उपकरण की प्राप्ति<br>Q4- उपकरण की तैनाती | DSNG प्रणालियों (डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग) के लिए निविदाओं का मूल्यांकन जारी है। |
| 7 | स्टॉफ के लिए आवास (मेट्रो स्टॉफ क्वार्टर) | प्रसार भारती कर्मचारियों के लिए मेट्रो केन्द्रों पर स्टॉफ क्वार्टर के निर्माण के लिए | 1.00 | 1.00 | दिल्ली - दिल्ली में फेज -2 (203 क्वार्टर) का काम पूरा | फेज -2 का काम पूरा | |

| क्र.सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2011-12 | | मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम | प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | मुंबई - मुंबई में 68 क्वार्टर बनाने का काम | Q1- कार्य सौंपना<br>Q2- कार्य जारी करना<br>Q3- कार्य जारी करना<br>Q4- कार्य पूरा करना | सुपरस्ट्रक्चर के लिए निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं |
| | | | | | चेन्नई - चेन्नई में 52 क्वार्टर बनाने का काम | | CMDA के साथ योजना की अनुमति पर बात की जा रही है। |
| | | | | | कोलकाता - कोलकाता में 81 क्वार्टर बनाने का काम | | कोलकाता मेट्रो विकास प्राधिकरण) द्वारा भूमि के एकपक्षीय वापसी के विरुद्ध याचिका दायर की गई है। अदालत ने स्थगनादेश दिया है तथा मामला विचाराधीन है। |
| 2 | नई स्कीमें | | | | | | |
| 2.1 | ट्रांसमीटरों, स्टूडियो, कनेक्टिविटी और DTH चैनल का डिजिटलीकरण | डिजिटल मोड में राष्ट्रव्यापी कवरेज के लिए SW DRM Tr. एफएम विस्तार स्टूडियो डिजिटाइजेशन और कनेक्टिविटी | 133.77 | 27.06 | | | |
| | MW DRM ट्रांसमीटर | | | | | | |
| 1 | मौजूदा स्टेशनों पर नए DRM MW ट्रांसमीटर लगवाकर 31 पुराने MW ट्रांसमीटर को बदलना | | | | | | |
| | 20 KW -5 संख्या, दिल्ली VB, बाड्मर & बीकानेर (राजस्थान), चेन्नई (तमिलनाडु) VB], गुवाहाटी B | | | | 1. लोक निर्माण का काम पूरा, उपकरण की खरीद, उपकरण का संस्थापन | Q1- लोक निर्माण कार्य के लिए प्रारंभिक अनुमानों की मंजूरी।<br>Q2- लोक निर्माण सौंपना<br>Q3- लोक निर्माण को पूरा करना। उपकरण की प्राप्ति<br>Q4- उपकरण का संस्थापन | दस 100 KW और नौ 200 KW के लिए टीई एक 50 KW, छह 300 KW और 20KW के लिए निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन पूरा हो चुका है। |
| | *50 KW-1 [मुंबई 'C' (महाराष्ट्र)] | | | | 1. लोक निर्माण का काम पूरा, उपकरण की खरीद उपकरण का संस्थापन | Q1- लोक निर्माण कार्य के लिए प्रारंभिक अनुमानों की मंजूरी।<br>Q2- लोक निर्माण कार्य सौंपना<br>Q3- लोक निर्माण को पूरा करना।<br>Q4- उपकरण का संस्थापन | दस 100 KW के लिए तकनीकी मूल्यांकन पूरा और मूल्य निविदा खोली जा चुकी है और खरीद प्रस्ताव की प्रक्रिया जारी है। |

| क्र.सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2011-12 | मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम | प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 100 KW-10 संख्या [विजयवाड़ा (आंप्र), पटना (बिहार, पणजी (गोवा), रांची (बिहार, मुंबई 'A' (महा), मुंबई 'B' (महा), पुणे (महा), तिरूचिरापल्ली (तमिल), वाराणसी (उ.प्र.), कोलकाता 'A' (प.बं.)] | | | 1. लोक निर्माण का काम पूरा, उपकरण की खरीद, उपकरण का संस्थापन | Q1-लोक निर्माण कार्य के लिए प्रारंभिकअनुमानों की मंजूरी। उपकरण के लिए आर्डर प्लेसमेंट<br>Q2- लोक निर्माण सौंपना<br>Q3- लोक निर्माण कार्य पूरा करना। उपकरण की प्राप्ति में प्रगति लाई जाएगी।<br>Q4- उपकरण की प्राप्ति पूरी तथा उपकरण के संस्थापन में प्रगति लाई जाएगी | दस 100 KW के लिए तकनीकी मूल्यांकन पूरा और मूल्य निविदा खोली जा चुकी है और खरीद प्रस्ताव की प्रक्रिया जारी है। |
| | *200 KW -9 संख्या [दिल्ली 'A', अहमदाबाद (गुजरात), बंगलुरू और धारवाड (कर्नाटक, जबलपुर (म.प्र.), अजमेर (राजस्थान), चेन्नई 'A' (तमिलनाडु), सिलीगुडी और कोलकाता 'B' (पं. बंगाल) | | | 1. लोक निर्माण का काम पूरा, उपकरण की खरीद, उपकरण का संस्थापन | Q1- कुछ स्थानों पर लोक निर्माण कार्य के लिए प्रारंभिक अनुमान की प्राप्ति और मंजूरी। उपकरण की लिए आर्डर देना।<br>Q2- बाकी स्थानों के लिए प्रारंभिक अनुमानों की मंजूरी। ऐसे स्थानों पर भवन निर्माण कार्य सौंपा जहां प्रारंभिक अनुमानों को पिछली तिमाही में मंजूरी दी गई थी।<br>Q3- बाकी स्थानों के लिए भवन निर्माण कार्य सौंपना। ऐसे स्थानों पर भवन निर्माण कार्य पूरा करना जहां कार्य दूसरी तिमाही में सौंपा गया था।<br>Q4- बाकी स्थानों पर भवन निर्माण कार्य पूरा करना उपकरण की प्राप्ति शुरू। ऐसे स्थानों पर विभागीय कार्य की प्रगति जहां भवन निर्माण कार्य तीसरी तिमाही में पूरी हो चुकी है। | नौ 200 KW- के लिए निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकित किया जा रहा है। |
| | *300 KW -6 संख्या [डिब्रूगढ (असम), राजकोट (गुजरात), जम्मू (जम्मू-कश्मीर), जालंधर (पंजाब), सूरतगढ़ (राजस्थान), लखनऊ (उ.प्र.)] | | | 1. लोक निर्माण का काम पूरा, उपकरण की खरीद, उपकरण का संस्थापन | Q1- कुछ स्थानों पर लोक निर्माण कार्य के लिए प्रारंभिक अनुमान की प्राप्ति और मंजूरी। उपकरण की लिए आर्डर देना।<br>Q2- बाकी स्थानों के लिए प्रारंभिक अनुमानों मंजूरी। ऐसे स्थानों पर भवन निर्माण कार्य सौंपा जहां प्रारंभिक अनुमानों को पिछली तिमाही में मंजूरी दी गई थी।<br>Q3- बाकी स्थानों के लिए भवन निर्माण कार्य सौंपना। ऐसे स्थानों पर भवन निर्माण कार्य पूरा | छह 300 KW- के लिए निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकित किया जा रहा है। |

| क्र.सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2011-12 | मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम | प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | करना जहां कार्य दूसरी तिमाही में सौंपा गया था।<br>Q4- बाकी स्थानों पर भवन निर्माण कार्य पूरा करना उपकरण की प्राप्ति शुरू। ऐसे स्थानों पर विभागीय कार्य की प्रगति जहां भवन निर्माण कार्य तीसरी तिमाही में पूरी हो चुकी है। | |
| 2 | अरूणाचल-चीन सीमा पर कैप्टिव पावर प्लांट के साथ 3 MW DRM Tr. का उन्नयन | | | | | |
| | पासीघाट -100 KW (10 KW का विस्थापन) | | | 1. लोक निर्माण का काम पूरा<br>2. उपकरण की खरीद<br>3. उपकरण का संस्थापन | Q1- लोक निर्माण शुरू करना<br>Q2- लोक निर्माण पूरा करना तथा विभागीय कार्य शुरू करना<br>Q3- उपकरण प्राप्ति और संस्थापन शुरू करना<br>Q4- संस्थापन पूरा करना | उपकरण के लिए निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है। पासीघाट में लोक निर्माण कार्य के लिए अनुमान को मंजूरी दे दी गई है। |
| | ईटानगर 200 KW (100 KW का विस्थापन) | | | 1. लोक निर्माण का काम पूरा<br>2. उपकरण की खरीद<br>3. उपकरण का संस्थापन | Q1-लोक निर्माण कार्य सौंपना। उपकरण के लिए ऑर्डर देना।<br>Q2-लोक निर्माण कार्य जारी<br>Q3-भवन निर्माण को पूरा करना और विभागीय कार्य को पूरा करना। उपकरण की प्राप्ति<br>Q4-संस्थापन और विभागीय कार्य की प्रगति | उपकरण के लिए निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है। पासीघाट में लोक निर्माण कार्य के लिए अनुमान को मंजूरी दे दी गई है। |
| | त्वांग-20 KW (10 KW का विस्थापन) | | | 1. लोक निर्माण का काम पूरा<br>2 उपकरण की खरीद<br>3. उपकरण का संस्थापन | Q1-लोक निर्माण कार्य सौंपा गया। उपकरण के लिए ऑर्डर दिया गया।<br>Q2-लोक निर्माण कार्य पूरा करना<br>Q3-उपकरण की प्राप्ति<br>Q4- उपकरण का संस्थापन | उपकरण के लिए निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है। त्वांग में लोक निर्माण कार्य के अनुमान को मंजूरी दे दी गई है। |
| 3 | MW DRM ट्रांसमीटर द्वारा छह 10 KW MW मोबाइल को बदलना | | | मामूली लंबित काम पूरा | | ट्रांसमीटर को भेजने से पहले का निरीक्षण पूरा हो चुका है तथा 10 दिसंबर तक प्राप्त होने की सम्भावना। |
| 4 | 36 मौजूदा DRM कम्पेटीबल MW Tr. का DRM में रूपांतरण | | | 1. DRM उपकरण की प्राप्ति और संस्थापन का काम पूरा | Q1- प्रमुख DRM उपकरण की प्राप्ति शुरू<br>Q2- संस्थापन की शुरुआत 5<br>Q3- उपकरण का संस्थापन पूरा करना<br>Q4- परीक्षण और मापन | PAC (प्रोप्राइटरी स्वीकृति प्रमाणपत्र) प्रस्ताव अनुमोदन के लिए मंत्रालय को भेजा गया। मंत्रालय द्वारा मांगे गए प्रमाणन का जवाब दिया जा रहा है। |

| क्र.सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2011-12 | मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम | प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 36 मौजूदा DRM कम्पेटीबल MW Tr. का DRM में रूपांतरण | | | 1. DRM उपकरण की प्राप्ति और संस्थापन का काम पूरा | Q1- प्रमुख DRM उपकरण की प्राप्ति शुरू<br>Q2- संस्थापन की शुरुआत 5<br>Q3- उपकरण का संस्थापन पूरा करना<br>Q4- परीक्षण और मापन | PAC (प्रोप्राइटरी स्वीकृति प्रमाणपत्र) प्रस्ताव अनुमोदन के लिए मंत्रालय को भेजा गया। मंत्रालय द्वारा मांगे गए प्रमाणन का जवाब दिया जा रहा है। |
| | FM डिजिटल कम्पेटीबल ट्रांसमीटर | | | | | |
| 5 | मौजूदा 24 AIR/TV साइट पर FM विस्तार | | | 1. लोक निर्माण का काम पूरा<br>2. उपकरण की खरीद<br>3. उपकरण का संस्थापन का काम पूरा : 1 KW (12) & 5 KW (12) | Q1- कुछ स्थानों पर लोक निर्माण कार्य को पूरा करना<br>Q2- बाकी स्थानों पर लोक निर्माण कार्य पूरा करना। उपकरण की प्राप्ति शुरू और संस्थापन<br>Q3- उपकरण की प्राप्ति को पूरा करना और कुछ स्थानों पर संस्थापन पूरा करना<br>Q4- बाकी स्थानों पर संस्थापन पूरा करना | उपकरण के लिए निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन पूरा तथा वाणिज्यिक बोली खोली गई। जोनल कायाल्य कार्यक्रम इनपुट रैंक, ऑडियो प्रोसेसर और आडियो एनलाइजर जैसे संबंधित उपकरण खरीद रहा है। |
| | DD/AIR के मौजूदा 100 LPTs पर 100 Watt FM Trs. | | | 1. उपकरण की खरीद<br>2. उपकरण (100) का संस्थापन का काम पूरा | Q1- सिविल माडिफिकेशन कार्य पूरा करना<br>Q2- जोनल कार्यालय में उपकरण की प्राप्ति शुरू और करीब 35 स्थानों पर संस्थापन को पूरा करना<br>Q3- उपकरण की प्राप्ति को पूरा करना, 35 स्थानों पर संस्थापन को पूरा करना<br>Q4- बाकी स्थानों पर संस्थापन पूरा करना | ट्रांसमीटर के लिए खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है |
| 6 | 40 मौजूदा स्टेशनों पर ज्यादा पावर द्वारा FM/MW ट्रांसमीटर का विस्थापन | | | 1. निर्माण कार्य पूरा<br>2. 6 KW FM (27) Trs और 10 KW FM Trs. (13) की खरीद<br>3. संस्थापन का काम पूरा | Q1- सिविल माडिफिकेशन कार्य सौंपना और शुरू<br>Q2- सिविल माडिफिकेशन कार्य पूरा करना और विभागीय कार्य शुरू करना। उपकरण की डिलीवरी शुरू।<br>Q3- विभागीय कार्य और संस्थापन कार्य जारी।<br>Q4- संस्थापन कार्य पूरा करना | सिविल जरूरतों के उपकरण के लिए निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन पूरा होने वाला है। जोनल कार्यालय कार्यक्रम इनपुट रैंक, ऑडियो प्रोसेसर और ऑडियो एनलाइजर जैसे संबंधित उपकरण खरीद रहा है। |
| 7 | 5 SW ट्रांसमीटर (दिल्ली-2 स., अलीगढ़-2 संख्या, बंगलुरू-1 संख्या) का SW DRM Trs से विस्थापन | | | 1. दिल्ली (किंग्जवे) में 100 KW SW (2 संख्या) Trs. की खरीद<br>2. अलीगढ़ (उ.प्र.) में 250 KW SW Trs. (2) Trs. की खरीद<br>3. बंगलुरू (WB) (कर्नाटक)-500 KW SW और खरीद | Q1- दिल्ली (किंग्सवे) और अलीगढ़ में सिविल कार्य के लिए अनुमानों की संस्तुति। 100 KW और 250 KW SW Trs. के लिए ऑर्डर प्लेसमेंट। 500 KW SW Trs. के लिए खरीद प्रस्ताव की प्रोसेसिंग<br>Q2- दिल्ली (किंग्जवे) और अलीगढ़ में सिविल कार्य को सौंपना तथा बंगलुरू में सिविल | 100 KW और 250 KW SW Trs. के लिए निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन पूरा हो चुका है तथा 500 KW SW Trs. के लिए प्रगति पर है। |

| क्र.सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2011-12 | मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम | प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | कार्य के लिए अनुमानों की मंजूरी। 500 KW SW Trs. के लिए ऑर्डर का प्लेसमेंट<br>Q3- सिविल कार्यों की प्रगति<br>Q4- अलीगढ़ और दिल्ली (किंग्जवे) में सिविल कार्य पर तथा उपकरण की डिलीवरी पूरी। | |
| | स्टूडियो | | | | | |
| 8 | 98 स्टूडियो का डिजिटलीकरण और स्टूडियो की नेटवर्किंग | | | 1. ग्यारह स्टूडियो का जीर्णोद्धार<br>2. AC प्लांट, DG सेट इत्यादि विविध उपकरणों की खरीद और संस्थापन<br>3. 48 स्टूडियो केंद्रों का डिजिटलीकरण पूरा | Q1- कोन इन कनसोल, पोर्टेबल डिजिटल रिकार्डर, डिजिटल वर्क स्टेशनों और डिजिटल कनसोल जैसे प्रमुख उपकरणों की डिलीवरी शुरू। विभागीय कार्य शुरू<br>Q2- उपकरण की डिलीवरी जारी, विविध उपकरण का संस्थापन पूरा करना, 11 स्टूडियो का जीर्णोद्धार का संस्थापन कार्य शुरू करना<br>Q3- उपकरण की डिलीवरी पूरी करना। 11 स्टूडियो के जीर्णोद्धार का संस्थापन और चालू करने का कार्य पूरा करना तथा विविध कार्य<br>Q4- डिजिटल केबलिंग और 48 स्टूडियो का डिजिटलीकरण पूरा करना | फोन इन कनसोल, पोर्टेबल डिजिटल रिकार्डर, डिजिटल वर्क स्टेशनों, डिजिटल कनसोल और डिजिटल केबलिंग जैसे स्टूडियो उपकरणों के लिए एनआईटी जारी। फोन इन कनसोल और पोर्टेबल डिजिटल रिकार्डर का तकनीकी मूल्यांकन पूरा। जोनल कार्यालयों ने यूपीएस डीजी सेट एसी प्लांट इत्यादि की खरीद की कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी है। |
| | | | | स्टूडियो नेटवर्किंग - केंद्रीकृत स्टोरेज और सिस्टम साफ्टवेयर के साथ सर्वर का SITC कार्य | Q1- उपकरण के लिए आर्डर का प्लेसमेंट<br>Q2- उपकरण की प्राप्ति और संस्थापन शुरू<br>Q3- उपकरण की प्राप्ति पूरी और संस्थागत | स्टूडियो नेटवर्किंग के लिए निविदाएं 21.10.2010 को खोली गईं। सर्वर के SITC कार्य के साथ केंद्रीकृत भंडार और सिस्टम साफ्टवेयर की निविदाओं की छंटनी की जा रही है। |
| 9 | दिल्ली में अभिलेखीय सुविधा बढ़ाना और चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में अभिलेखीय सुविधा का सृजन | | | उपकरण की खरीद और SITC (आपूर्ति, संस्थागत जांच और चालू) कार्य की प्रगति | Q1- निर्माण कार्य सौंपा गया। आंतरिक फाइनांस द्वारा खरीद प्रस्ताव की मंजूरी<br>Q2- निर्माण कार्य प्रगति में। SITC कार्य के लिए मंजूरी और आर्डर<br>Q3- निर्माण कार्य को पूरा करना और विभागीय और संस्थापन कार्य शुरू करना<br>Q4- उपकरण की प्राप्ति और SITC कार्य शुरू | SITC कार्य के लिए निविदाएं 26.10.2010 को खोली गई तथा छंटनी की जा रही है। |

| क्र.सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2011-12 | मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम | प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | मौजूदा 44 न्यूज यूनिट का ऑटोमेशन और जोधपुर (राज.) राजकोट (गुजरात), विशाखापट्टनम (मध्यप्रदेश), दरभंगा (बिहार), सबलपुर (ओड़िशा), करगिल (जम्मू-कश्मीर) और पासीघाट (अरूणाचल) में 7 नई क्षेत्रीय न्यूज यूनिट बनाना | | | 1. मौजूदा 44 क्षेत्रीय समाचार इकाइयों का डिजिटलीकरण पूरा | Q1- मौजूदा आरएनयू के लि सर्वर, वर्कस्टेशनों और सिस्ट सॉफ्टवेयर का कार्य शुरू<br>Q2- SITC कार्य जारी करना<br>Q3- SITC कार्य को पूरा करना | निविदाएं 28.10.2010 को खोली गई हैं तथा आरएनयू के लि सर्वर वर्कस्टेशनों और सिस्टम सॉफ्टवेयर के SITC कार्य के लिए निविदाओं का तकनीकी रूप से मूल्यांकन किया गया है। जोनल अधिकारियों ने V-SAT, ISON कनेक्टिविटी, UPS, TV सेट, रेडियो सेट, प्रिंटर, PDWA जैसे अन्य आइटम के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। |
| | | | | 2. सात नई क्षेत्रीय समाचार इकाईयों का डिजिटलीकरण पूरा | Q1- निर्माण कार्य शुरू<br>Q2- निर्माण कार्य को पूरा करना और SITC कार्य शुरू<br>Q3- SITC कार्य जारी<br>Q4- SITC कार्य पूरा करना | |
| | | | | 3. 13 जगहों पर न्यूज ऑन फोन सेवा का उन्नयन तथा 16 नई जगहों (29) से यह सेवा शुरू | Q1- आंतरिक फाइनांस द्वारा खरीद प्रस्ताव की अनुमति<br>Q2- खरीद प्रस्ताव की मंजूरी और उपकरण के लिए आर्डर प्लेसमेंट<br>Q3- उपकरण की डिलीवरी और साइटों पर संस्थापन कार्य शुरू<br>Q4- संस्थापन काम पूरा करना | उपकरण के लिए निर्धारण विचार का मुद्दा |
| 11 | STL कनेक्टिविटी का विस्थापन | | | जगहों पर मौजूदा STL का डिजिटाइलजेशन की खरीद और संस्थापन पूरा | Q1- साइटों पर उपकरण की प्राप्ति<br>Q2- STC (आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और उपकरण को चालू करना) शुरू<br>Q3- STC कार्य को पूरा करना | मूल्य निविदाएं अभी तक नहीं खोली गई हैं क्योंकि एक वेंडर से पुन: प्रस्तुति के बारे में निर्णय के लिए पीबी सचिवालय की प्रतीक्षा है। |
| 12 | CES और STL के नए प्रस्ताव | | | 35 जगहों परग नए डिजिटल STL और तिरूचिरापल्ली, मदुरई और धारवाड़ में कैप्टिव भू केंद्र का संस्थापन पूरा | Q1- साइटों पर उपकरण की प्राप्ति शुरू<br>Q2- STC कार्य आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और उपकरण को चालू करना) शुरू<br>Q3-STC कार्य को पूरा करना | 1. नए STLs के लिए तकनीकी मूल्यांकन के अधीन निविदाएं<br>2. तिरूचिरापल्ली, मदुरई और धारवाड में नए कैप्टिव भू केंद्रों के लिए तकनीकी मूल्यांकन के अधीन निविदाएं |
| 13. | C-बैंड RNT (44) का प्रावधान | | | STC कार्य पूरा | Q1- STC कार्य (आपूर्ति, संस्थापन परीक्षण और उपकरण को चालू करना) के लिए ऑर्डर प्लेसमेंट<br>Q2- साइटों पर उपकरण की प्राप्ति शुरू | निविदाओं का तकनीकी रूप से मूल्यांकन किया गया और मूल्य बोली खोली गई |

| क्र.सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2011-12 | | मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम | प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | Q3-SITC कार्य (आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और उपकरण को चालू करना) शुरू<br>Q4- SITC कार्य को पूरा करना | |
| 14. | DTH चैनल को बढ़ाना | | | | उपकरण की खरीद DTH (18 जगह) उपलिंक/डाउनलिंक का संस्थापन पूरा | Q1- साइटों पर उपकरण की प्राप्ति शुरू 5<br>Q2- SITC कार्य (आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और उपकरण को चालू करना) की शुरूआत<br>Q3- SITC कार्य को पूरा करना | उपकरण के लिए निर्धारण विचारणीय मुद्दा |
| 2.2 | बाहरी सेवाओं को मजबूत करना | SW ट्रांसमीटरों का डिजिटलाइजेशन | 0.50 | 0.50 | | | |
| | कम्पेटीबल बाहरी सेवाओं SW Trs. को DRM (दिल्ली- 250 KW SW Trs.-2 और अलीगढ़ - 250 KW SW Trs.-2) में रूपांतरण | | | | 250 KW SW Trs के कनवर्जन के लिए उपकरण दिल्ली और अलीगढ़ में दो-दो DRM के लिए खरीदे और लगाए जाएंगे। | Q1- कनवर्जन किट्स के लिए खरीद का आर्डर<br>Q2- उपकरण की प्राप्ति<br>Q3- SITC कार्य पूरा होने की संभावना | PAC (प्रोप्राइटरी स्वीकृति प्रमाणपत्र) प्रस्ताव अनुमति के लिए मंत्रालय को भेजा गया। मंत्रालय द्वारा मांगे गए प्रमाणन का जवाब दिया जा रहा है। |
| 2.3 | तटीय क्षेत्र के लिए ई-गवर्नेंस, प्रशिक्षण, संसाधन, सुरक्षा, IOF, D/G, अतिरिक्त आवास, कल्याण गतिविधियां और स्टाफ क्वार्टर इत्यादि<br>बुनियादी ढांचे में सुधार | बुनियादी ढांचे में सुधार | 25.50 | 2.93 | | | |
| 1 | ई-गवर्नेंस और आईटी सुविधाओं का उन्नयन | | | | 231 केंद्रों/कार्यालयों में अतिरिक्त 924 कम्प्यूटरों की खरीद | Q1- EFC अनुमोदन और निविदाओं की प्रोसेसिंग एवं तकनीकी मूल्यांकन<br>Q2- वाणिज्यिक बोलियों को खोलना और खरीद प्रस्ताव की प्रोसेसिंग<br>Q3- ऑर्डर प्लेसमेंट<br>Q4- उपकरण की प्राप्ति और संस्थापन | पेबी सचिवालय द्वारा अनुमति के बाद टिप्पणी के लिए SFC प्रस्ताव प्रचारित |
| 2 | क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों सहित STI(T) और STI(T) को बढ़ाना | | | | | | सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 31.8.2010 को प्रस्ताव स्वीकृत |

| क्र.सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2011-12 | | मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम | प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | (a) दिल्ली STI(T) ऑडिटोरियम/कानफ्रेंस हाल और स्वागत कक्ष का निर्माण | | | | ऑडिटोरियम/कान्फ्रेंस हाल और स्वागत कक्ष का निर्माण कार्य पूरा | Q1- निर्माण कार्य सौंपना<br>Q2- & 03- निर्माण कार्य जारी करना<br>Q4- भवन पूरा करना | निर्माण कार्य के लिए अनुमान प्रस्तुत करने के अधीन |
| | STI(P), तिरूवनंतपुरम में होस्टल आवास का निर्माण | | | | होस्टल आवास का निर्माण कार्य पूरा | Q1- निर्माण कार्य सौंपना<br>Q2 & Q3- निर्माण कार्य जारी करना<br>Q4- भवन पूरा करना | निर्माण कार्य के लिए अनुमान प्रस्तुत करनेके अधीन |
| | STI(P), हैदराबाद में होस्टल आवास का निर्माण | | | | | Q1- निर्माण कार्य सौंपना<br>Q2 & Q3- निर्माण कार्य जारी करना<br>Q4- भवन पूरा करना | निर्माण कार्य के लिए अनुमान प्रस्तुत करने के अधीन |
| | STI(P), लखनऊ में होस्टल आवास का निर्माण | | | | | Q1-सिविल कार्य को पुरस्कार<br>Q2 & Q3- निर्माण कार्य जारी करना<br>Q4- भवन पूरा करना | निर्माण कार्य के लिए अनुमान प्रस्तुत करनेके अधीन |
| | STI(P),अहमदाबाद में होस्टल आवास का निर्माण | | | | | Q1-सिविल कार्य को पुरस्कार<br>Q2 & Q3- निर्माण कार्य जारी करना<br>Q4- भवन पूरा करना | निर्माण कार्य के लिए अनुमान प्रस्तुत करने के अधीन |

| क्र.सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2011-12 | मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम | प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 |
| | RTI(T) मलाड, मुंबई में होस्टल और प्रशिक्षण सुविधाएं | | | होस्टल, लेक्चर हाल और कम्प्यूटर लैब कार्यालय कक्ष इत्यादि का निर्माण | Q1- सिविल कार्य को पुरस्कार<br>Q2 & Q3- निर्माण कार्य जारी करना<br>Q4- भवन पूरा करना | निर्माण कार्य के लिए अनुमान प्रस्तुत करने के अधीन है। उपकरण के लिए खरीद कार्रवाई शुरू |
| | दिल्ली STI(T)- एनलॉग आडियो स्टूडियो को डिजिटल रूप में बदलना | | | उपकरण की स्थापन | Q1- वाणिज्यिक बोलियां खोलना और खरीद प्रस्ताव की प्रोसेसिंग<br>Q2- आर्डर प्लेसमेंट<br>Q3- उपकरण की प्राप्ति और संस्थापन<br>Q4- संस्थापन को पूरा करना | उपकरण की खरीद के लिए खरीद की कार्रवाई शुरू की गई। डिजिटल वर्क स्टेशनों, डिजिटल कनसोल जैसे उपकरण की खरीदकी प्रक्रिया समग्र प्रस्ताव के भाग के रूप में पहले ही प्रक्रियाधीन है। |
| 3 | मौजूदा केंद्रों में I.O.F. | | | | | मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार पीबी बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजे गए |
| | आपातकालीन हालात के लिए 5 जोनल कार्यालयों में 5 मोबाइल FM Trs. | | | उपकरण की स्थापन | Q1- EFC अनुमोदन और उपकरण के लिए निविदा मंगाना। Q2- निविदा की प्रोसेसिंग और तकनीकी मूल्यांकन, Q3- वाणिज्यिक बोलियों को खोलना और खरीद प्रस्ताव की प्रोसेसिंग, Q4- आर्डर प्लेसमेंट | |
| | स्टूडियो के लिए मापन उपकरण का प्रावधान | | | उपकरण की स्थापन | वही | |
| | 23 स्थानों पर रिमोट कंट्रोल के लिए MW Trs. पर टेलीमीटरों का प्रावधान | | | | वही | |
| | 80 स्थानों पर मौजूदा एफएम केंद्रों पर यूपीएस का प्रावधान | | | | वही | |
| | ग्वालियर, रत्नागिरी और सांगली में स्टूडियो को नया रूप देना | | | | वही | |
| 4 | श्रीनगर में होस्टल, आवास, सहित, गुवाहाटी में कार्यालय आवास और स्टाफ क्वार्टर | | | गुवाहाटी में पूर्वोत्तर जोन के लिए कार्यालय, आवास/स्टाफ क्वार्टर और श्रीनगर में होस्टल सुविधाओं का निर्माण | Q1- अनुमानों की मंजूरी ओर पूर्वोत्तर जोन कार्यालय के लिए निविदाएं आमंत्रित करना। गुवाहाटी में स्टाफ क्वार्टर और श्रीनगर में होस्टल के लिए निर्माण कार्य सौंपना<br>Q2- पूर्वोत्तर जोन कार्यालय के लिए निविदाओं की प्रोसेसिंग और निर्माण कार्य सौंपना। स्टाफ | |

| क्र.सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2011-12 | | मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम | प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | क्वार्टर के लिए प्रक्रिया जारी<br>Q3- निर्माण कार्य जारी<br>Q4- स्टाफ क्वार्टर का निर्माण कार्य पूरा करना। कार्यालय आवास का निर्माण का कार्य जारी होने की उम्मीद | |
| 2.4 | नई प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी (अनुसंधान एवं विकास) | सेटेलाइट और टेरोट्रीयल मोड में मल्टी मीडिया प्रसारण, वेब कास्टिंग/ब्राडकास्टिंग | 1.00 | 0.15 | | | |
| | नई प्रौद्योगिकी | | | | | | |
| 1 | वेबकास्टिंग | | | | संस्थापन का काम पूरा और कार्यक्रम की विषय सामग्री विकसित की जा रही है। | कार्यक्रम की विषय सामग्री का विकास | |
| 2 | अनुसंधान एवं विकास | | | | स्कीमों को पूरा करना | Q1- 26 MHz AM DRM Tr. क्रास फील्ड एंटीना और 1 KW MW DRM Tr., जैसे उपकरणों के लिए निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन को पूरा करना<br>Q2- वाणिज्यिक बोलियों को खोलना, खरीद प्रस्ताव को प्रोसेस करना<br>Q3- आर्डर देना<br>Q4- उपकरण की प्राप्ति | Issued for 26 MHz AM DRM Tr., क्रास फील्ड एंटीना और 1 KW MW DRM Trs. के लिए NIT जारी की गई, निविदा खोली गई और छंटनी की जा रही है। |
| 2.5 | साफ्टवेयर | (i) सामान्य श्रेणी, जम्मू-कश्मीर विशेष पैकेज और पूर्वोत्तर विशेष पैकेज के संबंध में इन हाउस और कमीशन्ड कार्यक्रमों का निर्माण, (ii) किसान वाणी, (iii) CD की खरीद, (iv) विविध कनसर्ट/ रेडियो कार्यशालाएं/आकाशवाणी, संगीत सम्मेलन इत्यादि (v) महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आयोजनों का निर्माण और कवरेज (vi) आकाशवाणी अभिलेखागार नेटवर्क का डिजिटाइलेजेशन (vii) समाचार गतिविधियां | 15.00 | 4.50 | 1. नई और ताजगी भरी विषय सामग्री बनाना<br>2. रेडियो कार्यशालाएं, संगीत सम्मेलन, कनसर्ट आदि<br>3. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का कवरेज<br>4. फ्लैगशिप कार्यक्रम निर्माण<br>5. आकाशवाणी अभिलेखागार का डिजिटलीकरण<br>6. सूचना और प्रसारण मंत्रालय EFC प्रस्ताव के लिए पहले ही 46.16 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे चुका है लेकिन वर्ष 2011-12 के लिए बजट आगे प्राप्त होना है। | साफ्टवेयर प्रोडक्शन/अधिग्रहण और विषय सामग्रह निर्माण के लिए फ्लैगशिप कार्यक्रमों अभिलेखागार का डिजिटलीकरण इत्यादि के लिए कोष का उपयोग करना। अनुमति की तिथि से निर्धारित समय के भीतर काम पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। | |

| क्र.सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2011-12 | | मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम | प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.6 | जम्मू-कश्मीर फेज-III | जम्मू-कश्मीर में सीमा क्षेत्र के एफएम कवरेज के और सुधार के लिए | 10.00 | | एफएम और टीवी एचपीटी की स्थापना करने के लिए 3 नई साइट का अधिग्रहण, निर्माण कार्य पूरा करना, उपकरण की खरीद और 100 W FM के चार ट्रांसमीटर नौशेरा में 10 KW FM ट्रांसमीटरों और राजौरी में 5 KW TV के 2 ट्रांसमीटरों की संस्थापन गतिविधियां को पूरा करना | Q1- तीन नई साइट की पहचान और अनुमान की स्वीकृति तथा लोक निर्माण कार्य सौंपा गया। वाणिज्यिक बोलियां खोलना तथा उपकरण के लिए खरीद प्रस्ताव को प्रोसेस करना<br>Q2- आर्डर देना और निर्माण कार्य को पूरा करना<br>Q3- उपकरण की प्राप्ति<br>Q4- संस्थापन को पूरा करना | 1. सरकार की अनुमति 18.08.2010 को प्राप्त हुई।<br>2. नाथाटोप (जम्मू क्षेत्र) तीन रिज (श्रीनगर क्षेत्र), और हिम्बोटिगला (लद्दाख क्षेत्र) में 3 नई साइट की पहचान और अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू |
| | आकाशवाणी का योग | | 260.37 | 97.07 | | | |
| | | राजस्व | 17.00 | 6.38 | | | |
| | | पूंजी | 243.37 | 90.69 | | | |

# प्रसार भारती
## आकाशवाणी - वार्षिक योजना ( 2010-11 )
## परिव्यय परिणाम/लक्ष्य

*(करोड़ रुपये में)*

| क्रमांक | योजना/कार्यक्रम | उद्देश्य/परिणाम | लागत 2010-11 योजना बजट | व्यय (दिसंबर 10 तक) | मात्रात्मक लाभ/ भौतिक परिणाम | प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) | उपलब्धियां (31.12.10 तक) कालम 5 के अनुसार | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **क** | **चालू योजनाएं**<br>पूंजी<br>राजस्व | | | | | | | |
| 1 | जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष पैकेज<br>फेज़-I और फेज़-II | जम्मू एवं कश्मीर में रेडियो कवरेज का विस्तार | 3.50 | 4.67 | जम्मू कश्मीर में पैकेज चरण 1 की योजना पूरी हो गई हैं। जम्मू कश्मीर पैकेज चरण 2 एसआईटीसी (आपूर्ति, संस्थापन ,परीक्षण और कमीशनिंग) का कार्य पूरा। 1 MVA (3) डीजीसेट का कार्य पूरा-2 सेट के लिए कार्य सौंपा गया। तीसरे के लिए करीब 1.78 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की जरूरत है जो फेज-II के तहत आकाशवाणी को उपलबध कराए गए 5.70 करोड़ के अलावा है। | डीजी सेट 1 एमवीए (3) क्यू 2 संस्थापन का काम पूरा।<br>क्यू-3 परीक्षण और कमिशनिंग का काम पूरा | जम्मू में प्राप्त दो सेट संस्थापित और चालू। नारबल, श्रीनगर में तीसरे सेट के लिए आर्डर प्रसार भारती से अतिरिक्त राशि के आश्वासन के बाद दिए गए हैं तथा वर्ष के अंत तक काम पूरा होने की संभावना है।<br>नारबल, श्रीनगर में डीजी सेट 500 केवीए (2) का कार्य पूरा | |
| | पूंजी | | 1.50 | 2.277 | | 2 डीजी सेट 500 केवीए-कार्य सौंपा गया। | | |

*(करोड़ रुपये में)*

| क्रमांक | योजना/कार्यक्रम | उद्देश्य/परिणाम | लागत 2010-11 योजना बजट | व्यय (दिसंबर 10 तक) | विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम | प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) | उपलब्धियां (31.12.10 तक) कालम 5 के अनुसार | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 2 | **राजस्व** | | **2.00** | **1.90** | | | | |
| | पूर्वोत्तर के लिए विशेष पैकेज | पूर्वोतर में रेडियो कवरेज बढ़ाना | 40.00 | 4.91 | **19 नए एफएम स्टेशन**<br>(i) साइट-15 साइट का अंतिम रूप से (14 साइट अ्धिग्रहीत और एक शीघ्र ही ली जा रही है)। मणिपुर में तमेंग लोंग और उखरूल जुनेहबोतो (नगालैंड) और अनिनी (अरुणाचल) में शेष 4 साइट का शीघ्र अधिग्रहण किया जाना है। | **19 नए एफएम स्टेशन**<br>(i) साइटस-क्यू 1 शेष 4 साइट का शीघ्र अधिग्रहण होने की संभावना है। | 15 साइटों का अधिग्रहण कर लिया गया है और 1 साइट जुनेहबोतो (नगालैंड) का अधिग्रहण होने की संभावना है। अरूणाचल में अनिनी, मणिपुर में उखरूल और तमेंगलोंग को राजय सरकारों द्वारा आवंटित किया जाना है। | संबंधित राज्य सरकारों को चेम्फई, फेक, गोलपाड़ा और कोलासिब में आकाशवाणी साइट्स तक सड़क मार्ग बनाना होगा। चामंलाग, खोनसा और दापोरिजो का मामला आगे बढ़ाया जा रहा है। |
| | पूंजी | | 37.00 | 10.54 | (ii) लोकनिर्माण कार्य-<br>(क) सुरक्षा बाड़<br>उदयपुर और नूतन बाजार में पूरी हो चुकी है। बोमडिला, गोलपाड़ा, बमडिंग, टोपोरिजो, योनसा, तुईपांग, चेम्फई, और कोलासिन में 9 स्थानों पर कार्य प्रगति पर है। | (ii) लोक निर्माण कार्य-<br>(क) सुरक्षा बाड़<br>क्यू-1 9 स्थानों पर कार्य पूरा होने की संभावना है। क्यू-2 4 स्थानों पर कार्य पूरा होने की संभावना है। | मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है। लमडिंग, तुईपांग, उदयपुर, नूतनबाजार, दापोरिजो, कोलासिब, बोमडिला , खोनसा, चेम्फाई और गोलपाड़ में निर्माण पूरा हो चुका है। चेरापूंजी , फेक, लोखा और चांगलांग में 4 स्थानों पर कार्य प्रगति पर है। भूमि का मसला हल होने के बाद चांगलांग में बुनियाद का कार्य अभी शुरू हुआ है। करीमगंज में बाड़ कार्य के लिए अनुमान प्रक्रियाधीन है। | करीमगंज में भूमि के मुआवजे का मुद्दे पर यह पता चलता है कि मसला अभी सुलझा नहीं है कयोकि पूर्ववर्ती भू-स्वामी ने निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी है। डीसी करीमगंज द्वारा भेजा गया भूमि का प्रस्ताव असम सरकार के राजस्व विभाग के सचिव की अनुमति के लिए लंबित है। आकाशवाणी के डीजी ने भी असम सरकार के मुख्य सचिव को शीघ्र मसला हल करने के लिए लिखा है। मामला आगे बढ़ाया जा रहा है। |

*(करोड़ रुपये में)*

| | | | लागत 2010-11 योजना बजट | व्यय (दिसंबर 10 तक) | विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम | प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) | उपलब्धियां (31.12.10 तक) कालम 5 के अनुसार | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | राजस्व | | 3.00 | 0.00 | लक्ष्य जून, 2010 चेरापूंजी, करीमगंज, वोखा और फेक में कार्य मार्च 10 तक शुरू होने की संभावना है। शेष 4 साइट के लिए प्रावधान किया गया है जो अधिग्रहीत की जानी है।<br><br>ख. ट्रांसमीटर भवन और उपकरण संस्थापन - गोलपाड़ा, तुइपांग, कोलासिब, दापोरिजो, नूतन बाजार, उदयपुर और चेम्फई में 8 स्थानों के लिए अनुमानों को मंजूरी दी जा चुकी है तथा खोनसा के लिए प्रक्रियाधीन है। भवन निर्माण कार्य शुरू करने के लिए निविदा कार्य प्रगति पर है। लक्ष्य - अक्तूबर 10। सात स्थानों के लिए अनुमान तैयार हैं तथा फरवरी, 2010 में प्राप्त होने की संभावना है। इन स्थानों पर कार्य वर्ष 2010-11 के दौरान | ख. ट्रांसमीटर भवन<br>क्यू-1 भवन का निर्माण कार्य में पहले से पास 15 साइट पर प्रगति होने की संभावना है तथा टॉवर्स के लिए आर्डर देने की संभावना है।<br>क्यू-2 टॉवर्स को खड़ा करना शुरू होने की संभावना है।<br>क्यू-3 भवन को पूरा करना तथा 8 स्थानों पर संस्थापन की शुरुआत जिनके लिए कार्य पहले ही सौंप दिया गया है या सौंपा जा रहा है। टॉवर का कार्य पूरा होने की संभावना है।<br>क्यू-4 पहले से पास हो चुकी 8 साइटों पर संस्थापन पूरा होने की संभावना है। ट्रांसमीटर भवन पहले से पास हो चुके शेष 7 स्थानं पर पूरे होने की संभावना है। लोक निर्माण कार्य शेष 4 अधिग्रहीत किए जाने वाले स्थानों पर शुरू होने की संभावना है। | ट्रांसमीटर भवन का तकनीकी क्षेत्र तुईपांग, नूतन बाजार, उदयपुर, गोलपाड़ा, दापोरिजो और कोलासिब में 6 स्थानों पर तैयार है तथा फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है। इन 6 स्थानों पर ट्रांसमीटर भवन के तकनीकी क्षेत्र का निरीक्षण सीसीडब्ल्यू को समन्वय से पूरा किया जा रहा है। इन स्थानों पर संस्थापन मार्च, 2011 तक तैयार करने का लक्ष्य है। 4 स्थानों पर कार्य प्रगति पर है। चेम्फई और लन्डिंग में भवन छत के स्तर तक पहुंच गया है तथा योनसा में कार्य प्लिंच लेवल से ऊपर है। चांगलांग बुनियाद कार्य प्रगति में है। चेरापूंजी, बोमडिला, फेक और वोखा में भवन के लिए अनुमान प्रक्रियाधीन है। 6 स्थानों पर टॉवर के लिए फर्म के लिए आशय पत्र जारी किए गए हैं जहां संस्थापन मार्च, 2011 तक पूरा करने का लक्ष्य है। | समुचित पहुंच मार्ग उपलब्ध न होने के कारण कार्य की प्रगति धीमी है जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है तता कई क्षेत्रों खास तौर पर मणिपुर, नगालैंड और असम में कानून और व्यवस्था की समस्या है। |

| | | | लागत 2010-11 योजना बजट | व्यय (दिसंबर 10 तक) | विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम | प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) | उपलब्धियां (31.12.10 तक) कालम 5 के अनुसार | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | | | | | प्रगति में होगा। शेष चार साइट के लिए अनुमान साइट के अधिग्रहणछ`क बाद तैयार किए जाएंगे तथा वर्ष के दौरान कार्य शुरू होने की संभावना है। उपकरण-ट्रांसफर खरीद लिए गए हैं। 50 एम टावर खरीदने की प्रक्रिया जारी, निविदा बुलाई गई। | | | |
| | | | | | 2 सिल्चर-5 के डब्ल्यू एफ एम ट्रांसमीटर - ट्रांसमीटर और पैनल एंटीना की खरीद औरग संस्थापन। ट्रांसमीटर के लिए खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। पैनल एंटीना के लिए निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है। | 2 सिल्चर-5 के डब्ल्यू एफ एम ट्रांसमीटर-<br>क्यू-2 ट्रांसमीटर उपकरण की प्राप्ति और संस्थापन शुरू।<br>क्यू-3 एंटीना की प्राप्ति और संस्थापन तथा ट्रांसमीटर संस्थापन का काम पूरा।<br>क्यू-4 परीक्षण और मापन का काम पूरा। | ट्रांसमीटर के लिए खरीद आर्डर दे दिए गए हैं तथा वर्ष के आखिर तक ये प्राप्त होने की संभावना है। पैनल एंटीना की निविदा फिर जारी की गई है। | |
| | | | | | 3. गैंगटॉक-10 केवी के एफएम ट्रांसमीटर की खरीद और इंस्टॉलेशन का काम करना। याचिका के कारण देरी। दिल्ली | 3. गैंगटॉक-10 केडब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर - क्यू-1 ट्रांसमीटर का आर्डर जारी होने की संभावना। होस्टल निर्माण शुरू।<br>क्यू-3 ट्रांसमीटर की प्राप्ति और संस्थापन शुरू<br>क्यू-4 काम पूरा | 3. फर्म के समुचित पीबीजी जमा करने के बाद ट्रांसमीटर के लिए औपचारिक एटी 9.3.10 को की गई। ट्रांसमीटर 2010-11 में प्राप्त होने की संभावना है। | |

*(करोड़ रुपये में)*

| | | | लागत 2010-11 योजना बजट | व्यय (दिसंबर 10 तक) | विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम | प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) | उपलब्धियां (31.12.10 तक) कालम 5 के अनुसार | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | | | | | उच्च न्यायालय ने याचिका रद्द कर दी है (21.5.09) लेकिन एल-1 फर्म बैंक गारंटी नहीं दे सकी। | | | |
| | | | | | 4. चिन्सुरा- 1000 केवी एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर का लोक निर्माण पूर्ण, ट्रांसमीटर की खरीद और इंस्टॉलेशन | 4. चिन्सुरा 1000 केडब्ल्यू एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर-क्यू-1 लोक निर्माण कार्य पूरा और विभागीय काम चालू। क्यू-3 ट्रांसमीटर प्राप्त और इंस्टॉलेशन का काम शुरू। क्यू-4 ट्रांसमीटर के इंस्टॉलेशन का काम पूरा। | 4. निर्माण कार्य पूरा, ट्रांसमीटर के प्रेषण से पूर्व निरीक्षण में काल प्राप्त और मंजूरी के लिए प्रस्ताव मंत्रालय को सौंपा जा रहा है। | |
| | | | | | 5. 100 स्थानों पर 100 वॉट एफएम ट्रांसमीटर। शेष 20 स्थानों (80 स्थानों पर संस्थापन पिछले वर्ष पूरा हो गया था) पर संस्थापन का काम पूरा। | 5. क्यू-1 मार्च, 2010 के बाद बचे स्थानों पर संस्थापन। | 5. 9 स्थानों पर संस्थापित (कुल 89 स्थानों पर काम पूरा) तथा 3 स्थानों पर कार्य जारी। 8 स्थानों पर राज्य सरकार (2 अरुणाचल में) की मंजूरी तथा कानून-व्यवस्था में सुधार (मणिपुर में 4 और त्रिपुरा में 2) के बाद कार्य शुरू होगा। | |
| | | | | | 6. डीएसएलजी/एमएसएस (3) टर्मनल की खरीद के लिए निविदा दोबारा मंगाई गई। | 6. डीएसएनजी एमएसएस सिस्टम्स-(3) निविदा प्रक्रिया की उम्मीद तथा तकनीकी मूल्यांकन की संभावना। | 6. डीएसएनजी- एमएसएस टर्मिनल-(1) डीएसएनजी निविदा स्वीकृत नहीं हुई और 31.8.10 को दोबारा मंगाई गई। (2) निविदा 27-10-10 को खोली गई और छंटनी की जा रही है। | |

*(करोड़ रुपये में)*

| | | | लागत 2010-11 योजना बजट | व्यय (दिसंबर 10 तक) | विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम | प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) | उपलब्धियां (31.12.10 तक) कालम 5 के अनुसार | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 3. | एमडब्ल्यू सेवाओं का विस्तार | प्राथमिक कवरेज क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ट्रांसमीटर का आधुनिकीकरण करना। | 0.00 | 0.03 | कार्य पूरा | कार्य पूरा | | |
| 4. | एफएम सेवाओं का विस्तार | बेहतरीन गुणवत्ता के कारण लोकप्रिय हुए एमएम कवरेज का विस्तार | 30.00 | 12.47 | तीन 1 केवी एफएम ट्रांसमीटर का इंस्टॉलेशन श्रीकाकुलम में पूरा<br>नई टिहरी में भवन पूरा और संस्थापन शुरू<br>गैरषेण में भवन पूरा और संस्थान शुरू | 1 केवी एफएम ट्रांसमीटर (3) श्रीकाकुलम-ट्रांसमीटर की खरीद लेकिन विजयवाड़ा में संस्थापित वहां नया ट्रांसमीटर आगे के बाद इसे वापस लाया जाएगा। | | श्रीकाकुलम में ट्रांसफारमर वापस लाया जाएगा। नई टिहरी में वन विभाग की मंजूरी न मिलने के कारण देरी। |
| 5 | निर्माण सेवाओं का डिजिटलीकरण | सामग्री की तकनीकी गुणवत्ता बढ़ाना | 1.00 | 1.00 | डिजिटल कंसोल (27) खरीद प्रस्ताव की प्रक्रिया चालू है। डिजिटल रिकार्डिंग कंसोल (16) खरीद प्रस्ताव की प्रक्रिया चालू है। | डिजिटल कंसोल-क्यू 1 खरीद होने की संभावना। कंसोल का संस्थापन पूरा होने की संभावना | | |
| 6 | स्टूडियो सुविधाओं और अन्य योजनाओं का स्वचलन | | 6.00 | 28.60 | सिल्चर और देहरादून में कैप्टिव अर्थ स्टेशन की स्थापना उपकरणों की खरीद एवं इंस्टॉलेशन। नई एनआईटी जारी की गई। | सिल्चर और देहरादून में कैप्टिव अर्थ स्टेशन-क्यू 1 आर्डर दिए जाएंगे। क्यू 3 उपकरण प्राप्त हो जाएंगे और इंस्टॉलेशन शुरू होगा। 48 स्थानों पर हार्ड डिस्क आधारित प्रणाली (हाई एंड सर्वर वाले एसआईटीसी) की खरीद | 48 स्थानों पर हार्ड डिस्क आधारित प्रणाली (हाई एंड सर्वर वाले एसओटीसी) की खरीद। क्यू-1 एसआईटीसी कार्य सौंपा जाएगा। क्यू-2 एसआईटीसी कार्य शुरू होने की संभावना। | डिजिटल अपलिंक स्टेशन और कंपयूटरीकृत वर्क स्टेशन कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। |

*(करोड़ रुपये में)*

| | | | लागत 2010-11 योजना बजट | व्यय (दिसंबर 10 तक) | विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम | प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) | उपलब्धियां (31.12.10 तक) कालम 5 के अनुसार | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | | | | | राजकोट-1000 केडब्ल्यू एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर टावर-लोक निर्माण कार्य पूरा करना। | राजकोट-1000 केडब्ल्यू एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर-क्यू1 लोक निर्माण कार्य पूरा और विभागीय काम जारी। क्यू-3 ट्रांसमीटर प्राप्त और इंस्टॉलेशन का काम शुरू। क्यू-4 इंस्टॉलेशन का काम पूरा और परीक्षण शुरू। | | पुराने ट्रांसमीटर को नए डिजिटल ट्रांसमीटर द्वारा बदला जाएगा, जिसकी क्षमताअधिक है। |
| | | | | | तवांग में स्थायी स्टूडियो- (कार्य का सीमित मौसम) का कार्य प्रगति पर | तवांग में स्थायी स्टूडियो-(कार्य का सीमित मौसम) क्यू-1 इंस्टॉलेशन काकाम पूरा। | | डिजिटल कंसोल, डिजिटल अपलिंकिंग, डाउनलिंकिंग उपकरण कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। |
| | | | | | जयपुर में स्थायी स्टूडियो- उपकरणों को इंस्टॉल करने का कार्य पूरा होने की संभावना | जयपुर में स्थायी स्टूडियो- क्यू-1 लंबित काम पूरा। संयुक्त निरीक्षण और कमीशनिंग | | |
| 7. | मेट्रो शहरों में स्टाफ क्वार्टर बनाना | प्रसार भारती के स्टाफ के लिए मेट्रो शहरों में स्टाफ क्वार्टर बनाना | फंडिंग दूरदर्शन द्वारा की जा रही है | | दिल्ली चरण 1 (323) निर्माण कार्य पूरा होने के करीब और चरण 2 - (203) ठेका दिया गया<br><br>मुंबई - 68 क्वार्टरों का निर्माण। दो प्रखंडों के लिए स्थानीय निकाय से मंजूरी मिली। | दिल्ली - निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना<br><br>मुंबई- क्यू-1 निर्माण का ठेका दिए जाने की उम्मीद। क्यू-4 काम जारी रहने की उम्मीद। | | कल्याण गतिविधियों की फंडिंग दूरदर्शन द्वारा की जा रही है |

*(करोड़ रुपये में)*

| | | | लागत 2010-11 योजना बजट | व्यय (दिसंबर 10 तक) | विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम | प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) | उपलब्धियां (31.12.10 तक) कालम 5 के अनुसार | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | | | | | चेन्नई- स्थानीय निकाय से भवन निर्माण योजना को मंजूरी की प्रतीक्षा | चेन्नई - सीएमडीए को भवन निर्माण योजना को मंजूरी देनी बाकी है। सीएमडीए ने अतिरिक्त ढांचे और सुविधा शुल्क की मांग की है जिसे पूरा करना संभव नहीं है, क्योंकि जमीन सरकार की है। मामले पर काम जारी है। | | |
| | | | | | कोलकाता- केएमसी द्वारा उत्परिवर्तन की कमी से भवन योजना को स्थानीय निकाय की मंजूरी मिलना बाकी। | कोलकाता- केएमसी द्वारा उत्परिवर्तन की कमी से भवन योजना को स्थानीय निकाय की मंजूरी मिलना बाकी और केएमडीए द्वारा एकपक्षीय विदड्रॉअल। कोलकाता उच्च न्यायालय में याचिका दायर। | | |
| | **कुल** | | **80.50** | **57.31** | | | | |
| 2 | **नई योजनाएं** | | **102.98** | **29.68** | | | | |
| 2.1 | ट्रांसमीटर स्टूडियो, कनेक्टिविटी और डीटीएच चैनल को डिजिटल बनाना | एसडब्ल्यू, डीआरएम ट्रांसमीटर के राष्ट्रीय स्तर के कवरेज को डिजिटल मोड में करना, एफएम विस्तार, स्टूडियो को डिजिटल बनाना और कनेक्टिविटी बढ़ाना | 30.00 | 23.93 | | | | |

*(करोड़ रुपये में)*

| | | | लागत 2010-11 योजना बजट | व्यय (दिसंबर 10 तक) | विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम | प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) | उपलब्धियां (31.12.10 तक) कालम 5 के अनुसार | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 2.1.1 | एम डब्ल्यू डीआरएम ट्रांसमीटर | | | | | | | |
| 2.1.1 क | पुराने एम डब्ल्यू ट्रांसमीटरों (31) की जगह मौजूदा स्टेशनों पर नए डीआरएम एम डब्ल्यू ट्रांसमीटर लगाना | | | | ईएफसी प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन | क्यू-1 ईएफसी स्वीकृति और उपकरण के लिए निविदा मंगाई गई।<br>क्यू-2 निविदा की प्रोसेसिंग और तकनीकी मूल्यांकन<br>क्यू-3 वाणिज्यिक बोली खोली गई और खरीद प्रस्ताव की प्रोसेसिंग<br>क्यू-4 ठेका दिया गया | | ईएफसी प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन |
| 2.1.1. ख | (i) 3 एम डब्ल्यू डीआरएम ट्रांसमीटर का अरूमाचल-चीन सीमा पर कैप्टिव पावर प्लांट के साथ उन्नयन | | | | ईएफसी प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन | क्यू-1 ईएफसी स्वीकृति और उपकरण के लिए निविदा मंगाई गई।<br>क्यू-2 निविदा की प्रोसेसिंग और तकनीकी मूल्यांकन<br>क्यू-3 वाणिज्यिक बोली खोली गई और खरीद प्रस्ताव की प्रोसेसिंग<br>क्यू-4 ठेका दिया गया | | ईएफसी प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन |
| 2.1.1. ग | एम डब्ल्यू डीआरएम ट्रांसमीटरों द्वारा 10 केडब्ल्यू एम डब्ल्यू (6) मोबाइल का प्रतिस्थापन | | | | 19.00 करोड़ रुपए की राशि की एसएफसी के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मंजूरी। ट्रांसमीटर के लिए अग्रिम एटी दिसंबर 2010 को दी गई | क्यू-3 ट्रांसमीटर प्राप्त होने की संभावना | | |

*(करोड़ रुपये में)*

| | | | लागत 2010-11 योजना बजट | व्यय (दिसंबर 10 तक) | विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम | प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) | उपलब्धियां (31.12.10 तक) कालम 5 के अनुसार | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 2.1.1. घ | 36 मौजूदा डीआरएम कंपेटीबल एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर का डीआरएम में रूपांतरण | | | | डीआरएम में रूपांतरण अनुमति के लिए इएफसी प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन उपकरण खरीद और संस्थापन मार्च 2011 तक करने का लक्ष्य | क्यू-1 ईएफसी अनुमति और उपकरण के लिए निविदा मंगाई गई क्यू-2 टेंडर मूल्यांकन क्यू-4 संस्थापन पूरा | | |
| 2.1.2. | एफएम डीआरएम कंपेटीबल ट्रांसमीटर | | | | | | | |
| 2.1.2 क | मौजूदा 24 आकाशवाणी/टीवी साइटों पर एफएम विस्तार तथा डीडी के मौजूदा 100 एलपीटी पर 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर | | | | ईएफसी प्रस्ताव मंत्रालय की अनुमति के अधीन। उपकरण की खरीद मार्च 2011 तक होने की उम्मीद | क्यू-1 ईएफसी अनुमति और उपकरण के लिए निविदा मंगाई गई क्यू-4 ठेका दिया गया | | |
| 2.1.2. ख | मौजूदा 40 स्टेशनों पर हायर पावर द्वारा एफएम/एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर का स्थापन | | | | ईएफसी प्रस्ताव अनुमति के लिए मंत्रालय के विचाराधीन। उपकरण की खरीद मार्च 2011 तक होने की संभावना | क्यू-1 ईएफसी अनुमति और उपकरण के लिए निविदा मंगाई गई क्यू-4 ठेका दिया गया | | |
| 2.1.3. | 5 एस डब्ल्यू ट्रांसमीटरों (दिल्ली-2, छ अलीगढ़ -2, बंगलुरू-1) का एस डब्ल्यू डीआरएम ट्रांसमीटर प्रतिस्थापन | | | | ईएफसी प्रस्ताव अनुमति के लिए मंत्रालय के विचाराधीन | क्यू-1 ईएफसी अनुमति और उपकरण के लिए निविदा मंगाई गई क्यू-4 ठेका दिया गया | | |

*(करोड़ रुपये में)*

| | | | लागत 2010-11 योजना बजट | व्यय (दिसंबर 10 तक) | विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम | प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) | उपलब्धियां (31.12.10 तक) कालम 5 के अनुसार | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 2.1.4क | 98 स्टूडियो का डिजिटलीकरण तथा नेटवर्किंग | | | | वर्ष के दौरान 36 स्टूडियो में उपकरण प्राप्त होने की आशा | क्यू-1 ईएफसी अनुमति और उपकरण के लिए निविदा मंगाई गई<br>क्यू-4 ठेका दिया गया | | |
| 2.1.4 ख | दिल्ली में अभिलेखीय सुविधा तथा चेन्नई, मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में भी ये सुविधाएं देना | | | | | क्यू-1 ईएफसी अनुमोदन। क्यू-2 उपकरणों के लिए विशिष्टताएं तय कर निविदा मंगाना। क्यू-3 तकनीकी मूल्यांकन। क्यू-4 निविदा खोलना और खरीद प्रस्ताव की प्रक्रिया आगे बढ़ाना। | | |
| 2.1.4 ग | 44 मौजूदा इकाइयों का ऑटोमेशन तथा नई क्षेत्रीय इकाइयों का सृजन | | | | | -वही- | | |
| 2.1.5 क | एसटीएल कनेक्टिविटी को बदलना | | | | मंत्रालय ने इस उप-स्कीम के लिए 31.50 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। लक्ष्य - मार्च 2011 | क्यू-1 तकनीकी मूल्यांकन के बाद वाणिज्यिक बिड खोलने की आशा। क्यू-2 खरीद प्रस्ताव प्रक्रिया आगे बढ़ने की आशा। क्यू-4 उपकरण आपूर्ति की संभावना। | | |
| 2.1.5 ख,ग | सीईएस, एसटीएल, डीएसएनजी के नए प्रस्ताव | | | | | -वही- | | |
| 2.1.5 ज | सीबैंड आरएनटी (44) का प्रावधान | | | | इस उप स्कीम के लिए मंत्रालय ने 4.28 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन<br>लक्ष्य - दिसंबर-10 | -वही- | | |

*(करोड़ रुपये में)*

| | | | लागत 2010-11 योजना बजट | व्यय (दिसंबर 10 तक) | विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम | प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) | उपलब्धियां (31.12.10 तक) कालम 5 के अनुसार | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 2.1.5 ङ | डीटीएच चैनलों का आग्मेंटेशन | | | | | क्यू-1 ईएफसी अनुमोदन उपकरण विशेषताएं निर्धारित करना। क्यू-2 टेंडर मंगाना। क्यू-3 टेंडर प्रक्रिया तथा तकनीकी मूल्यांकन। क्यू-4 वाणिज्यिक बिड खोलना तथा खरीद प्रस्ताव की प्रक्रिया। | | |
| 2.2 | विदेश सेवा को मजबूत करना | एसडब्ल्यू का डिजिटलीकरण | 0.10 | - | मंत्रालय ने 10.00 करोड़ रुपये की उपयोजना को अनुमति दे दी है | | | |
| 2.3 | ई गर्वनेंस, प्रशिक्षण, सुरक्षा अतिरिक्त कार्यालय परिसर, स्टाफ क्वार्टर बनाना | ढांचागत संरचना में सुधार | 21.38 | 0.60 | | | | |
| 2.4 | नई तकनीक और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | सेटेलाइट और क्षेत्रीय मोड में मल्टीमीडिया प्रसारण, ब्राडकास्टिंग और पाड कास्टिंग | 1.50 | 0.49 | | | | |
| 2.4 क | अनुसंधान और विकास | | | | अनुमोदन प्राप्त उपकरण विशिष्टताएं प्रक्रियाधीन। | क्यू-1 ईएफसी स्वीकृत क्यू-3 टेंडर खोला जाना। क्यू-4 आर्डर दिया गया। | | |

*(करोड़ रुपये में)*

| | | | लागत 2010-11 योजना बजट | व्यय (दिसंबर 10 तक) | विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम | प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य) | उपलब्धियां (31.12.10 तक) कालम 5 के अनुसार | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 2.5 | साफ्टवेयर | उच्च क्वालिटी का साफ्टवेयर बनाने के लिए ताकि प्रतिस्पद्धी मीडिया माहौल में आकाशवाणी के श्रोताओं को आकर्षित और बनाया रखा जा सके। | 10.00 | 4.60 | 100 करोड़ रुपये के लिए संशोधित ईएफसी प्रस्ताव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को आनवर्ड ट्रांसमीशन के लिए प्रसार भारती को सौंपा जा रहा है। | | | |
| 2.6 | जम्मू-कश्मीर फेज-III | जम्मू-कश्मीर सीमा क्षेत्रों में एफएम कवरेज में और सुधार के लिए | 40.00 | | ईएफसी अनुमति के अधीन है। 2010-11 के दौरान ट्रांसमीटर और संबंधित उपकरण खरीदे जाएंगे और लोकनिर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। उपकरण एकल स्रोत के जरिए खरीदने का प्रस्ताव है। | क्यू-1 ईएफसी अनुमोदन और उपकरण के लिए निविदा आमंत्रण तथा लोक निर्माण कार्य के लिए प्रारंभिक अनुमान के प्रोसेसिंग क्यू-2 निविदाओं औरतकनीकी मूल्यांकन की प्रोसेसिंग तथा अनुमानों को मंजूरी तथा लोक निर्माण कार्य सौंपा गया। क्यू-3 वाणिज्यिक बोली बोलना और खरीद प्रस्ताव की प्रोसेसिंग तथा लोक निर्माण कार्य प्रगति की संभावना क्यू-4 आर्डर प्लेसमेंट तथा लोक निर्माण कार्य पूरा करना | | उच्च पावर वाले तीन एफएम ट्रांसमीटर पहाड़ों के चोटियों पर लगाए जाएंगे और एक एफएम ट्रांसमीटर मौजूदा डीडी सेंटर में लगाएजाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त कम पावर वाला ट्रांसमीटर अनकवर्ड क्षेत्रों में लगाए जाने का प्रस्ताव है। |
| | **II.का कुल** | | **102.98** | **29.62** | | | | |
| | **आकाशवाणी का कुल** | | **183.48** | **86.93** | | | | |
| | | | | | | | | |

# प्रसार भारती

# दूरदर्शन - वार्षिक योजना ( 2010-11 )

## परिणाम तथा परिणाम/लक्ष्य 2010-11

*(करोड़ रुपये में)*

| क्रमांक | योजना/कार्यक्रम | उद्देश्य/परिणाम | लागत 2010-11 योजना बजट | व्यय 2010-11 | विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम | प्रक्रिया/समयबद्धता | | उपलब्धियां | टिप्पणियां/जोखिम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | | 8. | 9. |
| | **चालू योजनाएं** | | | | | | | | |
| 1 | **जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष पैकेज- चरण 1 और चरण 2 ( पूंजी )** | जम्मू कश्मीर में दूरदर्शन कवरेज प्रसारण में सुधार। अमृतसर में टावर निर्माण के अतिरिक्त जम्मू एवं कश्मीर के विशेष पैकेज का पहला चरण कार्यान्वित हो गया है। अमृतसर में टावर निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके परिणामस्वरूप जम्मू एवं कश्मीर में दूरदर्शन प्रसारण की गुणवत्ता और कवरेज क्षेत्र में सुधार होगा। योजना के दूसरे चरण में कन्टेंट के सुधार पर जोर दिया जाएगा। | 4.00 | 5.51 | अमृतसर में 300 मीटर का टावर बनाया गया | सीमापारीय क्षेत्रों में डीडी 1 और डीडी न्यूज चैनल उपलब्ध कराना | अमृतसर में टावर का निर्माण कार्य पूर्ण | टावर की लंबाई 130 मीटर तक हो गई है। 282 मीटर तक बनाने के लिए टावर सामग्री साइट पर पहुंच चुकी है। | संस्था द्वारा धीमा काम |
| | | | | | अमृतसर में 300 मीटर ऊंचे टावर पर लगे एंटीना से डीडी 1 और डीडी न्यूज एचटीपी का आरंभ | | डीडी1 और डीडी (न्यूज) के लिए ट्रांस्मीटर का स्थापन | भवन निर्माण हो चुका है। एंटीना का ऑर्डर दे दिया गया है। फीडर केबल साइट पर पहुंच चुकी है। | टावर 300 मीटर बनने और एंटीना व फीडर केबल ढोकर ले जाने के बाद इंस्टॉलेशन किया जाएगा, चूंकि मौजूदा ट्रांसमीटर (जो मौजूदा स्टेशन में लगा है) का भी उपयोग करना है। |
| | **राजस्व** | | **31.00** | **41.00** | | | | | |

*(करोड़ रुपये में)*

| क्रमांक | योजना/कार्यक्रम | उद्देश्य/परिणाम | लागत 2010-11 योजना बजट | व्यय (दिसंबर 10 तक) | विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम | प्रक्रिया/समयबद्धता | | उपलब्धियां | टिप्पणियां/जोखिम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | | 8. | 9. |
| 2 | निर्माण सुविधाओं (स्टूडियो-ओबी) का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण | कार्यक्रमों की तकनीकी गुणवत्ता बढ़ाना | 10.00 | 8.99 | स्टूडियो केंद्र, केंद्रीकृत रिकॉर्डिंग, संपादन और प्लेबैक का सभी 17 मुख्य दूरदर्शन केंद्रों में आधुनिकीकरण। ओबी सुविधाओं का विस्तार और तेज न्यूज डिलिवरी प्रणाली | स्टूडियो का डिजिटलीकरण | कार्य में प्रगति | कार्य में प्रगति | मल्टी कैमरा ओवी वैन का आपूर्ति में देर |
| 3 | पूर्वोत्तर के लिए विशेष पैकेज, चरण 2 (पूंजी) | पूर्वोत्तर और अंडमान और निकोबार क्षेत्र में दूरदर्शन कवरेज को मजबूत बनाना। पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान निकोबार एवं लक्षदीप के द्वीपीय इलाकों में दूरदर्शन सेवाओं के विस्तार और सुधार के लिए सरकार ने मई 2006 में 256.85 करोड़ रुपए | 4.00 | 3.67 | कोकराझार में 10 के वी एचपीटी टावर का कार्य पूर्ण | | परियोजना पुर्ण | 150 मीटर तक टावर बन चुका है। | |
| | | | | | डीएसएनजी यूनिट-4 पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार में | और तकनीकी गुणवत्ता में सुधार। टीवी सिग्नल प्रदान करना | ट्रांस्मीटर का स्थापन | 10 किलोवाट ट्रांस्मीटर आमंत्रित | |
| | | | | | पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार में समाचार संकलन | | | गुवाहाटी में अतिरिक्त (2 प्लस 1) अपलिंक चेन का इंस्टॉलेशन हो चुका है। | |
| | | | | | | | | | |
| | **राजस्व** | | **21.00** | **10.00** | | | | | |

*(करोड़ रुपये में)*

| क्रमांक | योजना/कार्यक्रम | उद्देश्य/परिणाम | लागत 2010-11 योजना बजट | व्यय (दिसंबर 10 तक) | विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम | प्रक्रिया/समयबद्धता | | उपलब्धियां | टिप्पणियां/जोखिम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | | 8. | 9. |
| 4 | डीटीएच | इस योजना का उद्देश्य शेष बचे क्षेत्रों में टीवी कवरेज उपलब्ध कराना है। डीटीएच की वर्तमान क्षमता 50 टीवी चैनल हैं। | 0.00 | 0.00 | | | शून्य | | डीटीएच सुविधा शुरू हो चुकी है |
| 5 | एडीटीवी | यह वह तकनीक है जो उत्कृष्ट पिक्चर और वाइट स्क्रीन इमेज के कार्यों में अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इस तकनीक से 35 एमएम फिल्म जैसी पिक्चर क्वालिटी मिलती है। यह तकनीक डिजिटल सराउंडिंग साउंड भी उपलब्ध कराती है। एचडीटीवी फिल्म प्रोडक्शन के लिए प्रायोगिक परियोजना का कार्य चालू है। | 2.00 | 3.55 | एचडीटीवी प्रोडक्शन के लिए एक फील्ड वैन | प्रायोगिक योजना एचडीटीवी फॉरमेट में निर्माण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। | उपकरणों की आपूर्ति और उन्हें लगाना | एचडीटीवी कैमकॉर्डर और आमंत्रित वीसीआर की खरीद की। | क्षेत्रीय निर्माण आरंभ |
| 6 | दसवीं योजना की अनुमानित योजना | | 10.00 | 29.66 | | | | | |
| | स्टाफ के लिए आवास, बुनियादी ढांचे और सुरक्षा में वृद्धि | स्टाफ के लिए आवास सुविधा का प्रावधान। बुनियादी ढांचे में वृद्धि- विभिन्न स्टेशनों पर सुरक्षा को मजबूत करना। | | | चार मेट्रो शहरों में स्टाफ के लिए क्वार्टर | चार मेट्रो शहरों और 11 गैर मेट्रो शहरों पर स्टाफ के लिए आवास का निर्माण तथा बुनियादी ढांचे व | स्टाफ के लिए आवासों का काम पूरा हो चुका है। | | |

*(करोड़ रुपये में)*

| क्रमांक | योजना/कार्यक्रम | उद्देश्य/परिणाम | लागत 2010-11 योजना बजट | व्यय (दिसंबर 10 तक) | विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम | प्रक्रिया/समयबद्धता | | उपलब्धियां | टिप्पणियां/जोखिम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | | 8. | 9. |
| | | | | | 11 मेट्रो शहरों में स्टाफ के लिए क्वार्टर<br><br>विभिन्न दूरदर्शन केंद्रों पर सुरक्षा और बुनियादी ढांचे में वृद्धि | | | निविदा निकाली गई है। 8 स्थानो पर स्टाफ क्वार्टर बनाए जा चुके हैं। बैंगलोर, पटना और संभलपुर में क्वार्टर बनाए जा रहे हैं। | लखनऊ, जयपुर, वाराणसी, भवानीपटना, हिसार, इलाहाबाद, त्रिचूर और इटानगर में स्टाफ क्वार्टर बन गए हैं। |
| | अन्य योजनाएं | | | | | | | | |
| | स्टूडियो संबंधी योजना | स्टूडियो केंद्रों के निर्माण और उत्पादन सुविधाओं की वृद्धि से स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करना। | | | स्टूडियो की स्थापना | नेटवर्क में शामिल स्टूडियो में निर्माण की गुणवत्ता में सुधार | चंडीगढ़ (अतिरिक्त), जम्मू (अतिरिक्त) और लेह में स्टूडियो परियोजना पूर्ण | चंडीगढ़, लेह, जम्मू में भवन निर्माण का काम पूरा हो गया है। इन स्थानों पर इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। देहरादून और तिरुपति में भवन निर्माण का काम चल रहा है। | पणजी और गोरखपुर में स्टूडियो से पहले ही बन गए हैं। |
| | ट्रांसमीटर संबंधी योजना | क्षेत्रीय कवरेज में सुधार | | | ऑटोमोड एलपीटी 50 | क्षेत्रीय प्रसारण तथा कवरेज क्षेत्र की गुणवत्ता में सुधार | एचपीटी महबूबनगर का कार्य प्रगति पर है। एचपीटी बिलासपुर, कुन्नूर और कुंभकोणम का कार्य प्रगति पर है। एलीपीटी ऑटोमोड की खरीद और इंस्टॉलेशन। | 11 एलपीटी के इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो गया है। 29 स्थानों पर काम चल रहा है। 50 एलपीटी खरीदने का काम चल रहा है। नए टेंडर मिल चुके हैं। ट्रांसमीटर का ऑर्डर दिया जा चुका है। तीसरे स्थान (महबूबनगर) में भवन निर्माण का काम चल रहा है। टावर और ट्रांसमीटर उपकरण के लिए ऑर्डर देने का काम चल रहा है। | तकनीकी कारणों से 50 एलपीटी के लिए प्राप्त निविदाओं को रद्द कर दिया गया है। नई निविदाओं पर काम चल रहा है। एचपीटी सहरसा शुरू हो चुका है। |
| | कुल (i) | | 82.00 | 103.29 | | | | | |

*(करोड़ रुपये में)*

| क्रमांक | योजना/कार्यक्रम | उद्देश्य/परिणाम | लागत 2010-11 योजना बजट | व्यय (दिसंबर 10 तक) | विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम | प्रक्रिया/समयबद्धता | | उपलब्धियों | टिप्पणियां/जोखिम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | | 8. | 9. |
| | | | | | | | | | |
| | नई योजना | | | | | | | | |
| 1. | ट्रांसमीटर का डिजिटलीकरण, आधुनिकीकरण, ट्रांसमीटर उपकरणों का संवर्धन और नए उपकरण लगाना | | 20.00 | 1.30 | | | | | अनुमति/ अनुसमर्थन जारी करना है। |
| | क) ट्रांसमीटर का डिजिटलीकरण | क्षेत्रीय प्रसारण का डिजिटलीकरण | 15.50 | | 40 डीटीटी ट्रांसमीटर के लिए उपकरणों की खरीद (आंशिक परिणाम) | क्षेत्रीय प्रसारण के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया शुरू (आंशिक परिणाम) | 11 वीं योजना में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण होने की संभावना | | अप्रैल 2010 में स्कीम अनुमोदित |
| | ख) ट्रांसमीटर उपकरणों का आधुनिकीकरण, संवर्धन और दूसरे उपकरण लगाना | ट्रांसमीटर उपकरणों का आधुनिकीकरण, संवर्धन और तकनीक पुरानी हो जाने और उपकरण के पुराने पड़ जाने के कारण नए उपकरण लगाना। | 5.00 | | 15 एचटीपी और 60 एलपीटी के स्थान पर ऑटोमोड एलपीटी लगाना (आंशिक परिणाम) | क्षेत्रीय प्रसारण की गुणवत्ता और कवरेज में सुधार (आंशिक परिणाम) | पूर्ण होने की संभावना | | ईएफसी अपराज़ड |

*(करोड़ रुपये में)*

| क्रमांक | योजना/कार्यक्रम | उद्देश्य/परिणाम | लागत 2010-11 योजना बजट | व्यय (दिसंबर 10 तक) | विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम | प्रक्रिया/समयबद्धता | | उपलब्धियां | टिप्पणियां/जोखिम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | | 8. | 9. |
| 2. | स्टूडियो डिजिटलीकरण : आधुनिकीकरण, संवर्धन, स्टूडियो-ओबी उपकरणों का प्रतिस्थापन | | 25.00 | 2.50 | | | | | |
| | क) स्टूडियो का डिजिटलीकरण | निर्माण, पोस्ट प्रोडक्शन, संपादन और अभिलेख सुविधाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण | 20.00 | | छोटे केंद्रों के 31 स्टूडियो का आंशिक और पूर्ण डिजिटलीकरण और 8 केंद्रों का पूर्ण डिजिटलीकरण (आंशिक परिणाम) | प्रोडक्शन सुविधा का पूर्ण डिजिटलीकरण (आंशिक परिणाम) | 11 वीं योजना में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी | | स्कीम अप्रैल 2010 में स्वीकृत |
| | ख) स्टूडियो उपकरणों का डिजिटलीकरण, संवर्धन और प्रतिस्थापन | निर्माण संबंधी उपकरणों का आधुनिकीकरण, संवर्धन और प्रतिस्थापन, क्योंकि बदलती तकनीक के कारण वे उपकरण पुराने पड़ गए हैं। | 5.00 | | सभी छोटे और 66 बड़े केंद्रों पर निर्माण, पोस्ट प्रोडक्शन, ऑडियो लाइटिंग और विद्युत आपूर्ति में वृद्धि (आंशिक परिणाम) | तकनीकी गुणवत्ता में वृद्धि (आंशिक परिणाम) | 11 वीं योजना में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी | | स्कीम स्वीकृत होनी है। |

*(करोड़ रुपये में)*

| क्रमांक | योजना/कार्यक्रम | उद्देश्य/परिणाम | लागत 2010-11 योजना बजट | व्यय (दिसंबर 10 तक) | विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम | प्रक्रिया/समयबद्धता | | उपलब्धियां | टिप्पणियां/जोखिम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | | 8. | 9. |
| 3. | डीटीएच : आधुनिकीकरण, संवर्धन और सेटेलाइट ब्रॉडकास्ट उपकरणों का प्रतिस्थापन | | 5.00 | 0.28 | | | | | |
| | क) डीटीएच | डीटीएच प्लेटफार्म में चैनलों को बढ़ाना | | | डीटीएट प्लेटफार्म पर चैनलों में वृद्धि | आंशिक परिणाम | 11 वीं योजना में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी | | योजना को मंजूरी मिलनी बाकी है। |
| | ख) सेटेलाइट ब्रॉडकास्ट उपकरणों का डिजिटलीकरण, संवर्धन और प्रतिस्थापन | पुराने हो चुके सेटेलाइट उपकरणों का आधुनिकीकरण, संवर्धन और नए डिजिटल उपकरणों द्वारा प्रतिस्थापन, समाचार जुटाने की सुविधा में वृद्धि | | | अर्थ स्टेशन का उन्नयन, वी सेट की संख्या 10 करना, 50 वी सेट टर्मिनल, 9 नए डीएसएनजी, 6 पुराने डीएसएनजी और अन्य उपकरणों के प्रतिस्थापन के साथ 5 नए अर्थ स्टेशन (आंशिक परिणाम) | प्रगति पर | 11 वीं योजना में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी | सीपीसी में 5 चैनल एमसीपीसी के कंप्रेशन उपकरण को बदलने के लिए निविदा मांगी गई हैं।<br><br>6 डीएसएनजी वैन के एसआईटीसी के लिए निविदा जारी<br><br>सीपीसी और डीडीके श्रीनगर में अपलिंक पीडीए के एसआईटीसी के लिए निविदा जारी | अनुमति मिल चुकी है। अनुसमर्थन फरवरी 09 में जारी किया जा चुका है। |

*(करोड़ रुपये में)*

| क्रमांक | योजना/कार्यक्रम | उद्देश्य/परिणाम | लागत 2010-11 योजना बजट | व्यय (दिसंबर 10 तक) | विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम | प्रक्रिया/समयबद्धता | | उपलब्धियां | टिप्पणियां/जोखिम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | | 8. | 9. |
| | एचडीटीवी | एचडीटीवी प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और प्रसारण सुविधा | 15.00 | 8.13 | दिल्ली और मुंबई में एचडीटीवी प्रोडक्शन सुविधा, दिल्ली में प्लेआउट एक्टिविटी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पोस्ट प्रोडक्शन सुविधा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के लिए फील्ड प्रोडक्शन सुविधा, दिल्ली, मुंबई में आउटडोर प्रोडक्शन सुविधा के लिए मल्टी मीडिया कैमरा | प्रगति पर | 11 वीं योजना में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी | सीसीईए द्वारा योजना स्वीकृत। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के लिए एचडीटीवी ट्रांसमीटर के लिए एनआईटी जारी | फरवरी, 09 में अनुमति मिल चुकी है। |
| | | | | | मोबाइल उपकरण, दिल्ली में फ्लाईअवे प्रोडक्शन सेट अप, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के लिए परव्यू सुविधा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में एचडीटीवी ट्रांसमीटर, एचडीटीवी अपलिंक | | | | |

*(करोड़ रुपये में)*

| क्रमांक | योजना/कार्यक्रम | उद्देश्य/परिणाम | लागत 2010-11 योजना बजट | व्यय (दिसंबर 10 तक) | विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम | प्रक्रिया/समयबद्धता | | उपलब्धियां | टिप्पणियां/जोखिम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | | 8. | 9. |
| | | | | | मोबाइल उपकरण, दिल्ली में फ्लाईअवे प्रोडक्शन सेट अप, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के लिए परव्यू सुविधा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में एचडीटीवी ट्रांसमीटर, एचडीटीवी अपलिंक | | | | |
| 5. | स्टाफ के लिए आवास, अन्य कार्य | स्टाफ के लिए आवास सुविधा का प्रावधान। विभिन्न स्टेशनों पर बुनियादी ढांचे में वृद्धि और सुरक्षा व्यवस्था का सुदृढीकरण | 5.00 | 4.51 | 17 स्थानों पर डीएमसी बिल्डिंग, 10 स्थानों पर एलपीटी, 7 स्थानों पर स्टाफ क्वार्टर, 22 स्थानों पर गेस्ट हाउस, गुवाहाटी में जोनल ऑफिस बिल्डिंग, डीडी भवन में टावर सी तथा अन्य बुनियादी ढांचे और सुरक्षा संबंधित कार्य | प्रगति पर | 11 वीं योजना में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी | सभी भवनों के लिए स्थान तय। एलपीटी भवनों, डीएमसी बिल्डिंग, गेस्ट हाउस और सामुदायिक केंद्रों के लिए टाइप डिजाइन। भवन योजना और योजना अनुमान तैयार किए जा रहे हैं। टावर सी के लिए योजना अनुमान मंजूरी की प्रक्रिया में हैं। | फरवरी, 09 में अनुमति मिल चुकी है। |

*(करोड़ रुपये में)*

| क्रमांक | योजना/कार्यक्रम | उद्देश्य/परिणाम | लागत 2010-11 योजना बजट | व्यय (दिसंबर 10 तक) | विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम | प्रक्रिया/समयबद्धता | | उपलब्धियां | टिप्पणियां/जोखिम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | | 8. | 9. |
| **6.** | **सॉफ्टवेयर अधिग्रहण** | **5.00** | **9.36** | **0.00** | | | | | |
| | **कुल ( ii )** | | **75.00** | **73.36** | | | | | |
| | **कुल** | | **157.00** | **129.37** | | | | | |
| | | राजस्व | **57.00** | **61.37** | | | | | |
| | | पूंजी | **100.00** | **68.10** | | | | | |

# प्रसार भारती

# दूरदर्शन - वार्षिक योजना ( 2011-12 )

## परिणाम बजट के परिणाम/लक्ष्य ( 2011-12 )

(रुपये करोड़ में)

| क्रम | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | लागत 2011-12 | व्यय दिसंबर, 2011 तक | मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम | अनुमानित परिणाम | प्रक्रियाएं/समयबद्धता | उपलब्धियां 31.12.11 तक | टिप्पणी/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **चालू योजना** | | | | | | | | |
| 1. | जम्मू-कश्मीर विशेष योजना प्रथम तथा द्वितीय चरण (पूंजी) | जम्मू-कश्मीर में दूरदर्शन कवरेज प्रसारण में सुधार। अमृतसर में टावर निर्माण के अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर विशेष पैकेज का पहला चरण कार्यान्वित हो गया है। अमृतसर में टावर, निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इसके परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर में दूरदर्शन प्रसारण की गुणवत्ता तथा कवरेज एरिया में सुधार होगा। योजना के द्वितीय चरण में कंटेट सुधार पर जोर दिया गया है। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर, लेह तथा जम्मू की क्षेत्रीय सेवाओं तथा कशीर चैनल पर 24 घंटे के लिए कार्यक्रमों का निर्माण | 2.20 | 0.72 | अमृतसर में डीडी-1 तथा डीडी न्यूज 300 मीटर का टावर पूरा | सीमापार क्षेत्रों में टीवी कवरेज में वृद्धि। डीडी-1 और डीडी न्यूज के सिगनल सुदूर सीमाक्षेत्रों में उपलब्ध कराना | दूसरी तिमाही में टावर का काम पूरा और एंटिना लगाने का कार्य पूरा। | टॉवर खड़ा करने का काम प्रगति पर, अब तक 283 मीटर की उंचाई हासिल कर ली गई है | एजेंसी द्वारा धीमा कार्य |
| | | | | | 300 मीटर टावर पर अमृतसर में डीडी 1 तथा डीडी (न्यूज) की कमीशनिंग | | नई साइट पर डीडी-1 और डीडी नयूज का संस्थापन | भवन निर्माण पूरा, एंटिने का आदेश और फीटर केबल साइट पर पहुंचा। | 300 मीटर की पूरी उंचाई तक टॉवर खड़ा करने के बाद संस्थापन किया जाएगा। |
| | (राजस्व) | | 53.89 | 42.94 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | निर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण तथा डिजिटलीकरण | कार्यक्रमों की तकनीकी गुणवता बढ़ाना | 3.00 | 0.09 | स्टूडियो केंद्र, केंद्रीकृत रिकार्डिंग, संपादन तथा प्लेबैक का सभी 17 मुख्य दूरदर्शन केन्द्रों के लिए | स्टूडियो का डिजिटलीकरण करने के लिए | कार्य जारी करने के लिए | कार्य जारी | |
| 3. | पूर्वोत्तर विशेष पैकेज चरण-II (पूंजी) | पूर्वोत्तर तथा अंडमान-निकोबार क्षेत्र में दूरदर्शन कवरेज का सुदृढ़िकरण। पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप के द्वीपीय इलाकों में दूरदर्शन सेवाओं के विस्तार तथा सुधार के लिए सरकार ने एक विशेष पैकेज मई 2006 में 256.85 करोड़ रुपये (द्वितीय चरण) को मंजूरी दी। (हार्डवेयर के लिए 134.3 तथा सॉफ्टवेयर के लिए 122.55) | 1.91 | 0.32 | एनई के लिए 4 तथा एएंडएन के लिए 1 डीएसएनजी यूनिट | गुवाहाटी से अंपलिकिंग सुविधा बढ़ाना, अंडमान निकोबार में डीटीएच उपलबध कराया जाएगा<br>स्थलीय प्रसारण के क्षेत्र और तकनीकी गुणवत्ता में सुधार | पहली तिमाही में ट्रांसमीटर उपकरण की आपूर्ति | डीएसएनजी के लिए आर्डर<br>एसएनजी की आपूर्ति के टेंडर मंगाए गए | |
| | राजस्व | | 20.00 | 14.47 | | | | | |
| 4. | डीटीएच | इस योजना का उद्देश्य शेष बचे क्षेत्रों में टीवी कवरेज उपलब्ध कराना है। वर्तमान में 50 डीटीएच चैनलों की क्षमता | 0.00 | 0.00 | | | | | डीटीएच सेवा शुरू हो चुकी है |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | एचडीटीवी | यह वह तकनीक है जो उत्कृष्ट पिक्चर तथा वाइड स्क्रीन इमेज के कार्यों में अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इस तकनीक से 35 मी.मी. फिल्म जैसी पिक्चर क्वालिटी मिलती है। यह तकनीक डिजिटल सराउंडिंग साउंड भी उपलब्ध कराती है। एचडीटीवी फिल्ड प्रोडक्शन के लिए प्रायोगिक परियोजना का कार्य चालू है। | 0.40 | 0.19 | | प्रायोगिक योजना एडीटीवी फार्मेट में निर्माण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। | | | प्रायोगिक परियोजना पूरी |
| 6. | दसवीं योजना की अन्य अनुमोदित योजना | | 25.00 | 10.92 | | | | | |
| क. | स्टाफ के लिए आवास, बुनियादी ढांचे तथा सुरक्षा में वृद्धि। | स्टाफ के लिए आवास सुविधा का प्रावधान। बुनियादी ढांचे में वृद्धि/विभिन्न स्टेशनों पर सुरक्षा को मजबूत करना। | | | 4 मेट्रो शहरों में स्टाफ के लिए आवासों का निर्माण।<br><br>11 गैर मेट्रो शहरों में स्टाफ के लिए आवासों का निर्माण। | चार स्थानों पर मैट्रों शहरों में स्टॉफ कवार्टरों का निर्माण और गैर मैट्रों में प्रगति | बंगलुरु, पटना और संबलपुर में स्टॉफ कवार्टरों का निर्माण पूरा- तीसरी तिमाही | एआईआर द्वारा परियोजना की निगरानी<br><br>नौ स्थानों पर स्टॉफ क्वार्टर बना लिए गए है। पटना और संबलपुर में प्रगति।<br>सेबलपुर मे 16 में से 12 कवार्टर बन गए हैं | पटना एसक्यू को संशोधित पीई को मंजूरी |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ख) ट्रांस्मीटर से संबंधित योजनाएं | स्थलीय कवरेज में सुधार | | | आटोमोड एलपीटी 50 | स्थलीय प्रसारण तथा कवरेज क्षेत्र की गुणवत्ता में सुधार। | पहली तिमाही में एलपीटी की आपूर्ति। दूसरी और तीसरी तिमाही में एलपीटी का संस्थापन | आठ ऑटो मोड एलपीटी चालू, 22 अतिरिक्त ऑटोमोड एलपीटी का संस्थापन पूरा। 50 अतिरक्ति ऑटोमोड एलपीटीकी खरीद के लिए निविदाएं खोली गई, तकनीकी मूल्याकंन पूरा। | टेंडर प्रक्रियाधीन |
| | **नई योजनाएं** | | | | | | | | |
| 1. | ट्रांसमीटर का डिजीटलीकरण, आधुनिकीकरण, ट्रांसमीटर उपकरणों की वृद्धि तथा नये उपकरण लगाना। | | 20.00 | 1.23 | | | | | |
| क. | ट्रांसमीटर का डिजिटलीकरण | स्थलीय ट्रांसमिशन का डिजिटलीकरण | | | 19 डिजिटल एचपीटी | स्थलीय ट्रांसमिशन का डिजिटलीकरण की प्रक्रिया शुरु | आर्डर, आपूर्ति और स्थापन कार्य जरुरी | 19 डिजिटल ट्रांसमीटरों की खरीद के लिए निविदाएं आमंतित की गई, 15 स्थानों पर टॉवर की मजबूती का कार्य | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ख. | ट्रांसमीटर उपकरणों का आधुनिकीकरण, वृद्धि तथा दूसरे उपकरण लगाना। | ट्रांसमीटर उपकरणों का आधुनिकीकरण, वृद्धि तथा तकनीक पुरानी हो जाने और उपकरण के पुराने पड़ जाने के कारण नये उपकरण लगाना। | | | | | स्थलीय ट्रांसमिशन की गुणवत्ता तथा कवरेज में सुधार। | | फरवरी 2011 में स्कीम मंजूर |
| 2. | **स्टूडियो डिजीटलीकरण : आधुनिकीकरण, वृद्धि, स्टूडियो/ ओबी उपकरणों का प्रतिस्थापन** | | **80.00** | **25.53** | | | | | |
| क. | स्टूडियो का डिजीटलीकरण | निर्माण, पोस्ट प्रोडक्शन, संपादन तथा अभिलेख सुविधाओं का पूर्ण डिजीटलीकरण। | | | छोटे केंद्रों पर 31 स्टूडियो का आंशिक से लेकर पूर्ण डिजिटलीकरण तथा आठ केंद्रों का पूर्ण डिजिटलीकरण। | उत्पादन सुविधाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण। | चरणबद्ध ढंग से काम करना है | 26 उपकरणों के लिए निविदा आमंतण प्रक्रियाधीन है। एक उपकरण की आपूर्ति | |
| ख. | डिजिटलीकरण, वृद्धि तथा स्टूडियो उपकरणों का प्रतिस्थापन | निर्माण संबंधी उपकरणों का आधुनिकीकरण, वृद्धि तथा प्रतिस्थापन और इसके साथ डिजिटल काउंटर पार्ट को भी तकनीकी रूप से उपयुक्त पाया गया है। | | | सभी छोटे तथा 66 बड़े केंद्रों पर निर्माण, पोस्ट प्रोडेक्शन, आडियो, लाइटिंग तथा विद्युत आपूर्ति में वृद्धि। | तकनीकी गुणवत्ता में वृद्धि। | चरणबद्ध ढंग से काम करना है | | स्कीम फरवरी 2011 में मंजूर |
| 3. | **डीटीएच : आधुनिकीकरण, वृद्धि, उपग्रह प्रसारण उपकरणों का प्रतिस्थापन** | | **20.00** | **0.41** | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क. | डीटीएच | हाइब्रिड मॉडल के साथ डीटीएच पर चैनलों की संख्या 59 से बढ़ाकर 97 करना (फ्री-टू-एयर चैनल तथा पेड चैनल) | | | डीटीएच प्लेटफॉर्म का उन्नयन | | | | प्रसारभारती ने 97 से 150 चैनलों ोक डीटीएच पर लाने को मंजूरी दी |
| ख. | उपग्रह प्रसारण उपकरणों का डिजिटलीकरण, वृद्धि तथा प्रतिस्थापन | पुराने हो चुके उपग्रह उपकरणों का आधुनिकीकरण, वृद्धि तथा नये डिजिटल उपकरणों द्वारा प्रतिस्थापन, समाचार जुटाने की सुविधा में वृद्धि। | | | 10 अर्थ स्टेशन का उन्नयन | 11 वीं योजना में चरणबद्ध ढंग से काम किया जाएगा। | 11 वीं योजना में चरणबद्ध ढंग से काम किया जाएगा। | | |
| 4. | **एचडीटीवी** | एचडीटीवी प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन तथा प्रसारण सुविधा | 29.00 | 10.80 | | एचडी फारमेट में प्रोडक्शन अपलिंकिंग और क्षेत्रीय प्रसारण | उपकरणों के लिए आर्डर | टेंडर मूल्यांकन प्रक्रिया में | |
| | | | | | दिल्ली, मुंबई में एचडीटीवी प्रोडक्शन सुविधा<br><br>दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के लिए पोस्ट प्रोडक्शन सुविधा<br><br>दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई के लिए फील्ड प्रोडक्शन सुविधा<br><br>दिल्ली में फ्लाई अवे प्रोडक्शन सेट अप | | पहली तिमाही में कुछ उपकरणों के लिए आर्डर<br><br>पहली तिमाही में कुछ उपकरण की आपूर्ति। चौथी तिमाही में आंशिक उपकरण की आपूर्ति।<br><br>चौथी तिमाही में उपकरण की आंशिक आपूर्ति। पहली तिमाही में आंशिक उपकरण का आदेश<br><br>पहली तिमाही में उपकरणों के लिए ऑर्डर दिया | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | **स्टॉफ के लिए आवास और अन्य विविध योजना** | स्टाफ के लिए आवास सुविधा का प्रावधान विभिन्न स्टेशनों पर बुनियादी ढांचे में वृद्धि और सुरक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण | **15.00** | **6.84** | 7 स्थानों पर स्टाफ क्वार्टर 22 स्थानों पर गेस्टहाउस 10 स्थानों पर कम्यूनिटी सेंटर, 17 स्थानों पर डीएमसी भवन 10 स्थानों पर एलपीटी भवन डीडी भवन, काम्प्लैक्स में टावर सी। | स्टाफ क्वार्टर, गेस्टहाउस, कम्यूनिटी सेंटर, डीएमसी भवन, एलपीटी भवन, जोनल ऑफिस के भवन, टावर सी भवन का निर्माण | चरणबद्ध ढंग से काम सौंपा गया। एलपीटी भवन का निर्माण पूरा और चार डीएमसी भवन का निर्माण चौथी तिमाही में पूरा | | |
| 6. | **सॉफटवेयर अधिग्रहण और निर्माण** | इन-हाउस निर्माण | **1.00** | **47.78** | | | | | |
| | **कुल** | | **271.40** | **160.24** | | | | | |
| | | **राजस्व** | **74.89** | **105.19** | | | | | |
| | | **पूंजी** | **196.51** | **55.05** | | | | | |

# अध्याय-5

## वित्तीय समीक्षा

## 2009-2010

(हजार रुपये में)

| मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि | बजट अनुमान 2009-2010 | | | संशोधित अनुमान 2009-2010 | | | वास्तविक 2009-2010 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल |
| *राजस्व खंड* | | | | | | | | | |
| **प्रमुख शीर्ष '2251' - सचिवालय सामाजिक सेवाएं** | | | | | | | | | |
| 1. मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित) | **135000** | **394900** | **529900** | **130400** | **380100** | **510500** | **117487** | **367730** | **485217** |
| **प्रमुख शीर्ष - '2205' - सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का कला और संस्कृति से संबंधित प्रमाणन** | | | | | | | | | |
| 2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड | 13500 | 56000 | 69500 | 7000 | 55300 | 62300 | 6208 | 50927 | 57135 |
| 3. फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 1875 | 1875 |
| **कुल प्रमुख शीर्ष '2205'** | **13500** | **58000** | **71500** | **7000** | **57300** | **64300** | **6208** | **52802** | **59010** |
| **प्रमुख शीर्ष - '2220' - सूचना, फिल्म और प्रचार** | | | | | | | | | |
| 4. फिल्म प्रभाग | 63000 | 378900 | 441900 | 68000 | 360600 | 428600 | 70130 | 354523 | 424653 |
| 5. फिल्म समारोह निदेशालय | 42700 | 75700 | 118400 | 42700 | 97200 | 139900 | 40518 | 96479 | 136997 |
| 6. भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार | 40000 | 25200 | 65200 | 70000 | 31000 | 101000 | 69988 | 29472 | 99460 |
| 7. सत्यजीत रे फिल्म और टेली. सं., कोलकाता का अनुदान सहायता | 70000 | 60000 | 130000 | 70000 | 60000 | 130000 | 42500 | 60000 | 102500 |
| 8. बाल फिल्म समिति को अनुदान सहायता | 40000 | 11200 | 51200 | 40000 | 17500 | 57500 | 40000 | 17500 | 57500 |
| 9 भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को अनुदान सहायता | 60000 | 95000 | 155000 | 95000 | 129400 | 224400 | 93500 | 129400 | 222900 |
| 10. फिल्म सोसायटी को अनुदान सहायता | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद | 0 | 48000 | 48000 | 0 | 28700 | 28700 | 0 | 26793 | 26793 |
| 12. गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग | 11800 | 20000 | 31800 | 3000 | 19700 | 22700 | 1193 | 18216 | 19409 |
| 13. आईआईएमसी को अनुदान सहायता | 7000 | 50000 | 57000 | 7000 | 78500 | 85500 | 2000 | 78500 | 80500 |
| 14. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय | 268800 | 648700 | 917500 | 368800 | 670000 | 1038800 | 368130 | 672138 | 1040268 |
| 15. पत्र सूचना कार्यालय | 190300 | 342200 | 532500 | 190300 | 372600 | 562900 | 175558 | 369207 | 544765 |
| 16. भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहायता | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 45600 | 45600 | 0 | 45600 | 45600 |
| 17. पीटीआई के ऋण पर ब्याज के बदले रियायत | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 19. पत्रकार कल्याण कोष में हस्तांतरण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय | 4900 | 412700 | 417600 | 4900 | 406600 | 411500 | 4168 | 411120 | 415288 |
| 21. गीत एवं नाटक प्रभाग | 40000 | 200200 | 240200 | 40000 | 222500 | 262500 | 43496 | 228331 | 271827 |
| 22. प्रकाशन विभाग | 1900 | 241400 | 243300 | 1900 | 246900 | 248800 | 1649 | 233964 | 235613 |

(हजार रुपये में)

| मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि | बजट अनुमान 2009-2010 | | | संशोधित अनुमान 2009-2010 | | | वास्तविक 2009-2010 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल |
| 23. रोजगार समाचार | 500 | 285900 | 286400 | 500 | 231900 | 232400 | 482 | 226959 | 227441 |
| 24. भारत का समाचारपत्र पंजीयक | 1700 | 39100 | 40800 | 1700 | 38600 | 40300 | 1578 | 36615 | 38193 |
| 25. फोटो प्रभाग | 7000 | 33500 | 40500 | 21000 | 38000 | 59000 | 20947 | 37939 | 58886 |
| 26. संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1370 | 1370 |
| 27. एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के लिए योगदान | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 1780 | 1780 |
| **कुल : प्रमुख शीर्ष '2220'** | **849600** | **3006200** | **3855800** | **1024800** | **3098900** | **4123700** | **975837** | **3075906** | **4051743** |
| **कुल : प्रमुख शीर्ष 2251, 2205 और 2220** | **998100** | **3459100** | **4457200** | **1162200** | **3536300** | **4698500** | **1099532** | **3496438** | **4595970** |

(हजार रुपये में)

| मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि | बजट अनुमान 2009-2010 | | | संशोधित अनुमान 2009-2010 | | | वास्तविक 2009-2010 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल |
| **प्रसारण ( प्रमुख शीर्ष-2221 )** | | | | | | | | | |
| **ध्वनि प्रसारण ( उप प्रमुख शीर्ष )** | | | | | | | | | |
| **निर्देशन और प्रशासन ( लघु शीर्ष )** | | | | | | | | | |
| वेतन | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| **टेलीविजन ( उप प्रमुख शीर्ष )** | | | | | | | | | |
| वेतन | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| **सामान्य ( उप प्रमुख शीर्ष )** | | | | | | | | | |
| **प्रसार भारती ( लघु शीर्ष )** | | | | | | | | | |
| अनुदान सहायता | 2131900 | 14221400 | 16353300 | 1754600 | 12464200 | 14218800 | 1935000 | 12472150 | 14407150 |
| **कुल-प्रसारण** | **2132100** | **14221600** | **16353700** | **1754800** | **12464400** | **14219200** | **1935000** | **12472150** | **14407150** |
| **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के फायदे के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र अन्य व्यय योजना** | | | | | | | | | |
| एकमुश्त प्रावधान (प्रमुख शीर्ष-2552) | 389700 | 0 | 389700 | 249700 | 0 | 249700 | 0 | 0 | 0 |
| **कुल-राजस्व खंड** | **3519900** | **17680700** | **21200600** | **3166700** | **16000700** | **19167400** | **3034532** | **15968588** | **19003120** |

(हजार रुपये में)

| मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि | बजट अनुमान 2009-2010 | | | संशोधित अनुमान 2009-2010 | | | वास्तविक 2009-2010 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल |
| **पूंजी खंड** | | | | | | | | | |
| 1. फिल्म प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. पत्र सूचना कार्यालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 8500 | 0 | 8500 | 8500 | 0 | 8500 | 9450 | 0 | 9450 |
| 4. गीत एवं नाटक प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 468 | 0 | 468 |
| 5. फोटो प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. मुख्य सचिवालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. भारतीय जनसंचार संस्थान हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| 8. सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता का अधिग्रहण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 3099 | 0 | 3099 |
| 11. फिल्म समारोह निदेशालय में प्रिंट इकाई के स्तर में सुधार | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 93 | 0 | 93 |
| 12. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र-मशीनरी तथा उपकरण | 18000 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 |
| 13. प्रकाशन विभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 976 | 0 | 976 |
| 14.. रोज़गार समाचार हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| **बी- भवन** | | | | | | | | | |
| 15. फिल्म प्रभाग हेतु बहु-मंजिला भवन - प्रमुख कार्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. चलचित्र संग्रहालय की स्थापना (फिल्म प्रभाग)- प्रमुख कार्य | 125000 | 0 | 125000 | 125000 | 0 | 125000 | 125000 | 0 | 125000 |
| 17. नाइट्रेट वॉल्ट्स/कर्मचारी आवास (एनएफएआई हेतु) निर्माण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. एनएफएआई परिसर हेतु दूसरे चरण का भवन निर्माण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. फिल्म समारोह परिसर - अतिरिक्त और वैकल्पिक - प्रमुख कार्य | 39000 | 0 | 39000 | 39000 | 0 | 39000 | 39000 | 0 | 39000 |
| 20. कोलकाता में फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना, - भूमि अधिग्रहण और भवन निर्माण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. सूचना भवन का निर्माण - प्रमुख कार्य | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 |
| 22. क्षेत्रीय प्रचार हेतु कार्यालय और आवासीय परिसर का निर्माण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. पत्र सूचना कार्यालय हेतु राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र और मिनी मीडिया केन्द्र की स्थापना | 50000 | 0 | 50000 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 |
| 24. भारतीय प्रेस परिषद हेतु भवन का निर्माण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(हजार रुपये में)

| मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि | बजट अनुमान 2009-2010 | | | संशोधित अनुमान 2009-2010 | | | वास्तविक 2009-2010 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल |
| 25. आईआईएमसी हेतु भवन निर्माण तथा आवास परियोजना | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 1750 | 0 | 1750 |
| 26. निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के लिए भवन और टावर | 32000 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 32000 | 10889 | 0 | 10889 |
| 27. मास मीडिया संस्थान की स्थापना | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. इलेक्ट्रोनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 |
| **निवेश** | | | | | | | | | |
| राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| **कुल - पूंजी खंड प्रमुख शीर्ष '4220'** | **411300** | **0** | **411300** | **401300** | **0** | **401300** | **350825** | **0** | 350825 |
| **सूचना और प्रचार हेतु ऋण ( प्रमुख शीर्ष - 6220 )** | | | | | | | | | |
| फिल्म (उप प्रमुख शीर्ष) | | | | | | | | | |
| सार्वजनिक क्षेत्र और अधीन उपक्रमों के लिए ऋण | | | | | | | | | |
| **( लघु शीर्ष )** | | | | | | | | | |
| राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम | | | | | | | | | |
| ऋण और अग्रिम राशि | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **प्रसारण के लिए ऋण ( प्रमुख शीर्ष - 6221 )** | | | | | | | | | |
| **सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य अधीन उपक्रमों के लिए ऋण** | | | | | | | | | |
| प्रसार भारती | | | | | | | | | |
| ऋण और अग्रिम राशि | 3558400 | 0 | 3558400 | 1302100 | 0 | 1302100 | 1348500 | 0 | 1348500 |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत | | | | | | | | | |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना (प्रमुख शीर्ष - 4552) | | | | | | | | | |
| क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के लिए उपकरणों का अधिग्रहण | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत | | | | | | | | | |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना (प्रमुख शीर्ष - 6552) | | | | | | | | | |
| प्रसार भारती | 509500 | 0 | 509500 | 199000 | 0 | 199000 | 0 | 0 | 0 |
| **कुल - पूंजी खंड** | **4480100** | **0** | **4480100** | **1903300** | **0** | **1903300** | **1699325** | **0** | **1699325** |
| **कुल - मांग संख्या - 59** | **8000000** | **17680700** | **25680700** | **5070000** | **16000700** | **21070700** | **4733857** | **15968588** | **20702445** |

# वित्तीय समीक्षा
# 2010-2011

(हजार रुपये में)

| मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि | बजट अनुमान 2010-2011 | | | संशोधित अनुमान 2010-2011 | | | वास्तविक 2010-2011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल |
| *राजस्व खंड* | | | | | | | | | |
| **प्रमुख शीर्ष '2251' - सचिवालय सामाजिक सेवाएं** | | | | | | | | | |
| 1. मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित) | **170100** | **380700** | **550800** | **153100** | **369300** | **522400** | **191282** | **343335** | **534617** |
| **प्रमुख शीर्ष - '2205' - सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का कला और संस्कृति से संबंधित प्रमाणन** | | | | | | | | | |
| 2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड | 13000 | 55000 | 68000 | 13000 | 58300 | 71300 | 8493 | 49339 | 57832 |
| 3. फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 988 | 988 |
| **कुल प्रमुख शीर्ष '2205'** | **13000** | **57000** | **70000** | **13000** | **60300** | **73300** | **8493** | **50327** | **58820** |
| **प्रमुख शीर्ष - '2220' - सूचना, फिल्म और प्रचार** | | | | | | | | | |
| 4. फिल्म प्रभाग | 56000 | 380000 | 436000 | 56000 | 373400 | 429400 | 60538 | 318618 | 379156 |
| 5. फिल्म समारोह निदेशालय | 45000 | 79200 | 124200 | 45000 | 86400 | 131400 | 48850 | 87970 | 136820 |
| 6. भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार | 50000 | 31500 | 81500 | 89000 | 38500 | 127500 | 99864 | 31651 | 131515 |
| 7. सत्यजीत रे फिल्म और टेली. सं., कोलकाता का अनुदान सहायता | 70000 | 60000 | 130000 | 70000 | 61800 | 131800 | 70000 | 61800 | 131800 |
| 8. बाल फिल्म समिति को अनुदान सहायता | 40000 | 14300 | 54300 | 40000 | 15300 | 55300 | 40000 | 15300 | 55300 |
| 9. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को अनुदान सहायता | 80000 | 125000 | 205000 | 72000 | 144400 | 216400 | 70000 | 144400 | 214400 |
| 10. फिल्म सोसायटी को अनुदान सहायता | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद | 21800 | 41000 | 62800 | 0 | 43600 | 43600 | 0 | 37739 | 37739 |
| 12. गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग | 2500 | 19700 | 22200 | 1000 | 18900 | 19900 | 0 | 16273 | 16273 |
| 13. आईआईएमसी को अनुदान सहायता | 7000 | 67000 | 74000 | 7000 | 71700 | 78700 | 7000 | 71700 | 78700 |
| 14. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय | 445000 | 622800 | 1067800 | 445000 | 643700 | 1088700 | 494767 | 666217 | 1160984 |
| 15. पत्र सूचना कार्यालय | 345000 | 368800 | 713800 | 340000 | 381700 | 721700 | 239144 | 350142 | 589286 |
| 16. भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहायता | 0 | 42100 | 42100 | 0 | 48900 | 48900 | 0 | 48900 | 48900 |
| 17. पीटीआई के ऋण पर ब्याज के बदले रियायत | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 19. पत्रकार कल्याण कोष में हस्तांतरण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय | 4500 | 357200 | 361700 | 4500 | 411400 | 415900 | 4670 | 396770 | 401440 |
| 21. गीत एवं नाटक प्रभाग | 47200 | 202400 | 249600 | 47200 | 212400 | 259600 | 59345 | 218317 | 277662 |
| 22. प्रकाशन विभाग | 1000 | 210400 | 211400 | 1000 | 215900 | 216900 | 982 | 233808 | 234790 |

(हजार रुपये में)

| मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि | बजट अनुमान 2010-2011 | | | संशोधित अनुमान 2010-2011 | | | वास्तविक 2010-2011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल |
| 23. रोजगार समाचार | 600 | 284600 | 285200 | 600 | 258100 | 258700 | 596 | 256011 | 256607 |
| 24. भारत का समाचारपत्र पंजीयक | 1700 | 35900 | 37600 | 1700 | 37700 | 39400 | 1696 | 36350 | 38046 |
| 25. फोटो प्रभाग | 25300 | 35500 | 60800 | 17800 | 35500 | 53300 | 6321 | 34785 | 41106 |
| 26. संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान | 0 | 1600 | 1600 | 0<br>0 | 26600 | 26600 | 0 | 25000 | 25000 |
| 27. एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के लिए योगदान | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 1754 | 1754 |
| **कुल : प्रमुख शीर्ष '2220'** | **1242600** | **2981100** | **4223700** | **1237800** | **3128000** | **4365800** | **1203773** | **3053505** | **4257278** |
| **कुल : प्रमुख शीर्ष 2251, 2205 और 2220** | **1425700** | **3418800** | **4844500** | **1403900** | **3557600** | **4961500** | **1403548** | **3447167** | **4850715** |

(हजार रुपये में)

| मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि | बजट अनुमान 2010-2011 | | | संशोधित अनुमान 2010-2011 | | | वास्तविक 2010-2011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल |
| **प्रसारण (प्रमुख शीर्ष-2221)** | | | | | | | | | |
| **ध्वनि प्रसारण (उप प्रमुख शीर्ष)** | | | | | | | | | |
| **निर्देशन और प्रशासन (लघु शीर्ष)** | | | | | | | | | |
| वेतन | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| **टेलीविजन (उप प्रमुख शीर्ष)** | | | | | | | | | |
| वेतन | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| **सामान्य (उप प्रमुख शीर्ष)** | | | | | | | | | |
| **प्रसार भारती (लघु शीर्ष)** | | | | | | | | | |
| अनुदान सहायता | 3447500 | 14123500 | 17571000 | 1578300 | 14123500 | 15701800 | 1548800 | 14123500 | 15672300 |
| **कुल-प्रसारण** | **3447700** | **14123700** | **17571400** | **1578500** | **14123700** | 15702200 | **1548800** | **14123500** | **15672300** |
| **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के फायदे के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र अन्य व्यय योजना** | | | | | | | | | |
| एकमुश्त प्रावधान (प्रमुख शीर्ष-2552) | 281200 | 0 | 281200 | 281200 | 0 | 281200 | 0 | 0 | 0 |
| **कुल-राजस्व खंड** | **5154600** | **17542500** | **22697100** | **3263600** | **17681300** | **20944900** | **2952348** | **17570667** | **20523015** |

(हजार रुपये में)

| मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि | बजट अनुमान 2010-2011 | | | संशोधित अनुमान 2010-2011 | | | वास्तविक 2010-2011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल |
| **पूंजी खंड** | | | | | | | | | |
| 1. फिल्म प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. पत्र सूचना कार्यालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 4849 | 0 | 4849 |
| 4. गीत एवं नाटक प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 351 | 0 | 351 |
| 5. फोटो प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. मुख्य सचिवालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. भारतीय जनसंचार संस्थान हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
| 8. सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता का अधिग्रहण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 9000 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 7548 | 0 | 7548 |
| 11. फिल्म समारोह निदेशालय में प्रिंट इकाई के स्तर में सुधार | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 9948 | 0 | 9948 |
| 12. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र-मशीनरी तथा उपकरण | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 16600 | 0 | 16600 |
| 13. प्रकाशन विभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 1000 | 0 | 1000 | 1600 | 0 | 1600 | 1380 | 0 | 1380 |
| 14.. रोज़गार समाचार हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **बी- भवन** | | | | | | | | | |
| 15. फिल्म प्रभाग हेतु बहु-मंजिला भवन - प्रमुख कार्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. चलचित्र संग्रहालय की स्थापना (फिल्म प्रभाग)- प्रमुख कार्य | 290000 | 0 | 290000 | 340000 | 0 | 340000 | 340000 | 0 | 340000 |
| 17. नाइट्रेट वॉल्ट्स/कर्मचारी आवास (एनएफएआई हेतु) निर्माण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. एनएफएआई परिसर हेतु दूसरे चरण का भवन निर्माण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. फिल्म समारोह परिसर - अतिरिक्त और वैकल्पिक - प्रमुख कार्य | 40000 | 0 | 40000 | 64200 | 0 | 64200 | 64195 | 0 | 64195 |
| 20. कोलकाता में फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना, - भूमि अधिग्रहण और भवन निर्माण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. सूचना भवन का निर्माण - प्रमुख कार्य | 100000 | 0 | 100000 | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 180000 |
| 22. क्षेत्रीय प्रचार हेतु कार्यालय और आवासीय परिसर का निर्माण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. पत्र सूचना कार्यालय हेतु राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र और मिनी मीडिया केन्द्र की स्थापना | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 |

(हजार रुपये में)

| मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि | बजट अनुमान 2010-2011 | | | संशोधित अनुमान 2010-2011 | | | वास्तविक 2010-2011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल |
| 24. भारतीय प्रेस परिषद हेतु भवन का निर्माण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. आईआईएमसी हेतु भवन निर्माण तथा आवास परियोजना | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 26. निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के लिए भवन और टावर | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 27. मास मीडिया संस्थान की स्थापना | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. इलेक्ट्रोनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 |
| **निवेश** | | | | | | | | | |
| राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 |
| **कुल - पूंजी खंड प्रमुख शीर्ष '4220'** | **655600** | **0** | 655600 | **832200** | **0** | 832200 | **786671** | **0** | **786671** |

| मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि | बजट अनुमान 2010-2011 | | | संशोधित अनुमान 2010-2011 | | | वास्तविक 2010-2011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल |
| **सूचना और प्रचार हेतु ऋण (प्रमुख शीर्ष - 6220)** | | | | | | | | | |
| फिल्म (उप प्रमुख शीर्ष) | | | | | | | | | |
| सार्वजनिक क्षेत्र और अधीन उपक्रमों के लिए ऋण | | | | | | | | | |
| **(लघु शीर्ष)** | | | | | | | | | |
| राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम | | | | | | | | | |
| ऋण और अग्रिम राशि | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **प्रसारण के लिए ऋण (प्रमुख शीर्ष - 6221)** | | | | | | | | | |
| **सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य अधीन उपक्रमों के लिए ऋण** | | | | | | | | | |
| प्रसार भारती | | | | | | | | | |
| ऋण और अग्रिम राशि | 2274800 | 0 | 2274800 | 3896400 | 0 | 3896400 | 4159200 | 0 | 4159200 |

(हजार रुपये में)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत | | | | | | | | | |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना (प्रमुख शीर्ष - 4552) | | | | | | | | | |
| क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के लिए उपकरणों का अधिग्रहण | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत | | | | | | | | | |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना (प्रमुख शीर्ष - 6552) | | | | | | | | | |
| प्रसार भारती | 410000 | 0 | 410000 | 502800 | 0 | 502800 | 0 | 0 | 0 |
| **कुल - पूंजी खंड** | **3345400** | **0** | **3345400** | **5236400** | **0** | **5236400** | **4945871** | **0** | **4945871** |
| **कुल - मांग संख्या - 59** | **8500000** | **17542500** | **26042500** | **8500000** | **17681300** | **26181300** | **7898219** | **17570667** | **25468886** |

# वित्तीय समीक्षा

## 2011-2012

(हजार रुपये में)

| मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि | बजट अनुमान 2011-2012 | | | संशोधित अनुमान 2011-2012 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | Total | योजना | गैर-योजना | कुल |
| *राजस्व खंड* | | | | | | |
| **प्रमुख शीर्ष '2251' - सचिवालय सामाजिक सेवाएं** | | | | | | |
| 1. मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित) | **348400** | **406100** | **754500** | **261900** | **377900** | **639800** |
| **प्रमुख शीर्ष - '2205' - सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का कला और संस्कृति से संबंधित प्रमाणन** | | | | | | |
| 2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड | 12000 | 63000 | 75000 | 12000 | 61000 | 73000 |
| 3. फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 1000 | 1000 |
| **कुल प्रमुख शीर्ष '2205'** | **12000** | **65000** | **77000** | **12000** | **62000** | **74000** |
| **प्रमुख शीर्ष - '2220' - सूचना, फिल्म और प्रचार** | | | | | | |
| 4. फिल्म प्रभाग | 108000 | 382800 | 490800 | 108000 | 334900 | 452900 |
| 5. फिल्म समारोह निदेशालय | 74000 | 92000 | 166000 | 74000 | 93800 | 167800 |
| 6. भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार | 200000 | 46800 | 246800 | 200000 | 40500 | 240500 |
| 7. सत्यजीत रे फिल्म और टेली. सं., कोलकाता का अनुदान सहायता | 70000 | 70000 | 140000 | 88000 | 73900 | 161900 |
| 8. बाल फिल्म समिति को अनुदान सहायता | 63000 | 15500 | 78500 | 63000 | 15500 | 78500 |
| 9. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को अनुदान सहायता | 113200 | 135000 | 128200 | 95200 | 145000 | 240200 |
| 10. फिल्म सोसायटी को अनुदान सहायता | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 42800 | 42800 |
| 12. गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग | 2500 | 21700 | 24200 | 2500 | 17400 | 19900 |
| 13. आईआईएमसी को अनुदान सहायता | 10500 | 71700 | 82200 | 6500 | 71700 | 78200 |
| 14. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय | 560000 | 673300 | 1233300 | 887900 | 653300 | 1541200 |
| 15. पत्र सूचना कार्यालय | 127500 | 412300 | 539800 | 127500 | 363300 | 490800 |
| 16. भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहायता | 0 | 53200 | 53200 | 0 | 53200 | 53200 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. पीटीआई के ऋण पर ब्याज के बदले रियायत | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| 19. पत्रकार कल्याण कोष में हस्तांतरण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय | 6900 | 413500 | 420400 | 6900 | 404100 | 411000 |
| 21. गीत एवं नाटक प्रभाग | 48000 | 217400 | 265400 | 48000 | 227400 | 275400 |
| 22. प्रकाशन विभाग | 1000 | 222300 | 223300 | 1000 | 219600 | 220600 |
| 23. रोजगार समाचार | 500 | 272900 | 273400 | 500 | 267600 | 268100 |
| 24. भारत का समाचारपत्र पंजीयक | 1700 | 43500 | 45200 | 1700 | 40500 | 42200 |
| 25. फोटो प्रभाग | 20800 | 39600 | 60400 | 17300 | 39400 | 56700 |
| 26. संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान | 0 | 1700 | 1700<br>0 | 0<br>0 | 1700 | 1700 |
| 27. एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के लिए योगदान | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 |
| **कुल : प्रमुख शीर्ष '2220'** | **1407600** | **3232300** | **4639900** | **1728000** | **3117700** | **4845700** |
| **कुल : प्रमुख शीर्ष 2251, 2205 और 2220** | **1768000** | **3703400** | **5471400** | **2001900** | **3557600** | **5559500** |

(हजार रुपये में)

| मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि | बजट अनुमान 2011-2012 | | | संशोधित अनुमान 2011-2012 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | Total | योजना | गैर-योजना | कुल |
| **प्रसारण ( प्रमुख शीर्ष-2221 ))** | | | | | | |
| **ध्वनि प्रसारण ( उप प्रमुख शीर्ष )** | | | | | | |
| **निर्देशन और प्रशासन ( लघु शीर्ष )** | | | | | | |
| वेतन | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 |
| **टेलीविजन ( उप प्रमुख शीर्ष )** | | | | | | |
| वेतन | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 |
| **सामान्य ( उप प्रमुख शीर्ष )** | | | | | | |
| **प्रसार भारती ( लघु शीर्ष )** | | | | | | |
| अनुदान सहायता | 716200 | 14123500 | 14839700 | 1116200 | 14623500 | 15739700 |
| **कुल-प्रसारण** | **716400** | **14123700** | **14840100** | **1116400** | **14623700** | 15740100 |
| **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के फायदे के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र अन्य व्यय योजना** | | | | | | |
| एकमुश्त प्रावधान (प्रमुख शीर्ष-2552) | 250200 | 0 | 250200 | 249700 | 0 | 249700 |
| **कुल-राजस्व खंड** | **2734600** | **17827100** | **20561700** | **3368000** | **18181300** | **21549300** |

(हजार रुपये में)

| मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि | बजट अनुमान 2011-2012 | | संशोधित अनुमान 2011-2012 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल | गैर-योजना | Total | योजना | गैर-योजना | कुल |
| **पूंजी खंड** | | | | | | |
| 1. फिल्म प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. पत्र सूचना कार्यालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 27100 | 0 | 27100 | 17500 | 0 | 17500 |
| 4. गीत एवं नाटक प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 5. फोटो प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. मुख्य सचिवालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. भारतीय जनसंचार संस्थान हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 13000 | 0 | 13000 | 3600 | 0 | 3600 |
| 8. सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता का अधिग्रहण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
| 11. फिल्म समारोह निदेशालय में प्रिंट इकाई के स्तर में सुधार | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
| 12. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र-मशीनरी तथा उपकरण | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| 13. प्रकाशन विभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 8500 | 0 | 8500 | 4400 | 0 | 4400 |
| 14.. रोज़गार समाचार हेतु उपकरण का अधिग्रहण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **बी- भवन** | | 0 | | | | |
| 15. फिल्म प्रभाग हेतु बहु-मंजिला भवन - प्रमुख कार्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. चलचित्र संग्रहालय की स्थापना (फिल्म प्रभाग)- प्रमुख कार्य | 625100 | 0 | 625100 | 480000 | 0 | 480000 |
| 17. नाइट्रेट वॉल्ट्स/कर्मचारी आवास (एनएफएआई हेतु) निर्माण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. एनएफएआई परिसर हेतु दूसरे चरण का भवन निर्माण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. फिल्म समारोह परिसर - अतिरिक्त और वैकल्पिक - प्रमुख कार्य | 12800 | 0 | 12800 | 2800 | 0 | 2800 |
| 20. कोलकाता में फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना, - | | 0 | | | | |
| भूमि अधिग्रहण और भवन निर्माण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. सूचना भवन का निर्माण - प्रमुख कार्य | 362200 | 0 | 362200 | 313000 | 0 | 313000 |
| 22. क्षेत्रीय प्रचार हेतु कार्यालय और आवासीय परिसर का निर्माण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. पत्र सूचना कार्यालय हेतु राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र और मिनी मीडिया केन्द्र की स्थापना | 205000 | 0 | 205000 | 300000 | 0 | 300000 |
| 24. भारतीय प्रेस परिषद हेतु भवन का निर्माण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. आईआईएमसी हेतु भवन निर्माण तथा आवास परियोजना | 168500 | 0 | 168500 | 34800 | 0 | 34800 |
| 26. निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के लिए भवन और टावर | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 27. मास मीडिया संस्थान की स्थापना | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. इलेक्ट्रोनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र | 1800 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 |
| **निवेश**<br>राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| **कुल - पूंजी खंड प्रमुख शीर्ष '4220'** | **1464600** | **0** | 1464600 | **1198600** | **0** | 1198600 |

(हजार रुपये में)

| मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि | बजट अनुमान 2011-2012 | | | संशोधित अनुमान 2011-2012 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | कुल | योजना | गैर-योजना | कुल |
| **सूचना और प्रचार हेतु ऋण ( प्रमुख शीर्ष - 6220 )**<br>फिल्म (उप प्रमुख शीर्ष)<br>सार्वजनिक क्षेत्र और अधीन उपक्रमों के लिए ऋण<br>**( लघु शीर्ष )**<br>राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम<br>ऋण और अग्रिम राशि | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **प्रसारण के लिए ऋण ( प्रमुख शीर्ष - 6221 )**<br>**सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य अधीन उपक्रमों के लिए ऋण**<br>प्रसार भारती<br>ऋण और अग्रिम राशि | 3799700 | 0 | 3799700 | 2755500 | 0 | 2755500 |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत<br>पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना<br>(प्रमुख शीर्ष - 4552) | | | | | | |
| भारतीय जन संचार संस्थान के लिए उपकरणों का अधिग्रहण | 7000 | | 7000 | 3500 | | 3500 |
| क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के लिए उपकरणों का अधिग्रहण | 5000 | 0 | 5000 | 2500 | 0 | 2500 |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत<br>पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना<br>(प्रमुख शीर्ष - 6552)<br>प्रसार भारती | 599100 | 0 | 599100 | 539100 | 0 | 539100 |
| **कुल - पूंजी खंड** | **5875400** | **0** | **5868400** | **4499200** | **0** | **4499200** |
| **कुल - मांग संख्या - 60** | **8610000** | **17827100** | **26430100** | **7867200** | **17681300** | **25548500** |

# वित्तीय समीक्षा
## विषय-शीर्षानुसार वर्गीकरण

(हजार रुपये में)

| विवरण | बजट अनुमान 2009-2010 | | संशोधित अनुमान 2009-2010 | | वास्तविक 2009-2010 | | बजट अनुमान 2010-2011 | | संशोधित अनुमान 2010-2011 | | वास्तविक 2010-2011 | | बजट अनुमान 2011-2012 | | संशोधित अनुमान 2011-2012 | | बजट अनुमान 2012-2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर योजना | योजना | गैर योजना | योजना | गैर योजना | योजना | गैर योजना | योजना | गैर योजना | योजना | गैर योजना | योजना | गैर योजना | योजना | गैर योजना | योजना | गैर योजना |
| ***राजस्व खंड*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| वेतन | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| स्वीकृत | 3450 | 1798750 | 700 | 1841720 | 273 | 1823747 | 3200 | 1681960 | 3200 | 1787300 | 292 | 1720620 | 3000 | 1928800 | 3000 | 1783000 | 10200 | 1925600 |
| भारित | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| मजदूरी | 340 | 36210 | 340 | 20312 | 259 | 19536 | 300 | 5590 | 340 | 4690 | 299 | 3849 | 350 | 5230 | 350 | 5485 | 16300 | 6940 |
| समयोपरि भत्ता | 70 | 8565 | 101 | 7503 | 47 | 6035 | 300 | 8575 | 300 | 8350 | 10 | 5954 | 110 | 8290 | 110 | 5865 | 0 | 6735 |
| चिकित्सा व्यय | 300 | 29495 | 1 | 28690 | 0 | 23081 | 20 | 29565 | 20 | 34585 | 13 | 26900 | 20 | 32415 | 20 | 33770 | 0 | 33065 |
| घरेलू यात्रा व्यय | 6500 | 48980 | 5300 | 47150 | 3885 | 49174 | 6300 | 48550 | 6300 | 55905 | 6042 | 59547 | 12900 | 57355 | 12900 | 58985 | 13800 | 58755 |
| विदेशी यात्रा व्यय | 10200 | 7550 | 10300 | 6795 | 4545 | 4104 | 7600 | 7950 | 7600 | 7400 | 4829 | 3347 | 11600 | 9000 | 11600 | 6395 | 12200 | 9000 |
| कार्यालय व्यय | 59840 | 192240 | 60658 | 190765 | 62226 | 200045 | 52380 | 197370 | 50540 | 215830 | 43335 | 215317 | 62115 | 217050 | 58615 | 213056 | 180900 | 219080 |
| किराया, महसूल और कर | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| स्वीकृत | 1600 | 30830 | 400 | 35215 | 1451 | 30987 | 0 | 39740 | 0 | 40425 | 0 | 36363 | 0 | 41840 | 0 | 52371 | 0 | 46295 |
| भारित | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| प्रकाशन | 0 | 36750 | 0 | 43835 | 0 | 58471 | 0 | 39420 | 0 | 39250 | 0 | 43339 | 0 | 39540 | 0 | 39198 | 600 | 39740 |
| बैंकिंग नकदी लेन-देन कर | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अन्य प्रशासनिक व्यय | 114700 | 15170 | 115900 | 15640 | 111502 | 13577 | 232500 | 16225 | 229200 | 18530 | 149656 | 18535 | 17800 | 19120 | 17800 | 19220 | 19100 | 19620 |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 12600 | 261400 | 12600 | 216400 | 11632 | 191074 | 35100 | 261400 | 17100 | 222400 | 14115 | 209542 | 18500 | 228700 | 18500 | 215400 | 49500 | 223995 |
| पी.ओ.एल. | 900 | 18455 | 1000 | 16735 | 988 | 14128 | 0 | 18455 | 0 | 20000 | 0 | 15357 | 1100 | 20200 | 1100 | 20200 | 0 | 20200 |
| विज्ञापन और प्रचार | 336450 | 497520 | 436600 | 497065 | 427721 | 508851 | 560000 | 497570 | 555000 | 497060 | 583852 | 513580 | 675400 | 497475 | 1003300 | 492325 | 997100 | 495675 |
| लघु कार्य | 0 | 74190 | 0 | 75440 | 0 | 74144 | 0 | 81390 | 0 | 72340 | 0 | 62518 | 5 | 78385 | 5 | 73785 | 0 | 75185 |
| व्यावसायिक सेवाएं | 128300 | 56330 | 123000 | 50110 | 118102 | 45562 | 161200 | 80850 | 146000 | 80900 | 203152 | 73124 | 272400 | 85130 | 230900 | 88255 | 502800 | 88355 |
| सहायता अनुदान | 2308900 | 14473105 | 1976600 | 12795680 | 2128000 | 12803515 | 3644500 | 14432430 | 1802300 | 14466125 | 1770800 | 14466120 | 109000 | 14406314 | 1289200 | 14438264 | 1280300 | 1384586 |
| पूंजी सृजन के लिए अनुदान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893900 | 63111 | 109700 | 545061 | 70000 | 551514 |
| अंशदान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13033325 |
| आर्थिक सहायता | 0 | 3400 | 0 | 3500 | 0 | 3150 | 0 | 3600 | 0 | 28600 | 0 | 26754 | 0 | 3700 | 0 | 3700 | 0 | 3700 |
| एकमुश्त प्रावधान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अन्य प्रभार | 389700 | 2000 | 249700 | 2000 | 0 | 1875 | 281200 | 2000 | 281200 | 2000 | 0 | 988 | 250200 | 2000 | 249700 | 1000 | 210500 | 1700 |
| अंत लेखा अंतरण | 140650 | 57530 | 167900 | 76915 | 163105 | 77060 | 162200 | 57610 | 158500 | 60970 | 174730 | 56376 | 405200 | 62585 | 360200 | 67285 | 245500 | 62985 |
| सूचना और प्रौद्योगिकी | 5400 | 31920 | 5600 | 28930 | 796 | 20472 | 7800 | 31940 | 6000 | 18340 | 1223 | 12536 | 1000 | 20560 | 1000 | 18380 | 1200 | 17550 |
| केंद्रीय अनुश्रवण सेवाएं | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **3519900** | **17680700** | **3166700** | **16000700** | **3034532** | **15968588** | **5154600** | **17542500** | **3263600** | **17681300** | **2952348** | **17570666** | **2734600** | **17827100** | **3368000** | **18181300** | **3610000** | **18323900** |

(हजार रुपये में

| विवरण | 2009-2010 | | 2009-2010 | | 2009-2010 | | 2010-2011 | | 2010-2011 | | 2010-2011 | | 2011-2012 | | 2011-2012 | | 2012-2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर योजना | योजना | गैर योजना | योजना | गैर योजना | योजना | गैर योजना | योजना | गैर योजना | योजना | गैर योजना | योजना | गैर योजना | योजना | गैर योजना | योजना | गैर योजना |
| ऋण प्रसार भारती | 3264000 | 02616600 | 02383100 | 0 3558400 | 01302100 | 01348500 | 02274800 | 03896400 | 03799700 | 0 | | | | | | | | |
| *पूंजी भाग* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| मशीन और उपस्कर | 95300 | 0 43200 | 0 32186 | 0 75500 | 0 96100 | 0 50676 | 0 89100 | 0 66000 | 0171000 | 0 | | | | | | | | |
| मुख्य निर्माण कार्य | 174000 | 0 358000 | 0 350825 | 0 550100 | 0706100 | 0 705995 | 01375500 | 01132500 | 0534000 | 0 | | | | | | | | |
| निवेश | 80000 | 0 100 | 0 o | 0 30000 | 0 30000 | 0 30000 | 0 0 | 0 100 | 0 0 | 0 | | | | | | | | |
| ऋण एवं अग्रिम | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | | | | | | | | |
| ऋण प्रसार भारती | 3264000 | 01302100 | 01348500 | 0 2274800 | 03896400 | 04159200 | 03799700 | 02755500 | 04010000 | 0 | | | | | | | | |
| उत्तर पूर्वी व सिक्किम | 510000 | 0 199900 | 01699325 | 0 415000 | 05236400 | 0 0 | 0611100 | 0545100 | 0725000 | 0 | | | | | | | | |
| के लाभ के लिए | | | | 0 0 | 0 | | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | | | | | | | | |
| **योग** | **4123300** | **0 1903300** | **0 3430836** | **0 3345400** | **0 9965000** | **0 4945871** | **0 5875400** | **0 4499200** | **0 5440000** | **0** | | | | | | | | |
| **कुल योग** | **7643200** | **17680700** | **5070000** | **16000700** | **6465368** | **15968588** | **8500000** | **17542500** | **13228600** | **17681300** | **7898219** | **17570666** | **8610000** | **17827100** | **7867200** | **18181300** | **9050000** | **18323900** |

# वित्तीय समीक्षा
## स्वायत्त संस्थानों के आधार पर वर्गीकरण

(हजार रुपये में)

| | | बजट अनुमान 2009-2010 | | संशोधित अनुमान 2009-2010 | | वास्तविक 2009-2010 | | बजट अनुमान 2010-2011 | | संशोधित अनुमान 2010-2011 | | वास्तविक 2010-2011 | | बजट अनुमान 2011-2012 | | संशोधित अनुमान 2011-2012 | | बजट अनुमान 2012-2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | योजना | गैर योजना | योजना | गैर योजना | योजना | गैर योजना | योजना | गैर योजना | योजना | गैर योजना | योजना | गैर योजना | योजना | गैर योजना | योजना | गैर योजना | योजना | गैर योजना |
| बाल फिल्म समिति | | 40000 | 11200 | 40000 | 17500 | 4000 | 17500 | 40000 | 14300 | 40000 | 15300 | 40000 | 15300 | 40000 | 15500 | 63000 | 15500 | 0 | 15500 |
| भारतीय फिल्म और | (R) | 60000 | 95000 | 95000 | 129400 | 93500 | 129400 | 80000 | 125000 | 72000 | 144400 | 70000 | 144400 | 80000 | 135000 | 95200 | 145000 | 0 | 135000 |
| टेलीविजन संस्थान पुणे | (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
| सत्यजीत रे फिल्म और | (R) | 70000 | 60000 | 70000 | 60000 | 42500 | 60000 | 70000 | 60000 | 70000 | 61800 | 70000 | 61800 | 70000 | 70000 | 88000 | 73900 | 80000 | 70000 |
| टेलीविजन संस्थान कोलकाता | (C) | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 70000 | 0 |
| भारतीय जनसंचार | (R) | 7000 | 50000 | 7000 | 78500 | 2000 | 78500 | 7000 | 67000 | 7000 | 71700 | 7000 | 71700 | 10500 | 71700 | 6500 | 71700 | 0 | 71700 |
| संस्थान | (C) | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 20000 | 0 | 38400 | 0 | 110000 | 0 |
| भारतीय प्रेस परिषद | | 0 | 35000 | 0 | 45600 | 0 | 45600 | 0 | 42100 | 0 | 48900 | 0 | 48900 | 0 | 53200 | 0 | 53200 | 0 | 53200 |
| प्रसार भारती | | 2131900 | 14221400 | 1754600 | 12464200 | 1935000 | 12472150 | 3447500 | 14123500 | 1578300 | 14123500 | 154800 | 14123500 | 716200 | 14123500 | 1116200 | 14623500 | 1119800 | 14623500 |

# उपभोग शेष के समेत विभिन्न निकायों को जारी अनुदान

(लाख रुपये में)

| क्र. सं. | नाम | अवधि में जारी अनुदान | | | | अप्रयुक्त शेष (यदि कोई हो) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009-10 | | 2010-2011 | | 2009-10 | | 2010-2011 | |
| | | योजना | गैर योजना | योजना | गैर योजना | योजना | गैर योजना | योजना | गैर योजना |
| 1. | बाल फिल्म समिति | 400.00 | 175.00 | 400.00 | 175.00 | 2.00 | Nil | 2.00 | Nil |
| 2. | भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे | 935.00 | 1294.00 | 935.00 | 1294.00 | NIL | NIL | NIL | NIL |
| 3. | सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता | 600.00 | 700.00 | 600.00 | 700.00 | 1.64 | NIL | 1.64 | NIL |
| 4. | भारतीय जनसंचार संस्थान | 37.5 | 7.85 | 37.5 | 7.85 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.14 |
| 5. | भारतीय प्रेस परिषद | Nil | 4.56 | Nil | 4.56 | Nil | 2.21 | Nil | 2.21 |
| 6. | प्रसार भारती | 32835.00 | 124721.00 | 32835.00 | 124721.00 | 11.00 | Nil | 11.00 | Nil |

# अध्याय-6

## स्वायत्तशासी निकायों की समीक्षा और प्रदर्शन

## सूचना क्षेत्र

## भारतीय जन संचार संस्थान

जन संचार के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षण और अनुसंधान के मामले में आईआईएमसी का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा क्योंकि आईआईएमसी ने अपने पाठ्यक्रम के संचालन के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों, सेना और अर्द्ध सैनिक बलों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया। आईआईएमसी ने मंत्रालयों और सरकारी विभागों की ओर से शुरू की गयी अनुसंधान परियोजनाओं के संबंध में भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। ओबीसी आरक्षण के तीसरे और अंतिम चरण को 2010-11 के दौरान पूरा किया गया है। आईआईएमसी के विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में लगभग 60 % छात्राएं हैं।

आईआईएमसी ने योजना स्कीम के तहत अपने को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नयन की भी समय पर कार्रवाई की है। इस दिशा में, आईआईएमसी ने, पहले चरण में, मीडिया उद्योग की जरूरत को पूरा करने के लिए पत्रकारिता एवं जनसंचार के एक वर्ष के पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को मास्टर डिग्री के समतुल्य बनाने के लिए दो वर्ष के एडवांस पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में बदलने और जम्मू व कश्मीर, मिजोरम, महाराष्ट्र (विदर्भ) और केरल में चार नई शाखाएं खोलने की योजना बनाई है। दो क्षेत्रीय केंद्र आइजोल (मिजोरम) और अमरावती (महाराष्ट्र) में अस्थायी परिसरों ने कार्य शुरु कर दिया है।

## भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद विधि द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्था है। मंत्रालय में व्यय सुधार समिति की अनुशंसाओं पर विचार करते समय यह महसूस किया गया कि भारतीय प्रेस परिषद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जो कि प्रेस की एक स्वनियामक संस्था है, ऐसी समीक्षा न तो उपयुक्त होगी और ना ही उसके कार्यों की समीक्षा करने के लिए कोई अन्य निगरानी संस्था उपलब्ध है। उक्त निर्णय की जानकारी वित्त मंत्रालय को भी दे दी गयी।

तथापि, प्रेस परिषद के कार्य की समीक्षा संसद द्वारा सीधे उसके समक्ष प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट के द्वारा की जाती है।

# फिल्म क्षेत्र

## बाल फिल्म समिति, भारत

विगत पांच वर्षों से कई फिल्मों का निर्माण और बाल दर्शकों तक पहुंच निम्नलिखित हैं :

**2005-06**

**निर्माण :** 4 फीचर फिल्म पूरी की

**विपणन :** 7026 शो का आयोजन 27 लाख बच्चे दर्शक

**व्यय :** 448.68 लाख रुपये का व्यय

**2006-07**

**निर्माण :** 7 फीचर फिल्म और 4 लघु फिल्मों का निर्माण

**विपणन :** 7895 शो का आयोजन 32 लाख बच्चे दर्शक

**व्यय :** 273.8 लाख रुपये का व्यय

**2007-08**

**निर्माण :** पूरे वर्ष किसी फिल्म का निर्माण नहीं जबकि दो फीचर फिल्म और एक लघु एनिमेशन फिल्म लगभग पूरी।

**विपणन :** 6589 शो का आयोजन 32 लाख बच्चे दर्शक

**व्यय :** 246.00 लाख रुपये का व्यय

**2008-09**

**निर्माण :** 4 फीचर फिल्म और 1 लघु फिल्म पूरी

**विपणन :** 12957 आयोजित लगभग 35 लाख दर्शक बच्चे

**व्यय :** 381.00 लाख रुपये का व्यय

**2009-10**

**निर्माण :** 5 फीचर फिल्म पूरी कर ली गई

**विपणन :** 4741 आयोजित लगभग 23 लाख दर्शक बच्चे

**व्यय** : 419.00 लाख रुपये का व्यय

**2010-11**

**निर्माण** : अब तक कोई फिल्म नहीं बनी

**विपणन** : 6378 शो आयोजित

**व्यय** : 400.00 लाख रुपये व्यय

2011-12 (31-12-2011 तक)

**निर्माण** : 2 फीचर फिल्में पूरी

**विपणन** : 5,832 शो आयोजित, लगभग 26 लाख दर्शक बच्चे

**व्यय** : 494.00 लाख रुपये व्यय

# भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

भारतीय फिल्म संस्थान की स्थापना 1960 में हुई थी, जिसे 1974 में बदलकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय के रुप में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे कर दिया गया। सोसायटी में फिल्म, टेलीविजन, संचार, संस्कृति, संस्थान के पुराने छात्र और पदेन सरकारी सदस्य हैं। संस्थान का संचालन चैयरमैन की अध्यक्षता वाली परिषद करती है। जाने-माने फिल्म निर्देशक श्री सईद मिर्जा इसके अध्यक्ष हैं।

2. संस्थान निर्देशन, सिनेमैटोग्राफी (फिल्म और टेलीविजन), संपादन (फिल्म और टेलीविजन) आडियोग्राफी (फिल्म और टेलीविजन) में तीन वर्ष का पीजी डिप्लोमा, अभिनय, कला निर्देशन और निर्माण डिजाइन में 2 वर्ष का पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम और एनीमेशन और कंप्यूटर ग्राफिक्स, आडियोग्राफी और टेलीविजन इंजीनियरिंग में एक वर्ष का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चलाता है।

3. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अलावा संस्थान कार्यरत पेशेवरों के लिए और संबंधित क्षेत्रों में रुचि रखने वालो के लिए लघु कालिक पाठ्यक्रमों का भी आयोजन करता है।

4. संस्थान फिल्म और टीवी उद्योग कुशल विशेषज्ञ और तकनीशियन प्रदान करता है। एफटीआईआई के छात्र भारतीय फिल्म और टेलीविजन उद्योग में अपनी पहचान बना चुके हैं। उद्योग की अनेक जानी-मानी हस्तियां संस्थान के छात्र रह चुके हैं। छात्रों की डिप्लोमा फिल्मों ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंर्तराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेती हैं और छाप छोड़ती हैं।

5. एफटीआईआई के पूर्व छात्रों ने 57 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों 2009 में आठ पुरस्कार जीते। तथागत सिंह निर्देशित संवाद फिल्म एकती काकतालियो गोल्पो और कौशल ओझा निर्देशित वैष्णव जन तो... को एक निर्देशक की पहली गैर फीचर फिल्म के लिए रजत कमल तथा निर्माता और निर्देशक प्रत्येक को 37,500/-रुपए प्रदान किए गए। सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी के लिए रजत कमल और 50,000/-रुपए का इनाम (कैमरामैन और फिल्म प्रासेसिंग लेबोरेटरी को) फिल्म गरुड़ के कैमरामैन दीपू एस उमी और एडलैब को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ आडियोग्राफी के लिए रजत कमल और 50,000/-रुपए का पुरस्कार लिपिका सिंह देसाई को दिया गया। फिल्म समारोहों के निदेशकों द्वारा विजय की सिनेमैटोग्राफी के लिए स्व. कैमरामैन नितिका भगत को विशेष उल्लेख के रुप में (केवल प्रमाण पत्र) प्रदान किया गया।

6. एफटीआईआई की डिप्लोमा फिल्म नार्मीनि (निर्देशक दीप्ति गोगना) सर्वश्रेष्ठ भारतीय प्रविष्टि के रुप में पैटन एवार्ड और स्वाति खत्री की रिफ्लेक्शंस को कोलकाता में 8 वें कल्पनिर्झर अंतर्राष्ट्रीय लघुकथा फिल्म समारोह में जूरी ने विशेष उगेख किया।

7. राधिका मूर्ति की फिल्म मोटरवाइक ने 2011 में 9वें पुणे अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, श्याम रात सहर (जी मुरली की सिनेमैटोग्राफी) को सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी और तथागत सिंहा की एकती काकतालियो गोल्पो ने सर्वश्रेष्ठ एफटीआईआई छात्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ।

8. तथागत सिंहा की कम एंड सी (प्लेबैक) को इंडो-कनाडा स्टुडेंट इनोवेशन पुरस्कार 2011 मिला। संस्थान के ग्राफिक और एनिमेशन के छात्र को मिलने वाला यह पहला पुरस्कार है।

9. संस्थान के कामकाज पर सरकार समय समय निगरानी करती है, जबकि अनुदान सहायता जारी करने के लिए, संचालन परिषद और स्थायी वित्त समिति आदि की बैठकों में, जिसमें सरकार के भी प्रतिनिधि होते हैं। संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा की आडिट रिपोर्ट से पता चलता है कि संस्थान का कामकाज आमतौर पर संतोषजनक पाया गया है।

# सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

## सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के कार्यों की समीक्षा

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत 1995 में की गई थी। इसे पश्चिम बंगाल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। सोसायटी में फिल्म, टेलीविजन,संचार, संस्कृति, संस्थान के पूर्व छात्र, सरकार के पदेत सदस्य जैसी जानी-मानी हस्तियां हैं। संस्थान का संचालन चेयरमैन की अध्यक्षता वाली एवं संचालन परिषद द्वारा किया जाता है। वर्तमान में प्रसिद्ध फिल्मी कलाकार रणजीत मलिक इसके चेयरमैन हैं।

2. संस्थान तीन वर्ष का स्नातोकोत्तर डिप्लोमा निर्देशन और स्क्रीनप्ले व लेखन, संपादन, सिनेमेटोग्राफी और ऑडियोग्राफी।

3. संस्थान में बुनियादी डिप्लोमा के साथ अन्य लघुकालिक पाठ्यक्रम आयोजित करता है और अन्य संस्थाओं और फिल्म उद्योग के अनुरोध पर विभिन्न परियोजना पर कार्य करता है।

4. संस्थान फिल्म और टीवी उद्योग के उच्च कौशल वाले विशेषज्ञ और तकनीशियन प्रदान करता है। छात्रों द्वारा बनाई गई डिप्लोमा फिल्में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेती हैं और सराही जाती हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान छात्रों की निम्नलिखित फिल्मों को भारत और विदेश के विभिन्न समारोहों में चुना गया।

| क्रमांक | फिल्म के नाम | पुरस्कार जीता | निर्देशक/सिनेमोटोग्राफी |
|---|---|---|---|
| 1. | पोचा एप्पल | प्रथम पुरस्कार (संयुक्त विजय) सर्वश्रेष्ठ डिप्लोमा फिल्म, कैंपस फ्रांस फिल्म स्कूल कंपीटीशन ऑफ डिप्लोमा फिल्म एम्बेसी ऑफ फ्रांस, भारत स्थित और कैम्पस फ्रांस ने जनवरी 2010 में पुरस्कृत किया। | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | माई अर्मीनिया नेबरहुड (अंग्रेजी) | बेस्ट सिनेमोग्राफर का पुरस्कार, डाक्यूमेंटरी फिल्म फेस्टीवल, केरला, 2009 | सिनेमोटोग्राफर : के. अपाल्ला स्वामी |
| 3. | बाक्सिंग लेडी (हिंदी) | 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2010 में रजत कमल (खेल पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म) प्रदान किया गया। | निर्देशक : अनुषा नंदकुमार |
| 4. | धर्म (हिन्दी) | 58वें राष्ट्रीय पुरस्कार-2010 में रजत कमल पुरस्कार (सर्वश्रेष्ठ संपादन) | निर्देशक : तिन्नी मित्र |
| 5. | बाघेर बाच्चा (बंग्ला) | वर्ल्ड सिनेमा, एम्सटर्डम 2010 में प्रदर्शन के लिए चयनित | निर्देशक : विष्णु देब हालदर |
| 6. | फालिंग अवेक | चौथे केरल फिल्म समारोह 2010 में प्रदर्शन के लिए चयनित | निर्देशक : रेयान डी मेलो |
| 7. | सीताहरण और अन्य कहानियां | चौथे केरल फिल्म समारोह 2010 में प्रदर्शन के लिए चयनित | निर्देशक : अनुषा नंदकुमार |
| 8. | मेरे जीवन साथी | चौथे केरल फिल्म समारोह 2010 में प्रदर्शन के लिए चयनित | निर्देशक : राजदीप पाल |
| 9. | बाक्सिंग लेडी (हिंदी) | वोमेन मेल वेव्स फिल्म समारोह, ताइवान 2010 और सिनेमैक्स फिल्म समारोह स्टटगार्ट 2010 के लिए चयनित | निर्देशक : अनुषा नंदकुमार |
| 10. | सीताहरण और अन्य कहानियां | केरल लघु फिल्म/वृत्त चित्र समारोह 2011 में सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो के लिए पुरस्कृत | निर्देशक : अनुषा नंदकुमार |
| 11. | कुसुम (हिंदी) | मई में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों 2010-2011 | निर्देशक : शुभन बनर्जी |

5. संशोधित अनुमान और अंतिम अनुदान 600.00 लाख रुपए के मुकाबले वर्ष 2009-10 के दौरान गैर योजना व्यय 652.82 लाख रुपए हुए। 52.8 लाख रुपए का अधिक व्यय वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों से किया गया।

योजना के तहत 2009-10 के लिए स्वीकृत 700.00 लाख रुपये के अनुदान की तुलना में वर्ष में 425.00 लाख रुपये प्राप्त हुए। जिसमें पिछले वर्ष 2008-09 का व्यय न हुआ शेष भी शामिल है। 423.35 लाख रुपए का उपयोग 2009-10 में हुआ और 1.65 लाख रुपए की शेष राशि का 2009-10 में उपयोग नहीं हो सका।

संस्थान के कामकाज की समीक्षा सरकार समय-समय पर करती है, जबकि अनुदान सहायता की किस्त जारी करने के लिए संचालन परिषद और स्थायी वित्त समिति आदि की बैठकें होती हैं जिसमें सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिट लेखा विवरण के अनुसार समग्र रुप से कामकाज संतोषजनक रहा।

# प्रसारण क्षेत्र

## एफ एम प्रकोष्ठ

### आउटकम बजट के प्रस्तुतीकरण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई

परियोजना के भौतिक के साथ वित्तीय कामकाज की मानीटरिंग मंत्रालय द्वारा मासिक, त्रैमासिक और छमाही बैठकों में की जा रही है।

# प्रसार भारती

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) देश में सार्वजनिक सेवा प्रसारणकर्ता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन इसके दो घटक हैं। देश के लोगों को जानकारी देने, शिक्षित करने और उनका मनोरंजन करने के साथ ही प्रसारण का एक संतुलित विकास सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक प्रसारण सेवाएं आयोजित करने और उन्हें संचालित करने के अधिदेश के साथ 23 नवंबर, 1997 को प्रसार भारती की स्थापना की गई।

प्रसार भारती द्वारा वर्ष 2010-11 के दौरान तथा वर्ष 2011-12 की तीसरी तिमाही तक वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन संबंधी उपलब्धियों का वर्णन अध्याय-IV में दिया गया है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की स्कीमों/परियोजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन की निगरानी के दो स्तर है- (i) मीडिया इकाई स्तर और (ii) मंत्रालय स्तर। प्रसार भारती को जारी किए गए योजना व्यय फंड की गति की निगरानी के लिए साप्ताहिक आधार पर मंत्रालय में समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। प्रगति की निगरानी वित्तीय और भौतिक दोनों मापदंडों पर की जा रही है। योजना परिव्यय के उपयोग स्तर के संबंध में मंत्रालय तीव्र विकास प्रक्रिया की आवश्यकता पर बल देता है और आने वाली अड़चनों को दूर करने पर जोर देता है।

# मुख्य सचिवालय प्रसारण विंग स्कीम

# भारत में समुदाय रेडियो आंदोलन को बढ़ावा

### आउटकम बजट प्रस्तुतीकरण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई

व्यावसायिक रुप से प्रशासित कम्युनिटी रेडियो सपोर्ट स्कीम (सीआरएसएस) की स्थापना वर्तमान और नए समुदाय रेडियो स्टेशनों को आधारतंत्र/उपस्कर/प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/विषयवस्तु विकास और संचालन लागत आदि के लिए अनुदान देने के लिए की जाएगी। सीआरएसएस में अंतर मंत्रालय समिति, स्क्रीनिंग समिति और कार्यक्रम प्रबंधन इकाई होगी।

सीआरएसएस अनुदान देने के अलावा उसका मूल्यांकन, प्रबंधन और दस्तावेज बनाएगा। अनुदान प्राप्त करने वालों को वित्तीय और विवरणात्मक रिपोर्ट देनी होगी।

आईईसी गतिविधियों के तहत जागरुकता/क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का कामनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया (सीईएमसीए) नई दिल्ली और समुदाय रेडियो एसोसिएशनों के सहयोग से पूरे देश में आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय सम्मेलन और पोस्टर प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सीआर आपरेटरों के तकनीकी प्रशिक्षण के माडयूल, डिजाइन किए जाएंगे, एक सीआरएस माडल का भारत और विदेश में अध्ययन दौरा किया जाएगा, प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा, आईईसी सामग्री का मुद्रण और समुदाय रेडियो क्षेत्र में नवीनीकरण का समर्थन किया जाएगा।

आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए मंत्रालय में सिफारिशें/सुझाव स्वीकार किए जाते हैं।